

नागरिक शास्त्र के सिद्धान्त

नागरिक शास्त्र के सिद्धान्त

पहला भाग

ओम्प्रकाश मिहल एम० ए०
बहेन्द्र कालेन, वट्टियाला

१९५६

एस० चन्द्र एण्ड कम्पनी
दिल्ली - जालंधर - लखनऊ

पंजाबी संस्करण भी प्राप्य है

एस० चन्द्र० एण्ड कम्पनी

दिल्ली—फव्वारा

कम्पनऊ—काल बाग

लाहौर—मार्ड हीरा रोड



मूल्य ३॥) रुपये

प्रकाशक : श्रीरोचकर शर्मा, एस० चन्द्र एण्ड कम्पनी, फव्वारा, दिल्ली ।

मुद्रक : श्रीनिवास प्रेस, श्रीरोचकर, दिल्ली ।

भूमिका

यह पुस्तक इंटरमीडियेट के विद्यार्थियों की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए लिखी गयी है। यह नागरिक शास्त्र की बोर्ड पुस्तक तक ही अपना अन्तर्गत मर्यादित नहीं रखती है। यदि वह राष्ट्र के नौजवान लड़कों और लड़कियों में सीधे-सीधे गीतों, शायरी, नृत्य, खेलों और ईमानदारी के व्यवहार करने की भावना डालने में मदद दे, ऊँचे उठने की इच्छा और इच्छा के लिए मुक्तता देना दे, और हम लोग सब करने वाली समस्याओं को सुलझाने का होमला उनमें बसाए। इन पुस्तक में वाद-विवाद, कमीडि, और काम करने के, व्यक्ति स्वयं जीवन के पक्ष-प्रदर्शन के, कुछ निम्न मिलेंगे।

इस शास्त्र इस पुस्तक में कुछ ऐसी सामाजिक समस्याएँ सीधे-सीधे से देना करने की कोशिश की गयी है, जो पढ़ाई के बाद विद्यार्थी के सामने जरूर आयेगी। भारत के नागरिकों पर अब जो नयी जिम्मेदारियाँ आ रही हैं उन्हें देखते हुए यह पुस्तक भारतीय नागरिकता का शास्त्र बनाना है।

महेश कालेज, पटियाला।
१५ जून, १९५६।

ओम्प्रसाद सिंहल -
१५/७/५६

विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
1	नागरिक शासन (Civics) किसे कहते हैं ~	१
2	नागरिक शासन को परिचारा, क्षेत्र, श्रद्धा और उपयोगिता ~	६
3	नागरिक शासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों से सम्बन्ध --	१४
4	प्रमुख और समाज ~	१९
5	माहुर्य या गण ~	२६
6	समुदाय—गाव और नगर ~	३९
7	सामाजिक समस्या (समस्या आति और धर्म)	४६
8	राज्य और हमारे घटक तत्व ~	५८
9	राज्य का उद्भव और प्रकृति ~	६८
10	राज्य के भाग और लक्ष्य ~	७७
11	मिश्रा ~	९१
12	नागरिक और नागरिकता ~	९९
13	नागरिक के अधिकार और कर्तव्य ~	११०
14	विधि, स्वाधीनता और समता-अपराध और दण्ड ~	१२२
15	सरकार—विधानात्मक कार्य, न्यायालय ~	१३९
16	सरकार के रूप—पारलमन्त, कुलीनतन्त्र, लोकतन्त्र और अधिनायकतन्त्र ~	१५७
17	शासन के रूप (प्रमाणित) ~	१६६
18	निर्वाचन प्रणाली लोकतन्त्र, और राजनैतिक दलों का कार्य ~	१८१
19	समृद्धि और सम्यक्ता अवकाश और मनोरंजन ~	२०१
20	राष्ट्रवाद और अन्तराष्ट्रवाद गवर्नराष्ट्र सभ ~	२१२

अध्याय :: १

विषय-प्रवेश

नागरिक शास्त्र (Civics) किसे कहते हैं ?

नागरिक शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्य को, नागरिक के रूप में, अध्ययन करता है, और इस बात पर विचार करता है कि समाज और राज्य के सदस्य के रूप में मनुष्य के जीवन-योग से अधिकार और कर्तव्य हैं। इस प्रकार, नागरिक शास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन के एक पहलू पर विचार करता है और वह है उसका नागरिक पहलू। अन्य सामाजिक विज्ञान उसके सामाजिक जीवन के दूसरे पहलुओं पर विचार करते हैं। इतिहास मनुष्य के गुजरे हुए सामाजिक जीवन की तस्वीर बनाना है, अर्थशास्त्र मनुष्य के राजी बमाने की कोशिशों पर विचार करता है, आचार शास्त्र (Ethics) मनुष्य के कार्यों के नैतिक पहलू, अर्थात्-सुझाई, पर गौर करता है, राजनीति विज्ञान राजनैतिक कार्यों की चर्चा करता है, इत्यादि। अमल बात यह है कि मनुष्य समाज बनाकर रहने वाला प्राणी है। अपने स्वभाव और अपनी आवश्यकता, दोनों, से वह एक सामाजिक प्राणी है। कोई आदमी अपने सब काम खुद नहीं कर सकता। हर सामाजिक विज्ञान अस्तित्व के इस समूह के कथन की सचाई का मानता है कि जो आदमी सामाजिक नहीं है, वह या तो देवता होगा या पशु। मनुष्य के सामाजिक कार्यों के बहुत से रूप हैं, अर्थात् आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक। इन सब कार्यों में उसे परिवार, जाति, गांव, गहर, मजहब, राज्य, फैक्टरी, और कब्र जैने कई साहचर्य या मध्य, समुदाय या बिगदरी और मस्याओं बनानी पड़नी है।

पर नागरिक शास्त्र में हम य ता सारे सामाजिक जीवन पर विचार करते हैं, और न मब सचा, बिगदरिया और मस्याओं पर। नागरिक शास्त्र में हम सामाजिक जीवन के सिर्फ एक पहलू पर विचार करते हैं और वह यह है कि नागरिक के रूप में मनुष्य का क्या काम है, और हम किसे उन साहचर्यों या मध्यों, बिगदरियों और मस्याओं का अध्ययन करते हैं, जो नागरिक के तौर पर मनुष्य के जीवन और कार्यों पर गहरा असर

१ साहचर्य या मध्य (Association) एक एकत्र रहने वाले लोगों के संगठित समूह का कहते हैं।

२ समुदाय या बिगदरी उन लोगों के समूह को कहते हैं जिनके कुछ मल्ले मिले हैं और इस मल्ले मिलने के कारण जिनसे एकता की शक्ति आती है।

३ मस्या उन सम्बन्ध का नाम है जो बिना मनुह के सदस्यों के बीच होता है।

झालनी है और उन पर भी उसी हद तक विचार करने है जहां तक वे ऐसा असर डालती है। मियाज के तौर पर, बहुत से माहवयों या मधों में से हम निम्न परिवार और राज्य पर विचार करते हैं। परिवार पर हम इस विषय पर करते हैं क्योंकि नागरिक की गुरु की शिक्षा, आदमी, और लाठी पर हमका बड़ा असर पड़ता है। नागरिक को अपने परिवार में ही सबसे पहले बच्चे के रूप में नागरिकता का पहला सबक मिलता है। जो आज बच्चा है, बड़ी काल नागरिक हो जायेगा, और बच्चा नैसा ही बनेगा, जैसा उसका परिवार उसे बनायेगा। हम राज्य पर इस विचार करने हैं क्योंकि राज्य के बिना कोई नागरिक नहीं हो सकता। नागरिक हमेशा किसी राज्य का नागरिक होगा। जहां राज्य नहीं, वहां नागरिक भी नहीं। इसके अलावा, नागरिक के अधिकार और कर्तव्य उसे राज्य की सहायता से प्राप्त होते हैं। नागरिक शास्त्र मुख्य रूप से नागरिक के इन अधिकारों और कर्तव्यों पर ही शोध-विचार करता है। यह पक्ष है कि अधिकारों का जन्मदाता राज्य नहीं है, पर उनका आगम में और मुक्तिक्रम तौर पर फावदा उठाने के लिये यह विष्णु लक्षणों है कि राज्य इन अधिकारों की रक्षा करे, और उनकी शिक्षा करे। नागरिक विचारों हमेशा दूसरों के साथ में बँटकर चलने की जिन्दगी है। हमें समाज के और लोगों को देखते हुए अपना आचरण ऐसा रखना चाहिए कि धर्म में कोई उद्वेग नहीं या अदृष्टा पैदा न हो। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे निम्न वह नाम करना चाहिए जिन पर हमने लीम ऐतबार न करें। इसी तरह, दूसरों को भी आपन में ऐसा ही मान्य करना चाहिए। इस तरह अधिकार का मतलब यह हो जाता है कि उन्हें हमारे में नष्ट जाया है, जितना धर्म में नष्ट कर दिया गया है, और राज्य अपनी ताकत के और से उन अधिकारों की, दूसरों की दखलबादी से, रक्षा मान करेगा है।

नागरिक शास्त्र में हम क्या अध्ययन करते हैं ?

इस प्रकार नागरिक शास्त्र के विद्वानों के लिये राज्य का अध्ययन विष्णु लक्षणों है। राज्य का अध्ययन करते हुए हमें हमारे जन्म, धर्म, कानून, मरणा और स्थिति का भी अध्ययन करना होगा। राज्य का नागरिक में सम्बन्ध एक मुश्किल समस्या है क्योंकि एक ओर तो राज्य की सत्ता बड़ी और सीमाहीन शक्ति है और दूसरी ओर आदमी की आजादी है। राज्य की सत्ता उंची और असीमित शक्ति को सर्वोच्चता या प्रभुता (Sovereignty), कहते हैं। राज्य इन शक्ति के जेने के कारण ही बनाना होता है। इस प्रकार नागरिक शास्त्र के विद्वानों के विचार के लिये सर्वोच्चता, कानून, आजादी, सहायता और अधिकारों की सम्बन्ध बड़ी जटिल बात हो जाती है।

राज्य के अध्ययन में सरकार पर भी विचार करना पड़ता है। सरकार के बिना राज्य अपना काम नहीं कर सकता। राज्य एक विचार मात्र है। हम राज्य की कल्पना ही कर सकते हैं, उसे महसूस नहीं कर सकते और न सुझा देह ही सकते हैं। सरकार में मंत्री, मसद, उच्च न्यायालय और नेता आदि हैं, और इन सब चीजों को हम देख सकते हैं। राज्य कोषा में कानून और व्यवस्था बनावे रखने से लिये होता है। इस

नाम को यह सरकार के जरिये करता है ।

इस तरह नागरिक शास्त्र के विचार्यों के लिये सरकार पर बारीकी से विचार करना जरूरी हो जाता है । इसलिये हम सरकार के रूपों, इसके समझ और कामों पर विचार करते हैं । हर एक सरकार की तीन शाखाएँ होती हैं । (१) विधायिका (Legislature), (२) कार्यपालिका (Executive) और (३) न्यायपालिका (Judiciary) । सदन और विधान सभाएँ विधायिका का रूप हैं । राष्ट्रपति, राज्यपाल और सभी कार्यपालिका को सूचित करते हैं । न्यायालय न्यायपालिका के रूप में है । सरकार का अध्ययन करते हुए हम राजनैतिक दलों का भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि विधान सभाओं और सदन के चुनावों में उनका बहुत महत्व हिस्सा होता है । सभी भी किसी न किसी राजनैतिक दल के ही सदस्य होते हैं ।

हम ऊपर बता चुके हैं कि सभों में से विधायी परिवार और राज्य पर हम विस्तार से विचार करते हैं । इसी प्रकार, समुदायों में गांव का और नगर का अध्ययन नागरिक शास्त्र के विचार्यों के लिये बहुत जरूरी है । परिवार से बाद नागरिक के कामों का केन्द्र गांव और नगर छोटे हैं । परिवार की तरह गांव और नगर भी नागरिकता की शिक्षा देते हैं । किसी नागरिक को लोकतन्त्र का पहला पाठ गांव-सभाओं और नगर-पालिकाओं में ही मिलता है ।

साहचर्यों या सभों और समुदायों के अलावा हम जाति, सम्पत्ति और धर्म आदि कुछ सत्ताओं का भी अध्ययन करते हैं । हमारे मूल्य में जाति बहुत पुरानी सत्ता है और इसने लोगों की जिल्दगी में अच्छा और बुरा, दोनों तरह का असर डाला है । आजकल इसे सब जगह बुरी चीज समझा जाता है, क्योंकि इसके कारण हमारी जनता का बहुत बड़ा हिस्सा पिछड़ा रहा । इसी प्रकार धर्म का भी किसी नागरिक के जीवन में बहुत बड़ा हिस्सा होता है । इसका भी अच्छा और बुरा, दोनों तरह का असर होता है । धर्म के बहुत ज्यादा असर ने हमें भाव्यवादी और फिराफिरस्त बनाया है । फिरफे-दाराणा सगळे समाज के मान्य जीवन को अनाथ कर देने हैं—नागरिक शास्त्र शास्त्र जीवन का निर्माण करना चाहता है । पर धर्म कुछ अच्छी बातें भी मिलाता है जो मनुष्य को नागरिक बनाने में बड़ी सहायक हो सकती हैं । यह हम सहनशीलता, हमदर्दी, दया, भाईचारे और प्रेम का पाठ पढ़ाता है । इस प्रकार, नागरिक शास्त्र के विचार्यों को नागरिक के जीवन पर धर्म के अच्छे और बुरे प्रभावों पर भी गौर करना चाहिये । सम्पत्ति भी नागरिक के जीवन पर गहरा असर डालती है । कुछ न-कुछ सम्पत्ति के बिना आदमी पूरी तरह सुखी नहीं हो सकता । पर जब सम्पत्ति की अगमनता से गरीबी और बेरोजगारी की समस्या पैदा होती है । गरीब और बेरोजगार नागरिक समाज पर छोड़ा है ।

नागरिक शास्त्र में हम नागरिक के जीवन पर असर डालने वाले साहचर्यों या सभों, समुदायों और सत्ताओं पर ही विचार नहीं करते, बल्कि उन बला पर भी विचार करते हैं, जिससे कोई आदमी अच्छा नागरिक बनता है । नागरिक शास्त्र सामाजिक इंजीनियरिंग या विज्ञान भी है । इस दृष्टि में नागरिक शास्त्र एक व्यावहारिक विज्ञान

है। इसका मकसद है अच्छे नागरिक तैयार करना और साथ ही शान्तिमय, सुगुहाल तथा बेल्जिमियन वाला सामाजिक और नागरिक जीवन बनाना। उदाहरण के लिए, शिक्षा अच्छा नागरिक बनाने में मदद करती है। बिना शिक्षा के आदमी जानवर जैसा रहता है। बिना तालीम पाये किसी नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में ठीक-ठीक ख्याल नहीं पैदा हो सकता, और मुन्नी सामाजिक जीवन के लिये यह बिलकुल लाजमी है कि आदमी को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में सही ख्याल हो। बिना ठीक तालीम के कोई नागरिक सामाजिक जीवन में अपना पूरा योगदान भी नहीं कर सकता।

आखिरी बात यह है कि नागरिक शास्त्र में हम नागरिक के इसी रूप पर विचार नहीं करते कि वह एक राज्य का अंग है, बल्कि इस रूप पर भी विचार करते हैं कि वह सारी मनुष्य जाति का एक हिस्सा है। मारा सत्तार एक बड़ी विरादरी है। अगर इस बड़ी विरादरी की ज़िन्दगी में हल्कन बची हुई हो तो किसी राज्य में शानि नहीं हो सकती। इसलिए हमें नागरिक के जीवन के अन्तर्राष्ट्रीय पहलू पर भी विचार करना होगा। हम राष्ट्रवादिता (nationalism) और अन्तर्राष्ट्रीयता के फायदे और नुकसान भी मोचने होंगे। राष्ट्रवादिता का अर्थ है अपने देश से प्रेम, अन्तर्राष्ट्रीयता का मतलब है अन्य राष्ट्रों से भी दुस्खन। मयुन राष्ट्र मय (United Nations Organisation) जैसी मर्यादा जाति कायम रखने और दुनिया को लड़ाई की मरवाबी से बचाने के लिये बनी हुई है। इसलिए मयुन राष्ट्र मय के लक्ष्य, मण्डन और कानों का अध्ययन भी नागरिक शास्त्र में किया जाता है।

सारांश

नागरिक शास्त्र कितने कहते हैं — नागरिक शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। यह नागरिक के रूप में मनुष्य का और उसके अधिकारों तथा कर्तव्यों का अध्ययन करता है। अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है और उन्हीं की तरह यह मनुष्य के समाजगत जीवन के मिक एक पहलू का अध्ययन करता है।

नागरिक शास्त्र में हम क्या अध्ययन करते हैं? — नागरिक शास्त्र के अध्ययन का केन्द्रबिन्दु नागरिक है। प्रथम तो, हम नागरिक का, उसके अधिकारों और कर्तव्यों का और उन अनेक प्रभावों का अध्ययन करने हैं जो उसे अच्छा या बुरा नागरिक बनाने हैं, उदाहरण के लिये, हम उन पर परिवार, शिक्षा, सम्पत्ति, सम्मान और कुसुन या अवकाश के प्रभावों का अध्ययन करते हैं। इसलिए नागरिक शास्त्र एक व्यावहारिक विज्ञान है।

दूसरे, हम कुछ ऐसे माहुरों या मयों, समुदायों और मरवाओं का अध्ययन करते हैं, जिनका नागरिक के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सातव्यों में से हम परिवार और राज्य का, समुदायों में से गांव और सहर का, तथा संस्थाओं में से सम्पत्ति, धर्म, जाति या वर्ग का अध्ययन करते हैं।

तीसरे, हम राज्य और उसके उद्गम (Origin), बृद्धि, कार्यों, और

प्रयोजन या मतभेद का अध्ययन करने है। राज्य का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना कोई आदर्शी नागरिक नहीं बन सकता। हम उन सब समस्याओं का भी अध्ययन करते हैं जिनका राज्य और नागरिक के बीच सम्बन्ध है, अर्थात् बानून, सर्वोच्चता या प्रभुत्वता, स्वतन्त्रता, अधिकारों और मर्यादा की समस्याएँ।

चौथे, राज्य के अध्ययन में सरकार और इसके रूपों, नीतियों और इसके संगठन का अध्ययन भी करना पड़ता है। आज के जमाने में जबकि राज्य लाक्षणिक हैं, सरकार को चलाने में नागरिक का जो हिस्सा है उसका अध्ययन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी कारण, हम राजनैतिक दलों और लोकमत का भी अध्ययन करते हैं।

अन्त में, नागरिक शासन अपने अध्ययन की, राज्य के एक मंडल के रूप में मनुष्य का जो कार्य है, उसके अध्ययन तक ही सीमित नहीं रहता। यह उम्मा, अधिक बड़ी विरादरी, अर्थात् मालव विरादरी, के मंडल के रूप में भी अध्ययन करता है। इस मिश्रितले में हम मनुष्य राष्ट्र रूप जैसे संगठनों का अध्ययन करते हैं।

नागरिक शास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र, विधियाँ और उपयोगिता

नागरिक शास्त्र की परिभाषा

नागरिक शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों का अध्ययन होता है। 'सिविक' शब्द लैटिन के 'सिविटस' और 'मिषिस' शब्दों से मिलकर है। पहले शब्द का अर्थ है 'नगर' और पिछड़े शब्द का अर्थ है 'नागरिक'। उन अर्थ में, यह कहा जा सकता है कि नागरिक शास्त्र मनुष्य का नगर के मध्य के रूप में अध्ययन है, या यह कहा जा सकता है कि नागरिक शास्त्र मनुष्य का नगर में आम तौर पर नगर-राज्य (City-State) द्वारा कहे जाते हैं। मनुष्य के नगरों के साथ राज्य का आकार बढ़ता गया, यहाँ तक कि आज, कम, चीन और भारत के समान बड़े बड़े राष्ट्रीय राज्य बन गये हैं। राज्य का आकार बढ़ जाने के साथ नागरिक शब्द का अर्थ भी विस्तृत हो गया है। आज नागरिक मगर नगर का मध्य नहीं है, बल्कि वह एक लम्बे-चौड़े और बड़े राजनयिक संगठन, अर्थात् राज्य, का भी सदस्य है, पर नागरिक शास्त्र के क्षेत्र की दृष्टि से इतना भी बढ़ी है। प्रत्येक नागरिक राज्य का मध्य होने के अनिवार्य मानी मनुष्य विराट् की भी एक शिखा है। अब मारी मनुष्य ज्ञान का साथ प्रत्येक अच्छे नागरिक की विज्ञान का विषय समझा जाता है। इसमें नागरिक शास्त्र का महत्व बहुत विस्तृत हो जाता है। इसलिए अब नागरिक शास्त्र को मनुष्य के साम-प्रयोग की भाषा का ही अध्ययन, अर्थात् उसके परिवार, गाँव या नगर का ही अध्ययन, न समझना चाहिए, जैसा कि कुछ समय पहले तक समझा जाता था, अब इसे नागरिक और राज्य के सब सम्बन्धों का, चाहे वे स्थानीय हों, राष्ट्रीय हों, या अन्तराष्ट्रीय हों, अध्ययन मानना चाहिए।

नागरिक शास्त्र का क्षेत्र—इस पुस्तक के विषय-प्रवेश में हमने नागरिक शास्त्र के क्षेत्र और विषयवस्तु का काफ़ी परिचय दिया है। यहाँ हम उस सबका क्षेत्र में उल्लेख करने जिसमें ये बात स्पष्ट रूप से विद्यादिश के सामने आ जाए। नागरिक शास्त्र के क्षेत्र में एक बार तो नागरिक के रूप में मनुष्य के सब कानों का अध्ययन शामिल है, और दूसरे ओर, उन सब कानों का अध्ययन इसमें शामिल है जिनमें उनके अच्छा नागरिक बनने में मदद या बाधा होती है। हर नागरिक किसी समाज का और किसी राज्य का अंग होता है। समाज में अनेक सादृश्य या मध्य, मधुदाय और

तरफ़ाए होती हैं। उन्हें मनुष्य ने अपनी तरह-तरह की जरूरतें पूरी करने के लिये और अपने फायदे के लिये बनाया है। परिवार, गाँव, नगर और राज्य और दूसरे अनेक समूह नागरिक के काम करने की जगह हैं और इन सबका उसने जीवन के ऊपर गहरा असर पड़ता है। जाति, सम्पत्ति और धर्म जैसी अनेक सत्थाएँ भी उन पर अच्छा या बुरा असर डालती हैं, पर नागरिक किसी राज्य का सदस्य अवश्य होता है। इसलिए नागरिकता का अध्ययन करते हुए राज्य का, इसके जन्म, प्रवृत्ति, कामों और प्रयोजन का अध्ययन भी जरूरी हो जाता है। मनुष्य के नायक राज्य का सम्बन्ध सर्वोच्चता या प्रभुता, कानून, आजादी, समानता और अधिकारों के मसले पैदा करता है। नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी को, इन सत्थों का अर्थ और इनका आपसी सम्बन्ध साफ-साफ समझ लेना चाहिए। फिर राज्य अपने अभिप्रायों, सरकार, के जरिये काम करता है। इसलिए सरकार के रूप, संगठन और कार्यप्रणाली भी नागरिक शास्त्र के क्षेत्र में आते हैं। नागरिक शास्त्र सामाजिक इंजीनियरिंग का विज्ञान है। इस नाते इसका काम है अच्छे नागरिक पैदा करना और समाज में सान्ति और तान्त्रिक व्यवस्था करना। शिक्षा, छुट्टी, मनोरंजन, सस्त्रुति और सभ्यता से अच्छे और उपयोगी नागरिक पैदा करने में मदद मिलती है। दूसरी ओर, गरीबी, अनपठन, सराब सन्दुरस्ती, बुरी सामाजिक प्रथाएँ, बुरी सत्थाएँ और बुरे कानून अच्छी नागरिकता के दुश्मन हैं। इसलिए, नागरिक शास्त्र के गम्भीर विद्यार्थी का यह पता होना चाहिए कि नागरिक के जीवन के लिए अच्छी बातें कौन सी हैं, और बुरी बातें कौन सी हैं। फिर, अच्छे नागरिक को अपनी निष्ठा सही जगह रखनी चाहिए। उसे न केवल अपने मूल्य के प्रति सच्चा होना चाहिए, बल्कि उसे मनुष्य मात्र से भी उतना ही प्रेम रखना चाहिए। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीयता और मनुष्यवैराग्य राव आदि अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सत्थाओं का अध्ययन भी नागरिक शास्त्र में आता है।

नागरिक शास्त्र विज्ञान भी है और कला भी—जिन विषयों में मनुष्य और उसके कामों का अध्ययन होता है वे सामाजिक विज्ञान कहलाती हैं। उनमें से एक नागरिक शास्त्र है। पर यह भौतिकी और रसायन की तरह धर्मार्थ विज्ञान (exact science) नहीं है। भौतिकी और रसायन में निष्कर्ष धर्मार्थ और सुनिश्चित होते हैं। उनके परिणामों में कोई हेर-फेर नहीं हो सकता। यदि कोई हेर-फेर हो जाय प्रयोग द्वारा उसका कारण बताया जा सकता है। नागरिक शास्त्र में यह नहीं हो सकता। मनुष्य और उसके सत्थाओं पर प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं किये जा सकते। इसके अतिरिक्त, भौतिकी और रसायन में जिन वस्तुओं का वर्णन है, उनकी प्रवृत्ति और आचरण बदलन नहीं, पर मनुष्य का आचरण बदलता रहता है। यदि हम उसके आचरण के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालें तो समझ है कि कुछ समय बाद वे बिल्कुल बदल जाय। फिर, एक ही आदमी अलग-अलग वातावरण में अलग-अलग आचरण करता है। इस प्रकार नागरिक शास्त्र को धर्मार्थ विज्ञान नहीं कहा जा सकता।

इसलिए यह सुझाया गया है कि सांसारिक शास्त्र को विज्ञान नहीं माना जा सकता। यह बात स्वीकार करने योग्य नहीं। यदि विज्ञान शब्द का अर्थ एक दूसरे से सम्बन्धित बहुत समस्याओं का व्यवस्थित अध्ययन है तो सांसारिक विज्ञान का विज्ञान माना जाना चाहिए। सांसारिक विज्ञान का विद्यार्थी अपने विषय के, समस्याओं पर वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करने की कोशिश करता है। यह इतिहास पढ़कर सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी और तथ्य हासिल करता है, उनके अगर देखता है और तब में कुछ नतीजे निकालता है। इन सब बातों में सांसारिक शास्त्र का विज्ञान गहनता का साथ मजबूत साबित हो जाता है।

पर सांसारिक विज्ञान का एक यही वापस नहीं। इसका मतलब इतना है कि पूरा विशाल ब्रह्मा और उसे एक आदर्श सांसारिक बनाना है। यह यह भी लोचन करता है कि बिना अवस्थाओं में सामाजिक जीवन सुखी और मेल-मिलाप वाला हो सकेगा है। इस जगह सांसारिक विज्ञान गूँघल बन जाता है। इसका एक क्रियात्मक मतलब ही होता है।

मनो में, यह कहा जा सकता है कि सांसारिक विज्ञान विज्ञान भी है और ब्रह्मा भी।

सांसारिक विज्ञान के अध्ययन की विधियाँ

सांसारिक विज्ञान का अध्ययन ऊँची विधियों में होता है जिनमें अन्य सामाजिक विज्ञानों का।

(१) प्रयोगिक विधि

हम मनुष्य और उसकी समस्याओं में उस तरह प्रयोग नहीं कर सकते, जिस तरह भौतिकी और रसायन विज्ञान में करते हैं। पर मनुष्य के प्रयोगों के लिये सारा सारा एक प्रयोगशाला है। हम प्रतिदिन देखते हैं कि मनुष्य के अनुभवों के अनुसार व्यवहारों और समस्याओं के रूप बदलते रहते हैं। हर अनुभव मनुष्य को अधिक बुद्धिमान बना देता है, और वह सत्यता की ओर बढ़ता जाता है। परीक्षण या प्रयोग की विधि सांसारिकता की प्रयोगशाला में बड़ी महत्वपूर्ण होती है।

(२) प्रेक्षण (Observation) की विधि

प्रयोग की विधि अमल में प्रेक्षण या अच्छी तरह देखने पर आधारित है। हम अपनी सामाजिक समस्याओं की बात करने हुए देखते हैं, उनके प्रभावों का विश्लेषण करते हैं और कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। हम दूसरे देशों में हम प्रकार की समस्याओं की कार्यप्रणाली देखते हैं और उनकी मुल्यता अपनी समस्याओं से करते हैं।

तब तब कोई इशारा हासिल नहीं होता जब तब हम जाच-पड़ताल करें और विधियों का भी उपयोग न करें।

(३) तुलनात्मक विधि (Comparative Method)

अमल में प्रेरण की विधि है। तुलना के लिए जाच करन बाग्य सामग्री जमा करता है, उसे व्यवस्थित करता है और वहाँ में यादता है और तुलना तथा छटाई (selection) द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समस्याओं के आदर्श रूपों का पता लगाना है।

(४) ऐतिहासिक विधि

तुलनात्मक विधि तब तब उपयोगी नहीं हो सकती जब तब हमका कोई ऐतिहासिक आधार न हो। सामाजिक समस्याओं को भूतकाल के ज्ञान के द्वारा ही अच्छी तरह समझा जा सकता है और इन समस्याओं के जन्म और विकास की परिस्थितियों को जानकर तथा इस बात की ध्यानपूर्वक करके कि आज उनका होना कहाँ तक उचित है हम भविष्य के लिये कुछ नीति तय करने हैं।

(५) दार्शनिक विधि

नागरिक विज्ञान यह भी बताता है कि नागरिक कौशल होना चाहिए। इसलिए विद्यार्थी को कल्पना की दुनिया में घुसना पड़ता है। यह मनुष्य की प्रकृति के बारे में कुछ व्यापक सिद्धान्तों के आधार पर अपने निष्कर्ष निरधारित है और सामाजिक समस्याओं से उनका सम्बन्ध जोड़ता है।

परन्तु एक चेतावनी देना उचित होगा। हमारी कल्पना बहुत उड़न वाली न होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, यह बात जरा तब हो मक इस बात में प्रसन्न होनी चाहिए कि कैसा हुआ जा सकता है। इस प्रकार कल्पना करते समय हमें उन सामाजिक परिस्थितियों में, जिनमें कोई नागरिक रहता है, निष्कुल अलग पक्ष न हो जाना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आदर्श नागरिक पैदा करने के लिए सच्चाई में चलना चाहिए।

नागरिक शास्त्र का अध्ययन क्यों किया जाता है? इसकी उपयोगिता

नागरिक विज्ञान के अध्ययन के व्यावहारिक फायदे बहुत अधिक हैं और उनसे निम्नलिखित लाभ होने हैं —

(१) पहली बात तो यह है कि नागरिक विज्ञान सामाजिक इंजीनियरिंग का विज्ञान है। यह हमें मित्रवर रूढ़ि का ठोस तरीका सिखाता है। यह हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में सही विचार देता है और इस तरह हमारे अन्दर नागरिक बुद्धि पैदा करता है। यदि हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों का सही पता हो तो समाज के समर्थ बहुत कम हो जाते हैं, नागरिकों में अधिक मत-भिन्नता और शांति रहती है, और नाराय समाज अच्छी तरह चलती रहता है। लोगों में अधिक सहयोग और प्रेम होता है। अधिकारों के बारे में मिथ्या भावनाओं पर होने वाली लड़ाइयों पर जो ताकत बरबाद होती है, उसे खराब समझौता, अनपेक्षित, गरीबी, बुरी प्रथाओं

और अन्य सामाजिक बुराइयों को हटाने में इन्तेजान दिया जा सकता है।

मासखाननया हम सब लोगों में यह ध्येय है कि हम अपने अधिकारों पर ठो धोर देखें, पर साथ ही अपने कर्तव्यों को नहीं पड़वाने। नागरिक विज्ञान हमें यह सिखाता है कि अधिकार और कर्तव्य एकट्ठे चलते हैं। जहाँ कर्तव्य नहीं, वहाँ अधिकार भी नहीं। इसी प्रकार यह हमें सिखाता है कि हमें हर बात के लिये हमें सा सम्म और सरकार का ही सह मद देना चाहिए। हमें, कम से कम, अपनी ही मर्यादा करके राज्य की मदद करना चाहिए। नागरिकों की मर्यादा के बिना राज्य का कुछ भी काम नहीं चल सकता।

(२) दूसरी बात यह है कि नागरिक विज्ञान हमारा इस-उपर काई हुई निष्ठाओं (loyalties) को समझा रहा करता है—यह सामाजिक व्यवस्था का मान-सह कायम करता है और मनुष्य को यह समझने लायक बनाता है कि उसे अपने परिवार अपने पड़ोसियों, अपने साथ या नगर अपने राज्य, और अन्ततः, मनुष्य मान में कैसे व्यवहार करना चाहिए। हमारे परकी निष्ठा मर्यादा के समूह के लिये होना चाहिए और हमें सामाजिक लाभ के लिये छोटे स्वार्थों को छोड़ना सीखना चाहिए।

(३) तीसरी बात यह है कि नागरिक विज्ञान सदाय तथा सरकार की मर्यादा, मर्यादा और कार्य प्रणाली के बारे में हमारे दृष्टिकोण और ज्ञान को विष्णुन करता है। हम यह जानने लगते हैं कि भाव का उपाय सिनना जगता हुआ है। हमें यह पता चलता है कि हमें हमारा स्थान कहाँ है और हमें अपने अर्थों में हमारा क्या सम्बन्ध है। इस ज्ञान में नागरिक को अपने रोजाना के कार्यों में असी मदद मिलती है। हमें समझा अपना काम अच्छी तरह करने का हीमना बहुत है। इसके बिना नागरिक समाज और सरकार का अधिकतम उपयोग नहीं कर सकेगा, मर्यादा समाज के लिये बहुत कुछ कर सकेगा।

(४) चौथी बात यह है कि लोकतन्त्र के नागरिकों के लिये ज्ञान हर नागरिक का। अध्ययन बहुत आवश्यक और लाभदायक है। लोकतन्त्र की आदर्शपरिभाषा की गई है कि 'जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिये शासन।' इस प्रणाली में किसी अच्छी, या बुरी, सरकार की चुनने की अधिकार जिम्मेदारी और मर्यादा रखकर हमें नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी नागरिकों के कंधों पर पड़ती है। इस प्रकार, यदि किसी लोकतन्त्र के नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का अहसास नहीं, तो उन्हें, लोकतन्त्र की सरकार ठीक तरह काम नहीं कर सकती। हर नागरिक को अपना बोट का अधिकार समझारी और ईमानदारी में इन्तेजान करना चाहिए। बोट के अधिकार का समझारी में इन्तेजान करने के लिये सामाजिक और राजनैतिक मानकों की अच्छी जानकारी होनी जरूरी है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है नागरिक विज्ञान से नागरिक को यह जानकारी हासिल होने में मदद मिलती है। आजकल अधिकतर देशों में लोकतन्त्र का मर्यादा है इसलिए आज के जमाने में नागरिक विज्ञान के अध्ययन का और भी अधिक महत्व हो गया है।

(५) पाचवी बात यह है कि नागरिक विज्ञान के अध्ययन का छात्रों के लिये बड़ा महत्व है। आज के छात्र हों कल के नागरिक होयें। नागरिक विज्ञान की जानकारी उन्हें ठीक तरह का नागरिक बनने में मदद देती है। नौजवाब ही किसी राष्ट्र की आशा होती है। कुछ वर्ष बाद वे ही नागरिक बनकर इससे साम्य विधाता होंगे। राष्ट्र की शक्ति उनके चरित्र और जिज्ञा पर निर्भर है। इसलिए नौजवानों को अपने शरीरों को शिक्षित करना, अपने दिमाग को योग्य बनाना और अपने चरित्र का विकास करना जरूरी शुरू कर देना चाहिए जिससे वे देश के सामने आने वाले बार्न अनेक समस्याओं को हल कर सकें। नागरिक विज्ञान उनके सामने नागरिकता और गुसी समाज, इन दोनों के जरूरी आदर्श पेश करता है।

हमारे देशवासियों के लिये नागरिक विज्ञान का महत्व

यद्यपि भारत का आकार, आबादी और साधन बहुत बड़े हैं, तो भी यदि उसकी तुलना अमरीका, रूस और इंग्लैंड जैसे भागों के साथ की जाये तो वह बहुत पिछड़ा हुआ है। उससे पिछड़े होने का एक कारण यह है कि उसने सदियों की गुलामी के बाद अभी हाल में आजादी हासिल की है। पर साथ ही हम अपनी समाज की गहरी सुराईयों में भावें नहीं मोच सकते। हमारे अन्दर नागरिक बुद्धि की बहुत कमी है। साम्प्रदायिकता, भ्रातृघना, जहाल्ल, गरीबी और कराव तन्तुगर्दी हमारी कुछ मोटी सुराईयों में से हैं। जानि प्रथा, छुआछूत, स्त्री-पुरुष का भेदभाव और ब्रह्म प्रथा जैसी सुराईया हमारे देश में आज भी फैली हुई हैं। हमारे अन्दर वह चरित्र नहीं जो स्वतन्त्र लोकतन्त्रीय देश के नागरिकों में हुआ करता है। खुदगर्बी, बाहिली, बड़ो का हुकूम न मानना, आगे बढ़ने से श्रम और जिम्मेदारी की भावना की कमी, हमारे चरित्र की कुछ मोटी विशेषताएँ हैं। अगर हमारा बस चले तो हम टैक्स ठा अदा करने ही नहीं और वसा न करने पर फस भी करने हैं। हम रोज सरकार का गाली देते हैं कि उनसे अबतक रामराम नहीं बनाया और स्वयं उसके लिये कोई कागिज नहीं करते।

यदि ऊपर कही गई सब बातों को चलने दिया जाए तो इससे हमारी नयी आजादी को खतरा पैदा हो जाएगा। यदि हमने अपनी कमियों को सहस्रन नहीं किया तो लोकतन्त्र का प्रयोग असफल हो जायेगा। हमें अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करनी चाहिए और नागरिक विज्ञान का अध्ययन हमारी समस्याएँ हल करने में बहुत मदद करेगा।

सारांश

नागरिक शास्त्र की परिभाषा

मिचिगन राज्य स्कूल के 'मिचिगन' और 'मिचिम' शब्दों से निष्पत्ति है, जिनका अर्थ क्रमशः 'नगर' और 'नागरिक' है। इसका यह अर्थ नहीं है कि नागरिक शास्त्र मनुष्य का सिर्फ नगर के सदस्य के रूप में अध्ययन करता है। आज राज्य नगर में बहुत बड़ी चीज है और इसलिए नागरिक शास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र भी बड़ा गया है। नागरिक न केवल राज्य का सदस्य है बल्कि वह सारी मानव विषयों का भी एक सदस्य है। इस

प्रकार, नागरिक शास्त्र की भी परिभाषा यह की जा सकती है कि 'नागरिक का और राज्य का उनकी स्थानीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सब प्रकार की समस्याओं की दृष्टि से अध्ययन करना।'

क्षेत्र—नागरिक शास्त्र के अध्ययन में निम्नलिखित क्षेत्र आती हैं —

(१) नागरिक का और उसके अधिकारों तथा कर्तव्यों का अध्ययन; (२) महत्वपूर्ण साहचर्य—जैसे परिवार और राज्य का, नगर और शहर जैसे समुदायों का, सम्पत्ति, जाति और धर्म जैसे मसालों का अध्ययन, (३) उन अनेक ताह के प्रभावों का अध्ययन जो नागरिक को अच्छा या बुरा बनाते हैं, जैसे परिवार, सम्पत्ति, जाति या धर्म, धर्म, शिक्षा, अवकाश या छुट्टी, मनोरंजन, गृहस्थि, और सम्पत्ति, (४) राज्य का, और अलग-अलग नागरिक के साथ उनके सम्बन्ध का, अध्ययन, इसमें राज्य के उद्गम, प्रकृति, बापों, प्रयोजन या मकसद का और प्रभुत्वता, कानून, अधिकार, स्वतन्त्रता और समानता आदि समस्याओं का अध्ययन भी शामिल है, (५) राज्य के अधिकारों, सरकार, का अध्ययन, जिसमें सरकार के बापों का, और तीन भगों, अर्थात् विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायालय, के रूप में इनके संगठन का अध्ययन भी शामिल है; (६) जनता के कार्य का अध्ययन जिसमें राजनैतिक दलों और लोकसभा का अध्ययन भी शामिल है, (७) समुच्चय राष्ट्र मध्य जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन।

नागरिक शास्त्र विज्ञान भी है और कला भी

नागरिक शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। प्रणालीबद्ध ज्ञान के तौर पर यह एक विज्ञान है, पर यह भीतरी और रसायन की तरह यथार्थ विज्ञान नहीं है, क्योंकि इसे अनुभव का अध्ययन करना होगा है, जिसका व्यवहार समय और वातावरण के बदलने पर बदल जाता है।

नागरिक शास्त्र एक कला भी है, क्योंकि इसका लक्ष्य अच्छे नागरिक पैदा करना और सुखी तथा मेहनतिलाल का सामाजिक जीवन बनाना है।

नागरिक शास्त्र की विधियाँ

नागरिक शास्त्र में ही विधियाँ इस्तेमाल करना है जो अन्य सामाजिक विज्ञानों में इस्तेमाल होती हैं। प्रयोगात्मक विधि इस कारण उपयोगी है, क्योंकि मानवीय अनुभव से मानवीय मसाला बदल जाती है, और हर तत्वों के बाद इन्सान अधिक अलग-अलग हो जाता है। प्रेक्षण (observation) की विधि इसलिए उपयोगी है क्योंकि दुनिया भर में मौजूद अनेक मानवीय मसालों के काम से तरीकों को अच्छी तरह देखे बिना नागरिक शास्त्र में सही निष्कर्षों पर पहुँचना कठिन है। तुलनात्मक विधि हमें अलग-अलग मसालों के काम की तुलना करने में मदद देती है। ऐतिहासिक विधि हमें विभिन्न मसालों के अतीत के अध्ययन से उन्हें गहरी रूप से समझने का मौका मिलता है। दार्शनिक विधि में हम, जो होना चाहिए उसका, जो हो सकता है उसने साथ में विचारना सीखते हैं।

नागरिक शास्त्र की उपयोगिता

नागरिक शास्त्र के अध्ययन से निम्नलिखित लाभ होते हैं —

(१) यह हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों का सही रूप बताकर जीने की सही विधि सिखाता है ।

(२) यह हम बताता है कि हमारी पहली निष्ठा सबसे बड़े समुदाय के प्रति होनी चाहिए और हम तरह-तरह हमारी विभाजित निष्ठा का हल करने की कोशिश करना है, और हमें स्वार्थभाव छोड़ने में सहायता देता है ।

(३) यह हमें सामाजिक ढाँचे और सरकारों के पक्षी-दृष्टि और काम करने का तरीका बताकर हमारे दृष्टिकोण का बड़ा करता है ।

(४) लोकतन्त्र के नागरिकों के लिए नागरिक शास्त्र का अध्ययन उपयोगी और आवश्यक है ।

(५) छात्रों के लिये यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें ही नागरिक बनना है ।

(६) हम भारतीयानियों के लिए नागरिक शास्त्र का अध्ययन और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे सामाजिक जीवन में पार फुटिका है ।

प्रश्न

QUESTIONS

- १ नागरिक विज्ञान की परिभाषा लिखो और इसका क्षेत्र बताओ ।
1 Define Civics and give its scope
- २ नागरिक विज्ञान का क्षेत्र और उपयोगिता बताओ ? (५ वि. सितम्बर, १९५०)
2 Indicate the scope and utility of Civics (P U Sept 1950)
- ३ नागरिक विज्ञान के अध्ययन के क्या लाभ हैं ? (५ वि. अप्रैल, १९४८)
3 What are the advantages of the study of Civics ? (P U April, 1949)
- ४ नागरिक विज्ञान की परिभाषा लिखो । यह एक विज्ञान है या कला ?
4 Define Civics Is it a science or an art ?
- ५ नागरिक शास्त्र की परिभाषा करो और सामाजिक विज्ञान के रूप में इसका स्थान बताओ ? (५ वि. अप्रैल १९५०)
5 Define Civics and indicate its place in the social sciences. (P. U April, 1950)

नागरिक शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों में संबंध

जो विज्ञान मनुष्यों और उनके कामों का वर्णन करने हैं, वे सामाजिक विज्ञान कहलाते हैं। नागरिक शास्त्र, इतिहास, अपनाप्त्र, राजनीति विज्ञान, आचार शास्त्र (Ethics), समाजविज्ञान (Sociology) और मनोविज्ञान (Psychology) — ये सब सामाजिक विज्ञान हैं, क्योंकि उनमें अध्ययन का विषय मनुष्य-जीवन का कोई पहलू है। नागरिक विज्ञान नागरिकों के रूप में मनुष्य का अध्ययन करता है। मनुष्य का व्यक्तित्व एक 'अन्तर्गत सम्पत्ति' (integrated whole) है और इसके एक पहलू को दूसरे पहलूओं में अलग नहीं किया जा सकता। उसके सब तरह के कामों का अध्ययन दूसरे कामों को बिलकुल छोड़कर नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, यही आदर्श, एक ही समय, एक परिवार का सदस्य होता है, एक राज्य का सदस्य होता है, किसी का सम्बन्धी होता है, इत्यादि। इसी प्रकार, छात्र के रूप में तुम्हारे जो काम हैं, अर्थात् तुम्हारा पढ़ना और खेलना, उन पर तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति और दूसरी अन्य अवस्थाओं का प्रभाव पड़ता है। जैसे मनुष्य के जीवन के विभिन्न पहलूओं में सहृदय सम्बन्ध है, वैसे ही इन पहलूओं का अध्ययन करने वाले अनेक सामाजिक विज्ञान भी एक दूसरे में बहुत अच्छी तरह सम्बन्धित हैं।

नागरिक शास्त्र और समाज विज्ञान दोनों में अन्तर

(१) समाज विज्ञान सब सामाजिक विज्ञानों का जन्मदाता विज्ञान है। इसमें समाज के तारे रूप पर विचार होता है और इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। यह सामाजिक जीवन के सब पहलूओं, अर्थात् आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और कलात्मक पहलूओं का अध्ययन करता है। इस रूप में यह हर एक बात पर विस्तार से विचार नहीं कर सकता। दूसरी ओर, नागरिक शास्त्र सामाजिक जीवन के सिर्फ एक पहलू का विशेष अध्ययन करता है, अर्थात् नागरिक और अन्य व्यक्तियों तथा समूहों की दृष्टि से उसके अधिकार और कर्तव्य। अतः यह, समाज विज्ञान माना है और नागरिक शास्त्र सिर्फ पुत्री है। समाज विज्ञान में नागरिक शास्त्र भी आ जाता है।

(२) नागरिक शास्त्र यह मानकर चलता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज विज्ञान इस समस्या पर गहराई से विचार करता है कि मनुष्य क्यों और कैसे सामाजिक प्राणी है।

नागरिक शास्त्र परिवार, गांव, नगर और राज्य जैसी कई सामाजिक समस्याओं के जन्म और वृद्धि के बारे में सही जानकारी समाज विज्ञान से ही हासिल करता है। समाज विज्ञान से हम निजी सम्पत्ति और ममाज में प्रचलित कई अन्य प्रथाओं के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं।

नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान सम्बन्ध

(१) राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन होता है और नागरिक शास्त्र में नागरिकता का, और इन दोनों का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। राज्य के बिना नागरिक नहीं हो सकता। राज्य और नागरिकता का अध्ययन इन दोनों विभागों में होना है। फर्क सिर्फे जोर देने का है। नागरिक शास्त्र में नागरिकता और उसमें सम्मिलित रहने वाली समस्याओं के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी के लिए राज्य के अध्ययन का काम महत्व है। दूसरी ओर, राजनीतिक विज्ञान मुख्यतः राज्य का अध्ययन है और नागरिकता की चर्चा उसमें बड़ी प्रमत्त से ही आती है।

दोनों में अन्तर—

(१) जैसा ऊपर कहा जा चुका है, दोनों विज्ञानों के अध्ययन का क्षेत्र अलग-अलग है। इसके अलावा, राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र नागरिक शास्त्र के क्षेत्र का, अपेक्षा बहुत बड़ा है। राजनीतिक विज्ञान राज्य की समस्याओं तथा राष्ट्रपति और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की गहराई में जाता है। नागरिक शास्त्र का अध्ययन नागरिक के नागरिकता तथा ही सीमित रहता है।

(२) राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन अधिकतर विचारान्मक और दार्शनिक है। नागरिक शास्त्र अधिकतर एक प्रायोगिक विज्ञान है। नागरिक शास्त्र का मनमद है सर्वोत्तम नागरिक पैदा करना।

नागरिक शास्त्र और इतिहास का सम्बन्ध

इतिहास समाज के गुजरे हुए सामाजिक, राजनीतिक, जायिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन की अवस्थाओं और विकास की तस्वीर होता है। जो सत्पाए आज नागरिकों के जीवन पर इतना गहरा असर डाल रही है, उनकी मौजूदा कार्यप्रणाली को पूरी तरह समझने के लिये हम उनके जन्म और वृद्धि का भी अध्ययन करना होगा। यह ज्ञान हमें इतिहास से ही मिल सकता है। उदाहरण के लिये, जाति प्रथा, अविभक्त परिवार, छुआछूत, अमीदारी और उत्तराधिकार के कानून आदि नागरिक के जीवन पर इतना गहनपूर्ण असर डालते हैं, पर उन्हें उनका इतिहास बिना देखे ठीक तरह समझा नहीं जा सकता। इसी प्रकार नागरिक का राज्य से बड़ा सम्बन्ध है। राज्य की भूमि, प्रकृति और प्रयोजन को समझने के लिये नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी को इसके जन्म और वृद्धि पर अवश्य विचार करना चाहिए।

जोनों में अन्तर

(१) पर उनकी विषय-वस्तु भिन्न है। एक तो आचार-व्यवस्था का विज्ञान है और दूसरा नागरिकता का, (२) आचार शास्त्र का मुख्य काम के भंति (प्रेरक और आशय) तथा बाहरी (स्वयं काम) दोनों भागों से है। नागरिक शास्त्र निरुक्त मनुष्य के बाहरी व्यवहार से मुख्य रखा है।

नागरिक शास्त्र और मनोविज्ञान

मनोविज्ञान में मन का अध्ययन होता है। यह भावना, गहना, अनुमान, सहजवृत्ति, भाव, भावभावना, और बुद्धि का अध्ययन करता है। इनमें ही मानवीय व्यवहार प्रेरित होता है। नागरिक शास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान है। यह मनुष्यों के रूप में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। स्वभाव मनुष्य के कार्यों के प्रत्यक्ष भावों की जानकारी, अर्थात् यह जानना कि वे मनुष्य एक सामान्य तरह के कार्य और नवी व्यवहार करने हैं, नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी के लिए उपयोगी होता है।

सारांश

नागरिक शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ सम्बन्ध है क्योंकि सब सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन का विषय एक, अर्थात् मनुष्य, है।

नागरिक शास्त्र और समाज विज्ञान

समाज विज्ञान जनक विज्ञान है और इनमें सब यह माना है तथा नागरिक शास्त्र इसके पुत्र है। समाज विज्ञान का ध्येय नागरिक विज्ञान का ध्येय की अपेक्षा बहुत विस्तृत है। समाज विज्ञान सारे सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है, पर नागरिक शास्त्र निरुक्त एक पहलू का, अर्थात् मनुष्य के नागरिक रूप का अध्ययन करता है। तो भी, परिवार, नगर और राज्य जैसी कई सामाजिक समस्याओं के उद्गम और बुद्धि की सही जानकारी के लिये नागरिक शास्त्र समाज विज्ञान पर निर्भर है।

नागरिक शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान

नागरिक का और राज्य का अध्ययन दोनों में एकजमान है, पर राजनीति विज्ञान मुख्यतः राज्य का अध्ययन है और नागरिकता पर वह निरुक्त प्रभाव विचार करता है। दूसरे ओर, नागरिक शास्त्र नागरिकता के अध्ययन पर ध्यान देता है और राज्य का अध्ययन नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी के लिए योग्य महत्व का है।

नागरिक शास्त्र और इतिहास

इतिहास नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी का नागरिक के जीवन में महत्वपूर्ण हिस्सा लेने वाला, अनेक सामाजिक समस्याओं के उद्गम, बुद्धि, प्रवृत्ति और मौजूदा कार्यप्रणाली को सही रूप में समझने में सहायता देता है। तो भी, इतिहास का अधिकांश नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी के लिए अप्रामाणिक है। दूसरे, इतिहास अधिकतर सम्प्रदाय और घटनाक्रम के रूप में होता है, पर नागरिक शास्त्र आदर्शमय (Normative) तथा क्रियात्मक विज्ञान है।

नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र

नागरिक शास्त्र का अर्थशास्त्र से भी सम्बन्ध है क्योंकि नागरिक और समाज का गुण सम्पत्ति के उत्पादन और उचित विवरण पर निर्भर है। गरीबों और बेकारी अच्छी नागरिकता के बड़े घाव हैं। इन समस्याओं को अर्थशास्त्र से हल दिया जाता है। तो भी नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र एक-दूसरे से अलग दो सामाजिक विज्ञान हैं।

नागरिक शास्त्र और आचार-शास्त्र

आचार शास्त्र आचार सम्बन्धी विज्ञान है। यह गुण और दोष में भेद करता है। अच्छे नागरिक को गुण प्राप्त करने चाहिए और दोषों से बचना चाहिए। इन गुणों और दोषों का ज्ञान, और अनुपयुक्त या सामान्य पर इनके प्रभावी या ज्ञान आधार शास्त्र में ही हो सकता है। इसलिए नागरिक-शास्त्र और आचार शास्त्र में सम्बन्ध है पर दोनों विज्ञानों में भेद भी है। आचार शास्त्र सारी क्रिया का अध्ययन करता है और नागरिक शास्त्र क्रिया के सिर्फ बाहरी भाग का अध्ययन करता है।

नागरिक शास्त्र और मनोविज्ञान

नागरिक शास्त्र मन का अध्ययन करता है और अनुपयुक्त के व्यवहार के विभिन्न प्रेरक शक्तियों के बारे में ज्ञान देता है। चूंकि नागरिक शास्त्र सामाजिक निर्माण का विज्ञान है, इसलिए जगें यह जानना जरूरी है कि आदर्शों एक साथ तरीके से कैसे और क्यों व्यवहार करना है।

प्रश्न

QUESTIONS

- 1 नागरिक शास्त्र की परिभाषा करो। नागरिक शास्त्र का राजनीति, अर्थशास्त्र, और आचार शास्त्र से किस प्रकार सम्बन्ध ? (५ वि सितम्बर १९५१)
- 1 Define Civics How is Civics related to Politics, Economics and Ethics ? (P U. Sep 1958)
- 2 स्पष्ट रूप से बताइये कि नागरिक शास्त्र समाज विज्ञान, आचार शास्त्र और इतिहास से किस तरह सम्बन्धित है।
- 2 Explain clearly how Civics is related to Sociology, Ethics and History

अध्याय :: ४ मनुष्य और समाज

मनुष्य की सामाजिक प्रकृति

मनुष्य की प्रकृति दो भागों में बर्ती है जिनमें से एक प्राकृतिक है और दूसरा बौद्धिक (animal and rational) । पशु के नाने उसमें कुछ सहज प्रवृत्तियाँ हैं, जो उसे सामाजिक होने के लिये मजबूर करती हैं। पहली बात तो यह है कि और पशुओं की तरह मनुष्य में प्रचल यूपचारों (gregarious) कृति होती है । जैसे पशु झुण्ड बनाकर चलते हैं, ठीक वैसे हैं, मनुष्य भी हमेशा मनुही में रहता हुआ पाया जाता है। वही कोई आदमी एकांत जीवन बिताता हुआ नहीं दिखाई देता। जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले साधुओं और फकीरों का उदाहरण दबकर प्रायः यह सिद्ध करने की कोशिश की जाती है कि मनुष्य बिना समाज के रह सकता है पर हमें यह याद रखना चाहिए कि इन लोगों का भी समाज में साकायदा मगन बना रहता है। उनसे पान कुछ शिष्यमंडली रहती है और गहर से भक्त मंडली उनके पान आती जाती रहती है ।

दूसरी बात यह है कि दो और सहज प्रवृत्तियाँ हैं जो मनुष्य की सामाजिक बनाती हैं, अपात् जनकांग प्रकृति (parental instincts) और प्रेय प्रकृति (Sex instinct) । ये दोनों प्रवृत्तियाँ पारिवारिक जीवन का मूल हैं। परिवार मनुष्य जाति में एक प्राकृतिक समूह है ।

पशु होने के अलावा, मनुष्य बुद्धियुक्त (rational) भी है । इस गुण से वह सामाजिक बनने के लिये और भी अधिक मजबूर हो जाता है। हर मनुष्य की मर्यादा के लिये और बराबर रहने के लिये धापी चाहिए । वह दूसरों के विचार सुनकर या अपने विचार उन्हें बताकर अपना मिर हल्का कर लेना चाहता है । इसी तथ्य से यह बात स्पष्ट होती है कि बहुत दिनों तनहाई की बंद की सजा सुगतने वाले लोग क्यों पागल हो जाते हैं । तनहाई की सबसे अधिक बढोर सवाओं में मानी जाती है । इसी प्रकार, हर आदमी का अपनी गुप्त बातें करने के लिये या सलाह लेने के लिये दोस्त चाहिए । फिर, यज्ञ प्राप्त करने, बुर्बाणी करने, कृतप्रता, प्रेम, और आदर प्राप्त करने की इच्छा दूसरों के साथ के बिना पूरी नहीं की जा सकती । इसीलिए अरस्तू ने कहा था कि 'जो आदमी सामाजिक नहीं है वह या तो पशु है या देवता ?' इस प्रकार समाज मनुष्य के लिये विलकुल स्वाभाविक है ।

मनुष्य अपनी आवश्यकता के कारण भी सामाजिक है । बहुत सी बातें उसे

दूसरों के साथ रहने के लिये मजबूर बनते हैं। वे बाँने जीवे दी जाती हैं —

शारीरिक कमजोरी—शारीरिक दृष्टि से मनुष्य इतना मजबूत नहीं कि अकेला प्रकृति का सामना कर सके। बर्षा और सूकान, गर्मी और सर्दी, पहाड़ और नदियाँ, जंगल पशु और रोग तथा दुर्घटनाएँ आदि दूसरी मनुष्यों के इतनी ज़रूरत हैं कि एक अकेला आदमी उन्हें बाँव नहीं कर सकता। इन सब सतहों में अपने जीवन की बचाने के लिए मनुष्यों को सहयोग करना होगा। मिमीजुली बोशिन ने मनुष्य को कुदरत को जीत लिया है।

आर्थिक सहायता—मनुष्य की ज़रूरतें बहुत भारी हैं। वह उन सबको अकेला पूरा नहीं कर सकता। किसी अकेले आदमी के लिये ज़रूरतें भोजन बनाना, भ्रमना भोजन उगावना, और अपने कपड़े पैदा कर सवना बिल्कुल असंभव है। इनसे अभाव, आदमी को और भी ग़रीब से, चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं। इन्हींके लिए धर्म, धन विभाजन के समुदाय पर काम करने हैं और इस तरह मददें ज़रूरतें पूरा करती हैं।

धार्मिक प्रवृत्ति और जनकीय प्रवृत्ति—ये दोनों प्रवृत्तियाँ उसे सामाजिक होने के लिये मजबूर करती हैं। नर और नारी का सम्मिलन यौन प्रवृत्ति के कारण ही है। यह सम्बन्ध आदम और स्त्रियाँ के जमाने में बना जाता है। हर इन्सान बालक में आदमी बनता है। अगर बच्चे न हो तो मनुष्य जाति सत्य हो जायगी। फिर, कोई बच्चा अपनी देवनाग्न नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए कुदरत में इन्सान में जनकीय प्रवृत्ति एवं ही है और इस तरह उसे परिवारों में अपने बच्चों का पालन करने के लिये मजबूर कर दिया है।

बोलने की ताकत—मनुष्य की बोलने की ताकत भी इन्हीं बज्रों से है कि वह सामाजिक प्राणी है। यदि किसी बच्चे से कोई भी न बोलें तो वह बोलना नहीं सीख सकता।

अच्छा जीवन—इन्सान सिर्फ़ रोटी में नहीं जीता। उसे समाज की ज़रूरतें सिर्फ़ अपनी आर्थिक आवश्यकताएँ पूरा करने के लिये ही नहीं हैं बल्कि अच्छा जीवन के लिये भी है। अच्छे जीवन में सम्मान और सम्पत्ति भी आती है। अन्तःकरण के आविष्कार, दर्शन और कला तथा साहित्य की चीज़ें खानी बचन और विचारों की आपसी ज़बल-बजल का गर्जना है। अगर समाज न हो तो न खाड़ी बन होगा और न कोई विचारों की जड़-बजड़ होगी।

समाज किसे कहते हैं—इस देश में है कि हर आदमी को दूसरे आदमी का साथ ज़रूर हमिल करना पड़ता है। जब लोग एक उद्देश्य रखकर आपस में मिलते हैं या कुछ माले हितों के कारण वे झट्टे हो जाते हैं तब उनका एक समाज बन जाता है। मिमिलिविड वाता में समाज के बारे में स्पष्ट विचार बन जायगा —

(१) **समाज एक व्यापक शब्द है और इसका अर्थ बहुत बिल्कुल है।** समाज शब्द १० व्यक्तियों के समूह के लिये भी बोला जा सकता है, और नारी मनुष्य जाति के लिये भी। किसी परिवार को भी बड़े तौर से समाज कहा जा सकता है। अलग-अलग तरह के समूहों के लिये अलग-अलग शब्द हैं।

(२) समाज अस्थायी भी हो सकता है और स्थायी भी। रेल के टिकटों में गफर करने वाले मुद्रांकित भी एक समाज बना लेते हैं, यद्यपि यह अस्थायी ढंग का होता है। दूसरी ओर, राज्य एक स्थायी ढंग का समाज है।

(३) समाज षड्वक्त्र के अन्दर संगठित और असंगठित दोनों तरह के समूह आते हैं। कोई परिवार कालेज या क्लब संगठित समूहों के उदाहरण है। बाजार में जादू या खेल देखने जाने लोगों की भीड़ असंगठित समूह का उदाहरण है।

(४) समाज की कोई प्रादेशिक सीमा नहीं होती। एक अर्थ में भूमण्डल पर रहने वाली सारी मनुष्य जाति ही एक समाज है।

समाज का मंडल—समाज की सरचना बड़ी जटिल होती है। इसमें अनेक साहचर्य, समुदाय और गणना शामिल होती हैं।

साहचर्य या सभ (Association)—साहचर्य या सभ उस समूह का नाम है जिसमें कई व्यक्ति एक साझे उद्देश्य की पूर्ति के लिये अपने आपको संगठित कर लेते हैं।

समुदाय—समुदाय उन लोगों के समूह को कहते हैं जिसमें कुछ मात्रे हितों के कारण एकता की भावना हो। बर्मी-यभी लोगों में गुन भूतल पर निवास के कारण कुछ मात्रे हित पैदा हो जाते हैं। इसी अर्थ में मैकाइवर ने गांवों और गरीबों को समुदाय कहा। अन्यथा समुदाय के लिये प्रदेश का होना आवश्यक नहीं। उदाहरण के लिये, जब हम छात्र समुदाय कहते हैं, तब समुदाय शब्द से हमारा मतलब किसी प्रदेश से नहीं होता। इसी प्रकार धर्म के मात्रे हित के कारण हम लोगों को हिन्दू, मिस्र, मुस्लिम और ईसाई समुदायों में रखते हैं। ईसाई समुदाय सारी दुनिया में फैला हुआ है। समुदाय के सदस्यों के लिए सभ की तरह संगठित होना जरूरी नहीं। समुदाय सभ से बड़ा भी होता है। सभ तो यह है कि एक समुदाय में कई सभ हो सकते हैं।

संस्था—उन नियमों या प्रथाओं और बानूनों को संस्था कहते हैं जो किसी समूह के सदस्यों के आपसी सम्बन्ध निर्दिष्ट करते हैं। जाति-प्रथा, विवाह, दम्पक और अभिषेक परिवार प्रणाली, ये सब संस्थाएँ हैं।

समाज का जन्म और विकास—कोई नहीं कह सकता कि मनुष्य ने समाज में रहना पहले शुरू किया। समाज उसना ही पुराना होगा जितना आदमी, क्योंकि इस धरती पर मनुष्य के जीवन के बिलकुल शुरू में वह सामाजिक है। समाज की वृद्धि सरल से जटिल की ओर हुई है। आज समाज का ढांचा बड़ा जटिल है। समाज का विकास इन अवस्थाओं में हुआ होगा —

परिवार—सबसे पुराना और सबसे सरल मानव समाज ऐसा परिवार होगा जिसमें पति, पत्नी और उनके बच्चे होंगे।

गोत्र (Clan)—जबान छटके सारों के बाद अपने अलग परिवार बनाने के, पर वे अब भी उन्हीं बृजुर्ग की बात मानकर चलने के। इस तरह एक जगह में घुस होने वाले परिवारों का समूह गोत्र कहलाने लगा।

गण या जनजाति या कबीला (Tribe)—कई गोत्र मिलकर एक गण हो गए।

गण की अदम्या में एक सम्बन्ध बमजोर हो गया और सत्ता सुन की दृष्टि में सबसे बड़े सभ्य से हटकर सबसे अधिकारी सभ्य के पास पहुँच गई जो लडाई के समय बर्बाने की रक्षा कर सकता था। यह आदमी बर्बाने का सरदार बहाना लगा। बर्बाने का सरदार धरि-आने राजा हो गया।

राज्य—जब किसी साम्राज्य में रहने वाले बर्बानों ने कानून और व्यवस्था के लिये किसी राजा को मान्य बनने जादवा समझि बनना शुरू किया तब राज्य का जन्म हुआ। तभी से मानव समाज कई राज्यों में बँटा हुआ है।

समाज का प्रयोजन—जब हमें समाज का प्रयोजन स्पष्ट हो गया होगा। मनुष्य स्वभाव में और जातव्यवस्था में एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में ही अपनी अनेक तरफ की जरूरतें पूर्ण कर सकता है। समाज की बदौलत वह न केवल जी सकता है, बल्कि अच्छे, तरफ भी जी सकता है। अच्छा जीवन यही है जो समाज के अन्दर जीवन है। समाज के बिना मनुष्य पूर्ण तरह मुक्त नहीं हो सकता। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि समाज में सब मनुष्यों की समान परभाव है। हर एक आदमी का आत्म-सम्मान और व्यक्तिगत एक सा कीर्ति है। इसलिए समाज सब आदमियों की शिष्ट और सुख, जीवन बिताने का बराबर मोवा दता है।

मनुष्य और समाज—जब समाज मनुष्य के लिए इतना कीमती है तो स्वभावतः यह पूछा जा सकता है कि मनुष्य और समाज में क्या सम्बन्ध होता चाहिए। इन दोनों का सम्बन्ध इतना नजदीकी है कि इनमें से कोई भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता और जब ये दोनों एक दूसरे पर इतने निर्भर हैं तो स्वभावतः यह सवाल पैदा होता है कि मनुष्य का अधिक महत्व है या समाज का। इस सवाल पर लोगों की राय अलग-अलग है और दो चरम (extreme) विचार ये हैं —

(१) मनुष्य का अधिक महत्व है—कुछ विचारक जिन्हें व्यक्तिवादी (individualist) कहते हैं, यह मानते हैं कि मनुष्य की समाज की बहुत जरूरत नहीं। समाज की जरूरत सिर्फ इसलिए है कि वह बचाने की गारंटी से कमजोर को बचा सके। और किसी बात के लिये मनुष्य की समाज की जरूरत नहीं। मनुष्य खुद इतना अकाम्य है कि वह अपने फायदे के लिए काम कर सके और इन काम में उसे समाज की रहन-सहन की जरूरत नहीं। बल्कि व्यक्तिवादी तो यहाँ तक मानते हैं कि समाज की दखलान्दगी में मनुष्य को कर्म भी करना नहीं पड़ता। इसलिए समाज को उस विस्तृत आजाद रहने देना चाहिए। समाज की दखलान्दगी मनुष्य के व्यक्ति के विकास में बाधक होती है और उसके चरित्र को फलने नहीं देती। इसलिए वे कहते हैं कि मनुष्य को, जहाँ तक हो सके, व्यक्ति में व्यक्ति आजाद रहने चाहिए और यह मानते हैं कि मनुष्य समाज के बिना बिना रह सकता है और उसी फल-फूल सकता है।

समाज का अधिक महत्व है—कुछ और विचारक, जो आदर्शवादी (idealist) कहलाते हैं, समाज का अधिक महत्व मानते हैं। उनका कहना है कि समाज के बिना मनुष्य का कोई अर्थ या सार्थकता नहीं। उसका महत्व सजीव सन्धि (organic whole)

अर्थात् समाज के एक भाग के रूप में ही है। मनुष्य का अपना कुछ भी नहीं। मनुष्य का अनाज, कपड़े, खोलने की शक्ति, ज्ञान और अमल में तो उसका मास और हड्डिया भी समाज की ही हैं, और उसने समाज में ही शामिल की है। वे कहते हैं कि मनुष्य का लान इसी में है कि वह अपने-आपको पूरी तरह समाज में अंतर्गत कर दे। उसे समाज के ही लिये जीना और मरना चाहिए।

असली स्थिति—पर मनुष्य और समाज के आपसी सम्बन्ध के बारे में सचाई इन दोनों चरम विचारों के बही बीच में है। कोई भी आदमी पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। हम पढ़ते ही यह चूके हैं कि समाज मनुष्य के लिये स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी। उसे इससे न केवल जिन्दगी के लिये, बल्कि अच्छी जिन्दगी के लिये जरूरत है। अच्छी जिन्दगी में भौतिक और नैतिक तरकी भी शामिल हैं। सम्पत्ति और संस्कृति समाज में ही पैदा होती है। समाज के बिना आदमी पशु जैसा हो जाएगा। मनुष्य में जो बुद्धि का जरा है, जो उसमें और पशुओं में भिन्नता करता है, वह तभी विवर्धित होता है, जब वह समाज में रहे।

पर हम सबसे हमें यह न भूलने लगा चाहिए कि समाज मनुष्य में अधिक जैसा या अधिक महत्वपूर्ण है। कानिश्च, समाज है क्या? यह मनुष्यों का एक जमाव ही है। बिना मनुष्यों के समाज नहीं हो सकता। समाज का जपना मगल इसकी दृष्टियों के मगल पर ही निर्भर है। अगर दृष्टि पिछड़ी हुई है तो समाज आगे बढ़ा हुआ नहीं हो सकता। इसलिए समाज के अपने कामों के लिये यह जरूरी है कि यह ऐसी परिस्थितिया और पाठावरण बंध करे, जिसमें दृष्टि अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके।

इस प्रकार, अन्त में हम यह कह सकते हैं कि मनुष्य और समाज के आपेक्षिक महत्व के बारे में सारी बहस समतल है। कोई भी दूरी में अधिक महत्व का नहीं है, न उनके हित एक दूसरे के विरोधी हैं। दोनों का एक सा महत्व है और पारस्परिक सहयोग से ही दोनों को लाभ है।

सारांश

मनुष्य स्वभाव और आवश्यकता के कारण सामाजिक है। उसकी सामाजिक प्रकृति इन तथ्यों में सिद्ध होती है —

१. मनुष्य सदा अपुष्टों से रहता हुआ दिलाई देता है। वह कहीं भी अकेला जीना बिनाता हुआ नहीं देखता।

२. मनुष्य को गणराज और हँसने-हँसाने के लिये समाज की आवश्यकता है। वह किसी के साथ विचार-विविध करवा चाहता है। कंद तनहाई या एकाकी परिराज सबसे बंधोर मजाओं में से है।

३. कुछ इच्छाएँ, जैसे धर्म की, इच्छा, त्याग की इच्छा, कृतज्ञता प्राप्त करने की इच्छा, प्रेम और सम्मान पाने की इच्छा, दूसरों की मयति के बिना नहीं पूरी की जा सकती।

मनुष्य अपनी आवश्यकता के कारण भी सामाजिक है :—

१ मनुष्य अकेला जीवितिक घटनाओं का सामना नहीं कर सकता । सामाजिक प्रयत्न द्वारा मनुष्य प्रकृति का सामना कर सकता है ।

२ मनुष्य का अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों से सहयोग करना आवश्यक है ।

३ मान प्रकृति और जनकी प्रकृति उसे सामाजिक होने को मजबूर करती है ।

४ मनुष्य को जीने की एकमात्र गन्तव्य है ही पैदा हुआ है ।

५ समाज के बिना जलवायु जीवन असंभव है ।

समाज कैसे रहते हैं—यह सभी मनुष्य जिन्हें, मानें प्रकृति की प्रकृति के लिए साथ मिलकर रहते हैं, जो कुछ नामों द्वारा के कारण एकदूसरे के साथ मिल जाते हैं, जो एक समाज बनाते हैं । समाज व्यवस्था अपने आप बनती है । यह किसी छोटे समूह के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं और यह मानव समाज के लिए भी । समाज व्यवस्था के अन्दर सामाजिक और आर्थिक दोनों समूह आते हैं ।

समाज का संघटन—समाज की संरचना वैयक्तिक है । हमें जहाँ सामाजिक या मनुष्य, मनुष्य और मनुष्य मिलते हैं ।

समाज का उद्भव और वृद्धि—समाज उत्पन्न हो जाते हैं जिसका पुराना मनुष्य । यह समय जब से बहुरंग मनुष्य हो गया है । परिवार सबसे पुराना और सबसे बड़ा सामाजिक समूह है । हमें यह भी जानना है, जो सभी समाज के कई परिवारों का समूह है । कई लोग मिलकर कबीला या घर या जनजाति (tribe) बनाते हैं । जब किसी क्षण मनुष्य घर रहने वाले कबीलों में किसी राजा के अगुआ बनते हैं और व्यवस्था के लिए अपने आदेशों का प्रयोग करना शुरू किया, तब राज्य पैदा हुआ । हमें मनुष्य समाज की राज्या में बड़ा हुआ है ।

समाज का प्रयोजन—समाज मनुष्य को न केवल जीने के, बल्कि अच्छी तरह जीने के योग्य बनाता है । बिना समाज के मनुष्य अविश्वसनीय दुखी नहीं हो सकता ।

मनुष्य और समाज के आर्थिक महत्व के बारे में हम यह कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए समाज एक में महत्वपूर्ण हैं । जो व्यक्तिकारी यह कहते हैं कि समाज मनुष्य के अभाव में जीने हैं, वे व्यक्ति की अनुचित महत्व देते हैं । इसी प्रकार, जो समाज के अभाव में जीने हैं, वे व्यक्ति की अनुचित महत्व देते हैं । अतः हमें व्यक्ति और समाज का सम्बन्ध एक दूसरे पर इतना अधिक आधारित है कि दोनों को आपसी सहयोग से काम करना जरूरी है । दोनों का सम्बन्ध समाज एक में महत्वपूर्ण है ।

प्रश्न

QUESTIONS

१ इस कथन को स्पष्ट कीजिए, कि "मनुष्य सामाजिक प्राणी है।"

(यदि अगस्त १९४८, और सितम्बर १९५०) ।

1. Explain the proposition that, "man is a social animal."

(P U. April 1948 and Sep 1950)

- २ "मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है"—स्पष्ट कीजिये।
(५ दि सितम्बर १९५२)।
- ३ "Man is by nature a social animal" Explain (P U. Sep 1952)
- ३ "मनुष्य स्वभाव से और आवश्यकता से सामाजिक प्राणी है।" दृष्टांत देकर स्पष्ट कीजिए।
(५ मी १९४०)
- ३ "Man is by nature and necessity a social animal Explain clearly, giving illustrations. (U P 1940)
- ४ "समाज" शब्द से आप क्या समझते हैं? यह साहचर्य, अनुदाय और सत्य से किस तरह भिन्न है?
(पू वा १९३८)
- 4 What do you understand by the term "society"? How does it differ from an association, community and institution? (U P 1938)
- ५ मनुष्य समाज पर कैसे निर्भर है? समाज एवं सत्य है या मायन? —
(५ दि अप्रैल १९५४)
- 5 Explain the dependence of the individual on society. Is society an end or a means? (P U April, 1954)
- ६ मनुष्य और समाज का सम्बन्ध स्पष्ट कीजिये। क्या उनके हित एक दूसरे में विरोधी हैं?
- 6 Explain clearly the relation between the individual and society. Do they have conflicting interests?

अध्याय : : ५

साहचर्य या संग

(Associations)

परिभाषा—साहचर्य या संग लोगों के उस समूह की वह मकान है जो किसी काम या प्रयोजन के लिये अभिव्यक्त रूप में संगठित किया गया हो।

सब साहचर्यों में पाए जाने वाले लक्षण—ऊपर दी गई परिभाषा में साहचर्य या संग के निम्नलिखित लक्षण स्पष्ट होंगे —

(१) साहचर्य या संग एक संगठित समूह है। इसकी यह विशेषता इसे अम-गठित समूहों में अलग करती है। भाई साहचर्य नहीं हो सकती क्योंकि इसमें संगठन नहीं होता। इसी तरह रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठकर चलने वाले मुसाफिर, या बाजार में जाड़ का खेल देखने वाले लोग साहचर्य नहीं होते। साहचर्य क्योंकि संगठित समूह होता है, इसलिए इसके सदस्यों के साथ इसके सम्बन्धी को नियमित करने के लिये नियम या कानूनों का निर्माण जरूर होने चाहिए।

(२) साहचर्य किसी खास प्रयोजन की पूर्ति के लिये बनाया जाता है। हर एक संग का मतसब कोई न कोई लक्ष्य हासिल करना होता है। कोई एक साहचर्य आरम्भ की मकसद पूर्ण नहीं कर सकता। इस तरह, जहाँ अनेक अहमों की पूर्ण करने के लिये आरम्भ बहुत से साहचर्यों में शामिल होता है और उन साहचर्यों की मदद उनकी हो सकती है जिनकी मजदूरी की, जरूरतें।

(३) साहचर्य राज्य सिर्फ कुछ लोगों की निरूप करता है और यह किसी प्रदेश को निरूप नहीं करता। यह प्रादेशिक संगठन नहीं है। राज्य के अन्तर्गत और किसी साहचर्य का प्रदेश नहीं होता। अतः में किसी साहचर्य के सदस्य हैं। राज्यों में कौन हो सकते हैं। रैंड काम समारम्भायी साहचर्य है।

साहचर्य में भेद—साहचर्य, आकार, संगठन, प्रकृति, अवधि और बायों की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अपने कार्यक्षेत्र के अनुसार, ये आकार में छोटे-बड़े हो सकते हैं। खेलने के लिये बनाया गया क्लब क्लब किसी काम के लिए एक ही मकसद है और 'रेड क्रॉस' गंगा-संगठन, साहचर्य है। किसी साहचर्य का संगठन उसके आकार और बायों के अनुसार सरल व जटिल होना। कुछ साहचर्य, जैसे परिवार और राज्य, स्थानाधिक, अनिवार्य और स्थायी होते हैं। जब साहचर्य साधारणतया स्वेच्छा से बनाये गये और कम देर रहने वाले होते हैं। साहचर्यों के नाम भी अलग-अलग होते हैं अर्थात्, क्योंकि उनके उद्देश्य अलग-अलग होते हैं।

साहचर्यों के प्रकार—साहचर्यों को उनकी प्रकृति, अवधि और बायों के आधार

पर इन वर्गों में बाटा जा सकता है —

(१) स्वाभाविक और ऐच्छिक।

(२) स्थायी और अस्थायी।

(३) बायें की दृष्टि में साहचर्य जैविकीय (Biological), आर्थिक, राजनैतिक, मनोरंजनात्मक, सांस्कृतिक, धार्मिक और परोपकारी हो सकते हैं।

स्वाभाविक और ऐच्छिक—राज्य और परिवार मनुष्य के लिये स्वाभाविक हैं। आदमी जन्म में ही इन दोनों का सदस्य होता है। इनका सदस्य होना या न होना मनुष्य की इच्छा पर नहीं है। उसे इनका सदस्य बनना पड़ता है। ऐसा कोई आदमी नहीं होगा, जिसका जन्म और पालन किसी परिवार में न हुआ हो। इसी प्रकार, अपितर मनुष्य जाति राज्यों में गठित होकर रहने है।

स्थायी और अस्थायी—किर, राज्य और परिवार दोनों अस्थायी भी हैं। वे न मालूम कब में मौजूद हैं। और आगे भी बने रहेंगे। और साहचर्य ऐच्छिक तथा थोड़े बहुत अस्थायी होते हैं। मनुष्य को उनमें शामिल होने या उनमें अलग हो जाने की आजादी होती है। ये साहचर्य अपना प्रयोजन पूरा होने पर खराब हो जाते हैं।

जैविकीय साहचर्य का महत्व समान उत्पन्न करना और मनुष्य जाति को बचाने रहता है। परिवार एक जैविकीय साहचर्य है।

आर्थिक—आर्थिक साहचर्य अपने सदस्यों के आर्थिक हितों, वृद्धि और रक्षा के लिये बनाये जाते हैं। ट्रेड यूनियन या मजदूर मण्डल का मालिकों के मुकाबले में अपने हित आगे बढ़ाने और उनका रक्षा करने के लिये बनाया हुआ साहचर्य होता है। फिर, किसी वृद्धि, व्यापार या उपजीविका में लगे हुए लोगों का साहचर्य हो सकता है। अन्ध-पक तथा अज्ञान व्यापारी सम, बपड़ा व्यापार, भ्रष्ट, स्वार्थी मण्डल, ऐसे साहचर्यों के उदाहरण हैं।

राजनैतिक—राज्य और मजदूरराष्ट्र मध्य राजनैतिक साहचर्य हैं, जिनका लक्ष्य समाज में कानून और व्यवस्था को बचाये रखना है। वह राजनैतिक दल, जिनका लक्ष्य राज्य में राजनैतिक भ्रष्टाचार दूर करना है, इसी श्रेणी में आता है।

मनोरंजनात्मक—बचाने वाली शारीरिक और बौद्धिक मेहनत के बाद आदमी को अपने को तरो-ताजा करने के लिये कुछ मनोरंजन की आवश्यकता होती है। नाटक, सर्कस और खेल मध्य मनोरंजनात्मक साहचर्यों के उदाहरण हैं।

सांस्कृतिक—स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, वाद-विवाद समाज, अध्ययन केन्द्र, रोटरी सर्कल, समिति और नाटक क्लब, पेंटिंग और अन्य ललित कलाओं के स्कूल, ये सब सांस्कृतिक साहचर्य हैं। इनका लक्ष्य बुद्धि का पैना करना, ज्ञान को तरकीबों से बढ़ाना और मोक्ष का परिष्कार तथा उसे समझना है।

धार्मिक—पन्था धर्म आदि का प्रयोजन है। मन्दिर, मुहूर्त, मस्जिद और विराज-घर ऐसे स्थान हैं, जहाँ लोग भोतर्क, ध्यान और मुण की शक्ति में आते हैं। जिन साहचर्यों का लक्ष्य धर्म और समाज को बुराई से मुक्त करने में सुधार करना होता है, वे सुधारक सब कहलाते हैं। आर्यसमाज और ब्राह्मणसमाज इन प्रभु के उदाहरण हैं।

परोपकारी—मनुष्य सदा स्वार्थी नहीं होता । बहुत बार हम देखते हैं कि वह गरीब लाचार और पद्दलिन लोगों ने सहानुभूति और उदारता दिखाता है । समाज सेवा की प्रेरणा से बनाये गये साहचर्य परोपकारी मध्य कहलाते हैं । अनाथालय विधवाश्रम, यममयं व्यक्तियों और कोठियों के आश्रम, हृस्पनाल और औपधात्रम दश प्ररूप के साहचर्य हैं ।

साहचर्यों की उपयोजिता और महत्व

नागरिक की साहचर्यों ने निम्नलिखित लाभ होने हैं —

(१) कोई आदमी पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं होता । उसे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिये दूसरों से सहयोग करना होगा । इस प्रकार साहचर्य मनुष्य की तत्त्व-तरह की जरूरतें पूरी करने के लिये आवश्यक है ।

(२) साहचर्यों ने कठिन से कठिन कार्य की निधि के लिये मनुष्यन भांर सगठित कोशिश का साम्या बनना है ।

(३) आदमी के सर्वलोकमुखी विकास के लिये साहचर्य जरूरी है । अलग-अलग साहचर्य मनुष्य के व्यक्तिगत से अलग-अलग पहलुओं के विकास में सहायक होते हैं । तरह-तरह के लोगों से मिलने से उनका अनुभव और ज्ञान बहुत बढ जाता है ।

(४) एकठा में हीं भावि है । किसी साहचर्य के सदस्य के रूप में आदमी अपने हिनों की अधिक आमाजी से रक्षा कर सकने है, और अपने अधिकारों के लिये अधिक आमाजी से लढ सक्ते हैं, जैसे उदाहरण के लिये, ट्रेड यूनियन बनाकर ।

(५) बहुत से साहचर्यों का सदस्य बनकर ही आदमी अपने मित्रों और परिचितों का सेवा बढा सकता है । कोई आदमी जितने अधिक साहचर्यों में जाता है, उसकी ज्ञान-पहचान उसकी ही अधिक होने की सम्भावना है ।

साहचर्य और समुदाय में भेद

इन दोनों में भेद करने वागी वानें से है —

(१) समुदाय में गद्य गयठन नहीं होता पर साहचर्य में गयठन अवश्य होता है ।

(२) समुदाय के सदस्यों की ओरने वागी चीज कुछ मासं हिन होने हैं । उनका कोई एक ही लक्ष्य या उद्देश्य होता जरूरी नहीं, पर साहचर्य में कोई निश्चित प्रयोजन या लक्ष्य अवश्य होता चाहिए ।

(३) समुदाय साहचर्य की अवस्था बढा मझू है । इसमें कई साहचर्य हो सकते हैं । किसी नगर में, जो एक समुदाय है, कई साहचर्य हो सकते हैं । इसी प्रकार, छान समुदाय कई साहचर्यों में पयस्थित हो सकते हैं । किसी साहचर्य में भी विभिन्न समुदायों के लोग हो सकते हैं ।

(४) जब हम किसी गांव या नहर को समुदाय कहते हैं, तब समुदाय शब्द प्रादेशिक अर्थ भी रखता है । राज्य की छोडकर और कोई साहचर्य प्रादेशिक अर्थ नहीं रखता ।

साहचर्य और संस्था में भेद

बोलचाल में ये दोनों शब्द एक दूसरे की जगह अयुक्त कर दिये जाते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों से साहचर्य और संस्था का अन्तर भाषा तौर से समझ में आ जाएगा। कालेज उत्तम शिक्षा प्राप्त करने के साधन प्रयोजन के लिये छात्रों का साहचर्य है, सैनिक, हाजिरी, प्रिंसिपल की आज्ञा और परीक्षाएँ इन साहचर्यों की संस्था हैं। इसी प्रकार, राज्य कानून और व्यवस्था बनाये रखने के प्रयोजन के लिये एक साहचर्य है। इसका अधिपति और इसके कानून इस साहचर्य की संस्थाएँ हैं। इस प्रकार, साहचर्य किसी विशेष प्रयोजन के लिये संघटित छोटी बड़ी समूह है, परन्तु संस्था उन नियमों, प्रथाओं परम्पराओं और रुढ़ियों को कहते हैं जो किसी साहचर्य के सदस्यों के आचरण और व्यवहार से सम्बन्ध रखती हैं। (अपूर्ण)

अध्याय : : ५ (विषय)

परिवार

अनेक साहचर्यों में से दो साहचर्यों, परिवार और राज्य, का सामरिक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ हम परिवार के इससे पर विचार करेंगे।

परिवार क्यों कहते हैं—

परिवार उन स्वाभाविक साहचर्यों को कह सकते हैं, जो पति, पत्नी और बच्चों का होता है, और जिसमें कुछ नियम और धार्मिक कृत्य होने हैं, तथा जो सत्ता पैदा करने, और उनके पालन-पोषण के लिये बनाया जाता है।

इसकी भेदक विशेषताएँ—

परिवार की निम्नलिखित विशेषताएँ और सब समूहों में इसे चित्र करनी है

(१) यह राज्य की तरह एक स्वाभाविक साहचर्य है। हर आदमी जन्म से किसी न किसी परिवार का सदस्य होता है। उनका जीवन ही परिवार पर निर्भर होता है। परिवार उनके व्यक्तित्व के विकास में भी बड़ा हिस्सा लेता है। इन कारणों से यह सबसे महत्वपूर्ण मानवीय समूह है।

(२) प्राकृतिक होने के कारण, यह सबसे अधिक सामंजस्य साहचर्य भी है। मनुष्य जन्म से सहारे समूह में होता है। यह पशुओं और पक्षियों में भी मौजूद है।

(३) किसी परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से बांधने वाले बंधन सबसे तबदीकी होते हैं। मनुष्य जाति के और किसी समूह में एकता के सम्बन्ध इतने प्रबल नहीं होते। परिवार का आधार रक्त का सम्बन्ध है।

(४) समय के निहाय में परिवार प्राचीनतम समूह है।

सब परिवारों की सामाजिक विशेषताएँ

निम्नलिखित विशेषताएँ सब मानवीय परिवारों में होती हैं —

(१) पति और पत्नी के मध्य शीन और प्रेम सम्बन्ध सब मानवीय परिवारों की पहली विशेषता है।

(२) निवाह दूसरी विशेषता है। शीन सम्बन्ध के अलावा पति-पत्नी किसी तरह के विवाह में बंधे हुए होते हैं।

(३) सारी दुनिया में, परिवार ने ही मनुष्य का बस जाना जाता है।

(४) बच्चा सब मानवीय परिवारों का केन्द्र है। बच्ची का पालन-पोषण सब मानवीय परिवारों का ध्येय है।

(५) परिवार के सब सदस्यों का एक साझा निवास-स्थान होता है जिसे घर कहते हैं।

नागरिक बनने हों। ऐसे परिवारों को जकेले परिवार कहते हैं। हमारे देश में प्रायः परिवारों में बड़े और विवाहित पुत्र, बूढ़ बादा-दादी, विधवा बहिन और पाचिसा आदि भी होती हैं। इन परिवारों को अविकसित परिवार कहते हैं।

अविकसित परिवार प्रणाली

अविकसित परिवार के कामों का प्रबन्ध सबसे बड़ा नर सदस्य करता है जो बत्ता कहलाता है। परिवार की सम्पत्ति के सब भोग स्वामी होते हैं और बत्ता इसका अभिप्राय होता है। सब सदस्यों की कमाई इसटूटी कर ली जाती है और वे मिलकर उसे बांट लेते हैं। अविकसित परिवार प्रणाली छोटे पैमाने पर समाजवादी परीक्षण है। परिवार का हर एक सदस्य अपने सामर्थ्य के अनुसार काम करता और कमाता है और उसने सहने में, उनकी प्रकृति के अनुसार उसे दिया जाता है।

अविकसित परिवार के लाभ

(१) अविकसित परिवार प्रणाली बेमजदूरीयता का एक महान् प्रयोग है। यह मिलकर रहने और मिलकर काम करने का पाठ पढ़ाती है। यह परिवार के सदस्यों के मन में आदर, आभाषण, अनुमान, त्याग और सहकारीता की भावनाएँ पैदा करती है। इन गुणों से युक्त आदर्श अकष्ट नागरिक बन जाता है।

(२) पर इसका मुख्य लाभ यह है कि प्रत्येक की जीविका मिलनी निश्चित हो जाती है। अविकसित परिवार अनाथों, गैरिबों, बुढ़ों और विधवाओं के लिये, जिससे साम जीविका का और कोई साधन नहीं है, सुरक्षित साधन स्थापन है।

(३) अविकसित परिवार प्रणाली धर्म के विनाश का जो बहुत बड़ा तमूना है। परिवार के सब सदस्यों को घर के किसी न किसी काम में लगा दिया जाता है और हर एक वह काम करता है जिसके लिये वह अधिक से अधिक योग्य है। इसटूटे रहने और जाने से लच में भी बचत होती है।

(४) अन्तिम बात यह है कि अविकसित परिवार परिवार की समृद्धि और अधिकता अगली पीढ़ी को पढ़वाने का सर्वोत्तम साधन है। बच्चों का बचपन में परिवार की परम्पराओं और प्रथाओं का पाठ्य करना मिलाना जाता है।

अविकसित परिवार की हानियाँ

(१) पर अविकसित परिवार प्रणाली सरली हुई मर्यादा है और इसकी उपबोधिना के धारे में बड़ा गड़बड़ होना जाता है। इसकी मुख्य हानि यह है कि यह आदर्शों के व्यक्तिगत विकास के लिये सुझा और पूरा मोका नहीं देती। आदर्शों अपनी मृत-जन्म से मुक्त नहीं कर सक्ता। उसे परिवार की रक्षकानुक्ति परम्पराएँ बाधनी पड़ती हैं। फिर, हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति अविकसित होने को तैयार हो और परिवार के अन्य समाने वाले लोग यह अविकसित उद्योग पसन्द न करें।

(२) अविकसित परिवार प्रणाली की दुनियाँ। शक्ति यह है कि यह अपने सब 'सदस्यों' को एक निश्चित दायरे में बालती है। सबकी मर्यादा में परिवार की परम्पराओं का पाठ्य करना होता। जवान लड़की-लड़कियों के, दादी, तय करने का काम भी

पर के बहो का है। इस तरह विगी के निचे नई बाल गोषने का नया रास्ता बनाने की मुआइश नहीं। यह प्रकृति स्वस्थ नागरिक जीवन के निचे बड़ी शांतिवाक है।

(३) अविभक्त परिवार में अलग-अलग पसन्द, आदमी और स्वभावी के लोप होने हैं। उनकी उम्रों और दृष्टिकोणों में बड़ी समानता नहीं होती और पर म हागरे पैदा हो जाते हैं जिसमें गुण और शक्ति नष्ट हो जाती है।

अविभक्त परिवार का भविष्य

अविभक्त परिवार प्रभावी अब जनों की मर रही है। औद्योगिक समाज पैदा हो जाने, बहुत तरह के धर्म हो जाने, तारीफ के बीच मान और जान-बूझ के गोपन बढ़ जाने से भी पुराने अविभक्त परिवार का टूटने में मदद मिली। नयी पाई अलग लिय गुण गुणुर, पर अलग, पर बनाया बनती है जो वह अपर, हटा री गुण मानित हो। परिणामतः विगी परिवार के मध्य अपनी आमदनी, व मुताबिक रतन-गहन का गुण भागों के निचे अपने, हटा में अलग हो जान है।

पर हमाउ देग वृषि प्रवाल दग है और इस रूप में अविभक्त परिवार हमारी जल्दगी के लिय बड़ा ठीक पैडता है। अविभक्त परिवार के टूटने में जान छाई रह जाणी और हगन जो धुआइयां होती हैं व गव हारी। हमणि यदि हम मिश्वर एव ही मरान म नही रह गवने का भी जो नर जर्मीन के म्यामिद और पैदा का खवाल है, वही तब हमें मिलकर रहना चाहिए।

परिवार के कार्य

गुण मास्वरों के रूप में परिवार बहुत म महत्वपूर्ण कार्य करता है।

मनोवैज्ञानिक

मनुष्य और रत्नों का विकास व, स्व गुण रीति में सम्बलन की प्रकृति को मनुष्य करों का मरग भविष्य मैनिष रास्ता है।

जैविकीय (Biological)

परिवार का जैविकीय काम है मानव जाति को तनु की बढ़ाने जाना। इसमें मरान उन्नत करना और उनकी रक्षा करना, ये दोनों बात साधित हैं। मरान उन्नत करने का अर्थ है बच्चे पैदा करने मानव जाति को जारी रखना। पर बच्चा का पैदा हो जाना है, काफी नहीं, इनका पालन-पोषण और विकास से रक्षा भी करनी होगी। जननीय प्रकृति माना-पिता का अपर बच्चे को दबनाउ करने की प्ररणा देती है। बच्चों का पालन-पोषण बड़ा बडिद काम है। माता-पिता के बलावा और कोई बच्चा के गिग गुनी में आते गुन की कुर्वनी नहीं कर सक्ता। बच्चे माता पिता से जो प्रेम और आदर दिखलाते हैं, उनमें माना-पिता अपने मर तवर्त्तका का भूल जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि परिवार के द्वारा प्रकृति मरान पैदा करने और उनकी रक्षा करने की अपने, मात्रा को अधिक में अधिक अच्छ, रति में पूरा करती है।

परिवार एक जातिक हवाई भी है। परिवार के मध्य कर्तव्यों का भाग में बाट लेते हैं और जाणी मटपोष से रहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि परिवार

भी कामधन्य और सब अधिक से अधिक अच्छे तरीके से मजल जाने हें । प्रत्येक सदस्य नवद धन द्वारा या अपने काम द्वारा परिवार को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने का भरमब यत्न करता है । सब में भी बरबारी से बचने के लिये सब तरह की सावधानी बरती जाती है ।

दूसरी बात यह है कि परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम होने के कारण हर सदस्य बीमारी और बेरोजगारी में दूसरों की महानन्ता पर भरोसा कर सकता है । बड़े और क्षममय माता-पिता अपने बरध-पौधन के लिये अपने जवान लड़कों पर भरोसा कर सकते हैं । इस अर्थ में परिवार एक बौद्धिक सम्पत्ति का वास करता है ।

तीसरे, पुराने जमाने में, जब पिता का हुनर सटका सीखता था, परिवार एक शिक्षास्थल का काम भी करता था ।

शिक्षात्मक, साहित्यिक और नैतिक

बच्चा परिवार में अपने माता-पिता की निगरानी में जन्म लेता है । वह हर चीज के लिये उन पर निर्भर है । माता-पिता उसे बोलना, अच्छा भोजन करना और बपड़े पहनना सिखाते हैं । बच्चे पर बहुत जल्दी अमर पढ़ता है, और इगमें मकल की प्रवृत्ति होती है । अनेक चीजों के बारे में उसका ज्ञान और गन तथा उसकी आसों व पसन्द, तीर-तरीका और विश्वास, अधिकतर उसके माता-पिता से पाये हुए होते हैं । इस प्रकार शिक्षात्मक के अलावा परिवार का सामाजिक महत्व भी है ।

इसका नैतिक कार्य भी है । परिवार में ही बच्चे के चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण होता है । विशेष रूप से इस दिशा में माता बहुत कुछ कर सकती है । शिक्षावी की महत्ता का अधिकतर खेद उनकी माता की ही था ।

नागरिक कर्तव्य

घर में ही आदमी सबसे पहले नागरिक कर्तव्य सीखता है । हम पहले देख चुके हैं कि व्यक्ति के जीवन में परिवार का क्या स्थान है ? उसके चरित्र और व्यक्तित्व की नींव परिवार में ही पड़ती है । उसके व्यवहार और गतिविधि इसी से उभर निकलते हैं । बचपन में पैदा हुए गुण और दोष आदर्शों में बड़े होत पर भी बसे रहते हैं । अनुशासन और आज्ञागमन, जो नागरिक नागरिक जीवन के लिये इतनी जरूरी चीजें हैं, बच्चा पहले परिवार में ही सीखता है । इस अर्थ में परिवार एक छोटा सा राज्य है ।

हर मनुष्य के जीवन में जोरों के अनुकूल बनकर चलता पड़ता है । बच्चे को परिवार के जीवन में अपने-आपको अनुकूल बनाना पड़ता है । कुर्बानी, महिगुना और महरोज आदि गुणों के बिना अनुकूलन सम्भव नहीं । माता-पिता अपने बच्चों की निस्वार्थ सेवा द्वारा उनके सामने कुर्बानी का बहुत अच्छा उदाहरण देस करते हैं । इस तरह बच्चा स्वार्थ छोड़कर महरोज करता सीखता है । अनुभव में ही बच्चे यह सीखते हैं कि परिवार में अपने अधिकार पर जोर देने के साथ उन्हें कुछ कर्तव्यों की पूर्ति भी करनी चाहिए । इसी तरह उन्हें बहन-भाइयों से सम्बन्ध होने पर उनका दृष्टिकोण भी मानना चाहिए और बहुत से नागरिक गुणों, जैसे भलाई, ईमानदारी, समय-व्यवस्था,

वस्तुस्थिति की भावना और जिम्मेवारी, जो नागरिक जीवन के लिये बड़े महत्व के हैं, भी आदमी पहले परिवार में ही सीखता है। इस प्रकार नागरिक जीवन में परिवार बड़ा उपयोगी काम करता है।

परिवार का भविष्य

पिछले १०० सालों में आवुनिव मर्यादा जिस तेजी से आगे बढ़ी है, उसमें परिवार का महत्व कम हो रहा मानना पठना है। एल्डग टंकले जैसे लेखकों का विचार है कि शायद किसी दिन परिवार विलुप्त हो जाये क्योंकि इसके सब महत्वपूर्ण कार्य समाज के अन्य साहचर्य अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। बड़ा जाना है कि शिक्षा बलापन केन्द्र और बाल मन्दन परिवार की बच्चे पालने के काम में छुटकारा दे देते हैं। सब उम्रों के बच्चों के लिये स्कूल गोल्लर राज्य में शिक्षा का काम अपने ऊपर ले लिया है। बिडर-माटेन स्कूलों बच्चों की नाकबंदी में उन्हें सामेल और शिक्षा देने का काम करते हैं। आधुनिक दृष्टि में लोगों में आचार में बर्तन-बर्तन वस्तुएँ खरीदने की प्रवृत्ति है। हॉटेल और रेस्टोरेण्ट हर पल्लव की चीज देते हैं और इस तरह पर में रमोई की जगह नहीं रहता। स्त्रियों में बर्तन हुई पुरुषों में बराबरी और स्वतन्त्रता की भावना ने परिवार की नींव हिला दी है। इसका पर में बड़े रहन को संसार नहीं। पुरुषों की तरह वे भी नोबरी उड़ते हैं और स्वतन्त्र बर्तन करना चाहते हैं। वे भी समाज में धूमना-किरना चाहते हैं। तलाक ने विवाह-बंधन का तोड़ता आसान कर दिया है। इन सब बातों को देखते हुए, आमगौर में कहा जाता है कि परिवार की इबाई टटने की ओर बढ़ रही है।

पर हमें याद रखना चाहिए कि परिवार का भविष्य ऐसा निराशाजनक नहीं है। यह ठीक है कि परिवार की रचना और कामों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। इन सबके बावजूद इस बात का कोई सबूत नहीं कि परिवार टूट रहा है। अधिक से अधिक आगे बढ़े हुए देशों में भी परिवार मौजूद है। आदमी की जैविकीय और सामाजिक आवश्यकताओं के लिये इसे अब भी जरूरी समझा जाता है। स्त्रियों की पुरुषों के साथ बराबरी ने पारिवारिक जीवन में अधिक तालमेल की संभावना है। सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार में आपसी प्रेम, विश्वास, सहयोग और सहानुभूति का जो वातावरण होता है वह किसी और समूह में नहीं हो सकता।

सारांश

साहचर्य या सब लोगों का वह संगठन समूह है जो किसी काम सामे प्रयोजन की सिद्धि के लिये बनाया जाता है।

साहचर्य के प्रकार—साहचर्य स्वाभाविक या स्वेच्छया बनाये हुए, स्थायी या अस्थायी हो सकते हैं, और उनमें उनके कार्यों की प्रवृत्ति के अनुसार भी भेद हो सकता है।

साहचर्य की उपयोगिता—(१) मनुष्य की अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये साहचर्य की आवश्यकता है। (२) साहचर्य कठिन में कठिन उद्देश्य की

निर्दिष्ट के लिये शक्ति की व्यवस्था करने हे। (३) साहचर्य लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा के योग्य बनाने हे। (४) बिना साहचर्य के, मनुष्य के व्यक्तित्व का अनुभूती विकास सम्भव नहीं। (५) साहचर्यों द्वारा हम अपने मित्रों और परिचितों का दायरा बढ़ाने हे।

साहचर्य और समुदाय—(१) समुदाय का संगठित होना आवश्यक नहीं। साहचर्य एक संगठित समूह है। (२) समुदाय के सदस्यों को बाँधने वाली चीज सामाहित है। साहचर्य के सदस्यों का उद्देश्य या लक्ष्य सामा होता है। (३) समुदाय साहचर्य की अनेक अविव्य बड़ा समूह है। (४) गाँव या शहर के अर्थ में समुदाय क्षेत्र को भी सूचित करता है। साहचर्य में के सिर्फ राज्य में ही क्षेत्र होता है।

साहचर्य और सम्बन्ध—लोगों के संगठित समूह को साहचर्य कहते हैं। निजी संगठित समूह के सदस्यों के बीच के सम्बन्ध को निर्दिष्ट करने वाले, लिखे या बेलिखे नियमों को समूह को मर्यादा कहते हैं। कानिज एक साहचर्य है, पर मापन, परीक्षाएँ और आचार्य के आदेश इस साहचर्य को मर्यादा हैं।

परिवार

परिवार पति, उसकी पत्नी और बच्चे, के उस प्राकृतिक साहचर्य को कहते हैं जो मतानुबंध करने और बच्चों के पालन-पोषण के लिये होता है और जिसके साथ कुछ नियम तथा कर्मकांड जुड़े रहते हैं।

इसकी विशेषताएँ—(१) यह प्राकृतिक और मार्बनिक है। (२) इनके सदस्य पतिपुत्रत्व बंधनों से बंधे होते हैं। (३) पति और पत्नी का यौन सम्बन्ध विवाह पर आधारित है। (४) धनधन परिवार के जरिये होता है। (५) सब सदस्यों की रहने की जगह एक होती है जो घर कहलाती है।

परिवार का उद्गम और आधार—यह ज्ञान इतिहास के बाल से पहले पैदा हुआ। एक अर्थ में यह मनुष्य में भी पड़े का है। परिवार दो बलों, अर्थात् यौन बल और लुभा की पारस्परिक क्रिया का परिणाम है।

परिवार के प्रभु—(१) वयस्क के आधार पर परिवार या तो पैतृक होते हैं या मातृक अर्थात् या तो पिता के कम से कम देखा जाता है, या माता के कम से। (२) विवाह के रूप के आधार पर, परिवार एकपत्नीय बहुपत्नीय या बहुपति हो सकता है। (३) इसकी वनावट के आधार पर परिवार अकेला या अविवर्धन हो सकता है। अकेले परिवार में पति-पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे होते हैं। अविवर्धन परिवार में बड़े और विवाहित पुत्र, बड़े दादा-दादी, विधवा बहनें और चाचियाँ भी शामिल होती हैं। अविवर्धन परिवार का मुखिया कर्ता कहलाता है। अविवर्धन परिवार में सम्पत्ति सबकी इकट्ठी होती है और बर्माई को इकट्ठा कर लिया जाता है और सब मिलकर उसका उपयोग करने हैं।

अविवर्धन परिवार की अच्छाइयाँ—यह सहकारिता का एक महान् परीक्षण है और धर्म के विभाजन का एक अच्छा उदाहरण है। (२) इसमें हरेक की जीविका

- ५ "नागरिक जीवन घर में शुरू होता है" । इस कथन को स्पष्ट कीजिए ।
(५० वि० अप्रैल १९५०)
- ६ Elucidate the statement that civic life begins at home.
(P U April 1950)
- ७ "घर नागरिक गुणों का पहला विद्यालय है", इसे स्पष्ट करो और इसको सिद्ध करना करो ।
(५० वि० सितम्बर १९५३)
- ८ "The home is the primary school of civic virtues". Explain and discuss
(P U Sep 1953)
- ९ सभ्य में परिवार के काम गिनाइये और बताइये कि नागरिक के जीवन में इसका क्या महत्व है ?
- १० Briefly enumerate the functions of family and also give its importance in the life of a citizen
- ११ साहचर्य के रूप में परिवार का महिष्य क्या है ? क्या बिना इसके बिना काम चल सकता है ?
- १२ Discuss the future of family as an association. Is it possible to do without it ?

अध्याय : : ६

समुदाय—गांव और नगर

गांव

परिभाषा—गांव समाज की सबसे छोटी इकाई है। जब कई परिवार किसी निश्चित जमीन पर खेती और उससे सम्बन्धित और पेजों के लिये बस जाते हैं तो गांव बन जाता है। भारत में गांव कच्चे मवानों का वह समूह होता है, जिसमें वही कोई पवन मकान हो और जिनमें पारा और खेती की जमीनें हो।

उद्गम—गांव की परिभाषा में हम देख चुके हैं कि गांव समाज की एक प्रादेशिक इकाई है। इसका अर्थ यह है कि गांव तब पैदा हुए जब आदमी निश्चित प्रदेश पर स्थायी रूप से रहने लगा था। मानव समाज के विकास की पहली दो अवस्थाओं, अर्थात् शिकारी अवस्था और पशुपालक अवस्थाओं में मनुष्य बजारों का जीवन बिताता था। वह अपने लिये और अपने पशुओं के लिये भोजन खोजता हुआ एक जगह से दूसरी जगह फिरता रहता था। जब धीरे धीरे आदमी ने खेती करना सीख लिया, तब किसी खास जमीन में दिलबस्ती हो जाने से वह वहां स्थायी रूप से रहने को मजबूर हो गया होगा। जब उस जमीन पर खेती के लिए कई परिवार बस गये, तब गांव का जन्म हुआ।

एक बार पैदा हो जाने के बाद गांव के बरतने में आनपास के परिवारों की दिलबस्ती बढ जाने से और प्रतिरक्षा, पानी, सफाई और शिक्षा आदि मिली-जुली समस्याओं से मदद मिली। ये समस्याएँ हट करने के लिये गांव वालों की इकट्ठी बोलिया और सहयोग की जरूरत थी। आदमी की खेती की जरूरतें पूरी करने के लिये भी सहयोग और धन का विभाजन जरूरी हो गया। कोई भी परिवार अपने लिये काफी अनाज, कपड़ा और अन्य वस्तुएँ नहीं बना सकता था। आत्मनिर्भरता गांव की एक पहचान हो गई।

पुराने और नये गांव—पुराने जमाने में गांव का जीवन आर्थिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से आत्मनिर्भर हुआ करता था। आर्थिक दृष्टि से गांव वाले आपसी धन-विभाजन द्वारा अपनी सब जरूरतें पूरी किया करते थे। किसान जमीन खोता था और सारे गांव के लिये काफी अनाज और अन्य कच्चा सामान पैदा करता था। उसे गांव में इकट्ठी की स्थिति शामिल थी और लोग उसके अनाज में हिस्सा पाते थे और अलग-अलग तरह उसकी सेवा करते थे। ओहार और खट्टे उसका हल, बेलगाड़ी और खेती के अन्य औजार बनाते और मुधारते थे। जुलाहा घरों में औरतें द्वारा बाँटे हुए सूत से कपड़ा बनाता था, चमार जूने बनाता था, हत्थारि।

राजनीतिक दृष्टि से भी पुराने जमाने के गांव अंगत में आत्मनिर्भर हुआ

करते थे। वे गांव पचापनो द्वारा अपना नाम-नाम समालाते थे और अपने सगरे तप करते थे। नाम के लिए जेदाक बाव जिनी राज्य का हिस्सा होते थे पर कमल में राज्य की राजधानी की सरतार उनको जिनगी में कोई दमक न रखती थी।

पर वाचक गांव आत्मनिर्भर नहीं रहे। तेज सवारों और सवार साधनों ने उनकी आत्मनिर्भरता खत्म कर दी। उनका पास के कस्बों और शहरों से सम्बन्ध जुड़ गया। शहर की घंटटरी में बनी वस्तुएं गांवों में पहुँचने लगी। बाव इन गांव के बादमी को बिना में घने बपड़े और जूते पहने देखते थे। घातु के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, माडकिल और रेडियो जैसी विद्यमान-वस्तुएं आवाहन गांवों में आमतौर से पायी जाती हैं। गांव बाबा अपने बच्चों को तांगन के लिये शहरों के स्कूलों में भेजता है। राज-नैतिक दृष्टि से भी पचापनो को सना सम्म हो जाने के कारण गांवों के सगरे शहरों की अशांत में तप होने लगे।

नागरिक जीवन में गांव का महत्व—गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्रशासनीय और राजनैतिक इकाई है।

सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व—प्रथम जो, गांव मनुष्य के सामाजिक जीवन की उन्नत अवस्था को सूचित करता है। उसने पहले-सहज गांव में ही उन लोगों के साथ सहयोग करना और सामुदायिक रहना सीखा होगा जो उसके रक्त-सम्बन्धी नहीं थे।

दूसरी बात यह है कि गांव के जीवन में मनुष्य की उन प्रवृत्तियों को पूरा होने का मौका मिलता है जिसकी पूर्ति परिवार में नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, प्रपंच व्यक्ति को ऐसी भिन्नमहती चाहिए जिसके साथ वह बातचीत कर सके और हमी-अनाक कर सके। गांव में यह इच्छा आसानी से पूरी हो सकती है, क्योंकि सब गांव वाले उनके रक्त-सम्बन्धी नहीं हैं नकने।

तीसरे, नाटक, खेल, संगीत सम्मेलन और शौकनृत्य आदि मनोरंजन कम से कम गांव के ही स्तर पर हो सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों की तालीम के लिये स्कूल भी सब गांव वालों के सहयोग से ही बनाए जा सकते हैं।

आर्थिक दृष्टि से गांव किसी देश में उत्पादन की महत्वपूर्ण इकाई है। हम अनाक और बहुत से उद्योगों के लिये बच्चा सामान गांवों से ही हासिल करते हैं। गांव के खेतों की भातमुसारी या भुगतम्ब राज्य की आबादों का बहुत बड़ा हिस्सा होता है।

प्रशासनीय और राजनैतिक महत्व—किसी देश के प्रशासनतन्त्र में गांव की अधिकारी, जैसे पटवारी और मुखिया, महत्वपूर्ण बड़ी होते हैं। दूसरे, गांव पंचायत के नाम में गांव वालों को जो सबक मिलता है, वह लोकतन्त्रीय शासन को सफल बनाने में बड़ी मदद करता है। पचापनो में गांव वाले अपने मामलों की देखभाल और प्रबन्ध खुद करता सीखते हैं। परिवार के बाद गांव ही लोकतन्त्र के नागरिक का असली शिक्षागार्य है।

तीसरे, गांव वाले आम तौर से रुढ़ियोगी दृष्टिकोण रखते हैं, जिससे देश के राज-नैतिक जीवन में आकस्मिक परिवर्तन नहीं हो पाते।

चोये, सतुष्ट, सरल और बालू-वालक गांव समुदाय सरकार की शक्ति और रीढ़ की हड्डी का काम भी देता है।

पांचव, गांव वाले देश की रक्षा में बड़ा योग देते हैं। स्वस्थ और मेहनती गांव वाले अच्छे सिपाही बनते हैं।

नगर

नगर गांव से बड़ी और अधिक आबादी वाली इकाई है। नगरी और महानगरी का जीवन गांवों के जीवन से अपेक्षा अधिक समृद्ध और रगदिरमा होता है। गांव तो मुख्यतः कृषिजीवी होता है, पर नगरनिवासी अधिकतर उद्योग, व्यापार, वाणिज्य और नौकरी में लगे रहते हैं।

नगरी का उद्गम और वृद्धि—नगर मनुष्य के सामाजिक जीवन के विकास में अगली सीढ़ी है। जब तक मनुष्य की जरूरतें सादी थीं, तब तक वे गांव में पूरी की जा सकती थीं। पर सभ्यता के बढ़ने और मनुष्य की जरूरतों के बढ़ जाने पर मनुष्य बाहरी दुनिया में वस्तुओं को बदला-बदली करने लगा। व्यापार और वाणिज्य बढ़ गये और महत्वपूर्ण सड़क और बाजार नगरों के रूप में बदल गये। कभी-कभी उन जगहों पर फँटरिया बनने से भी, जहाँ अच्छा मायाज और शक्ति प्राप्त हो सकती थी, अनेक नगर और महानगर बन गए। बहुत से नगर कई गांवों के मिलने से बन गये हैं। तीर्थयात्रियों और भेड़ों के स्थान, धार्मिक नवियों के किनारे, तैमिक महत्त्व की जगह और सरकारी की राजधानिया भी धीरे धीरे समृद्ध नगर बन गयीं।

नगरों का महत्व—नगरों का देश के आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है।

कार्यिक—गांव तो कृषि की इकाई है, पर नगर और महानगर उद्योग, व्यापार और वाणिज्य के बड़े केन्द्र हैं। जहाँ-जहाँ फँटरिया, जो हमारी राज की बीजों की मूल्यों पर रहते पूरी करती हैं, सिर्फ नगरों और महानगरों में होती हैं। इन फँटरियों में देश के लाखों आदमियों को रोजगार मिलता है। देश के अन्दर और बाहर सब तरह की वस्तुएँ बेचने और खरीदने के लिए घोक बाजार और बड़े-बड़े बैंक और कपनिया नगरों और महानगरों में ही होती हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय सम्पत्ति के उत्पादन में नगरों का भी उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है।

सामाजिक—मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति को नगर में होने वाले अनेक तरह के साहचर्यों में अधिक सतोप हासिल होता है। नगर और महानगर निगोद और मनोरंजन के भी महत्वपूर्ण केन्द्र हैं। सिनेमा, नाचघर, खेल के मैदान, पार्क, व्यायाम-शालाएँ, प्रोवागण्ड और मण्डालय ऐसी जगहें हैं, जहाँ नगर-निवासी जा सकते हैं और लाभदायक मनोरंजन हासिल कर सकते हैं।

सांस्कृतिक—उपयुक्त सब स्थान तथा चिन्तनविद्यालय, कालेज, स्कूल, पुस्तकालय, कला और दर्शन के विद्यालय, वादविवाद मण्डल, नाटक, संगीत और रोटी समाज, नगरों में राष्ट्रीय संस्कृति फैलाती है। चिप्टाचार और फँडर भी नगरों

और महानगरों में शुरू होने हैं ।

राजनैतिक—नगरों और महानगरों के निवासियों का दृष्टिकोण प्रगतिशील होता है । परिवर्तन के लिये महत्वपूर्ण आन्दोलन नगरों में ही चलते हैं । दलीय प्रचार आंदोलन, सम्मेलन, जलूम और सार्वजनिक सभाएँ नगरों में रोजाना हुआ करती हैं । इसी कारण नगर-निवासियों को राजनैतिक शिक्षा भी अधिक अच्छी मिल जाती है, उसे देग में होनेवाली हर बात की पूरी जाकायी रहती है । सरकारों की राजधानियाँ भी नगरों में होने के कारण इन स्थानों के निवासियों को सरकार की नीतियों और कार्यों के बारे में अधिक अच्छी जानकारी मिल जाती है । राजनैतिक दलों के दफ्तर भी नगरों में होने हैं । हम प्रकार नगर राजनैतिक हलचल के बड़े केंद्र बने रहते हैं । हर नगर में अपना प्रबन्ध स्थापन करने वाली कोई नस्था होती है, जैसे नगरपालिका, जो शिक्षा, सफाई, डाकटरी मदद, नालियों, बिजली और मकान, आदि सब नगरनिवासियों के हित की चीजों का प्रबन्ध करती है ।

प्रान्त

प्रांत किसी देश के प्रदेश के बड़े टुकड़े को कहते हैं, जिसमें अनेक नगर और महानगर होने हैं । सामन की मुद्रिया के लिये देश को आमतौर से कई प्रांतों में बांट दिया जाता है । इसलिए प्रांत मुख्यतः प्रशासनीय और राजनैतिक इकाई है । कभी-कभी देश में जामि के बाद पहले बाले राज्यों को नए राज्यों के प्रांत बनाकर रख दिया जाता है । प्रांतों की सीमा रेखा संस्कृति और भाषा के आधार पर भी खींची जा सकती है । प्रांत में सार्वजनिक जीवन और समाज की शिक्षा के लिये और भी बड़ा क्षेत्र मिलता है ।

देश—देश शब्द भौगोलिक अर्थ का मुख्य है । भौगोलिक दृष्टि से दुनिया कई प्राकृतिक खंडों में बंटी हुई है और प्रत्येक खंड समुद्र, पहाड़ों या रेगिस्तानों द्वारा घेरे गे अलग है । ऐसी प्राकृतिक रकबटों में दो खंडों के बीच आया-जाता कठिन हो जाता है । इसलिए अलग-अलग खंडों के लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक जीवन का विकास अलग-अलग रूप में होता है । एक भूखंड के अन्दर लोगों के रहन-सहन का तरीका, आदतों और विचार-मनोरंज और समस्याएँ एक में होती हैं । देश शब्द का प्रयोग जब राजनैतिक दृष्टि से होता है तब यह उसी अर्थ का वाचक होता है जिसका वाचक राष्ट्र शब्द है । देश के सदस्यों के मारे आदमी का अधिक विस्तृत दृष्टिकोण होना चाहिए । उसे अपने निजी और स्थानीय हितों के मुकाबले में सारे देश के अधिक ऊँचे हितों का महत्व देना चाहिए ।

कभी ऐसा हो सकता है, कि अनेक समूहों के प्रति उसकी निष्ठाओं में विरोध हो जाए। उदाहरण के लिये, उसका अपना हित उसके परिवार के हित का विरोधी हो, या उसके परिवार का हित उसके गांव के हित का विरोधी हो, इत्यादि। तो फिर आदमी अपनी निष्ठाओं को कैसे काम में लाये ?

अपनी निष्ठाओं के प्रयोग की बात सोचने हुए आदमी को यह देखना चाहिए कि कौन सा दावा उसके व्यक्तित्व की आवश्यकताओं को अधिक पूरा करता है। उदाहरण के लिए, उसकी निष्ठा पर प्रातः, गांव या परिवार का जिनना दावा हो सकता है, उसमें अधिक दावा देना चाहिए। देश अस्पताल सोलगर उसकी स्वास्थ्य रक्षा अधिक अच्छी तरह कर सकता है, स्कूल और कालेज खोलकर उसकी बुद्धि को तीव्र और उसके दृष्टिकोण को विस्तृत कर सकता है, और सार्वजनिक उपयोगिता की वस्तुएं बनाकर उसके जीवन को आरामदेह और सुखी बना सकता है। देश आदमी के जीवन को भीतरी अराजकता और बाहरी हमलों में बचाता है। इस प्रकार सम्पूर्ण मानवता, देश, प्रातः, गांव या नगर, और परिवार का हमें क्या से उसके ऊपर पहले अधिकार होगा। व्यक्ति का अपना हित या अपने ऊपर व्यक्ति का दावा सबसे अन्त में आएगा। आदर्श नागरिक यह है जिसकी निष्ठाएं उचित रीति से प्रयोग में आती हैं और जो अपनी अनेक निष्ठाओं में विरोध नहीं पैदा होने देता।

पर निष्ठाओं की सही व्यवस्था का यह अर्थ नहीं है कि किसी एक सामाजिक इकाई के दावों को बिल्कुल उपेक्षित कर दिया जाए। आदमी का प्रत्येक इकाई की ओर उचित ध्यान देना चाहिए। उसे अपना आचरण ऐसा बनाना चाहिए कि उसकी अनेक निष्ठाओं के मध्य विरोध को सीधे कम से कम रह जाए। पर वास्तविक व्यवहार में निष्ठाओं की व्यवस्था बहुत दूर तक आदमी के चरित्र पर निर्भर है। बहुत बार हम देखते हैं कि आदमी के लिए अपने गांव, प्रातः या देश के हित में अपने या अपने परिवार के स्वार्थों की कुर्बानी करना कठिन हो जाता है। नागरिक शास्त्र का अध्ययन आदमी को यह शिक्षा देकर कि उसे बड़े समूहों के हितों के सामने अपने हितों की गोल कर लेना चाहिए, सही नागरिक बुद्धि का विकास करता है।

सारांश

गांव—गांव एक क्षेत्रीय समुदाय है जिसके सदस्यों का कृषि और सम्बन्धित धर्मों में सामान्य हित होता है।

इस प्रकार, क्षेत्र गांव की परमाधन्यक विशेषता है। यह तब ही अस्तित्व में आ गया होगा जब मनुष्य ने खेतों को कला सीखा।

पुराने जमाने में गांव आर्थिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों में आत्मनिर्भर हुआ करता था, और आज के जमाने में संचार के अधिक तेज साधनों के आविष्कार ने इस आत्मनिर्भरता को खत्म कर दिया है।

गांव का महत्व—(१) नागरिक दृष्टि में गांव मनुष्य के सामाजिक जीवन में एक उन्नत सीढ़ी का सूचक है। गांव में ही उसने पहली बार उन लोगों से महसूस

करना सीमा जो उसके संगे सम्बन्धी नहीं है। गांव में मनुष्य की मित्रों के साथ रहने की इच्छा की भी पूर्ति हो सकती है। (२) सामूहिक दृष्टि से कुछ मनोरंजन, जैसे नाटक और नाच, कम से कम गांव के स्तर पर हो सकते हैं। (३) आर्थिक दृष्टि से गांव उत्पादन की एक महत्वपूर्ण इकाई है। हमें अनाज और उद्योगों के लिये कच्चा सामान गांवों से ही मिलता है। (४) राजनैतिक दृष्टि से गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। गांव पचासवें लोगों को लोकतन्त्र की निशा देता है। गांव वालों की रुझानों ने क्रान्तियां होने में बड़ी रक्षाकट रहनी है।

नगर—नगर गांव की अपेक्षा बड़ा और अधिक आबादी वाला होता है। इसके लोग अधिकतर उद्योग, व्यापार, वाणिज्य और नौकरी में लगे रहते हैं।

शहर गांवों के बाहर बने। लोगों की बढ़ती हुई जरूरतों ने उन्हें बाहर की दुनिया को अपनी वस्तुएं देने और उनकी वस्तुएं लेने को मजबूर किया। सामारणतया नगर महत्वपूर्ण सड़कों के मिलने की जगह, बसियों में, तीर्थयात्रा और मैले के स्थानों पर, सामरिक महत्वों के स्थानों पर और सरकार के अतिष्ठान पर बने।

नगरी का महत्व—आर्थिक दृष्टि से नगर और महानगर उद्योग, व्यापार और वाणिज्य के महत्वपूर्ण केन्द्र होते हैं। फैक्टरियां, बैंक और बड़े बाजार अधिकतर नगरों और महानगरों में होते हैं। सामाजिक दृष्टि से नगरों में होने वाले अनेक तरह के माह-कर्मों में सामाजिक भावना की पूर्ति के लिये अधिक बड़ा क्षेत्र मिल जाता है। सांस्कृतिक दृष्टि से महानगरों के विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, कला विद्यालय, नाटक और संगीत गतिविधियां, ये सब सांस्कृतिक हटबल के केन्द्र होते हैं। राजनैतिक दृष्टि से नगर-निवासियों का दृष्टिकोण प्रगतिशील होता है। आन्दोलन, सम्मेलन और सार्वजनिक सम्मेलन नगरों में होती रहती हैं। राजनैतिक दली के दफ्तर नगरों में होते हैं। सरकार की राजधानी भी महानगरों में होती है।

प्रान्त—प्रान्त प्रथम एक प्रशासनीय और राजनीतिक इकाई है। प्रत्येक राज्य या देश को प्रशासनीय प्रयोजनों के लिये प्रान्तों में बांटा जाता है। प्रान्त में संकड़ी गांव और नगर होते हैं।

देश—नगर के उस भौगोलिक विभाजन को देश कहते हैं जो प्राकृतिक सीमाओं द्वारा ऐसे ही अन्य विभाजनों से पृथक् कर दिया जाता है।

निष्ठाओं को ठीक कम देना—जादगी अनेक दायरों अर्थात् परिवार, गांव या शहर, प्रान्त, देश और सारी दुनिया का सदस्य होता है। ये सब दायरे उसे लाभ पहुंचाते हैं, और इसलिए उसकी निष्ठा मांगते हैं। कभी-कभी उसकी एक दायरे के प्रति निष्ठा उसकी दूसरे दायरे के प्रति निष्ठा की विरोधी हो सकती है। तो, जादगी को अपनी निष्ठाओं को कैसे समबद्ध करना चाहिए? उसकी निष्ठा मनु अधिक बड़े दायरे के प्रति अधिक बड़ी होनी चाहिए क्योंकि दायरा जितना बड़ा होगा, वह उतना ही उसके व्यक्तित्व की आवश्यकताओं को अधिक पूरा करने वाला होगा। तो भी उसे किसी भी सामाजिक इकाई के दावे की पूरी तरह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सब तो यह

है कि उसे अपना आचरण ऐसा बनाना चाहिए कि उसकी कनेन निष्ठाओं में कोई विरोध पैदा न हो सके ।

प्रश्न

Questions

१. गांव और नगरों का राष्ट्रीय जीवन में क्या स्थान है ? (यू० पी० १९३१)
- 1 What important part do villages and towns play in national life ?
(U P 1931)
- २ गांव किसे कहते हैं ? किसी राष्ट्र के नागरिक जीवन में इसको कार्य और महत्व बताइये ।
- 2 What is a village ? Describe its functions and importance in the civic life of a nation.
- ३ निष्ठाओं के सही प्रयोग से आप क्या समझते हैं ? किसी नागरिक को अपनी निष्ठाओं का कैसे प्रयोग करना चाहिए और क्यों ?
- 3 What do you understand by 'right ordering of loyalties' ? How should a citizen order his loyalties and why ?
- ४ बताइये कि कहीं तक नागरिकता का अर्थ निष्ठाओं का सही प्रयोग है ।
(यू० पी० अप्रैल, १९५१)
4. Show how far citizenship means the right ordering of loyalties.
(P U. 1951)

अध्याय : : ७

सामाजिक संस्थाएं

सम्पत्ति, जाति और धर्म

सम्पत्ति

सम्पत्ति का अर्थ—सब आदमी और आदमियों के समूह भौतिक और मनोवैज्ञानिक सम्पत्तियों के स्वामी होने हैं, अर्थात् उन पर सम्पत्ति के अधिकार भागने हैं। सम्पत्ति शब्द में जमीन, पैसा, मकान, पन्ना, फरेलू सामान, और धन आदि भौतिक सम्पत्ति शामिल हैं। हममें पैसा या एकादश, प्रतिनिधित्व अधिकार या बार्गींग्डेंट और किसी बार्गींग या पन्ना की सम्पत्ति या गान (Goods) जैसी मनोवैज्ञानिक सम्पत्ति भी शामिल है। किसी समग्र लोग पुरानी और नई सम्पत्ति के भी स्वामी होने में और ये उस समय गुणवत्ता कहलाते हैं।

सम्पत्ति का महत्व—सम्पत्ति मनुष्य और समाज दोनों के लिये महत्वपूर्ण है। मनुष्य के लिये यह हम कारण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि उसे सम्पत्ति रखने की क्षमता है तो उसकी काम करने की इच्छा बढ़ जाती है। बढ़ती है मनुष्य की योग्यता की उसकी निजी सम्पत्ति की मात्रा में मापने है क्योंकि हम समझते हैं कि योग्य आदमी अधिक कामना है और अधिक बर्बाद है। सम्पत्ति मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए बड़ी आवश्यक है। समाज के लिये सम्पत्ति का महत्व इस बात से प्रकट होता है कि सामाजिक जीवन के अधिकतर अंगों में इस पर ही विचार होता है। किसी सम्पत्ति की प्रणाली में पन्ना की विपत्ति पैदा होती है और इसके साथ गरीबी और बेरोजगारी की समस्याएं आती हैं, जो लोगों में कई तरह के अपराध और दुर्व्यवहार पैदा करती हैं। राज्य भी, जो सामाजिक समग्रता का सर्वोच्च उच्च रूप है, लोगों की सम्पत्ति की रक्षा के लिये बना था। बहुत बार सम्पत्ति के पीछे ही राष्ट्रीय मंडल होने हैं। इसके अलावा, सम्पत्ति का महत्व इस बात में भी पता चलता कि मानव समाज मनुष्य की सम्पत्ति बढ़ने के कारण ही जाने बड़ा सक्रिय है। जिसकी जगह में मनुष्य के पास कोई साम्य सम्पत्ति नहीं होगी थी, पर आजकल उसकी सम्पत्ति में अलग सम्पत्ति है। अब तो यह है कि अगर आज की समस्या में मे सम्पत्ति की सम्पत्ति को निकाश दिया जाए तो समस्या का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा।

सम्पत्ति का उद्भव और वृद्धि—सम्पत्ति की मूल्य पहले निचले स्तरों में पैदा हुईं। पहले पत्थर के औजार और हथियार जैसी वस्तुएँ सम्पत्ति होती थी, और ये उसकी ही होती थी जिसका इन पर अलग में बर्बाद होता और जो इनका प्रयोग करता। मेनी की जमीन और मकानों के रूप में अनेक सम्पत्ति सेना के साथ आई। कृषि की आरम्भिक अवस्था में जमीन उसकी होती थी, जो उस पर पहले दबल कर ले। उद्योग का विकास होने पर सम्पत्ति सम्पत्ति निचले स्तर पर बढ़ गई। अब यह भी महसूस

दिया जाने लगा कि जिस चीज में आदमी अपनी मेहनत लगाए, वही उसकी सम्पत्ति है।

पर आजकल कोई भी इस बात पर ज़रा भी नहीं पड़ता कि शुरू में सम्पत्ति का जन्म कैसे हुआ। हम सब लोग सम्पत्ति की मन्था को एक मन्थारूपित तथ्य के रूप में समझते हैं। आजकल हमकी मान्यता कुछ तो प्रथा में और कुछ कानून में है। अधिकतर देशों के कानून आजकल निजी सम्पत्ति के अधिकार को गारंटी करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून भी इस अधिकार को मानता है।

निजी सम्पत्ति का अधिकार निरपेक्ष अधिकार (absolute right) नहीं, पर यह याद रखना चाहिए कि अन्य सब अधिकारों की तरह सम्पत्ति का अधिकार भी सीमित किया जा सकता है। स्वाभाविक के "नैसर्गिक अधिकार" (natural right) का सम्पत्ति के निरपेक्ष अधिकार जैसा कोई चीज नहीं है। प्रागैतिहासिक काल में बल ही एकमात्र अधिकार था। व्यक्ति का अपनी सम्पत्ति पर अधिकार धीरे-धीरे ही माना जाना शुरू हुआ। पहले यह प्रथा पर आधारित था, और फिर कानून द्वारा माना जाने लगा। सम्पत्ति पर अधिकार तब तक माना जाना रहेगा, जब तक यह आदमी और समाज, दोनों के लिये उपयोगी और आवश्यक समझा जाता है। समाजवादी विचारधारा ने असीमित निजी सम्पत्ति के अधिकार का समाज के लिये अहितकर बताया है। इस विचारधारा के प्रभाव में बहुत से देशों में निजी सम्पत्ति के अधिकार पर पाबन्दी लगा दी गई है, और हटाई जा रही है।

समाजीकरण या राष्ट्रीयकरण—इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। इनका अर्थ है सम्पत्ति पर राज्य का स्वाभिवल। राष्ट्रीयकरण का विचार समाजवादी विचारधारा का परिणाम है। समाजवादियों का कहना है कि फँडरियों और उत्पादन के अन्य माध्यमों के रूप में निजी सम्पत्ति सीधे ही सम्पत्ति की बहुत बड़ा विषमता पैदा कर देती है। यन् ही शक्ति है इसलिए असीमित निजी सम्पत्ति न केवल अधिक विषमता पैदा करती है, बल्कि सामाजिक और राजनैतिक विषमताओं को भी जन्म देती है। इस प्रकार धन का असीमित मध्यम अलोकतन्त्रीय समझा जाता है। यह इसलिए भी समाज के लिए हानिकारक समझा जाता है, क्योंकि इसमें धनी आदमी दूसरों के बल पर और अधिक धनी हो जाता है और दूसरे ज्यादा और ज्यादा गरीब होने लगते हैं। इस कारण समाजवादी उत्पादन के सब माध्यमों, अर्थात् भूमि, फँडरियों और वेतों, पर राज्य का स्वाभिवल कर देने के हामी हैं। वे सारी निजी सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते, बल्कि इसके सिर्फ उस हिस्से का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं जिसमें और धन पैदा होता है। समाजवाद में फँडरियों का नफा राजकोष में जाएगा, और वही से वह राज्य के सब लोगों के हितों के लिये खर्च किया जाएगा। समाजवादी शान्तिपूर्ण और क्रमिक उपायों में तथा भुजावजा देकर राष्ट्रीयकरण करने के पक्षपाती हैं, पर कम्युनिस्ट या मार्क्सवादी शान्तिकारी और हिंसक उपायों से तथा बिना भुजावजा दिये ही राष्ट्रीयकरण करने के पक्षपाती हैं।

दूसरी बात यह है कि आदमी की सम्पत्ति के उत्तराधिकार में प्राप्त हिस्से का

समाजोद्धार करने के लिये कहा जाता है। कहा जाता है कि जो सम्पत्ति व्यक्ति को करने पुरखों में मिलती है उसके लिए वह स्वयं को दिये जातु बानी नहीं करता। इसलिये सत्तारक्षिकार में मिली सम्पत्ति निम्नलिखित लोगों का एक दल पंश कर देती है और इसलिये वह समाज के लिए हानिकारक समझा जाता है। इसे अगर एकदम नहीं तो सोडा-सोडा करके राज्य की सम्पत्ति बना लेना चाहिए। बहुत से उन्नत देशों में सत्तारक्षिकार में मिली सम्पत्ति सोडा-सोडा करके समाज के अधिकार में लेने के लिये मृत्यु और सत्तारक्षिकार नामक उपाय जाते हैं।

निजी सम्पत्ति के पक्ष और विपक्ष में युक्तिवा—(१) निजी सम्पत्ति अध्यापन (acquisition) की प्रवृत्ति पर आधारित है, जो मनुष्य में बड़ी प्रबल होती है। इसलिए निजी सम्पत्ति बनें ही नैतिक है उन्ने परिदार, जो दान और जनकौम प्रवृत्तियों के आधार पर बनता है। यह आदमी के ज्ञान के लिये परिवार के ही समान प्रबलता की है। कोई भी आदमी, चाहे वह कितना भी सुनसुतल और बुद्धिमान हो, सम्पत्ति प्राप्त करने की प्रवृत्ति में खाली नहीं है। हम सोच सकते हैं कि निजी सम्पत्ति में मनुष्य का अनुराग और इससे मिलने वाला आनन्द सर्ववर्तक सम्पत्ति के प्रभाव और आनन्द से बड़े अधिक होता है। इसलिए यह कहा जाता है कि सम्पत्ति एक नैतिक सत्ता है।

(२) सम्पत्ति होने से इसके स्वामी की कुछ सुरक्षा बनून्वा होगी है। अगर किसी सम्पत्ति न हो तो किसी के पात्र अधिक के लिये कोई व्यवस्था न होगी और इसलिए सुरक्षा की भावना भी नहीं होगी। बनून्वा सभी उन्नति कर सकता है जब उसे निश्चिन्ता हो।

(३) सम्पत्ति से इसके स्वामी को कुछ आज़ादी की भावना भी मिलती है। जिस आदमी के पास जीवन-धारण के लिये कुछ धन है, उसे अपनी पसन्द न माने वाला काम स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य अपनी रचि के अनुसार अपनी योजनाओं का पालन कर सकता है। सम्पत्ति की उपस्थिति तभी होती है जब प्रत्येक व्यक्ति वह काम करे जिसके लिये वह सबसे अधिक उत्सुक है।

(४) कल्पित स्वप्न का अविचार अनुष्ठान को इच्छापूर्वक और बख्तीपूर्ण काम करने के लिये आशुप्त करता है। इस प्रकार, निजी सम्पत्ति उत्पन्न के लिये बड़ी प्रेरणा होती है।

(५) सम्पत्ति उत्पत्ति के अधिकार से धन बचाने को बचाव मित्रता है और इसके न होने पर आदमी धन बरबाद कर देता है। अनेक तरह के उत्पादक कार्यों में लाने के लिये धन बचाना बहुत जरूरी है। अगर बचत न होती तो लोग धीरे-धीरे वैयक्तिक सम्पत्ति, जो कालान्तर में बढ़े कर पड़े।

सहारा मिलता है जिनकी जीविका उत्तराधिकार में प्राप्त और संचित निजी सम्पत्ति पर होती है। अगर हर आदमी को अपनी जीविका बमाना पड़े और उसके पास कोई सारो समय न हो तो ये विज्ञान और कलाएँ खत्म हो जाएगी।

विपक्ष में युक्तिषा—समाजवादी और कम्युनिस्ट निजी सम्पत्ति के विपक्ष में युक्तिषा देते हैं। वे हम पर निम्नलिखित कारणों से आपत्ति उठाते हैं —

(१) निजी सम्पत्ति की प्रणाली मनुष्य को लोभी और स्वार्थी बना देती है और आम तौर पर समाज में अगडों का कारण होती है।

(२) इनमें धन की विषमता पैदा होती है। आर्थिक विषमता से सामाजिक और राजनैतिक विषमता का जन्म होता है। इसलिए निजी सम्पत्ति अलोकसंगीय है।

(३) निजी सम्पत्ति की प्रणाली अवलोकियों का जीने और फलने फूलने का अनुचित रूप से मौका देती है। दूसरी ओर, उन लोगों को जो योग्य और दक्ष हैं, और सम्पत्ति से हीन हैं, प्रायः जीवन को आर्थिक सुविधाएँ भी नहीं मिलती।

(४) सम्पत्ति होने से मनुष्य को भुरखा और जानासी की भावना तो मिल सकती है, पर यह उसे निष्कम्मा और फिजूलखर्च भी बनाती है। वह अपना समय और शक्ति उत्पादक बाजारों में समयाने के बजाय निरर्थक कामों में लगा सकता है।

(५) मनुष्य सदा निजी धन-लाभ की प्रेरणा से ही काम नहीं करता। बहूधा लोग समाज में यश और सम्मान पाने के लिये काम करते हैं और काम करने के लिये प्रेरित किये जा सकते हैं।

(६) कला, विज्ञान और साहित्य की उन्नति के लिये निजी सम्पत्ति की उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह काम विश्वविद्यालयों और अन्य निगमित निकायों { corporate bodies } द्वारा, जिनमें राज्य भी है, अधिक सरलता और दक्षता से किया जा सकता है। राज्य द्वारा कला, विज्ञान और साहित्य के संरक्षण के उपाहरण भूतकाल के भी हैं और परमाणु काल के भी।

(७) अन्ततः यह कहा जाता है कि निजी सम्पत्ति अभी उचित ठहराई जा सकती है, जब वह समाज के लिये उपयोगी या हितकर हो। अगर निजी सम्पत्ति ने ये ही शराइयाँ पैदा होती हैं जिनसे समाज काब कष्ट उठा रहा है तो इसकी कोई उपयोगिता नहीं और इसे खत्म कर देना चाहिए।

निष्कर्ष—हम मानते हैं कि निजी सम्पत्ति का कोई निष्पक्ष अधिकार नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी अधिकार सामाजिक दृष्टि से उचित होना चाहिए। तो भी, आदमी को रोजाना की जरूरतों में जाने वाली कुछ वस्तुओं पर निजी स्वामित्व में न केवल उसकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, बल्कि सामाजिक जीवन में गड़बड़ी भी रक जाती है। जमीन और भारी मशीनों का, जिनमें और सम्पत्ति पैदा होती है, निजी स्वामित्व राज्य को सौंपा जा सकता है, पर ऐसा होने से पहले इसके स्वामी को उचित मुआवजा अवश्य मिलना चाहिए। असल बात यह है कि यह तय करना बड़ा कठिन है कि किस सीमा तक सम्पत्ति का निजी या सार्वजनिक रहने दिया जाए।

जाति या वर्ण

हर एक समाज के सदस्यों में कोई न कोई भेदभाव आमनीर में पाया जाता है। ये भेदभाव, चाहे वे जन्म के आधार पर हो या धन सम्पत्ति के, समाज को कई समूहों में बांट देते हैं, जो श्रेणिया या वर्ण कहलाते हैं। पुराने जमाने में जन्म या कुलीनता, खास तौर से इन्डो-यूरोपीय भाषा बोलने वाले लोगों में, विशेषता प्रकट करने वाली महत्वपूर्ण बात रही है। आज के जमाने में जन्म का इतना महत्व नहीं है जितना धन का।

जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था अनेक देशों में फैली हुई है पर तीन दृष्टियों से यह भारत की खास चीज है —

(१) भारत में ही जातियों की मख्या हजारों में है और कहीं ऐसा नहीं है।

(२) जातियों की प्रणाली और योजना जितनी बारीकी में भारत में बनाई गयी है उतनी और किसी देश में नहीं है।

(३) और कहीं स्पृश्य और अस्पृश्य का भेदभाव नहीं है।

जाति प्रथा की कुछ विशेषताएँ—यद्यपि जाति की मनेक परिभाषाएँ हैं, फिर भी ऐसी कोई व्यापक असली परिभाषा नहीं है, जिसमें जाति प्रथा की सब विशेषताएँ आ जाय। असल में, जाति प्रथा इतनी जटिल चीज है कि इसकी परिभाषा करना कठिन है। ज्यादा से ज्यादा हम इसकी कुछ विशेषताएँ बता सकते हैं। जाति की कुछ विशेषताएँ ये हैं —

(१) हर जाति का एक नाम है जिससे उसके सदस्य पुकारे जाते हैं।

(२) पुराने जमाने में सब जातियों की पचायतें होती थी, जो अपने सदस्यों पर अर्धसर्वोच्च सत्ता (semi-sovereign authority) का प्रयोग करती थीं। पचायत का मुख्य काम फैसले करना होता था।

(३) जाति प्रथा की एक खास विशेषता यह थी कि एक जाति के सदस्य कुछ जातियों के लोगों के हाथ का भोजन नहीं करते थे। नये जमाने के साथ यह बान तेजी से खत्म होनी आ रही है।

(४) एक और महत्वपूर्ण रोक, जो अब भी बहुत कुछ अथल में आती है, अपनी जाति से बाहर घादी करने के बारे में थी।

(५) जाति की सदस्यता जन्म से होती थी। व्यक्ति के गुणों या उसमें कोई हज़ल न था।

(६) ऊँची जातियों के लोगों की नीची जातियों के लोगों के मुकाबले में समाज में कुछ विशेष मुविषाएँ हासिल थी। नीची जाति वाले लोगों को गिरा, पूजा और सेवा बदलने के मामलों में बड़ी रखावटें थी।

जाति प्रथा का उद्गम और वृद्धि—भारत में जाति का सबसे पुराना उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। आयौने जाति प्रथा प्रथम तो द्रविड़ों में, जिनका रंग काला था, अपने रक्त की मुड़ना बनाए रखने के लिए, और दूगरे, मूड में कुस्मनों के मुकाबिले में अपनी दवाया बदलने के लिये शुरू की थी। चार जातियों में धर्म के

विभाजन या वामो के बटवारे से उनके लिए लड़ते रहना और साथ ही साथ अपनी दूसरी जरूरतें पूरी करने रहना सम्भव हो गया। दुष्ट के जमाने में जाति प्रथा कठोर नहीं थी। पैसा बदला जा सकता था। दूसरी जाति में भोजन और विवाह करने की पाबन्दी भी इतनी सख्त नहीं थी। धीरे धीरे जाति प्रथा कठोर हो गयी और आदमी जन्म से ही किसी जाति का सदस्य होने लगा। निम्नलिखित कारणों के प्रभाव से जातियों की सख्या भी बढ़ने लगी —

(१) काम-धर्मों की वृद्धि—जोषा के जातिज जीवन में तरक्की के साथ काम-धर्मों की सख्या बढ़ गई। अलग-अलग पेयों और धर्म करने वाला लोग ने अपनी अलग जातियाँ बना ली, यद्यपि शुरू में वे किसी एक ही जाति के रहे होंगे।

(२) पूजा की रीति—अलग-अलग देवताओं की पूजा से भी जातियों में भेद पैदा हो गया।

(३) निवास और भाषा—एक ही जाति के लोग देश के अलग-अलग भाषा और संस्कृति वाले अलग-अलग भागों में निवास करने लगे। इस कारण भी अलग जातियाँ बन गईं।

(४) विदेशी आक्रमण का प्रभाव—विदेशी आक्रमणों के प्रभाव से भी जातियों की सख्या बढ़ गई। ग्रीक, हूण, मुगल आदि दुष्ट के आग्राता हिंदू जाति में विलीन हो गए। पर उन्होंने अपनी अलग जातियाँ बना लीं विदेशी आक्रमणों ने भी जाति प्रथा का कठोर बना दिया।

जाति प्रथा के लाभ—किसी समय जाति ने बड़ा उपयोगी काम किया

(१) जाति प्रथा के कारण आर्य लोग अपनी रक्त की शुद्धता कायम रख गये।

(२) जाति प्रथा द्वारा जन्म के विभाजन ने उनकी द्रविडों से लड़ने की शक्ति बढ़ा दी।

(३) पैसा बदलने के बारे में पाबन्दी लगा दी गई। जाति प्रथा ने विभिन्न वस्तुधारियों में वैशाल और शान की विशेष योग्यता पैदा की। धर्म का क्रोशाल पिता से पुत्र को प्राप्त हो जाता था।

(४) सदस्यों की बन्धुता और सहयोग की भावना बढिमाई के समय काम आती थी।

(५) जाति प्रथा की कठोरता ने हिन्दू समाज को विनाश से बचाया है। इस प्रथा ने विदेशियों को इसमें विलीन होने में सहायता दी। जो आग्राता, जैसे मुसलमान, हिन्दू समाज में विलीन नहीं हो सके, वे जाति से बाहर खाने और जाति से बाहर सादी करने के बारे में कठोरता के कारण, जो जाति प्रथा की विशेषता थी, हिन्दू धर्म को नष्ट नहीं कर सके।

जाति प्रथा की हानियाँ—(१) जाति प्रथा जन्म को अनावश्यक महत्व देती है और योग्यता की नीसत कम रक्खती है।

(२) इसने तरक्की की रोका, क्योंकि किसी को अपना पेशा या धुआ बढ़ने की इजाजत नहीं थी। विशेष रूप से नीची जातियों को बड़ी विधेयता (disabilities) मोकती पटती थी और उन्हें तरक्की करने का मौका नहीं था।

(३) मना का काम सिर्फ़ क्षत्रियों के जिम्मे था। इसलिए अन्य वर्ण दुस्मन से मुनाजत करने से उदासीन हो गये और उन्होंने देश की मुनाजत के समय भी हाथ पाश हिलाने की जरूरत नहीं समझी। इस प्रकार वर्ण-व्यवस्था ने विदेशियों के मुनाजत के समय देश को कमजोर रखा।

(४) जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था ने समाज को विलुप्त अलग विभागों में बांट दिया है, और यह देश की कुट ना बहुत बड़ा कारण है। इसने राष्ट्रीयता और देश प्रेम को बढ़ने से रोका।

जातिप्रथा या वर्ण व्यवस्था का भविष्य—यद्यपि वर्ण व्यवस्था अब भी हमारे समाज की बहुत बड़ी विशेषता है, तो भी समय गुजरने के साथ इसकी पुरानी शक्ति बहुत कुछ नष्ट हो गई है। मौजूदा जमाने में इसकी ज़रूरत तेज़ी से खत्म होनी जा रही है। शिक्षा के प्रसार और विज्ञान ने हमें इसमें बड़ा काम किया है। वर्ण की उपयोगिता खत्म हो चुकी है। और अगर हमें एक शक्तिशाली संगठन और लोकनगरीय राष्ट्र बनाना है तो इसे छोड़ना ही होगा। माथी की के छुआछूत विरोधी आन्दोलन ने वर्ण की व्यवस्था खिल करने में बड़ा काम किया है। जब तक हमारा समाज लोकनगरीय न हो, तब तक सब लोग बराबरी के आधार पर खड़े हों, सब एक लोकनगरीय सामन भी नहीं हो सकता। भारतीय गणराज्य के संविधान ने छुआछूत को खत्म कर दिया है।

धर्म

धर्म किसे कहते हैं—मनुष्य स्वभाव से कमजोर और दरपोर है। वह अपूर्ण है और कई कामों में असमर्थ है। बड़बड़ाने वाले पर वह मदद के लिए किसी अधिक बलवान ताकत की ओर देखता है। आदिकारिक जमाने में लोग अपने मृत पूर्वजों की ताकत के लिये बुझने से, और उन्हें खुद करने के लिये भेंट चढ़ावा करने से। इनके बाद के प्रकृति के बलों की पूजा करने लगे। हर प्राकृतिक प्रतीति का, उदाहरण के लिये, आकाश, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और वर्षा को, एक देवता माना जाता था। बाद में इन्होंने एक सर्वोच्च सत्ता, अर्थात् ईश्वर का विश्वास विकसित किया और सब प्राकृतिक प्रतीति का उम ईश्वर की शक्ति का ही माना जाने लगा। इस प्रकार, धर्म की यह परिभाषा की जा सकती है कि आदमी का अविमानवीय शक्ति में विश्वास धर्म है जो मनुष्य के माथु को अच्छा या बुरा बनाने में सक्षम है। "धर्म मनुष्य की उस व्यक्ति से की गई अवगत है जिसके बारे में यह माना जाता है कि वह वे काम कर सकता है जो आदमी खुद नहीं कर सकता।" धार्मिक व्यवहार आदि उन दूसरे व्यवहारों की तरह ही हैं जिनमें वह अपने से ऊंची किसी सत्ता से कृपा की मांग करता है। किसी की कृपा मांगने हुए आदमी उसकी प्रशंसा करता है। धर्म में प्रार्थना यही प्रयोजन पूरा करती है।

धर्म की आवश्यकता—बुद्धि की दृष्टि में आदमी आसानी से कह सकता है कि ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तविक युग तर्क का युग है और इसी कारण आज का आदमी अधिक धर्महीन है, पर धर्म विज्ञान की वस्तु है, तर्क की नहीं। यह हृदय को छूता है। मनुष्य का मस्तिष्क अपने बौद्धिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण सठोर हो सकता है, पर ऐसा बहुत कम मिलेगा कि किसी का दिल इतना कठोर हो कि उसे धर्म की आवश्यकता न रहे। आदमी अपने रोजाना के जीवन में, जब वह किसी मुसीबत में नहीं है, धर्महीन हो सकता है, पर कठिनाई के समय प्रायः हर आदमी किसी अनिमानवीय शक्ति का सहारा चाहता है। इन्सान जमी धर्म की आवश्यकता की मजिल में जाने नहीं पहुँचा। हो सकता है कि जब मनुष्य विज्ञान की सहायता से प्रकृति को पूरी तरह जीत ले तब धर्म की आवश्यकता न रहे।

धर्म और सम्प्रदाय—धर्म आदमी का विस्तृत वैयक्तिक और निजी मामला है। ठीक ठीक कहे तो यह मन्त्र और उसके आराध्यदेव या ईश्वर के बीच वैयक्तिक सम्बन्ध को सूचित करता है। इस सम्बन्ध को प्रकट करने के लिये किसी बाहरी चिन्ह की जरूरत नहीं। इस अर्थ में एक आदमी का धर्म दूसरे की प्रभावित नहीं करता और न इसे दूसरे को प्रभावित करना चाहिए। यह आपसी ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा नहीं पैदा कर सकता। धर्म के कारण जो अनेक ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धाएँ हैं, वे असल में अनेक सम्प्रदायों के कारण हैं। सम्प्रदाय उन व्यक्तियों के सामाजिक संगठन को कहते हैं जिनका विज्ञान, पूजा की रीति, धार्मिक कृत्य और ममारोह एक-से हो और यह उस विज्ञान की रक्षा, वृद्धि और प्रचार के लिये बनाया जाता है। सम्प्रदाय के कुछ मुनिर्दिष्ट मिद्धान्त और नियम होते हैं इसका एक संगठन, पुरोहित मंडल, पूजा और सम्मेलन की जगह तथा कोई प्रार्थना-मुस्तक होती है। मन्त्र धर्म को इनमें से किसी चीज की भी आवश्यकता नहीं है। वह तो हमारे अन्तःकरण का विषय है और अगर हमारा हृदय और आत्मा ईश्वर के साथ पूर्ण एकात्मता रखते हैं तो उसे किसी बाहरी चिन्ह या दिशाओं की जरूरत नहीं। जब लोग अपने आपकी सम्प्रदायों में संगठित कर लेते हैं और एक विज्ञान की दूसरे विज्ञान से धोखेना मिद करने लगते हैं, तब समाज में गड़बड़ी पैदा होती है।

धर्म और सामाजिक प्रथाएँ—जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, धर्म भवन और उसके आराध्यदेव के बीच निजी मामला है। इसका प्रयाजो से कोई सम्बन्ध नहीं। प्रथाएँ वे पुराने आचार हैं जिन्हें किसी जनसमूह ने उनकी उपयोगिता के कारण अपना लिया था, और अब वे या तो आशुन के कारण या भय के कारण चली आती हैं। धर्म व्यवस्था, विवाह, पर्दा और दहेज, ये सब सामाजिक प्रथाओं के उदाहरण हैं। धर्म का उनमें कोई वास्ता नहीं। अधिक से अधिक यह हो सकता है कि सम्प्रदाय इन्हें लोगों पर लागू कर दें।

धर्म और नैतिकता—नैतिकता मनुष्य के अनुभव और उसके अच्छे और बुरे परिणाम से पैदा होती है। अगर आदमी ईमानदार और सच्चा है तो इसका कारण

यह है कि वह देखता है कि बेईमानी और झूठ से वह मुनीषत में फँस जाएगा। इस प्रकार ठीक-ठीक बड़े तो नैतिकता और धर्म का दूसरे से स्वतन्त्र है। पर धर्म ने नैतिकता को फैलाने में बड़ा काम किया है। जब यह बड़ा जाना है कि अनैतिक काम करने से ईश्वर नाराज होगा तो बादभी उन्हें करते हुए रहता है।

धर्म के अच्छे परिणाम—(१) धर्म हमारी इन्द्रियों को अनुशासित करता है। यह हमें अपनी इच्छाओं, भावनाओं, भावों और बसनाओं का नियन्त्रण करना सिखाता है। यह हमें लोभ, कामुकता, अहंकार और नफरत से बचाता है। यह नैतिक शक्ति देता है, और बड़बोझों का मुकाबला करने का साहस पैदा करता है। धर्म आदमों की आन्तरिक जाति के लिए, जहाँ मन और आत्मा की समुचित के लिये, आवश्यक है।

(२) धर्म हमें ईश्वर के रूप में एक पूर्ण सत्ता का विचार देता है और हमें उस पूर्णता का रास्ता दिखाता है। यह हमें बताता है कि ईश्वर मनुष्य के भीतर है। आदमों को सिर्फ यह करना है कि वह ईश्वर को पहचाने और उसका साक्षात्कार करे।

(३) जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, धर्म आदमों को आत्म-नियन्त्रण, मान-वीर्यता, प्रेम, दया, मर्यादा और सहनशीलता आदि कई नैतिक गुण पैदा करने में सहायता देता है। यह जीवन के सम्मान की निगाह देता है और ईश्वर की मजरो में सब आदमियों की समानता का उपदेश करता है। इसके द्वारा मनुष्य के पार्श्विक गुण, अर्थात् अभिमान, अहंकार, लोभ, स्वार्थ और प्रीति नियन्त्रण में रखे जा सकते हैं।

(४) मनुष्य धर्म मनुष्यों में प्रतिष्ठाओं, पूजा और युद्ध के स्थान पर शांति, सामंजस्य और सहभावना पैदा करता है। पुराने सम्राटों में धर्म लोगों को बानून पालक बनाने में बड़ा सहायक होता था। मयाइसिम धर्मयुद्ध बसल में सम्प्रदायों के मध्य हुए युद्ध हैं। धर्म अपने आप में सभी लोगों को लड़ने के लिए प्रेरणा नहीं देता।

धर्म के विरुद्ध कुछ बातें—(१) धर्म समाज में परिवर्तन-विरोधी बल के रूप में काम करता रहा है। यह दुनिमाही बन्धुओं के प्रति उदासीनता का उपदेश करता है। इन तरह हमने समाज की भौतिक उत्पत्ति को रोका है। दूसरी बात यह कि धर्म के अधिष्ठाताओं ने प्रायः समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्रों में परिवर्तन करने के महान् आन्दोलनों की वृत्ति की है। सच तो यह है कि धार्मिक संगठन समाज के सभी वर्गों के सदा सहयोगी रहे हैं, जो इन परिवर्तनों के विरोधी होते हैं। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रति धार्मिक संगठनों का दृष्ट न केवल उदासीनता का, बल्कि बाकायदा उत्पीड़न का रहा है।

(२) जहाँ तक धर्म ग्रन्थ से पैदा होता है, वहाँ तक यह मनुष्य की गरिमा को कम करता है।

(३) धर्म भौतिकवाद के परमोच्च जीवन को महत्व देता है और इस लोक में जीवन के दुःखों और कष्टों को शीघ्र बहाता है। ईसाई धर्म के अनुसार मरीची और रोग सिर्फ इस लोक के जीवन में हैं। जीवन का ऐसा अवधारण उत्पत्ति को रोकता है।

(४) धर्म ग्रन्थ लोगों का आत्मविश्वास नष्ट कर देता है। वे अपनी कठिनाइयों और मुसीबतों को जीतने के लिये कुछ यत्न नहीं करते। वे भाग्यवादी हो जाते हैं और अपने दुखों का कारण भाग्य को बताते हैं जो उनके काबू से बाहर है। वे अपनी मुसीबतों दूर करने के लिये ईश्वर का सहारा देखते हैं और पूरी तरह उस पर ही निर्भर होते हैं।

(५) यह भी कहा जाता है कि धर्म बौद्धिक योग्यता को हीन मानता है, क्योंकि इसे थोड़ा लोगों को जरूरत है, तर्कशील लोगों को नहीं।

भारत

सम्पत्ति—सम्पत्ति शब्द में वे सब भौतिक और अभौतिक वस्तुएं शामिल हैं जिन पर मनुष्य का स्वामित्व होता है। सम्पत्ति मनुष्य और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह आदमी के व्यक्तिगत व पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। इसी के कारण लोगों में शांति और राष्ट्रीय युद्ध होने हैं। यह आदमी की योग्यता और समाज की प्रगति आपने की गयी है।

सम्पत्ति का उद्गम चाहे जो रहा हो, पर आज इसका आधार सृष्टि और कानून की मजबूती है।

सम्पत्ति का अधिकार कोई निष्पक्ष (absolute) अधिकार नहीं है। सारे समाज की भलाई को देखते हुए सम्पत्ति के अधिकार का सीमित किया जा सकता है और किया जाता है।

सम्पत्ति के सार्वजनिक या राज्य द्वारा स्वामित्व को राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। सम्पत्ति का सीमाहीन मध्यम मध्य के विरुद्ध भी माना जाता है और लोकतन्त्र के विरुद्ध भी। राष्ट्रीयकरण सम्पत्ति का समान और उचित वितरण कर देता है।

निजी सम्पत्ति के पक्ष में युक्तियाँ—(१) अवाप्ति की महज वृत्ति (instinct of acquisition) पर आधारित होने से यह प्राकृतिक है। (२) यह काम करने के लिए प्रेरणा देती है। (३) इसके द्वारा आदमी अपने भविष्य की रक्षा कर लेता है। (४) यह अपने स्वामी को स्वतन्त्रता की भावना देती है। (५) इसने विज्ञान, कला और साहित्य की उन्नति में भी सहायता दी।

निजी सम्पत्ति के विरुद्ध युक्तियाँ—(१) यह आदमी को लोभी और स्वार्थी बनाती है। (२) यह असमानताएं पैदा करती है। (३) यह निश्चय और फिजूल-खर्चों को बढ़ावा देती है। (४) यह अद्वेष को फलने-फूलने में सहायता देती है। (५) मनुष्य में सदा निजी आर्थिक लाभ की भावना ही नहीं रहती। (६) यह विज्ञान और कला की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं।

जाति या वर्ण (Caste)—जाति या वर्ण की परिभाषा करना कठिन है। सो भी, जाति-प्रथा या वर्ण-व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं ये हैं —

(१) प्रत्येक जाति का कोई नाम होता है।

(२) पहले सब जातियों की वधाएँ होती थी।

(३) ज्ञानि प्रथा का ध्वनितार्थ यह है कि यह दो जातियों में परम्पर चोवन और विराट पर पावन्दी लगायी है ।

(४) ज्ञानि को सदस्यता जन्म में होती है ।

भाग्य में रक्त को मुदता और शर्म के विभाजन के विचारों ने वैदिक काल में ज्ञानि प्रथा को जन्म और बढ़ावा दिया । इसके बढ़ने में धर्मों की बुद्धि, पूजा की रीतियों, रहन-सहन की व्यवस्थाओं और विदेशी आक्रमणों में भी भेद मिली ।

इसकी अच्छाईयाँ—(१) ज्ञानि जमाने में ज्ञानि या वर्ग बड़ा उपयोगी था :

(१) इसने आर्यों की रक्त की शुद्धता बनाये रखी । (२) शर्म के विभाजन में उनकी दक्षता बढ़ा दी । (३) इससे काम-धर्म, सम्बन्धों और व्यापार में सुगुलदा पैदा हुई । (४) हिन्दू धर्म को नष्ट शक्तों से बचाया ।

बुराईयाँ—(१) इसने योद्धा को गीर्ज कर दिया । (२) इसने समाज की प्रगति को रोक दिया । (३) इसके कारण गण्टवाद और देश-धर्म की मूर्खता न हो सकी । (४) इसने विदेशियों के मुचावले में हमारी प्रतिरक्षा को कमजोर कर दिया । (५) इसने बड़ी सामाजिक असमानताएँ पैदा कर दी ।

धर्म—मनुष्य स्वभाव से कमजोर और दरशक है । आविवाचन में वह अनेक प्रतीतिओं और बलों की पूजा करता जाँदा है, जिन्हें वह अपने में अक्षिप्त प्रकृत मानता रहा । इमराल्द “धर्म जैसे व्यक्ति से मनुष्य को प्रार्थना है जिससे धर्म में वह माना जाता है कि वह भी काम कर सकता है या मनुष्य खुद नहीं कर सकता ।” वह प्रार्थना द्वारा इन बलों से महापता मागता है ।

किन्ती आदमी का मन इतना मग्न हो सकता है कि उसे धर्म की ज़रूरत अनुभव न हो । पर ऐसा बहुत कम होता है कि उसका दिल भी इतना ही मजबूत हो । सुधीयों के समय प्रायः हर कोई अति मानवीय शक्ति को महापता के लिए पुकारता है ।

धर्म आदमी का वैयक्तिक और निजी मामला है । यह भक्त और उसके आगम्य-देव या ईश्वर के मध्य वैयक्तिक सम्बन्ध को सूचित करता है । धर्म के लिए किसी बाहरी चिन्त की आवश्यकता नहीं । धर्म के नाम पर जो ईश्वरों और विरोध बोध जाता है वह अन्त में धार्मिक समझों द्वारा पैदा किया जाता है ।

धर्म के अच्छे प्रभाव—(१) यह हमारी दृष्टियों को अनुशासित करता है । (२) यह धार्मिक शांति के लिए जरूरी है । (३) यह हमें सिखाता है कि ईश्वर मनुष्य में है, और कि मनुष्य भी पूर्णता प्राप्त कर सकता है । (४) यह मनुष्य में नैतिक गुण पैदा करके उसके नैतिक बचन प्रयोग में लाता है । (५) यह सामाजिक सम्बन्धों में शांति लाता है ।

धर्म के दुष्परिणाम—(१) इसने समाज की भौतिक दृष्टि में हजावट डाली है । (२) यह हम जीवन के दुश्मनों को कम करके दिनाता है और मनुष्य को भाग्यवादी बना देता है । (३) यह तर्क को बचाकर सदा को बढ़ावा देता है ।

प्रश्न

QUESTION

१ 'सम्पत्ति' शब्द से आप क्या समझते हैं ? इसका किसी नागरिक के जीवन में क्या स्थान है ?

1 What do you understand by the term Property ? What part does it play in the life of a citizen ?

२ निजी सम्पत्ति के पक्ष और विपक्ष में युक्तिर्था दीजिये ।

(१० वि० अप्रैल १९५२)

2 Make out a case for and against private property

(P U April 1952)

३ सम्पत्ति क्या तक निजी रहने दी जानी चाहिए और क्या तक इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिये ? दोनों बातों का उत्तर युक्तिर्था सहित दीजिये ।

3 To what extent property may be allowed to be private and to what extent should it be nationalised ? Support your answer with arguments in both the cases

४ धर्म किसे कहते हैं ? किसी नागरिक के जीवन में इसका क्या महत्व है ?

4 What is 'Religion' ? What is its importance in the life of a citizen ?

५ नागरिक जीवन पर धर्म के अच्छे और बुरे प्रभावों का उल्लेख कीजिए ।

5 Estimate the good and bad effects of religion on civic life

६ वंश या जाति किसे कहते हैं ? वंश या जाति अच्छे नागरिक जीवन में कैसे बाधा डालती है ?

6 What is 'caste' ? How is caste a hinderance to good civic life ?

७ वंश या जाति किसे कहते हैं ? इसके कुछ और दोष बताइये ।

7 What is caste ? What are its merits and demerits ?

अध्याय : : =

राज्य और इसके घटक तत्त्व

राज्य शब्द का गलत प्रयोग—आदर्श बोझान्त में राज्य शब्द का प्रयोग गलत प्रयोग किता जाता है। इसका राष्ट्र, समाज, सरकार और देश जैसे शब्दों के स्थान में प्रयोग करना और सम में डालने वाला है। उदाहरण के लिये, जब हम अनाज पर राज्य के नियंत्रण या सिकके डालने पर राज्य के गुणाधिकार की बात कहते हैं, तब असल में हमारा मतलब सरकार के नियंत्रण और सरकार के एकाधिकार से होता है। किसी समाज या देशवासियों के लिए राज्य शब्द का प्रयोग भी गलत है। वेन्स और अनाज भारतीय मय की इकाइया हैं। इस शब्द के अर्थ को दृष्टि से वे राज्य नहीं हैं, क्योंकि उनमें राज्य के एक परमावस्था गुण, अर्थात् सर्वोच्चता, का अभाव है।

नागरिक शास्त्र में राज्य शब्द का एक मुनिग्विच अर्थ है। यह राजनीतिक रूप से सङ्गठित और स्वतन्त्र किसी प्रादेशिक समाज के लिये प्रयुक्त होता है। राज्य आज एक समाज के विकास की सबसे ऊँची सीढ़ी को निरूपित करता है। राज्य एक सामान्य उद्देश्य की गिरि के लिए सङ्गठित मनुष्यों का साहचर्य भी है। पर यह एक क्षीय साहचर्य है। यह सब साहचर्यों से अधिक महत्वपूर्ण भी है।

नागरिक शास्त्र के विचारों के रूप में हमें राज्य का गहराई से अध्ययन करना होगा क्योंकि नागरिक और उसके अधिकारों और कर्तव्यों के अध्ययन में हमारी गहरी दिलचस्पी है। यदि राज्य न हो तो कोई नागरिक भी न होगा और उसके कोई अधिकार और कर्तव्य भी नहीं हो सकेंगे।

राज्य की परिभाषा—आज तक समझ-बुझ पर राज्य की असल परिभाषाएं की गई हैं। अरस्तू ने राज्य की यह परिभाषा की थी कि राज्य 'उन परिवारों और गांवों का साहचर्य है जिनका उद्देश्य धर्म और सामंतिभर जीवन है।' सोन्टकी राजाजी ने बोझान्त में राज्य की यह परिभाषा की कि 'यह परिवारों और उनकी सामी मध्यस्थियों का ऐसा साहचर्य है जो सर्वोच्च शक्ति और तर्क से सङ्गठित होता है।' पर ये परिभाषाएँ अब विलुप्त पुरानी हो गई हैं। वे परिवार को राज्य की इकाई मानकर बतली है, ध्यष्टि की नहीं।

आज के जमाने में हास्पेड ने राज्य की यह परिभाषा की कि 'मनुष्यों का बहुत सा समुदाय जो साधारणतया किसी प्रदेश पर रहता है और जिसमें बहुमत की या किसी निश्चित वर्ग की दण्ड, ऐसे बहुमत या वर्ग की शक्ति से, उनके मुखबतों से, जो इनका विरोध करते हैं, प्रभावी बनाई जाती है।' राज्य की सबसे अच्छी और सबसे स्पष्ट परि-

भाषा गार्नर ने दी है। उसके अनुसार राज्य "उन व्यक्तियों का एक समुदाय है, जिनकी सख्या वहीं कम कहीं अधिक होती है, और जो किसी निश्चित राज्य क्षेत्र पर स्थायी रूप से रहते हैं—यह समुदाय बाह्य नियंत्रण से स्वतन्त्र या लगभग स्वतन्त्र होता है, और इसमें एक संगठित सरकार होती है जिसकी आज्ञाओं का अधिकतर नागरिक आदतन पालन करते हैं।" बुढ़गे विलमन की परिभाषा छोटी और तथ्यमूलक है। यह कहना है, "राज्य यह जनसमुदाय है जो किसी मुनिश्चित राज्यक्षेत्र में कानून के लिये संगठित है।"

राज्य के घटक तत्त्व—गार्नर की उपर्युक्त परिभाषा में यह स्पष्ट होगा कि राज्य के गठन में चार परमावश्यक तत्त्व होते हैं। वे हैं—(१) आबादी, (२) क्षेत्र, (३) सर्वोच्चता, और (४) सरकार। ये चारो तत्त्व मिलकर राज्य बनाते हैं। राज्य का अर्थ न तो जन-समुदाय है और न वह राज्यक्षेत्र है, जिस पर वह रहता है, और न वह सरकार है जिसके द्वारा राज्य अपना कार्य करता है।

अब हम राज्य के विभिन्न तत्त्वों के महत्व पर एक एक करके विचार करेंगे।

आबादी—आबादी राज्य का पहला परमावश्यक तत्त्व है। बिना लोगों के राज्य नहीं हो सकता। राज्य का जन्म तब ही होता है जब मनुष्य जाति का एक भाग राजनैतिक दृष्टि से संगठित हो जाता है। पर राज्य के मदस्यों की कोई अधिकतम या न्यूनतम सख्या निश्चित नहीं है। सिर्फ इतनी बात है कि उनकी सख्या बहुत होनी चाहिए और दस-बीस आदमी, चाहे वे स्वतन्त्र और संगठित भी हों, राज्य का निर्माण नहीं करते। गार्नर के अनुसार आबादी सख्या में इतनी कमी होनी चाहिए कि वह राज्य के संगठन को बनाए रख सके। वह राज्य के क्षेत्रफल और साधनों के अनुपात में बहुत अधिक भी न होनी चाहिए। जब किसी राज्य की आबादी उसके साधनों की तुलना में बहुत अधिक होती है, तब इसका मतलब होता है कि गरीब राज्य की गरीब आबादी।

राज्य क्षेत्र—जन समुदाय के पास राज्य बनने में पहले एक मुनिश्चित राज्य-क्षेत्र होना चाहिए। कोई घूमने फिरने वाला कबोला राज्य का निर्माण नहीं करता, यद्यपि सब सबसे उसने एक सरकार के अधीन संगठित होते हैं। मुनिश्चित राज्य-क्षेत्र का होना राज्य की मनुष्या के और सब माहुरों से मिल करता है।

पर राज्य-क्षेत्र की कोई निश्चित सीमा नहीं है। प्राचीन ग्रीस में एक नगर ही राज्य हुआ करता था। आजकल बहुत बड़े-बड़े राज्य भी हैं, जैसे रूस, चीन और भारत, तथा बहुत छोटे-छोटे राज्य भी हैं जैसे लक्जमबर्ग और वल्बानिया। इसके अलावा, किसी राज्य का क्षेत्र सारा दगढ़ या बड़ा हुआ और भौगोलिक दृष्टि से अलग-अलग भी हो सकता है। पान्तिगा का राज्य क्षेत्र इन्ट्रॉ नहीं है।

सरकार—आवश्यक नहीं कि किसी मुनिश्चित क्षेत्र में रहने वाले जनसमुदाय राज्य का निर्माण करता ही हो। उसे राजनैतिक रूप से संगठित और सामूहिक कार्यवाही करने में समर्थ होना चाहिए। गार्नर के अनुसार "सरकार वह अभिकरण या तंत्र है जिसके जरिये सार्वभौमिक नीतियाँ तय की जाती हैं और जो सारे मामलों को नियमित करता

अभिव्यक्ति और माह्वयों पर एक समान लागू होती है। इस नियम का एकमात्र अपवाद अन्य राज्यों के राजनयिक प्रतिनिधि हैं। यह अपवाद मिफे गौजन्य (courtesy) है और सर्वोच्च प्रभु द्वारा वापिस लिया जा सकता है।

सर्वोच्चता अविभाज्य होती है—सर्वोच्चता विभाजित नहीं की जा सकती। जैसे यह कहना निरर्थक है कि आपा करें, उगो तरह आपो सर्वोच्चता भी कोई चीज नहीं हो सकती। सर्वोच्चता असड होती है। यदि सर्वोच्चता को विभाजित कर दिया जाए तो राज्य के जितने विभाग होंगे, उसमें उतने ही सर्वोच्च प्रभु या राज्य पैदा हो जाएंगे। उदाहरण के लिये, जब भारत की सर्वोच्चता विभाजित की गई तब भारत और पाकिस्तान में दो सर्वोच्च राज्य पैदा हो गए। निस्मदेह सर्वोच्चता की तकियों का प्रयोग एक से अधिक अंग द्वारा किया जा सकता है। किसी मघान या कंडरेमान में सर्वोच्चता संविधान में रहती है पर इसका प्रयोग कुछ अंगों में केन्द्रीय सरकार के अधि और कुछ अंगों में मघान करने वाले इकाइयों के अधि होना है।

सर्वोच्चता अमर्याद (inalienable) होती है—सर्वोच्चता राज्य का जीवन है। जैसे कोई आदमी अपना जीवन किसी दूसरे का नहीं दे सकता उसी प्रकार कोई राज्य अपनी सर्वोच्चता अत्यापों या स्थायी रूप से किसी दूसरे को नहीं दे सकता। राज्य सरकार को राज्य में प्रत्याबोधित शक्ति (delegated authority) प्राप्त होता है, पर राज्य का सर्वोच्च अधिकार हट नहीं जाता।

सर्वोच्चता स्थायी होती है—हम देन शुरू हैं कि राज्य और सर्वोच्चता को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। राज्य की तरह सर्वोच्चता भी स्थायी है। सर्वोच्चता तब तक बनी रहती है, जब तक राज्य मौजूद है। सरकार में होने वाले परिवर्तनों से सर्वोच्चता पर बने ही कोई अमर नहीं पड़ता, जैसे राज्य पर।

सर्वोच्चता के प्रकार—सर्वोच्चता के प्रकारों की बात करना अवैज्ञानिक है। सर्वोच्चता जमुर (abstract) होती है। यह राज्य के सर्वोच्च प्राधिकार की दिया गया नाम है जो सब अगह एक सा होता है। राज्य में यह किस जगह है, इस बारे में कठिनाई पैदा होती है। दर्शाए सर्वोच्चता के स्थान के बारे में कई विचार प्रचलित हैं।

तथ्य और विधि (De facto and De jure)—विधि सर्वोच्च प्रभु वह है जिने कानून की दृष्टि में लोगो में आज्ञा पालन कराने का हक है पर सभी बर्नी यह होता है कि लोग बिना अथ प्राधिकारी की आज्ञा मानने लगे हैं। दर्शाए तथ्य सर्वोच्च प्रभु वह है जो वास्तविक व्यवहार में बल द्वारा या सम्पत्ति द्वारा लोगो में आज्ञापालन करा ले। प्रायः विधित प्रभु तथ्य प्रभु भी होता है, यद्यपि उनका हमेशा ऐसा होना आवश्यक नहीं।

वैधिक सर्वोच्चता (Legal sovereignty)—कानून बनाना या विधिनिर्याय प्रभु का सबसे महत्वपूर्ण काम है। मैटेल के अनुसार 'विधित प्रभु वह प्राधिकारी है जो राज्य के सर्वोच्च समादना को विधि के रूप में अभिव्यक्त

(५) राज्य मुख्यतः लोगों के राज-नीतिक जीवन में सम्बन्ध रखता है।

समाज के लिये लोगों के सब कार्य, चाहे वे राजनैतिक हों, आर्थिक हों, सामाजिक हों, धार्मिक हों, या सांस्कृतिक हों, बराबर महत्व के हैं।

(६) राज्य मनुष्य के अस्तित्व के लिये सर्वथा अनिवार्य नहीं है।

पर समाज के बिना मनुष्य का जीना नठिन हो जाएगा।

राज्य और साहचर्य—राज्य भी एक साहचर्य है। हर एक साहचर्य की तरह राज्य का भी एक संगठन, एक कक्ष या प्रयोजन होता है। अपने आकार, सदस्य सत्त्वा और कार्यक्षेत्र की दृष्टि से राज्य सबसे बड़ा और अधिक सर्वांगीण साहचर्य है। यह सबसे अधिक दक्षिणशाली साहचर्य भी है। राज्य अपने क्षेत्र में अन्य सब साहचर्यों के कार्यों को अपनी हिदायत के अनुसार चलाता है और उन पर नियंत्रण रखता है। इसी कारण राज्य को साहचर्यों का साहचर्य कहते हैं। राज्य और साहचर्य में एक-दूसरे के माली मुख्य बातें ये हैं—

राज्य

साहचर्य

(१) क्षेत्र राज्य का आवश्यक गुण है।

साहचर्य के लिये क्षेत्र आवश्यक नहीं। क्षेत्र से युक्त साहचर्य सिर्फ राज्य है और किसी साहचर्य के पास क्षेत्र नहीं होता। अवलम्बित यह है कि किसी साहचर्य के सदस्य दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में रहते हो सकते हैं।

(२) एक आदमी एक समय में एक ही राज्य का सदस्य हो सकता है।

एक आदमी एक ही समय में अपनी उन आवश्यकताओं के अनुसार, जिन्हें वह पूरा करना चाहता है, चाहे जितने साहचर्यों का सदस्य हो सकता है। साहचर्यों की सदस्यता स्वेच्छया होती है। आदमी जब चाहे तब साहचर्य का सदस्य बन सकता है और जब चाहे तब अपनी सदस्यता छोड़ सकता है।

(३) राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है। मनुष्य अपने जन्म से राज्य का सदस्य होता है, अपने मृत्यु से नहीं। उसे इसके अधिकारियों का आदेश मानना पड़ता है, और वह जब चाहे तब इसकी सदस्यता से पुष्पक नहीं हो सकता।

(४) राज्य सर्वोच्च है। इसके आदेशों का पालन करना होगा अन्यथा दण्ड मिलेगा। राज्य किसी व्यक्ति का जीवन भी ले सकता है।

साहचर्यों को कोई सर्वोच्च प्राप्ति-कार नहीं होता। वे अपने आदेशों मानने वाले सदस्यों की धारीरिक दण्ड नहीं दे सकते। वे, अधिक में अधिक, किसी सदस्य को अपनी सदस्यता से अलग कर सकते हैं।

(५) राज्य का क्षेत्र बड़ा विस्तृत और

हर एक साहचर्य का एक सास

स्थापक है और इसके भीतर इसके राज्य-क्षेत्र में विद्यमान अनेक साहचर्यों के लक्ष्य शामिल है।

(६) राज्य स्थायी साहचर्य है।

(९) राज्य परिवार की तरह एक नैसर्गिक साहचर्य है।

राज्य और सरकार—राज्य और सरकार को प्रायः एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। वास्तव में वे एक दूसरे में बहुत भिन्न अवधारण हैं। इन दोनों में फर्क यह है कि राज्य के नागरिक शासन की कुछ बहुत महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में बड़ा प्रभाव डाल देने की सम्भावना है। सरकार राज्य के चार घटक तत्वों में से सिर्फ एक है। जैसे किसी कम्पनी का मालिक मजदूर हो कम्पनी नहीं होता, वैसे ही सरकार राज्य नहीं हो सकती। यह तो राज्य की एक एजेंट मात्र है। इन दोनों में मुख्य भेद ये है —

राज्य

सरकार

(१) राज्य अमूर्त है। हम इसे देख या छू नहीं सकते। हम राज्य का सिर्फ एक विचार बना सकते हैं।

दूसरी ओर, सरकार एक मूर्त वस्तु है। हम राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, अन्य मंत्रियों, मजदूर और नई दिल्ली के मन्त्रि-वालय के रूप में भारत सरकार को देख सकते हैं।

(२) राज्य से सर्वोच्चता होती है और हमारा प्राधिकार इसका अपना है। वह और किसी से पैदा नहीं होता।

सरकार सर्वोच्च नहीं होती। इसका प्राधिकार अपना नहीं है। वह राज्य से पैदा होता है। राज्य जब चाहे तो सरकार के प्राधिकार को बढ़ा, घटा, या छीन सकता है।

(३) राज्य स्थायी होता है। सरकार का परिवर्तन होने पर भी रहना रहता है।

सरकारें अस्थायी और छोटे दिन की होती हैं। हम देखते हैं कि देश में आम चुनाव के बाद सरकार बदल जाती है। एक राजा की मृत्यु और दूसरे के गद्दी पर बैठने से सिर्फ सरकार में परिवर्तन होता है।

(४) राज्य के किसी निश्चित क्षेत्र के सब लोग इसके सदस्य होते हैं। हम सब भारत राज्य के सदस्य हैं।

सब लोग सरकार के सदस्य नहीं होते। बहुत थोड़े से लोग सरकार चला सकते हैं।

(५) हम अपने राज्य को कभी नष्ट नहीं करना चाहते। हम सब भारत राज्य के प्रति निष्ठा रमते हैं। पर हम एक सरकार की जगह दूसरी सरकार साने की बात गभीरता से सोचते हो मन्वे हैं। हमारा सबका सरकार के प्रति निष्ठावान होना आवश्यक नहीं।

राज्य, राष्ट्र और जाति (State, nation and people)—राज्य में राष्ट्र और जाति से भी अंतर करना चाहिए। राज्य एक राजनैतिक अवधारण है। इसलिए यह मनुष्य जाति के एक अथवा अधिक राजनैतिक एकता या समूह को ही मनुष्य सूचित करता है। दूसरी ओर जाति और राष्ट्र जैसे अवधारणा से जो एकता सूचित होती है, वह अति गहरी है। जाति अधिकतर एक मूलवर्गीय (racial or ethnic) अवधारणा है। राष्ट्र राज्य तथा राष्ट्रियता (nationality) का संयोग है। राष्ट्रियता मूलवर्गीय सम्बन्ध के अलावा और बहुत सारे सम्बन्ध सूचित करती है।

सारांश

"राज्य उन व्यक्तियों का एक समुदाय है जिनकी संख्या नहीं कम और नहीं अधिक होती है और जो किसी निश्चित राज्यक्षेत्र पर स्थायी रूप से रहते हैं—यह समुदाय बाह्य नियंत्रण से स्वतन्त्र या लगभग स्वतन्त्र होता है और इसमें एक संगठित सरकार होती है जिसकी आज्ञाओं का अधिकतर नागरिक पालन करते हैं"—गार्नेर। इस प्रकार राज्य के ये चार आवश्यक तत्व हैं (१) आबादी, (२) राज्य क्षेत्र, (३) सरकार (४) सर्वोच्चता या प्रभुसत्ता।

इस सब तत्वों में से सर्वोच्चता सब से अधिक आवश्यक और विभेदकारी तत्व है।

सर्वोच्चता या प्रभुसत्ता—आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्चता राज्य के सर्वोच्च प्राधिकार का नाम है जो उसे अपने क्षेत्र में रहने वाले सब व्यक्तियों और समुदायों पर प्राप्त होता है। बाहरी दृष्टि से सर्वोच्चता राज्य की किसी अन्य बाहरी शक्ति के नियंत्रण से स्वतन्त्रता को ध्वनित करती है।

सर्वोच्चता निश्चय (absolute) असीमित, सार्वभौम, अविभाज्य अमर्याद और स्थायी होती है।

सर्वोच्चता के प्रकार—सर्वोच्चता के प्रकारों की बात करना अतार्किक है। शास्त्र में के सर्वोच्चता के स्थान के बारे में दृष्टिकोण है।

- (१) संप्रत्य—जो संप्रत्य सर्वोच्च प्राधिकार रखता है।
- (२) विधित—जिसे विधि द्वारा सर्वोच्च शक्ति का अधिकार प्राप्त है।
- (३) विधित सर्वोच्चता—राज्य में विधि बनाने का प्राधिकार।
- (४) राजनैतिक सर्वोच्चता—इसमें उन विभिन्न प्रभावों का समावेश है जो विभिन्न प्रभु के पीछे काम करते हैं।

(५) जनता की सर्वोच्चता—सर्वोच्च प्राधिकार जनता को होता है।

राज्य और समाज—(१) राज्य क्षेत्र और सर्वोच्चता राज्य के होते हैं, समाज के नहीं। (२) राज्य का मध्यन होता है, और समाज में अवगतिन समूह भी समाविष्ट है। (३) राज्य दण्ड दे सकता है पर समाज ऐसा नहीं कर सकता। (४) राज्य की मर्यादा अनिवार्य होती है, समाज की नहीं। (५) राज्य मनुष्य के जीवन के लिए परमावश्यक नहीं, पर समाज के बिना मनुष्य का जीवन कठिन हो जाता है।

राज्य और साहचर्य—(१) क्षेत्र और सर्वोच्चता राज्य की विशेषताएँ हैं, साहचर्य की नहीं, (२) एक जादगी अनेक साहचर्यों का मध्य हो सकता है, पर अनेक राज्यों का नहीं हो सकता। (३) राज्य की मर्यादा अनिवार्य है, साहचर्य की नहीं। (४) राज्य का क्षेत्र साहचर्य के क्षेत्र की अपेक्षा बहुत विस्तृत है। राज्य के अन्दर हजारों साहचर्य समाविष्ट हैं। (५) राज्य स्थायी होता है और साहचर्य प्रायः अस्थायी होता है।

राज्य और सरकार—(१) राज्य अमूर्त होता है, सरकार मूर्त होती है। (२) राज्य सर्वोच्चता धारण करता है और उसकी सत्ता मौलिक होती है। सरकार सर्वोच्च नहीं होती और इसका प्राधिकार लिमिटा होता है। (३) राज्य स्थायी होता है, सरकारें बदलती रहती हैं। जब लोग राज्य से मर्यादा होते हैं, सरकार के नहीं। (४) हम सब राज्य के प्रति निष्ठा रखते हैं, सरकार के प्रति नहीं।

प्रश्न

QUESTIONS

१. राज्य की परिभाषा करो। इसके तीन-चौन से गुण हैं ?

(५० वि० अग्रेष, १९४८)

1. Define 'state' ? What are its attributes ? (P. U. April, 1948)

या

साक्ष्यानी से राज्य के सारकून गुणों का वर्णन करो।

(५० वि० अग्रेष, १९५०)

Describe carefully the essential attributes of the state.

(P. U. April, 1950)

२. राज्य का क्या अर्थ है ? राज्य और सरकार में अंतर करो ?

(५० वि० मिलावर, १९५०)

2. What is meant by the state ? Distinguish between state and government (P. U. April, 1950)

३. समाज, राज्य और सरकार में अंतर करो।

(५० वि० मिलावर, १९५१ व अग्रेष, १९५२)

3. Distinguish between society, state and government.

(P. U. Sep. 1951, and Apr., 1950)

- ४ राज्य और साहचर्य की परिभाषा करो । इन दोनों का अंतर बताओ ।
(प० वि० अप्रैल, १९५४)
- 4 Define the state and an association Distinguish between them
(P U April 1954)
- ५ 'सर्वोच्चता' शब्द से आप क्या समझते हैं । इसके आवश्यक लक्षण क्या हैं ?
(प० वि० अप्रैल, १९५३)
- 5 What do you understand by the term Sovereignty ? What are its essential characteristics ?
(P U April 1953)
६. सर्वोच्चता के कौन से अनेक प्रकार हैं ?
- 6 What are the various kinds of sovereignty ?

राज्य का उद्गम और प्रकृति (Origin and Nature of the State)

राज्य का उद्गम—राज्य समाज में से उत्पन्न और विकसित हुआ है। इसका उद्गम प्रागैतिहासिक काल में है। इसी कारण यह अनिश्चित है। इस बात का कोई प्रायोगिक प्रमाण नहीं मिलता कि राज्य कैसे और कब उत्पन्न हुआ। इसी कारण विद्वानों में राज्य के उद्गम के बारे में बड़ा मतभेद है। इस प्रश्न में हम पाँच महत्वपूर्ण सिद्धान्तों पर संक्षेप से विचार करेंगे।

- (१) दैवगम सिद्धान्त (Theory of Divine Origin)।
- (२) समाज सन्धिदा सिद्धान्त (Social Contract Theory)
- (३) बल सिद्धान्त (Force Theory)
- (४) वैयक्तिक और मानव सिद्धान्त
- (५) ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धान्त।

दैवगम सिद्धान्त—राज्य के उद्गम के बारे में सबसे पुराना विचार यह है कि यह ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर ने केवल राज्य का सूत्रन करता है, बल्कि किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या वक्ता रूप में इस पर शासन भी करता है। राजा ईश्वर के ह्मना-पत्र के रूप में राज्य पर शासन करता है। यह सिद्धान्त सब धर्मों की धार्मिक पुस्तकों में पाया जाता है और मोनार्की मंत्री तक यह आम तौर पर माना जाता था, पर आज की दुनिया में यह नहीं माना जाता। इसके न माने जाने के ये अनेक कारण हैं—

(१) राजाओं के दैवी अधिकार का सिद्धान्त इसी सिद्धान्त में पैदा हुआ था। इस सिद्धान्त के अनुसार राजा अपने आपको सिर्फ ईश्वर के सामने जवाबदेह बनाता था, जनता के सामने नहीं। इस तरह के विचार ने इसे विलुप्त निरंकुश बना दिया और उसके गलत नामों के त्रिपुं उसमें छुछनाछ करने का जनता के सामने अधिकार नहीं छोड़ा। इसलिए जनता की ओर से राजाओं के दैवी सिद्धान्त के अधिकार का मुकाबला करने के त्रिपुं समाज सन्धिदा सिद्धान्त रखा गया। इस सिद्धान्त के अनुसार, राजा अपनी व्यक्ति जनता से प्राप्त करता है, और राज्य शासक और धार्मिक के बीच सन्धिदा होने से उत्पन्न हुआ है। समाज सन्धिदा सिद्धान्त बड़ा तत्त्वपूर्ण था, और हमने नीचे ही दैवगम सिद्धान्त को मैदान में भेजा दिया।

(२) दैवगम सिद्धान्त तब तक चलता रहा जब तक धर्म में अविश्वास मनुष्य समाज में जमा हुआ था। जब धर्म के सिद्धान्तों की समीक्षा होने लगी, तब यह

क्षत्रम हो गया। यह शासक अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी। इसलिए कोई आदमी तर्क-संगत रूप से यह नहीं मोच सकता था कि ईश्वर लोगों पर बुरे राजा से शासन कराने की इच्छा रख सकता है। इसलिए राज्य ईश्वरजनित नहीं हो सकता।

तो भी देवागम मिथान्त ने गुरु के समय में अधिवारियों ने प्रति सम्मान पैदा किया।

समाज सविदा सिद्धान्त—यह सिद्धान्त सविदा द्वारा राज्य का उद्गम बताया है। समाज सविदा के पक्षपाती प्रमुख लेखक तीन हैं, अर्थात् हॉब्स, लॉक और रूसो। ये सब अपने सिद्धान्त को नैसर्गिक अवस्था (state of nature) से गुरु करते हैं। नैसर्गिक अवस्था में उनका मतलब उस दशा से है जिसमें मनुष्य समाज और राज्य के बनने से पहले रहते थे। इन लेखकों के अनुसार लोगों ने आपस में सविदा या समझौता करके समाज और राज्य का निर्माण किया।

हॉब्स का सिद्धान्त—हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था अराजकता की थी। हमें हर आदमी अलग रहना था, बड़ी स्वार्थबुद्धि से काम करना था और हमारे के मुख की परवाह न करके अपने लिये अधिकतम मुश्किलें बनाने की कोशिश करना था, ऐसी अवस्था में किसी का जीवन और सम्पत्ति सुरक्षित नहीं हो सकती थी और हर आदमी दूसरे में डरता और उस पर मदेह करता था। इस अवस्था को देखकर ही लोगों ने आपस में सविदा करने का करार किया। इस सविदा द्वारा हॉब्स के अनुसार लोगों ने अपनी सत्ता एक तीसरे व्यक्ति को सौंप दी, जो शासक या प्रभु कहलाया, पर प्रभु स्वयं इस सविदा में शामिल नहीं था। इसके बाद सविदा द्वारा लोग कानूनन और नैतिक दृष्टि से प्रभु द्वारा दिए गए हर आदेश का पालन करने के लिए बंध गए। उन्हें प्रभु द्वारा दी गई आज्ञाओं और अधिकारों के अलावा और कोई आज्ञाओं और अधिकार नहीं रहे। इस प्रकार हॉब्स ने परम शक्तिवाद (Absolutism) को अनुचित ठहराने के लिये सविदा सिद्धान्त का प्रयोग किया।

पर हॉब्स समाज सविदा सिद्धान्त का प्राकृतिक लेखक नहीं है। यद्यपि सामाजिक सविदा सिद्धान्त में दो सविदाएँ होती आवश्यक हैं। एक समाज के निर्माण के लिये जो सामाजिक सविदा कहा जाएगी और दूसरी सरकार स्थापित करने के लिये जो सरकार सम्बन्धी सविदा कहा जाएगी। यहाँ भी सामाजिक सविदा सिद्धान्त का सामाजिक प्रयोजन राजाओं के देवी अधिकार या निरंकुशता का मुकाबला करना था। इस सिद्धान्त के द्वारा व्यक्ति के नैसर्गिक अधिकार, जो वह नैसर्गिक अवस्था से लाया था, समाज और राज्य की सत्ता पर सदा एक रोक बने रहते थे।

लॉक का सिद्धान्त—लॉक समाज सविदा सिद्धान्त का एक प्राकृतिक लेखक है। उपर्युक्त सब विचार उसके सिद्धान्त में आ जाते हैं। वह हॉब्स के प्रतिकूल बातें मानता है। उसने विरपास ने प्रभुवार, नैसर्गिक अवस्था प्रातिपूर्ण की जिसमें सब व्यक्ति एक दूसरे में तर्कसंगत रीति से व्यवहार करते थे। दो भी लॉक का यह विश्वास था कि सम्पत्ति का विचार आ जाने पर लोगों ने समझना शुरू कर दिया। उन्हें नैसर्गिक अवस्था

के स्थान पर मजिस्ट्रेट द्वारा एक जनसंघ समाज (Civil society) स्थापित करने की पड़ी। लोक के अनुसार समाज मजिस्ट्रेट द्वारा आदमी ने अपना मिर्क एक अधिकार समाज को दिया, अर्थात् अन्य आदमियों के साथ उगता सम्बन्ध तय करने का अधिकार। दोष अधिकार, जैसे जीवन, स्वतन्त्रता, और सम्पत्ति का अधिकार, जिन्हें लोक नैतिक अधिकार कहता है, व्यक्ति ने अपने पास रखे। समाज उसे इन अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता था। बाद में समाज ने उन्हीं लोगों पर सरकार सम्बन्धी मजिस्ट्रेट द्वारा एक सरकार या शासन स्थापित किया। लोक के अनुसार शासन ने सब तक शासन कहता था जब तक वह लोगों के नैतिक अधिकारों की रक्षा करे और जनता के हित की दृष्टि में शासन करे। यदि यह रक्षा नहीं करता तो जनता को शक्ति द्वारा उसे बदल देने का और उसके स्थान पर दूसरा शासन बना देने का अधिकार था।

क्यों का सिद्धान्त—लोगों की नैतिक अवस्था लोक की अवस्था में भी अधिक जानकारी है। पर लोक के अनुसार, वह मिर्क एक मजिस्ट्रेट का उत्पन्न करता है, जिसे सब लोग मित्रवर अपने सब अधिकार एक साधारण इच्छा (General will) को मानते हैं। और प्रत्येक आदमी इस इच्छा का एक भाग बन जाता है। इस प्रकार लोगों के अनुसार अधिकार किसी एक आदमी का नहीं माना जाता, जैसा कि हांग की सामाजिक मजिस्ट्रेट में होता था, बल्कि सब लोगों को मिलाकर माना जाता है। लोगों का साधारण इच्छा का सिद्धान्त बाद में जनता की सर्वोच्चता के सिद्धान्त का आधार बन गया। यद्यपि लोगों नैतिक अधिकारों में विचार नहीं करता था, तो भी वह सम्मति द्वारा शासन का प्रथा समर्थक था। वह प्रत्यक्ष लोकतन्त्र का हामी है जिसमें सब आदमी समान में बैठेंगे और कानून बनायेंगे।

समाज मजिस्ट्रेट सिद्धान्त की आलोचना—इस सिद्धान्त पर मुख्य आपत्तियाँ ये हैं —

(१) समाज मजिस्ट्रेट का मतलब यह हो जाता है कि लोगों में विचार-विमर्श करके राज्य बनाया। तब यह है कि ऐसी कोशिश का राज्य के विधान में बहुत प्रोत्साहन रहा है। मुख्यतः राज्य समाज में से स्वाभाविक रीति से बिना जानबूझकर कोशिश किसे पैदा हुआ है।

(२) समाज मजिस्ट्रेट इतिहास में सत्य नहीं है। इतिहास में सरकार सम्बन्धी मजिस्ट्रेट के उद्घाटन को मिलने है, पर मजिस्ट्रेट द्वारा समाज पैदा होने का कोई उद्घाटन नहीं मिलता।

(३) यह विचार भी इतिहासमय नहीं है कि आदमी नैतिक अवस्था में अलग-अलग जीवन बिताते थे। आदमी सभी इस तरह नहीं रहता था। बहुत आदिवासी लोग का अध्ययन करने से भी हमें यही पता चलता है कि मनुष्य सदा समूहों में रहता रहा है।

(४) कानूनी दृष्टि से मजिस्ट्रेट मिर्क मजिस्ट्रेटकारी पक्षों पर ही कानूनी होती

चाहिए । समाज सविदा के पक्षपाती लेखक यह कैसे मान लेंगे हैं कि जिन्होंने शुरू में सविदा की थी, उनके बेटों-पोतों पर भी वह बघनकारी होगी ।

(५) यह कहकर कि समाज सविदा ने अधीन लोग अपना शासन बदल सकते हैं, यह सिद्धान्त प्राधिकार की इज्जत न बरतने की सलाह देता है । यह लोगों को सुच्छ बातों पर विद्रोह पर देने के लिये बढ़ावा देता है ।

(६) इस सिद्धान्त में अधिकारों के बारे में गलत विचार पैदा होगा है । नैसर्गिक अधिकार जैसी कोई चीज नहीं होती । आदमी को समाज और राज्य पर कोई अधिकार नहीं मिल सकता ।

इस सिद्धान्त की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं —

(१) यह राज्य के उद्गम के बारे में अधिक अच्छी व्याख्या पेश करता है । इसके अनुसार राज्य मनुष्य का बनाया हुआ है, ईश्वर का नहीं ।

(२) इस सिद्धान्त में सम्मति द्वारा शासन का जो उगूल है, वह भाषुनिव लोकतन्त्र का आधार बना है ।

(३) इस सिद्धान्त ने सबसे पहले ठीक तरह से व्यष्टि का महत्व बनाया ।

बल का सिद्धान्त—यह सिद्धान्त यह कहता है कि राज्य बल द्वारा पैदा होता है और बल द्वारा ही यह कायम रखा जाता है । इसके समर्थक कहते हैं कि आदमी स्वभाव से शगडालू है । उसमें ताकत की चाह भी है । इसलिए समाज के शुरू के दिनों में जा आदमी-आदमी ने अधिक ताकतवर था, उसने अपने पड़ोस के कमजोर लोगों पर अधिकार कर लिया होगा और उन्हें गुलाम बना लिया होगा । धीरे-धीरे इमने बल के जोर से अपने साथियों की सख्या बढ़ा ली और वह कबीले का सरदार बन गया । जब एक कबीले ने अपने सरदार के नेतृत्व में बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया और वह उस पर स्थायी रूप से रहने लगा, तब राज्य का जन्म हुआ ।

इसके अलावा, बल के सिद्धान्त के पक्षपातियों का यह भी कहना है कि बल सिर्फ राज्य के मुज़न के लिये आवश्यक नहीं, बल्कि इसे कायम रखने के लिये भी लाज़मी है । आदमियों के स्वभाव से शगडालू होने के कारण, राज्य के भीतर कानून और व्यवस्था तथा बाहरी आक्रमणों से बचाव बल द्वारा ही किया जा सकता है ।

बल के सिद्धान्त की आलोचना—यह सिद्धान्त राज्य के उद्गम की पूरी व्याख्या नहीं करता । इसका यह कहना भी गलत है कि राज्य के पैदा करने और कायम रखने में बल ही एकमात्र कारण है । हम मानते हैं कि राज्य के उद्गम और विकास में बल ने महत्वपूर्ण कार्य किया है । हम यह भी मानते हैं कि राज्य को बनाये रखने के लिए बल आवश्यक है । राज्य के भीतर राज्य को इस वास्ते बल की आवश्यकता है जिससे लोग इसके कानूनों का पालन करें । बाहरी दृष्टि में किसी विदेशी शक्ति के आक्रमण को विफल करने के लिए बल आवश्यक है । पर हमें यह याद रखना चाहिए कि राज्य के उद्गम और उसके नष्टारण, दोनों, में बल सिर्फ एक कारण रहा है । यह न

के स्थान पर सविदा द्वारा एक जातपद समाज (Civil society) स्थापित करनी पड़ी। लॉक ने अनुसार समाज सविदा द्वारा आदमी ने अपना सिर्फ एक अधिकार समाज को दिया, अर्थात् अन्य आदमियों के साथ उसका सम्बन्ध तब करने का अधिकार। घेप अधिकार, जैसे जीवन, स्वतन्त्रता, और सम्पत्ति का अधिकार, जिन्हें लॉक नैसर्गिक अधिकार कहता है, व्यक्ति ने अपने पास रखे। समाज उसे इन अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता था। बाद में समाज ने उन्हीं चर्तों पर सरकार सम्बन्धी सविदा द्वारा एक सरकार या शासन स्थापित किया। लॉक ने अनुसार शासन ने तब तब सत्तास्थ रहना था जब तक वह लोगों के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे और जनता के हित की दृष्टि से शासन करे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो जनता की शक्ति द्वारा उसे बदल देने का और उसके स्थान पर दूसरा शासन बना देने का अधिकार था।

रूमो का सिद्धान्त—रूमो की नैसर्गिक अवस्था लॉक की अवस्था से भी अधिक आनन्दमय है। पर लॉक के अनुसार, वह सिर्फ एक सविदा का उल्लेख करता है, जिसमें सब लोग मिश्रकर अपने सब प्राधिकार एक सामारण इच्छा (General will) को सौंप देने हैं। और प्रत्येक आदमी इस इच्छा का एक भाग बन जाता है। इस प्रकार रूमो के अनुसार प्राधिकार किसी एक आदमी को नहीं सौंपा जाता, जैसा कि होम्स की सामाजिक सविदा में होता था, बल्कि सब लोगों को मिलाकर सौंपा जाता है। रूमो का सामारण इच्छा का सिद्धान्त बाद में जनता की सर्वोच्चता के सिद्धान्त का आधार बन गया। यद्यपि रूमो नैसर्गिक अधिकारों में विश्वास नहीं करता था, तो भी वह सम्पत्ति द्वारा शासन का पक्का समर्थक था। वह प्रत्यक्ष लोकतन्त्र का हामी है जिसमें सब आदमी भ्राता में बैठेंगे और कानून बनावेंगे।

समाज सविदा सिद्धान्त की आलोचना—इस सिद्धान्त पर मुख्य आपत्तियाँ ये हैं —

(१) समाज सविदा का मतलब यह ही जाना है कि लोगों ने विचार-विमर्श करके राज्य बनाया। तथ्य यह है कि ऐसी कोशिश का राज्य के विकास में बहुत प्रोत्साहन रहा है। मुख्यतः राज्य समाज में से स्वाभाविक रीति से बिना जानबूझकर कोशिश जिसे पैदा हुआ है।

(२) समाज सविदा इतिहास से संगत नहीं है। इतिहास में सरकार सम्बन्धी सविदा के उदाहरण तो मिलते हैं, पर सविदा द्वारा समाज पैदा होने का कोई उदाहरण नहीं मिलता।

(३) यह विचार भी इतिहाससंगत नहीं है कि आदमी नैसर्गिक अवस्था में खलम-खलम जीवन बिताने से। आदमी कभी इस तरह नहीं रहता था। बहुत आदिवासीन लोग का अध्ययन करने से भी हमें यही पता चलता है कि मनुष्य सदा समूहों में रहता रहा है।

(४) कानूनी दृष्टि से सविदा सिर्फ सविदाकारी पक्षों पर ही बंधनकारी होती

चाहिए । समाज सविदा के पक्षपाती ऐलान यह कर्ने मान लेने हैं कि जिन्होंने शुरु में सविदा की थी, उनके बेटों-पोतों पर भी वह बघनकारी होगी ।

(५) यह कहकर कि समाज सविदा के अधीन लोग अपना शासन बदल सकते हैं, यह सिद्धान्त प्राधिकार की इज्जत न करने की सलाह देता है । यह लोगों को कुछ बातों पर विश्रुह कर देने के लिये बढ़ावा देता है ।

(६) इस सिद्धान्त में अधिकारों के बारे में भ्रष्ट विचार पैदा होता है । नैसर्गिक अधिकार जैसी कोई चीज नहीं होती । आदमी को समाज और राज्य पर कोई अधिकार नहीं मिल सकता ।

इस सिद्धान्त की कुछ अच्छाइया भी हैं —

(१) यह राज्य के उद्गम के बारे में अधिक अच्छी व्याख्या पेश करता है । इसके अनुसार राज्य मनुष्य का बनाया हुआ है, ईश्वर का नहीं ।

(२) इस सिद्धान्त में सम्मति द्वारा शासन का जो उमूल है, यह आधुनिक लोकतन्त्र का आधार बना है ।

(३) इस सिद्धान्त में सबसे पहले ठीक तरह से व्यष्टि का महत्व बताया ।

बल का सिद्धान्त—यह सिद्धान्त यह कहता है कि राज्य बल द्वारा पैदा होता है और बल द्वारा ही यह कायम रखा जाता है । इसके समर्थक कहते हैं कि आदमी स्वभाव से अगदालू है । उसमें ताकत की चाह भी है । इसलिए समाज के शुरु के दिनों में जो आदमी औरों में अधिक ताकतवर था, उसने अपने पदों के कमजोर लोगों पर अधिकार कर लिया होगा और उन्हें गुलाम बना लिया होगा । धीरे-धीरे इसने बल के जोर में अपने साथियों की सख्या बढ़ा ली और वह कबीले का सरदार बन गया । जब एक कबीले ने अपने सरदार के नेतृत्व में बहुत बड़े हिस्से पर नियन्त्रण कर लिया और वह उस पर स्थायी रूप से रहने लगा, तब राज्य का जन्म हुआ ।

इसके अलावा, बल के सिद्धान्त के पक्षपातियों का यह भी कहना है कि बल सिर्फ राज्य के सुत्रन के लिये आवश्यक नहीं, बल्कि इसे कायम रखने के लिये भी लाजमी है । आदमी की स्वभाव में अगदालू होने के कारण, राज्य के भीतर कानून और व्यवस्था तथा बाहरी आक्रमणों से बचाव बल द्वारा ही किया जा सकता है ।

बल के सिद्धान्त की आलोचना—यह सिद्धान्त राज्य के उद्गम की पूरी व्याख्या नहीं करता । इसका यह कहना भी गलत है कि राज्य के पैदा करने और कायम रखने में बल ही एकमात्र कारण है । हम मानते हैं कि राज्य के उद्गम और विकास में बल ने महत्वपूर्ण भाग किया है । हम यह भी मानते हैं कि राज्य को बलसे रखने के लिए बल आवश्यक है । राज्य के भीतर राज्य को इस वास्ते बल की आवश्यकता है जिससे लोग इसके कानूनों का पालन करें । बाहरी दृष्टि से किसी विदेशी शक्ति से आक्रमण को विफल करने के लिए बल आवश्यक है । पर हमें यह याद रखना चाहिए कि राज्य के उद्गम और उसके सधारण, दोनों, में बल सिर्फ एक कारण रहा है । यह न

तो एक मान जा रहा है, और न सबसे महत्वपूर्ण बात। राज्य का आधार बल नहीं है। लोगों को एक सत्ता के अधीन रखने के लिए कोई और ही चीज आवश्यक है। लोगों को दम मना की ज़रूरतों का विवेक करना होगा और उनका विभाग जीना होगा। इसलिए राज्य का वास्तविक आधार 'इच्छा' (will) है, बल नहीं। निरा बल बिना चीज को मिलाकर नहीं रख सकता। निचे बल से दम बिना जानकर भी अपने काम में नहीं रख सकते। हमें माय-माय ज़रूरतों में प्रेम भी प्राप्त करना होगा। इसी प्रकार, राज्य जमीन म्यादी हो सकता है, जब लोग स्वेच्छा से उसको जाना का पान्न करें। बल पर आधारित राज्य अधिक दिन नहीं टिक सकता।

शैशुक और मानक सिद्धान्त—इन सिद्धान्तों में से एक को भी राज्य के उद्गम के बारे में सही तौर से कोई सिद्धान्त नहीं कहा जा सकता। वे समय में राजनीतिक सिद्धान्त होने के बजाए समाज शास्त्रीय सिद्धान्त हैं, जो मानव समाज के आरम्भ और इसके परिवर्तन के प्रक्रम की व्याख्या करने का यत्न करने हैं। उन सिद्धान्तों का मूल यह प्रश्न है कि पहले शैशुक परिवार हुआ, या मानक। इस प्रकार के राज्य के उद्गम की उनकी व्याख्या नहीं करते, ब्रितानी परिवार के उद्गम की। हम यह भी निश्चित रूप से जानते हैं कि राज्य परिवार में से विकसित नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों अपनी प्रकृति, मापडन, बायीं और लम्बाई में एक दूसरे से भिन्न हैं।

ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धान्त—यह सिद्धान्त राज्य के उद्गम की सबसे अच्छी और सबसे सही व्याख्या करता है। इसके अनुसार राज्य की यह इतिहास में है, और यह कमिज और अनुपम रीति से समाज में से विकसित हुआ है। इस रूप में हम यह टीका-टीक नहीं कह सकते कि समाज के राजनीतिक रूप से संगठित हुआ या राज्य का जन्म के हुआ। यह बात भी नहीं है कि राज्य सब जगह एक साथ प्रादुर्भूत हुआ है। पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम के पठान कबायली क्षेत्रों में राज्य का विकास अब तक नहीं हुआ।

समाज से राज्य का विकास होने में निम्नलिखित बातें मूलभूत रही होंगी -

१. एक सम्बन्ध।
२. धर्म।
३. राजनीतिक चेतना।

रक्त सम्बन्ध—रक्त सम्बन्ध एकल का पहला स्तम्भ रहा होगा। घर परिवार पहला सामाजिक समूह रहा होगा। परिवार में रक्त सम्बन्ध के कारण पिता की आज्ञा का परिवार के अन्य सदस्य पालन करते होंगे। जब परिवार लोगों के रूप में आ गये और गोत्र बढ़कर कबीलों के रूप में हो गये, तब भी रक्त सम्बन्ध बना रहा, यद्यपि यह बहुत कमजोर होता गया। सब लोग सबसे बड़े जीवित पुत्र सदस्य की आज्ञा का पालन करते थे। इस प्रकार शुरू के समाजों में रक्त-सम्बन्ध ने प्राधिकार की वृद्धि में बहुत कुछ सहायता की और यह प्राधिकार ही राज्य का आधार है।

धर्म—धर्म ने इन प्राधिकार का बल और बढ़ाया। आरम्भिक अवस्था में मृत पूर्वजों की पूजा अप्रत्यक्ष रूप में सबसे बड़े जीविन पुरुष सदस्य के प्राधिकार को साबित देती थी। बाद में, जब प्रकृति के देवताओं की पूजा होने लगी, सब बबीले का नेता सारे बबीले के निमित्त उन्हें बेट बनाता था। स्वभावतः बबीले के अन्य लोग उन्हीं देवताओं का प्यारा समझने लगे और उसकी आज्ञा भग करने से डरने लगे। इन प्रकार धर्म शासक के प्राधिकार को बलवान बनाने में और लोगो को बानून पालन बनाने में बड़ा सहायक हुआ।

राजनैतिक चेतना—राजनैतिक चेतना आधुनिक जीवन की प्रगति में पैदा हुई थी। आधुनिक दृष्टि से समाज विचार, पशुपालन, और खेती की अवस्थाओं में से गुजरा। पहली दो अवस्थाओं में लोग बजारी का जीवन बिताने में। पर धृति में उह तक निश्चित क्षेत्र में बगने को मजबूर कर दिया। इसी तरह समाज के विचार की प्रत्येक अवस्था में निजी सम्पत्ति बढ गई, और बबीले में युद्ध अधिक होने लगे। युद्ध ने राजनैतिक चेतना पैदा की और बबीले एक दूसरे के हमला से जीवन और सम्पत्ति की रक्षा की आवश्यकता अनुभव करने लगे। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि रक्त सम्बन्ध की दृष्टि से जो सदस्य सबसे बड़ा है, वह युद्ध में उनका नेतृत्व मही कर सकता। परिणामतः, हर बबीले ने ऐसे आदमी को अपना युद्ध नेता बना लिया, जिसमें युद्ध सम्बन्धी गुण सबसे अधिक थे। धीरे-धीरे युद्ध-नेता की प्रतिष्ठा और महत्त्व बढ़ते गये और वह राजा कहलाने लगा। उसका प्राधिकार एक विवेक क्षेत्र के सब लोगो पर होता था और उसका विभी रक्त विषेय के लोगो में कोई सम्बन्ध नहीं था। जब समाज के विकास में ऐसी अवस्था आ गई तब राज्य का जन्म हुआ।

राज्य की प्रकृति

हम देख चुके हैं कि मनुष्य स्वभाव में सामाजिक प्राणी है। आज के समाज में जो अनेक सभ्य और सभ्य हैं, वे मनुष्य के इसी सामाजिक स्वभाव का परिणाम हैं। इसलिए राज्य भी, जो एक सभ्य या साहचर्य ही है, स्वाभाविक है, पर एक बात याद रखनी चाहिए। अनेक साहचर्यों और संस्थाओं का विभाग पूरी तरह स्वाभाविक मार्ग से नहीं होता। मनुष्य द्वारा पाल-वृक्ष कर दिया गया प्रपात भी इसी रूप को बनाने में बहुत हिस्सा लेता है। इसलिए राज्य को अलग स्वाभाविक और अलग सभ्य प्रयत्न का परिणाम कहा जा सकता है। स्वाभाविक प्रकृति और सभ्य प्रयत्न राज्य के निर्माण में ऐसी मूल्यमता से मिल गये हैं कि लोगो में राज्य की प्रकृति के बारे में अलग-अलग विचार पैदा हो गये हैं।

कुछ लोगो की दृष्टि में राज्य विलुप्त कर्नाई हुई चीज है और इसमें जो एकता है वह सविदा आदि इन्तिम साधनो का परिणाम है। कुछ लोग राज्य को एक जीवविण्ड (Organism) समझते हैं और इसकी एकता को वैसी ही एकता समझते हैं जैसे किसी जीवविण्ड के अनेक भागो में होती है। अब हम राज्य की प्रकृति के बारे में इन दोनों दृष्टिकोणो पर संक्षेप में विचार करेंगे।

सविदा सिद्धान्त—हम इस सिद्धान्त पर राज्य के उदय के सिलसिले में भी विचार कर चुके हैं। राज्य की प्रवृत्ति के बारे में भी यह एक सिद्धान्त है। इसके अनुसार, समाज और राज्य सविदा या आपसी और स्वेच्छा विधे से बनने का परिणाम है। इन सिद्धान्त के समर्थकों का कहना है कि राज्य की आधारभूत एकता बनाई हुई एकता है, स्वामात्रिक नहीं। यह सिद्धान्त राज्य की स्वीकृति के आधार पर नहीं करता। यह राज्य के निर्माण में मनुष्यों के सोचे-विचारे और जानबूझकर विधे से प्रमाण पर अनुचित दल देता है। यह मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति की उपेक्षा करता है जो राज्य में अर्थीन लोगों को इकट्ठा करने में मूल प्रेरक है।

बीवरीशिय सिद्धान्त (Organismic Theory)—इस सिद्धान्त के लेखक राज्य की प्रवृत्ति की व्याख्या किसी जीवविज्ञ से इसकी तुलना द्वारा करते हैं। हर्बर्ट स्पेन्सर को राज्य और मानव शरीर को बिल्कुल एक ही मानना है। उसके अनुसार ये दोनों अपनी बुद्धि, संरचना और कार्यों में एक जैसे होते हैं। राज्य का मूल रूप में मनुष्य के रूप में विकसित होना किसी जीवविज्ञ की एक-कोशिकीय पिण्ड संवृद्धिकोशिकीय पिण्ड के रूप में वृद्धि में मिलना-जुलना है। राज्य के विभिन्न भागों का सहयोग यही है जैसे मानव शरीर के विभिन्न भागों का करने-काम करने हुए आपसी सहयोग। राज्य और मानव शरीर की संरचना के विषय में स्पेन्सर ने निम्नलिखित समानताएँ प्रस्तुत की हैं :

१. राज्य के लिए सरकार उसी रूप में है जिस रूप में मानव शरीर के लिए मस्तिष्क है।

२. रेल, सड़क और तार राज्य के लिए जैसे ही है जैसे शरीर के लिए धमनिया और शिराएँ।

३. पैर और आँखें शरीर को चोपक देती हैं—मैनुअल लैबर और इति कामें राज्य को जीवित रखते हैं।

जैसा कि स्पष्ट है, स्पेन्सर ने राज्य और मानव शरीर के बीच समानता बहुत दूर तक दिखाई है। राज्य की जीवविज्ञ कहा जाता है। यह कुछ बुद्धियों ने गिर्त जीवविज्ञ जैसा है। राज्य बहुत बातों में जीवविज्ञ से भिन्न भी होता है। जीवविज्ञ के भागों का अलग कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं होता। उदाहरण के लिए, हाथ शरीर में स्वतन्त्र रूप में नहीं रह सकता। व्यक्ति अपने आप में एक पूर्ण समष्टि है और वह राज्य के बिना भी जीवित रह सकता है। दूसरे, मनुष्य प्राणियों में एक जीवविज्ञ दुबरे में से पैदा होता है। राज्य के मापने में यह बात नहीं।

सारांश

राज्य का उद्गम—राज्य का उद्गम अज्ञात अतीत में हुआ था। हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि राज्य कब और कैसे आरम्भ हुआ। हम इसके उद्गम का अनुमान ही कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में कई विचार पेश किये गये हैं —

दैवी उद्गम का सिद्धांत—राज्य के उद्गम के बारे में सबसे पुराना विचार यह है कि इसे ईश्वर ने बनाया। यह सब धर्मों की पुस्तकों में मिलता है। इस विचार से राजा के दैवी अधिकार का सिद्धान्त पैदा हुआ। इस विचार का असली आधार धार्मिक पुस्तकों में था। यह तर्क की बसीटी पर खरा न उतरने के कारण खतम हो गया।

समाज सविदा का सिद्धांत—इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य का जन्म सविदा के द्वारा हुआ। हॉब्स, लाक तथा रुसो समाज सविदा के तीन महत्वपूर्ण लेखक थे। यद्यपि हॉब्स ने इस सिद्धान्त द्वारा परमशक्तिवाद (Absolutism) को उचित ठहराया था तो भी इस सिद्धान्त का असली प्रयोजन, जैसा कि लॉक ने बताया था, दैवी अधिकार के सिद्धान्त के मुकाबिले में जनता के अधिकारों पर बल देना था। साम्राज्य को अपनी जनता के साथ की गई सविदा द्वारा सत्ता मिलनी है। इस प्रकार इस सिद्धान्त ने लोकतन्त्र के बलों को जन्म दिया। पर राज्य प्राकृतिक है और किसी सविदा का परिणाम नहीं। सामाजिक सविदा बर्बोल-बलिप्त, इतिहास के विरुद्ध और कानून के विरुद्ध है। इसी प्रकार, इस सिद्धान्त की कुछ बुनियादी अवधारणाएँ, अर्थात् प्राकृतिक अवस्था और प्राकृतिक या नैसर्गिक अधिकार सर्वथा अवास्तविक हैं।

बल का सिद्धांत—इस सिद्धान्त का कहना है कि राज्य का जन्म सिर्फ बल से हुआ और बल के ही जोर पर यह कायम है। इस प्रकार यह बल को अनुचित महत्व देता है। राज्य के सृजन और गरिमा में बल सिर्फ एक कारक है। यह अधिक महत्वपूर्ण घटक भी नहीं है। अधिक महत्वपूर्ण घटक 'इच्छा' है, बल नहीं।

ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत—इसके अनुसार राज्य समाज में विकास के क्रमिक और अनजाने प्रक्रम का परिणाम है। इसका उद्गम ऐतिहासिक ढंग से खोजना चाहिए। समाज से राज्य का विकास होने में रक्त सम्बन्ध, धर्म और राजनैतिक चेतना में मदद मिली। रक्त-सम्बन्ध एतना का पहला चरण था। इसने लोगों को पहले परिवार में और इसके बाद भोज तथा कबीले में रक्त की दृष्टि से प्येष्ठ के अधीन समझने किया। धर्म ने सत्ता के प्रति आदर पैदा किया। जब समाज क्षिणिक की अवस्था में सेती की अवस्था में पहुँच गया, तब सम्पत्ति बढ़ जाने से राजनैतिक चेतना पैदा हुई। सम्पत्ति में वृद्धि हो जाने पर युद्ध अधिक होने लगे और युद्ध ने राजा को जन्म दिया। इस प्रकार जब एक राजा की सत्ता किसी निश्चित क्षेत्र के लोगों के ऊपर कायम हुई, तब राज्य का जन्म हुआ। राज्य के उद्गम के बारे में यह व्याख्या सबसे अधिक सर्वमान्य है।

सविदा सिद्धान्त—हम इस सिद्धान्त पर राज्य के उद्भव के मिलनिले में भी विचार कर चुके हैं। राज्य की प्रवृत्ति के बारे में भी यह एक सिद्धान्त है। इसके अनुसार, समाज और राज्य सविदा या आपसी और स्वेच्छा किये गये करार का परिणाम है। इस सिद्धान्त के समर्थकों का कहना है कि राज्य की आधारभूत एकता बनाई हुई एकता है, स्वामाजिक नहीं। यह सिद्धान्त राज्य की सतोषजनक व्याख्या नहीं करता। यह राज्य के निर्माण में मनुष्यों के मोचे-विचारे और जानबूझकर किये गये प्रयास पर अनुचित बल देता है। यह मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति की उपेक्षा करता है जो राज्य से अधीन लोगों को इकट्ठा करने में मूल प्रेरक है।

जीवविज्ञान सिद्धान्त (Organismic Theory)—इस सिद्धान्त के लेखक राज्य की प्रवृत्ति की व्याख्या किसी जीवविज्ञ से इसकी तुलना द्वारा करते हैं। हर्बर्ट स्पेन्सर तो राज्य और मानव शरीर को बिल्कुल एक ही बताता है। उसके अनुसार ये दोनों अपनी बुद्धि, मरचना और कार्यों में एक जैसे होते हैं। राज्य का गरल रूप से मनुष्य रूप में विविध होना किसी जीवविज्ञ की एक-नोशिकीय विज्ञ संयुक्तोमितीय विज्ञ के रूप में बुद्धि में मिलता-जुलता है। राज्य के विभिन्न भागों का महयोग बेसा ही है जैसे मानव शरीर के विभिन्न भागों का अपने कार्य करते हुए आपसी महयोग। राज्य और मानव शरीर की मरचना के विषय में स्पेन्सर ने निम्नलिखित समानताएं प्रस्तुत की हैं :

१. राज्य के लिए सरकार उसी रूप में है जिस रूप में मानव शरीर के लिए मस्तिष्क है।

२. रेशे, रुख और तार राज्य के लिए रीने ही हैं जैसे शरीर के लिए धमनिया और गिराए।

३. पैर और आँखें शरीर को पोषण देती हैं—सैन्यपूर्णचरित्र और हथियार कार्य राज्य का जीवन रखते हैं।

जैसा कि स्पष्ट है, स्पेन्सर ने राज्य और मानव शरीर के बीच समानता बहुत दूर तक दिखाई है। राज्य की जीवविज्ञ कहना गलत है। यह पृष्ठ दृष्टियों में मिले जीवविज्ञ जैसा है। राज्य बहुत कमों में जीवविज्ञ से भिन्न भी होता है। जीवविज्ञ के भागों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। उदाहरण के लिए, हाथ शरीर से स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। व्यक्ति अपने आप में एक पूर्ण समष्टि है और वह राज्य के बिना भी जीवित रह सकता है। दूसरे, मनुष्य प्राणियों में एक जीवविज्ञ दूसरे में से पैदा होता है। राज्य के मामले में यह बात नहीं।

इस सिद्धांत में सत्य का बीज—राज्य के भाग अपने कल्याण के लिए उसी तरह परस्पर आश्रित होते हैं जैसे किसी जीवविज्ञ के भाग। समाज और राज्य की एकता लक्षियों की गहरी की एकता के समान नहीं है। यह सजीव एकता है। जैसे कोई तेल-विज्ञ तेल की बूंदों और रंगों का संघट्टा नहीं होता उसी प्रकार राज्य व्यक्तियों का समूहमान नहीं है।

सारांश

राज्य का उद्गम—राज्य का उद्गम अज्ञान अतीत में हुआ था। हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि राज्य कब और कैसे आरम्भ हुआ। हम इसके उद्गम का अनुमान हो कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में कई विचार पेश किये गये हैं —

दैवी उद्गम का सिद्धान्त—राज्य के उद्गम के बारे में सबसे पुराना विचार यह है कि इसे ईश्वर ने बनाया। यह सब धर्मों की पुस्तकों में मिलता है। इस विचार से राजा के दैवी अधिकार का सिद्धान्त पैदा हुआ। इस विचार का असली आधार पामिर पुस्तकों में मिला था। यह तर्क की बसोटी पर खराब उत्तर देने के कारण खतम हो गया।

समाज सविदा का सिद्धान्त—इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य का जन्म सविदा के द्वारा हुआ। हॉम्स, लॉक तथा रुमो समाज सविदा के तीन महत्वपूर्ण लेखक हैं। यद्यपि हॉम्स ने इस सिद्धान्त द्वारा परमशक्तिवाद (Absolutism) को उचित ठहराया था तो भी इस सिद्धान्त का असली प्रयोजन, जैसा कि लॉक ने बताया था, दैवी अधिकार के सिद्धान्त के मुकाबिले में जनता के अधिकारों पर बल देना था। शासन का अपनी जनता के साथ की गई सविदा द्वारा सत्ता मिलती है। इस प्रकार इस सिद्धान्त ने लोकतन्त्र के बलों को जन्म दिया। पर राज्य प्राकृतिक है और किसी शक्ति का परिणाम नहीं। सामाजिक सविदा कपोल-कल्पित, इतिहास के विरुद्ध और कानून के विरुद्ध है। इसी प्रकार, इस सिद्धान्त की कुछ बुनियादी अवधारणाएँ, अर्थात् प्राकृतिक अवस्था और प्राकृतिक या नैसर्गिक अधिकार सर्वथा अवास्तविक हैं।

बल का सिद्धान्त—इस सिद्धान्त का कहना है कि राज्य का जन्म सिर्फ बल से हुआ और बल के ही जोर पर यह कायम है। इस प्रकार यह बल को अनुचित महत्त्व देता है। राज्य के मूलन और सरक्षण में बल सिर्फ एक कारक है। यह अधिक महत्वपूर्ण घटक भी नहीं है। अधिक महत्वपूर्ण घटक 'इच्छा' है, बल नहीं।

ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धान्त—इसके अनुसार राज्य समाज से विभाग के प्रथम और अनजाने प्रक्रम का परिणाम है। इसका उद्गम ऐतिहासिक ढंग से खोजना चाहिए। समाज से राज्य का विकास होने में रक्त सम्बन्ध, धर्म और राजनैतिक चेतना से मदद मिली। रक्त-सम्बन्ध एकता का पहला बन्धन था। इसने लोगों को पहले परिवार में और इसके बाद गोत्र तथा कबीले में रक्त की दृष्टि से जुड़े के गंधीन संगठित किया। धर्म ने सत्ता के प्रति आदर पैदा किया। जब समाज तिरार की अवस्था से सेती की अवस्था में पहुँच गया, तब सम्पत्ति बढ़ जाने से राजनैतिक चेतना पैदा हुई। सम्पत्ति में वृद्धि हो जाने पर युद्ध अधिक होने लगे और युद्ध ने राजा को जन्म दिया। इस प्रकार जब एक राजा की सत्ता किसी निश्चित क्षेत्र के लोगों के ऊपर कायम हुई, तब राज्य का जन्म हुआ। राज्य के उद्गम के बारे में यह व्याख्या सबसे अधिक तर्कमूलक है।

राज्य की प्रकृति—राज्य अथवा प्राकृतिक और अथवा सचेत प्रपन्न का परिणाम है। राज्य की इस प्रकृति के कारण इसकी प्रकृति के बारे में अनेक विचार पैदा हो गए हैं।

सविज्ञान विद्वानों के लेखकों के अनुसार, राज्य एक सर्वथा नया है और दूसरी आधारभूत एकता सविज्ञान जैसे कृत्रिम साधनों का परिणाम है। पर ये मनुष्य की सामाजिक प्रकृति को भूल जाते हैं जो लोगों को राज्य के अधीन इकट्ठा होने में मूल्य रूप से प्रेरणा देती है।

प्राविधिक विद्वानों के लेखक राज्य की तुलना औपनिषद् से करते हैं। हर्बर्ट स्पेन्सर ने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि राज्य एक औपनिषद् है, पर यह गलत है। अधिक से अधिक हम इतना कह सकते हैं कि राज्य की एकता एक औपनिषद् के समान है।

प्रश्न

QUESTIONS

1. राज्य के दो उद्गम के सिद्धांत की आलोचना करो।

1 Critically examine the theory of Divine Origin of the state

2. राज्य के उद्गम के बारे में समाज सन्धि विद्वानों का संक्षेप में उल्लेख करो। इस सिद्धांत में क्या दोष है?

2 State briefly the Social Contract Theory regarding the origin of the state. What is wrong with this theory?

3. आप राज्य का सही उद्गम क्या समझते हैं?

3 What do you think to be the correct origin of the state?

Or

राज्य के उद्गम के बारे में ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत का संक्षेप में उल्लेख कीजिए?

Briefly state the Historical and Evolutionary theory regarding the origin of the state

4. राज्य की प्रकृति क्या है? इन प्रश्नों में औपनिषदीय सिद्धांत का संक्षेप में विवेचन कीजिए।

4 What is the nature of the state. Briefly examine the organic theory in this connection

अध्याय : : १०

राज्य के कार्य और लक्ष्य

राज्य के कार्य

आजकल का कोई प्रारूपिक राज्य, जो अनेक कार्य करता है, उनका उत्प्रेषण करने से पहले हम इस मिलमिले में दो चरम विचारों की परीक्षा करेंगे। वे हैं व्यक्तिवादी (Individualistic) और समाजवादी विचार। व्यक्तिवादी लोग राज्य के कार्य कम से कम रखने के पक्ष में हैं। दूसरी ओर, समाजवादी राज्य को अधिक से अधिक कार्य सौंपना चाहते हैं।

व्यक्तिवादी विचार—व्यक्तिवादी लोग राज्य को एक बुराई समझते हैं जिसे मनुष्य की स्वार्थी और झगड़ालू प्रकृति के कारण रखा पड़ता है। यदि भीतरी अराजकता और बाहरी हमलों से व्यक्ति की रक्षा की जरूरत न हो तो व्यक्तिवादी राज्य को बर्तई रखना पसन्द न करे। उनकी राय में, राज्य व्यक्ति की स्वतन्त्रता का दुश्मन है। वे राज्य को अच्छाई पैदा करने या साधन नहीं मानते। व्यक्ति को अपने हितों की देखभाल करने के लिए आजाद छोड़ देना चाहिए। राज्य का दखल तभी उचित है, जब एक व्यक्ति की आजादी दूसरी व्यक्ति की इसी प्रकार की आजादी में टकराती है। अथवा, जैसा कि जे० एम० मिल ने कहा था 'अपने ऊपर अपने निज के शरीर और मन पर व्यक्ति सर्वोच्च प्रभुत्व रखता है।' व्यक्तिवादी के अनुसार, जहाँ तक व्यक्ति को अपने कल्याण या मजबूती के लिए वह जैसे तैसे प्राप्त करने के लिए पूर्णतया स्वतन्त्र छोड़ दिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि व्यक्ति स्वयं अपना भला-बुरा समझने की बुद्धि रखती है। इस प्रकार, औसत व्यक्तिवादी राज्य को निम्नलिखित कार्य देने को तैयार होता है —

- १ बाहरी हमलों से व्यक्ति की रक्षा।
- २ व्यक्तियों की एक दूसरे से रक्षा। इसमें उनकी सम्पत्ति की चोरी, हर्षण या हानि से रक्षा भी शामिल है।
- ३ व्यक्तियों की विध्या-सविदाओं, या सविदाओं के भंग से रक्षा।
- ४ निरसादेह, व्यक्तिवादियों ने व्यक्ति के महत्व पर बल देकर और व्यक्ति के दैनिक जीवन में सरकार के अनावश्यक दखल को खिलाफ आवाज उठाकर, उपायों की सेवा की है। पर व्यक्ति की स्वतन्त्रता के उत्साह में वे राज्य द्वारा व्यक्ति के भयंकर के लिये किये जाने वाले काम की कम कीमत लगाने हैं।

आलोचना—राज्य के कामों के बारे में व्यष्टिवादी सिद्धान्त की आलोचना करने पर यह से की गई है —

१ व्यष्टिवादी अथवा व्यष्टि की योग्यता के बारे में अनुचित रूप से अधिक आशंका है। वास्तव में, अधिकतर लोग अपने भले को नहीं समझते और उन्हें मार्ग दिखाना पड़ता है। अनपढ़ आदमी शिक्षा का मूल्य नहीं समझ सकता।

२ यह समझना सत्य है कि राज्य व्यष्टि की स्वतन्त्रता का दुश्मन है। यह तो उचितता भरी बात है। राज्य उसकी अवांछनीय (असह्यतावादी) स्वतन्त्रता का ही शत्रु है। नागरिक स्वतन्त्रता, जो व्यष्टि के व्यक्तिगत विकास के लिए परम आवश्यक है, राज्य ही की देन है।

३ व्यष्टिवादी व्यापार और उद्योग में राज्य की हस्तक्षेपशीलता होने की ओर भाग बनते हैं, वह मानी नहीं जा सकती। मूलिक और उसके मजदूरों में खुली प्रति-योगिता होने पर मजदूरों की निश्चित रूप से हानि उठनी होगी। राज्य की अपनी आबादी के अधिक दृष्टि से दुर्बल भाग की, धनियों के शोषण से, रक्षा करनी होगी।

अन्त में हम यह कह सकते हैं कि व्यष्टिवाद आज की दुनिया में अपना प्रभाव छोड़ चुका है। इसे धन-पहुँचाने में समाजवाद के माध्यम का बड़ा हाथ रहा है।

समाजवादी विचार—समाजवाद व्यष्टिवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, और ये दोनों एक-दूसरे से बिल्कुल विरुद्ध दोनों हैं। व्यष्टिवाद ने वैयक्तिक विकास वाली समाजवाद की निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय है —

१. समाजवादी सिद्धान्त में राज्य की मुनिश्चित अछाई का अभिप्राय माना जाता है। इसे व्यष्टि का उत्तम मित्र, हितकर्ता, और मार्गदर्शक माना जाता है।

२ समाजवादी राज्य की अधिक से अधिक काम भौपना चाहता है।

३ व्यष्टिवादी अनुषंग के स्वामी स्वतन्त्रता पर बल देते हैं। दूसरी ओर, समाजवादी मानव प्रवृत्ति पर आभावादी दृष्टिकोण रखते हैं, और उसे सारल एक सामाजिक प्राणी मानते हैं।

४ व्यष्टिवादी यह चाहते हैं कि व्यष्टि का अधिक से अधिक काम मुनिश्चित रूप से हो सके। समाजवाद का लक्ष्य है सारे समाज की अधिकतम काम प्राप्त करना। समाजवाद के अनुसार, समाज का बला होने पर व्यष्टि का बला तो हो ही जाता है।

५ व्यष्टिवाद में, उद्योगों का स्वामित्व व्यष्टियों के हाथ में होता है पर, समाजवाद उत्पादन के साधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थक है, या उन पर राज्य का स्वामित्व चाहता है।

६ व्यष्टिवाद (जिसे व्यक्तिगत अर्थ में पूँजीवाद कह सकते हैं) में समाज का धन उन लोगों की व्यष्टियों के हाथों में जमा हो जाता है, जो उत्पादन के साधनों की स्वामी होती हैं। समाजवाद का लक्ष्य समाज के सब सदस्यों में धन का समान वितरण है। उद्योग और व्यापार में होने वाले लाभ अन्त में मूल शिक्षा, स्वास्थ्य-सुविधाओं,

अच्छी सड़को और ऐसी ही अन्य सामाजिक सेवाओं पर खर्च किये जाए। इस प्रकार समाजवाद का लक्ष्य अधिक न्याय प्राप्त कराना है।

७ समाजवाद का लक्ष्य न केवल अर्थ-व्यवस्था को लोकतन्त्रीय बनाना है, बल्कि समाज को और राज्य का भी लोकतन्त्रीय बनाना है। इसका अर्थ यह है कि हर आदमी को राष्ट्रीय धन में हिस्सा पाने का समान अवसर होगा और जिस राज्य में वह रहते हैं, वह बराबरी वालों की साझेदारी होगा। उनमें कोई एक शासक वर्ग और दूसरे सामित लोग नहीं होंगे। यह बराबरी वाला का समान होगा।

आलोचना—शायद कहा जाना है कि समाजवाद सिद्धान्त में बड़ा आकर्षक प्रतीत होता है पर व्यवहार में इसमें कुछ कमियाँ भी होती हैं —

१ कहा जाता है कि यदि राज्य व्यष्टि के लिए सब कुछ कर दे तो व्यष्टि की स्वयं काम करने की प्रवृत्ति और निर्णय की स्वतन्त्रता खत्म हो जाएगी। राज्य लाड़-प्यार करने वाले माता पिता की तरह व्यष्टि के व्यक्तित्व की वृद्धि में रुकावट ही जाएगा।

२ यदि राज्य पर इतने सारे काम लाद दिये गये तो चारों तरफ अक्षता हो जाएगी। राज्य बहुत से काम थोड़े-थोड़े करेगा और पूरी तरह कोई भी काम न कर सकेगा।

३ यह भी कहा जा सकता है कि उद्योगों पर राज्य का स्वामित्व होने पर वस्तुओं की ब्यालीटी में वृद्धि और उत्पादन की लागत में बर्बाद सम्भव नहीं। मजदूर राज्य के नौकर होंगे और इसलिए उन्हें बर्बाद किये जान की चिन्ता न होगी और इस प्रकार उनमें काम से बचने की प्रवृत्ति होगी और उद्योग के प्रबन्धन भी बहुत सावधान नहीं होंगे, क्योंकि हानि होने में उनका अपना कुछ नुकसान नहीं।

इसलिए राज्य के कार्यों के बारे में सही रास्ता इन दोनों सिद्धान्तों के बीच में है।

आधुनिक काल में राज्य के कार्य—ज्यों-ज्यों राज्य का संगठन जटिल होता जाता है, त्यों-त्यों इसके कार्यों की विस्म और मर्यादा भी बढ़ती जाती है। १५० साल पहले राज्य मुख्यतः पुलिस राज्य होता था और इसके कार्य नकारात्मक वर्ग के थे। उसका काम आंतरिक कानून और व्यवस्था तथा बाहरी प्रतिरक्षा तक सीमित था। पर लोकतन्त्र होने पर भगवन्तारी राज्य का विचार पैदा हुआ। लोगों की पशुमुक्ती उन्नति करता राज्य की जिम्मेदारी मानी जाने लगी। राज्य को अपने नागरिकों के मानसिक, शारीरिक और नैतिक बल्यार्थ की वृद्धि करनी चाहिए। आज के जमाने में राज्य अब लोगों का मालिक नहीं रहा। अब यह उनका सबसे बड़ा और विद्वस्त नौकर हो गया है।

कोई प्रारूपिक आधुनिक राज्य जो कार्य करता है या जिन कार्यों के करने की उत्तरे जाता की जाती है, उनका वर्गीकरण निम्नलिखित रीति से किया जा सकता है —

(क) अनिवार्य कार्य

(१) आंतरिक कानून और व्यवस्था बनाए रखना।

(२) बाहरी आक्रमण से प्रतिरक्षा ।

ये कार्य करना प्रत्येक राज्य के लिये जरूरी है । इन कार्यों को राज्य पुलिस और मेना के द्वारा करता है ।

(ख) ऐच्छिक या वैवस्थिक कार्य .

(१) आर्थिक सुख-सुविधाएँ बढ़ाना ।

(२) सामाजिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, और चिकित्सा सम्बन्धी सहायता करना ।

(३) शिक्षा देना ।

(४) सामाजिक उपयोगिता की वस्तुएँ बनाना ।

(५) सामाजिक जीवन में सुधार करना ।

(६) सामाजिक गुरुता की योजनाओं के जरिये रोग, दुकापे और बेरोजगारी से लोगों को निर्विचन करना ।

राज्य चाहे तो इन कार्यों को करे, और न चाहे तो न करे । इनके बारे में राज्य की आवश्यकताओं और साधनों के अनुसार अलग-अलग राज्य में अलग-अलग स्थिति है । तो भी आवश्यक औषत मंगलकारी राज्य इनमें से बितने कार्य करना समझ हो, उतने कार्य करना अपना नैतिक वर्णव्य समझता है ।

अब हम इन कार्यों का एक-एक करके संधेप में वर्णन करेंगे ।

आन्तरिक व्यवस्था—राज्य बनाने के जो प्रमुख कारण थे, उनमें से एक था कानून और व्यवस्था की आवश्यकता । इस प्रकार प्रत्येक राज्य को अपने राज्य क्षेत्र के भीतर लोगों को आपस में लड़ने से रोककर पूर्ण शांति रखनी चाहिए । अपराधियों और अन्य बदमाशों को सजा देनी चाहिए । राज्य के कानून एक व्यक्ति के और दूसरे व्यक्ति के तथा राज्य और व्यक्ति के सम्बन्धों की स्पष्ट रूप से बनाने वाले होने चाहिए । राज्य को दश पुलिस दल और निरक्षर तथा स्वतन्त्र न्यायालय बनाना चाहिए जिसमें कानून तोड़ने वालों को गिरफ्तार किया जा सके । उन पर मुकदमे चलाए जाएँ और उन्हें दण्डित किया जा सके ।

प्रतिरक्षा—राज्य बनाने का एक और मुख्य कारण था बाहरी हमलों से प्रतिरक्षा की आवश्यकता । इस काम के लिए राज्य के पास गुप्तगठित, दश और सैन्य सामान से लैस स्थल सेना, वायु सेना और जल सेना होनी चाहिए । इसे राजनयिक प्रतिनिधियों के आदान-प्रदान द्वारा अन्य राज्यों के साथ मैत्री सम्बन्ध भी रखने चाहिए ।

आर्थिक कार्य—राज्य निम्नलिखित कार्यों द्वारा आर्थिक सुख को बढ़ाना है —

(क) शिक्षाई, खेती और खाद की के अधिक अच्छे तरीकों द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ाना ।

(ख) उद्योग और व्यापार की वृद्धि को बढ़ावा देना ।

(ग) बेरोजगारी और बीमारी की वृद्धि को बढ़ावा देना ।

(घ) रेलवे, सड़कें, वायु मार्ग, सार, टेलीफोन और बेगार आदि संचार तथा परिवहन के अधिक तेज साधनों को बढ़ाना ।

सैती के क्षेत्र में राज्य जमींदारी खत्म करने, चक्कन्दी कराने और निम्नो के नए खतम कराने के लिए कानून बनाता है । यह अपनी मनेषणा सस्थाओं में नये प्रकार के बीजों और खादों का प्रयोग करता है और उनके परिणाम लोगों को बताना है ।

औद्योगिक क्षेत्र में, राज्य विदेशी प्रतियोगिता के मुकाबले में नये उद्योगों को आर्थिक सहायता या सुरक्षण देकर बढ़ावा देता है । यह मालिकों और मजदूरों के सम्बन्धों को नियमित करने के लिए फंड्री कानून बनाता है और इस प्रकार मजदूरों को काम करने की अच्छी अवस्था प्राप्त कराता है । राज्य औद्योगिक मगदों को निबटाने के लिए भी व्यवस्था करता है । राष्ट्रीयकरण द्वारा राज्य स्वयं उत्पादक बन जाता है ।

अपने कल्याण यानी मुद्रा और अन्य देशों की मुद्राओं के नियन्त्रित करके राज्य-व्यापार को विनियमित करता है । संचार के अधिक तेज साधन बनाकर और बैंकिंग तथा बीमा कम्पनियों को बढ़ावा देकर राज्य उद्योग तथा वाणिज्य दोनों को बढ़ावा देता है । राज्य कीमतनियंत्रण और राजस्व की प्रणाली द्वारा कृषि-वस्तुओं और उद्योग वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण को नियंत्रित और विनियमित कर सकता है ।

राज्य के सामाजिक सेवा के कार्य—राज्य के वे काम जो इसकी जनता के जीवन को सुख तथा सुविधाजनक बनाने के लिए किये जाते हैं सामाजिक सेवा या सामाजिक-सेवा कार्य कहलाते हैं । सामाजिक सेवा का लक्ष्य है अज्ञान, बीमारी, गरीबी, बेरोजगारी और असमानता को समाज से दूर करना । किसी देश की सभ्यता और मस्कृति का स्तर इसकी सामाजिक सेवाओं के विस्तार और दक्षता में निर्धारित होता है । उनका विस्तार और दक्षता हर राज्य की वित्तीय स्थिति के अनुसार अलग-अलग होते हैं । अमेरिका जैसा धनी राज्य उन सबकी जिम्मेदारी आसानी से उठा सकता है । सामाजिक सेवाएँ पूर्णतः राज्य के सम्मिलित और प्रबन्ध में चलने वाली या असह स्वैच्छित और अगत राज्य की सहायता से या राज्य के नियंत्रण में चलने वाली हो सकती हैं ।

सामाजिक सेवा की आवश्यकता—गुलम राज्य का अर्थ आराधन मात्र है और उसकी जिम्मेदारी लेने वाले राज्य में सामाजिक सेवाओं की वरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता । पर औद्योगीकरण और लोकनन्द के तेजी में बढ़ने पर सामाजिक सेवाओं की आवश्यकता अधिकाधिक अनुभव की गई । गरीबों के उपबोध और फैक्ट्रियों की स्थापना ने नये नगर और महानगर बना दिये । औद्योगिक नगरों और फैक्ट्रियों में सफाई की हालत बड़ी खराब थी । मालिक लोग मजदूरों को बड़ी मुश्किल से निर्वाह-मजदूरी देते थे । राज्य की कुल आवादी का अधिकांश मजदूर होते थे । मजदूरों की गरीबी, बीमारी और निरक्षरता को और ध्यान रचना सामाजिक या । खासकर

तब जब राज्य लोकनवीय हो। कई कानूनों और बहुत मो सामाजिक सेवाओं द्वारा व्यवस्था की जाये-धीरे-धीरे सुधरने लगी। इस प्रकार भी राज्य की 'सामाजिक सेवा राज्य' का मौखिक नाम शामिल हुआ।

राज्य के सामाजिक सेवा कार्यों में निम्नलिखित ऐच्छिक कार्य भी शामिल हैं :-

१. सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा।
२. शिक्षा।
३. सामाजिक सुधार।
४. लोकनवीय निर्माण कार्य।
५. सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा—सामाजिक सेवा राज्य के विचार से पहले, सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा की व्यवस्था राज्य के कार्यों में शामिल नहीं थी। इन आदर्श स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य या। महामारियाँ पैदा होने से रोकने के लिए लोग कोई सामूहिक प्रयत्न नहीं करने थे। आरोग्य, चिकित्सा, हैजा और अन्य-रोगों जैसी महामारियाँ शुरू होती थीं, तो वे हजारों आदमियों के प्राण ले जाती थीं। लोग इनका कारण ईश्वरीय शक्ति की शक्ति से जोड़ इस तरह मानने की सव्यक्ति देते थे। लोगों के इलाज के लिए लोग शाद-भूत करने वाले हकीमों और वैद्यों के पास जाते थे। लोगों में कहीं-कहीं किसी व्यक्ति से या बच्चों की तरफ से मुक्त औरपाल्य भी होते थे, पर चिकित्सा की इनकी व्यवस्था सब लोगों की आवश्यकता पूरी करने के लिए नाकामी थी, मान करके महामारियों के दिनों में।

आज के जमाने में राज्य के स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों की दो भागों में बाटा जा सकता है :-

१. रोग के निवारण में सम्बन्ध रखने वाले कार्य।
२. रोग हो जाने के बाद उसके इलाज में सम्बन्ध रखने वाले कार्य।

पहले प्रकार के कार्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य कहलाते हैं। निम्नलिखित सब कार्य इस वर्ग में आते हैं

- (१) चिकित्सा, हैजा, टाइफाइड या मालेरिया और टी० बी० के टीके लगाना।
- (२) नाशिया बनाना।

(३) लोगों में पोलियो के लिए क्वीरीन-यूक्त पानी पहुंचाना। इस काम के लिए राज्य सरकार कुछ सुविधाएँ हैं और जवाबदार बनता है।

(४) मर्यादित निरोधकों का नाम यह देना है कि मर्यादों पर शाद लगाई जाए और नाशिया गाए की जाए। नगर का गंद नगर में बाली दूर फेंका जाता है।

(५) मरी बलिआ साक की जाती है और उनके स्थान पर हवादार तथा खुले मकान बनाये जाते हैं।

(६) नगरों में साने-पीने की मिलावटी और बुरी वस्तुओं की बिक्री रोकी जाती है।

(७) बीमारी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए छूट के हस्पताल बनाये जाते हैं, जहाँ छूट के रोगियों को बाकी लोगों से अलग रखा जाता है।

राज्य के चिकित्सा कार्य निम्नलिखित हैं।

(१) आजकल राज्य हस्पताल और औषधालय बनवाता है। उनमें नये से नये उपकरण और दवाइयाँ रखी जाती हैं। रोगों के निदान करने, नुस्खे लिखने और दवाइयाँ देने के लिए ग्रहन्ता-प्राप्त डाक्टर, नर्स और कम्पाउण्डर रखे जाते हैं। सरकारी हस्पतालों में डाक्टर को बार्ड पौख नहीं देनी पड़ती और दवाइयों की खर्च भी नहीं ली जाती।

(२) चिकित्सा और शस्त्र विद्या यानी मजदूरी का ज्ञान देने के लिए और डाक्टरों तथा नर्सों को शिक्षा देने के लिए डाक्टरों स्कूल और कालिज खोले जाते हैं।

(३) राज्य की गवेषणागालाभ नई दवाइयों के बारे में गवेषणाएँ करती है।

शिक्षा—राज्य डाक्टर ही नहीं शिक्षक भी है। शिक्षक के रूप में यह अपने सब नागरिकों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी लेता है। कोई भी खोजनशील राज्य अपनी जनता को उचित शिक्षा दूँए बिना दक्षतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता। इसलिए राज्य को अपने मालिकों तथा नागरिकों को शिक्षा देना जरूरी है। आज के जमाने में सब उन्नत राज्य अपने यहां के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा देते हैं। वे इस काम के लिए स्कूल और कालिज खोलते हैं और उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय स्थापित करते हैं।

सामाजिक सुधार—अपनी जनता के दारिद्र्य और बौद्धिक कल्याण के अलावा राज्य पर जनकी नैतिक प्रगति की भी जिम्मेदारी है। इस प्रकार राज्य अपनी जनता का डाक्टर और शिक्षक होने के अलावा जनकी नैतिक पथ-प्रदर्शक भी है। हर समाज में कुछ अनैतिक और अनुचित प्रथाएँ होती हैं। सती प्रथा, बाल हत्या, बाल विवाह, दहेज, छुआछूत, बेगार, गुलामी, शराब पीना और जुआ खेलना—ये सब सामाजिक दुःखदायक हैं। राज्य को इन्हें रोकना चाहिए, क्योंकि इनमें स्वास्थ्य और सुखी सामाजिक जीवन बनने में बाधा पड़ती है। भारत में ब्रिटिश सामन के दिनों में सती प्रथा, बाल-हत्या, दाम प्रथा और बाल विवाहों के विरुद्ध कानून बनाए गए थे। भारतीय गणराज्य के संविधान ने बेमार और छुआछूत को बंद कानूनी घोषित कर दिया है पर यह शर्त रखता है कि राज्य अच्छे सामाजिक सुधार नहीं कर सकता, यद्यपि उसे जागे-जागे चलना पड़ेगा। सामाजिक सुधारों की बहुत कुछ सफलता लोगों द्वारा अपने-आप बनाये गये ऐच्छिक साहस्यों पर निर्भर है।

सामाजिक सुरक्षा—अन्धे भगलकारी राज्य में नागरिकों को गरीबी, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और दुर्घटनाओं से होने वाली निर्दोषता से भी सुरक्षा प्रदान

करनी होगी । सामाजिक बीमा योजनाओं की प्रणाली द्वारा राज्य इन सब क्षेत्रों में अपने ऊपर बहुत विविध बोझ दिना जाने लोगों को मजदूरों का एकता है । अब उससे राग्यों में सामाजिक बीमा प्रणाली भी शुरू है । इंग्लैंड में रोग और बेकारी से बचाव करने के लिए १९११ में अनिवार्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा अधिनियम पास किया गया था । प्रत्येक मजदूर को कानून अपनी मजदूरी का एक हिस्सा एक निधि में जमा कराना होगा । मालिक और राज्य भी इसमें अपना हिस्सा देंगे । बीमारी या बेकारी होने पर मजदूर का इस रुपये में से सहायता दी जाएगी है । इसी प्रकार दुर्घटनाओं की अवस्था में दुर्घटना बीमा की प्रणाली बनाई गई है । बड़े आदमियों को सहायता देने की प्रणाली पहले स्वीडिश में शुरू हुई । १९०८ में ब्रिटिश संसद में भी बुढ़ापा वेधन कानून पास कर दिया । इस कानून के अर्धीन ७० वर्षों का इसमें अधिक के सब ब्रिटिश प्रवाजनों की मिली आयदनी ११। पौंड से कम होने पर ८ पौंड प्रति सप्ताह देने की व्यवस्था की गई ।

लोकोपयोगी सेवाएँ—इनमें निम्नलिखित चीजें शामिल हैं —

- (क) रेल, मछल, नदी, समुद्र और वायु के रास्ते परिवहन सेवाएँ ।
- (ख) डाक, गार और टेलीफोन प्रणाली ।
- (ग) बिजली, गैस और पानी का समरण ।

लोकोपयोगी सेवाओं के लाभ—(१) परिवहन सेवाएँ तथा तार टेलीफोन आदि संचार के क्षेत्र साधन लोगों के जीवन की अधिक आरामदेह बना देते हैं । दूर-दूर जाने में होने वाली भौतिक कष्टान, रेलों, बसों, ट्रायो और विमानों से यात्रा में गहरी हो रही । यात्रा अधिक सुरक्षित हो जाती है । डाक और तार साधन वेमा लेजर एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी सबर पहुँचा देते हैं । मूळ पत्र लोगों को बहुत से लोगों से बचता है । नेत्र की जगह बिजली का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए अधिक अच्छा है । रेडियो के मंत्रीमंत्र कार्यक्रम पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने हैं ।

(२) परिवहन के इन साधनों का होना देश की आर्थिक प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है । इनके द्वारा नौमना, लोहा और अनाज जैसी चीजें और बड़ी कस्तुएँ दूर-दूर स्थानों पर ले जाई जा सकती हैं । विमान अपना सान सबसे अधिक आवश्यकता की जगह सेजकर अच्छी से अच्छी कामग हासिल कर सकता है । परिवहन के इन साधनों के कारण जगल कम विनाशकारी हो गए हैं, क्योंकि अब अधिकता वाले क्षेत्रों में अनाज जमाओं में अकाल-प्रति इसके में ले जाया जा सकता है । पैकटरी मालिक कच्चा सामान निश्चित रूप से मिलने रहने और निमित्त बस्तुएँ जल्दी घर-घर पहुँचा दिये जाने के कारण अपनी धर्माँ चातु रख सकता है । परिवहन के क्षेत्र साधनों के कारण ही बिनी देशों को एक ही प्रकार का उत्पादन कर रहने की मुविधा हो गई है । परिवहन के अच्छे साधन न होने एक शाल से दूसरे शाल और एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार असम्भव हो जाएगा । सब तो यह है कि संचार के क्षेत्र साधनों

में सारे मसालों को एक बाजार बना दिया है।

(३) लोकसेवाओं में सेवाओं का मसूचित्र महत्व भी है। गन्धर्व और परिवहन के क्षेत्रों में सेवाओं के परिणामस्वरूप एक देश के लोगों में और मसालों के लोगों में एक दूसरे में साथ अधिक मिलना-जुलना हो सकता है। बसा, दूध और रेशम में हमें अलग-अलग जगहों के अलग-अलग राष्ट्रीय और मसूचित्रों के सब जगहों के लोग मिलने हैं। मसूचित्रों के आदान-प्रदान के लोग का जीवन सम्पन्न होता है और उनमें अधिक मोहार्थ और शान्ति पैदा होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सब लोकसेवाओं में सेवाएँ एक न एक दृष्टिकोण से परस्पर सम्बन्धित हैं। अतः सर्वत्र यह पैदा होता है कि क्या वे सेवाएँ निजी उपकरण के लिए छोड़ दी जानी चाहिए, या वे राज्य के स्वामित्व और प्रबन्ध में रहनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में इन सेवाओं के महत्व के कारण वे प्रायः राज्य के स्वामित्व और प्रबन्ध में ही होती हैं। परन्तु निजी उपकरण का भी काम करने दिया जाता है, जैसे, बगीचे, दूध, जल-संचरण, और बिजली की प्रवस्था में, वहाँ राज्य उनके काम संचालन के लिए नियम और धन बना देता है। इन क्षेत्रों में प्रतिदायिता अत्यन्त ही कम होती है। और इस प्रकार, सब जगह किसी बम्पनी या निवास की सरकार की सफल देख-रेख के अधीन एकाधिकार दे दिया जाता है। इन सेवाओं में निजी उपकरण के विच्छेद से मुक्ति है —

१. इन सेवाओं का संचरण नियमित और दृढ़ होना चाहिए। इन क्षेत्रों में जरा सी भी बाधा पड़ने से सारे राष्ट्र को भारी हानि हो सकती है। परिणामस्वरूप इन सेवाओं में निजी उपकरण पूर्णतः होमकारण नहीं हो सकता। यदि निजी संचालन या बम्पनी इन सेवाओं की कीमत बहुत अधिक बढ़ाकर गरीबों को इन सेवाओं का उपयोग से वंचित हो सकती है।

२. रेल, डाक और तार सेवाएँ महत्वपूर्ण सेवाएँ हैं। उनमें बहुत अधिक पैसा लगाता पड़ता है। इसलिए निजी, एक आदमी या बम्पनी के लिए उनका धन प्राप्त करना पसन्द नहीं आता। व्यवस्था करना यथावत् है।

३. मसालों में बड़ी मात्रा में पूँजी लगाकर भी जीवन कुछ लाभ मिलने की सम्भावना नहीं होती। इसलिए यदि निजी आदमी या बम्पनी उनका निर्माण करना पसन्द नहीं करता।

४. रेल और मसालों आदि के समय पैसे को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए बर्तन महत्वपूर्ण है। इस कारण भी उन निजी उपकरण और निरवयव के अर्थ में करना मुश्किल होता है।

राज्य का लक्ष्य या प्रयोजन

राज्य के आवश्यक गुणों उद्देश्य, प्रवृत्ति, और बाह्य पर विचार करने पर बाद में हमें यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि राज्य में किस लक्ष्य की पूर्ति का अर्थ है। समय-समय पर अनेक लोग न तो राज्य के लिए अर्थ-व्यवस्था लक्ष्य समझते हैं।

कानून और व्यवस्था बनाये रखना, अधिकतम, मर्यादा का अधिकतम मुख, सामाजिक सेवा, न्याय और प्रगति—ये सब राज्य के लिये उपयुक्त लक्ष्य मुझाए गये हैं। मोटे तौर से कहें तो राज्य के लक्ष्य सम्बन्धी विचारों को दो वर्गों में बाटा जा सकता है —

१ वे लोग जो राज्य को अपने आप में एक लक्ष्य समझते हैं।

२ वे लोग जो राज्य को एक लक्ष्य का प्राप्ति का साधन समझते हैं।

जो लोग राज्य को एक लक्ष्य का साधन समझते हैं, उन्हें फिर दो भागों में बाँटा जा सकता है —

(क) कुछ लोग राज्य को वैयक्तिक या सामाजिक कल्याण की सिद्धि का दुरा साधन समझते हैं।

(ख) दूसरे लोग राज्य को व्यक्ति और समाज दोनों की भलाई करने के लिए एकमात्र उपयुक्त साधन समझते हैं।

राज्य एक लक्ष्य के रूप में—प्राचीन यूनान के लोगों के लिए राज्य अपने-आप में एक साध्य या लक्ष्य था। यूनान के नगर-राज्य नागरिक के सम्पूर्ण व्यक्तिगत को अपने अधीन रखते थे। आदर्श, समाज के लिये ही जीता और मरता था। इन्हीं विचारों को १९वीं सदी में जर्मन आदर्शवादियों ने फिर सामने रखा। उनके अनुसार, राज्य अलग-अलग नागरिक के सर्वोत्तम लक्ष्य का प्रतिनिधि है। इसलिए आदर्श का अधिकतम भलाई इसी बात में है कि वह पूरी तरह राज्य की आज्ञा माने, उसे हमेशा अपने अह को राज्य के अह के तौर पर उठाने का यत्न करना चाहिए। राज्य व्यक्ति के लिए आदर्श है। यह व्यक्ति के जीवन का साध्य है। इन प्रकार आदर्शवादियों के अनुसार, राज्य की कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं करता। उसे तो अपने व्यक्तिगतों के कार्यों का मार्ग प्रदर्शन, नियंत्रण और विनियमन करना है जिससे इसका अपना अधिक से अधिक भलाई हो।

राज्य लक्ष्य-सिद्धि का दुरा साधन है—व्यक्तिवाद, अराजकतावादी और साम्यवादी, मार्क्स, एम्मुनस्ट आदमी का समाज की हित सिद्धि के लिए राज्य को दुरा साधन समझते हैं। व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। वे इसे खत्म नहीं करना चाहते। वे राज्य के भीतर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए और चाहते हैं। हमलों में इसकी रक्षा के लिए हैं, इसे बनाए रखते हैं। दूसरी ओर अराजकतावादी के लिए राज्य का कोई उपयोग नहीं है। उनके अनुसार, राज्य बल को निरूपित करता है और इसलिए यह कोई भलाई नहीं कर सकता। नैतिक जीवन बल तो नहीं बनाया जा सकता। साम्यवाद के पिता कार्ल मार्क्स ने राज्य को गरीबों के शोषण के लिए बनियों का हथियार बताया है।

राज्य लक्ष्य-सिद्धि का अच्छा साधन है—अरस्तू का विश्वास था कि अच्छा जीवन राज्य में ही सम्भव है। शोचिन राज्य की एक सगुण्य पद्धति समझता था। अराजकतावादी राज्य की अधिकतम व्यक्तिगतों के लिये अधिकतम सुख प्राप्त करने का साधन समझते थे। समाजवादी राज्य को समाज की सब तरह की भलाई के लिए सबसे अधिक उपयुक्त साधन समझते हैं।

राज्य का अमली सत्य—इस प्रकार सत्यता मलता है कि अकेली दृष्टि का मूल्य सारे समाज का सत्य और सत्य राज्य का मूल्य, धारी-वारी, राज्य के सत्य सत्य सत्य हैं। पर हमें याद रखना चाहिए कि न तो अकेली दृष्टि का लाभ, न अकेला सामाजिक कल्याण और न अकेला राज्य का अला ही राज्य के हान का लक्ष्य या प्रयोजन हो सकता है। राज्य साधन भी है और साध्य भी। यह एव एसा साधन है जिसके द्वारा दृष्टि का अधिकतम विनाश और समाज का अधिकतम भला हो सकता है। राज्य वही तब अपने आप में एव लक्ष्य है, जहाँ तब यह अपने नागरिकों की भाँति, पंक्तिपंक्ति के कल्याण पर भी विचार करता है।

मानंद ने राज्य के तीन लक्ष्य सुझाए हैं, जो बहुत ठीक सुझाए गए हैं —

(१) प्रथम तो, राज्य को दृष्टि के अच्छे से अच्छे विकास के लिए उचित अवस्थाएँ पैदा करने उद्योगों सहायता करने चाहिए।

(२) दूसरे, इसे समाज और राज्य के सदस्यों के हित में दृष्टियों के जो सामूहिक हित हैं, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए।

(३) तीसरे, इस अपनी गतिविधियों और अपने नागरिकों की गतिविधियों को ऐसे चलाना चाहिए कि सारा मानव जाति गति और प्रगति की ओर बढ़े।

सारांश

राज्य के कार्य—राज्य के कार्यों के बारे में दो चरम विचार हैं —

(१) दृष्टिवादी विचार—राज्य एव आवश्यक बुलाई है। इसलिए इसे कम से कम काम, अपांश भीतरी अराजकता और बाहरी हमले रोकना, हो दिया जाना चाहिए, और अन्य बातों में आदमी अपने कल्याण की प्राप्ति के लिए बिल्कुल आजाद रहना चाहिए। राज्य दृष्टि के लिए कोई विधायक मलाई नहीं कर सकता।

दृष्टिवादी भीम दृष्टि की योग्यता के बारे में अत्यधिक आशावादी है। वास्तव में दृष्टि को मार्ग प्रदर्शन की आवश्यकता है और मजबूत राज्य से अच्छा मित्र, सलाहकार, सेवक और रहनुमा कोई नहीं हो सकता। व्यापार और उद्योग में किसी तरह की दखलबाजी न होने से जनता के अधिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को हानि होने की संभावना है।

(२) समाजवादी विचार—(१) राज्य आदमी का सबसे अच्छा मित्र है। वह निश्चित रूप से मलाई करता है। इसे अधिक से अधिक कार्य देने चाहिए। (२) समाजवाद का लक्ष्य सारे समाज का अधिकतम लाभ है। (३) समाजवाद उत्पादन के साधनों के वैयक्तिक स्वामित्व का विरोधी और राष्ट्रीयकरण का समर्थक है। (४) समाजवाद सम्पत्ति का समाज वितरण करता है। इसलिए यह अधिक औद्योगिक और न्यायसंगत है।

पर समाजवाद सिद्धान्त रूप में जितना आकर्षक है, उतना व्यवहार में नहीं। व्यवहार की दृष्टि से, इसमें कुछ कमजोरियाँ हैं —

(१) राज्य को बहुत से बाध गोंध देने से सब कामों में दमो जाने की संभावना है ।

(२) राष्ट्रीयकरण होने पर अन्धरी और गस्ती वस्तुएँ नहीं बनाई जा सकीं ।

(३) कहा जाता है कि महाजवाहर आदमों की स्वयं अपने करने की भावना को और नियंत्रण की स्वायत्तता को नष्ट कर देगा ।

राज्य के कामें

(क) अनिवार्य काम :

(१) भीतरी कानून व्यवस्था बनाये रखना ।

(२) बाहरी आक्रमण से रक्षण ।

(ख) ऐच्छिक कार्य :

(१) कृषि उत्पादन और उपोग, व्यापार, बैंकिंग और बीमे को बढ़ावा देकर आर्थिक उन्नयन करना ।

(२) सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, और विज्जिता की व्यवस्था करना ।

(३) शिक्षा देना ।

(४) रेल और सड़क, डाक, नगर और टेलीफोन, बिजली, गैस और पानी आदि सार्वजनिक उपयोगिता के कामें करना ।

(५) सटी प्रथा, बाण हत्या, बाल विवाह, खंज, छुआछूत, बेगार, दामना, मराठ और जुग आदि कुछ कर्नातक और अनुचित सामाजिक प्रथाओं को दूर करके सामाजिक जीवन में सुधार करना ।

(६) लोगों को रोग, दुर्घटन और बेरोजगारी से निरिपन्त करने के लिये सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाना ।

राज्य का लक्ष्य या प्रयोजन—राज्य के राज्य के सम्बन्ध में जो विचार हैं, उन्हें सोंठे तौर से दो वर्गों में बांटा जा सकता है :-

(१) वे लोग जो राज्य की अपने आप में एक लक्ष्य या साध्य समझते हैं ।

(२) वे लोग जो राज्य को एक साध्य या साधन समझते हैं ।

राज्य एक साध्य है—आचीन ग्रीक लोगों और आधुनिक काल में जर्मन आदर्शवादियों के अनुसार, आदमों को राज्य के लिए होना और मरना चाहिए क्योंकि राज्य अपने आप में एक लक्ष्य है । इसलिए व्यक्ति का ध्यान इसी में है कि वह पूरी तरह से राज्य की आज्ञा का पालन करे ।

राज्य एक लक्ष्य का अच्छा साधन है—उपयोगितावादी राज्य का अधिकतम लोगो के लिए अधिकतम सुख का साधन समझने हैं। समाजवादी समाज को सब तरह से प्रगति करने के लिए सबसे अच्छा साधन मानने हैं।

सच्चा लक्ष्य—मानव के अनुसार, राज्य के तीन लक्ष्य होने चाहिए

- १ व्यक्ति का कल्याण।
- २ सारे समाज का कल्याण।
- ३ सारी मानव जाति का कल्याण।

प्रश्न

QUESTIONS

१ सरकार के कार्यों के धारे में व्यक्तिवादी और समाजवादी विचार लिखिए।

(५० वि० सितम्बर, १९५२)

1 State the views of the Individualistic and Socialist schools relating to the functions of government (P U Sep., 1952)

२ किसी आधुनिक राज्य के मुख्य कार्य क्या हैं? किस प्रकार का राज्य उन्हें अधिकतम सफलता से कर सकता है।

2 What are the main functions of a modern state? What kind of state can perform them most efficiently?

३ राज्य के सामाजिक सेवा कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

3 Give a brief account of the social service functions of the State

४ लोक-उपयोगी सेवाओं से आप क्या समझते हैं? वे राज्य के प्रथम और नियंत्रण में क्यों रहनी चाहिए?

4 What do you understand by public utility services? Why should they be managed or controlled by the state?

५ सामाजिक सुधार के प्रसंग में राज्य के कर्तव्य को विवेचन कीजिए। क्या मनुष्य को नैतिक बनाना राज्य का कर्तव्य है?

5 Examine the role of the state in relation to social reform? Is it the duty of the state to make man moral?

६ सामाजिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? क्या गरीबी, बीमारी और बेरोजगारी को दूर करना राज्य का कर्तव्य है?

6 What do you understand by 'social security'? Is it the duty of the state to remove poverty, unemployment and disease?

७ आधुनिक काल में राज्य के कर्तव्यों को देखते हुए यह सिद्ध कीजिए कि आज का राज्य भगल राज्य है, पुलिस राज्य नहीं।

7 In the light of functions of the state in modern times prove that the state of today is a welfare and not a police state.

- ८ राज्य के लक्ष्य के बारे में विभिन्न विचारों की संक्षेप में विवेचना कीजिए ।
 8 *Examine briefly the views regarding the end of the state*
 ९ आपकी राय में राज्य का सच्चा लक्ष्य क्या है ?
 9 *What in your opinion is the true end of the state ?*
 १० राज्य के लक्ष्य क्या हैं ? (पं० दि० सितम्बर, १९५१)
 10 *What are the ends of the state ?* (P. U. Sep., 1951)

शिक्षा

शिक्षा कितने कहते हैं—शिक्षा शब्द की बहुत सी परिभाषाएँ की गई हैं। गार्टर ऑक्सफोर्ड इण्डियन डिक्शनरी में इसकी यह परिभाषा है कि "जीवन के काम की तय्यारी में छोटे बच्चा को (और व्याप्ति द्वारा बड़े को) सी जाने वाली व्यवस्थित सिखलाई, अध्यापन या प्रशिक्षण।" वेबस्टर के शब्दकोश में शिक्षा की यह परिभाषा है, "व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक परिवर्द्धन कराने वाली मौख और प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त जानकारी और गुण का समुच्चय।"

उपर्युक्त दो तथा अन्य बहुत सी परिभाषाओं से निम्नलिखित बाने स्पष्ट हो जाती हैं —

१ शिक्षा मनुष्य के स्वाभाविक विज्ञान के बजाय उन्ने एवं विमर्शित (deliberate) निर्देशन और प्रशिक्षण है।

२ यह विमर्शित निर्देशन और प्रशिक्षण हमेशा किसी दत्त मानव समाज के आदर्शों के प्रसंग में होता है। मानव समाज के बड़े सदस्य अपने छोटी बने अपने जीवना-दर्शों के अनुसार ही प्रशिक्षित करते हैं।

३ शिक्षा में आदमी का सर्वनामस्वी विवास अभिप्रेत है। इसका अर्थ सिर्फ बुद्धि का प्रशिक्षण नहीं है। बौद्धिक विवास के अलावा शिक्षा का लक्ष्य भौतिक और नैतिक विवास भी है।

४ शिक्षा जीवन भर चलने वाला उपक्रम है जिसमें आदमी एव ही समय कई चीजें सीखना है और कई चीजें भूलना है। शिक्षा बचपन के साथ समाप्त नहीं हो जाती। बूढ़े हो जाने पर भी शिक्षा का मिलमिल चक्का रहना है।

शिक्षा के लक्ष्य—शिक्षा के लक्ष्यो के बारे में बड़ा विवाद है, और यह बहुत समय से चलता रहा है। कुछ लोग उदार शिक्षा के पक्षपाती हैं, और कुछ लोग व्यावसायिक या श्रमिक शिक्षा या प्रशिक्षण के पक्षपाती हैं। उदार शिक्षा के पक्षपातियों का लक्ष्य है लोग के शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास द्वारा पूर्ण व्यक्ति पैदा करना। व्यावसायिक शिक्षा के समर्थकों का मुख्य लक्ष्य किसी राजगार, कल या दस्तकारी में लोगों को प्रशिक्षित करके उन्हे उपयोगी बनाना है। पर आज की दुनिया में हर आदमी नागरिक भी अवश्य होता है इसलिए अच्छी शिक्षा प्रणाली के ये तीन लक्ष्य होने चाहिए —

१ प्रथम, शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति की प्रकृति की गुप्त शक्तियों और योग्यताओं का विकास करना होना चाहिए। दूसरा अर्थ होगा आदमी का पूर्ण शारीरिक, बौद्धिक

और नैतिक विकास । इस प्रकार शिक्षा सर्वथा उदार होनी चाहिए ।

२ दूसरे, शिक्षा व्यावसायिक होनी चाहिए, इसमें हर लड़का या लड़की अपनी जीविका कमाने योग्य हो जाना चाहिए ।

३ तीसरे, आधुनिक खोजतन्त्रीय युग में शिक्षा का महत्व नागरिकता का प्रशिक्षण देना भी होना चाहिए । 'व्यावसायिक शिक्षा नागरिक' को उपयोगी बनाने में सिर्फ एक पटक होंगे । आदमी उपयोगी नागरिक या अच्छा नागरिक तभी कहलाएगा जब उसमें कुछ नागरिक गुण होंगे ।

शिक्षा की मजिद—बच्चे के जीवन को छोटे नीर में तीन मुख्य अवस्थाओं में बाटा जा सकता है —

(१) बाल्यकाल—५ या ६ वर्ष की आयु तक ।

(२) रिपोराइस—१० से १४ वर्ष तक की आयु तक ।

(३) तृत्यावस्था—१४ से १८ वर्ष तक की आयु तक ।

बालकों की शिक्षा—बाल्यावस्था में बच्चा घरों और नर्सरी स्कूलों में उचित शिक्षा पा सकता है । इस अवस्था में बच्चे को ठीक स्वास्थ्य बनाए रखने में अलावा, अच्छा चरित्र निर्माण करने की आवश्यकता होती है । उसकी आदतें, शिष्टाचार और कथिया दब गमम बनाई जानी हैं । छोटे बच्चों के लिए बुद्धि के प्रशिक्षण का महत्व भी है पर उसकी जानकारी का दावरा अधिक से अधिक बिल्तुन हो सकता है ।

बालकों की शिक्षा में घर का स्थान—आदमी घर बच्चे के लिए सर्वोत्तम शिक्षा-स्थल है । बच्चा प्रेम से अधिक मौलता है और बच्चे से उनके अपने माता पिता के अनावा कोई और आदमी अधिक प्रेम से व्यवहार नहीं कर सकता । पर प्रेम के नाम-नाम बच्चे की प्रकृति को ठीक ठीक समझना चाहिए और उचित प्रकार का अनुशासन रहना चाहिए बिना अनुशासन का बहुत अधिक अनुराग बच्चे की विगाह देगा । इसी प्रकार बहुत अधिक अनुशासन बच्चे से स्वयं कर्तृत्व और मौलिकता की वृद्धि को रोक देता है । यह बड़े महत्व की बात है कि माता पिता को अपने बच्चों पर आने से बहर न हो जाना चाहिए । बच्चे में अनुकरण की बहुत प्रवृत्ति होती है । माता-पिता को उन सब कामों में भी सहायता चाहिए जिनसे उनके बच्चों पर गलत असर पड़ सकता है । इस प्रकार बच्चों का प्रशिक्षण बड़ा महत्व का है । उनकी प्रकृति को ठीक से समझना भी आसान काम नहीं । इसलिए बच्चे की उचित शिक्षा के लिए होमिपारी में काम करने की जरूरत है । माता-पिता माता पिता का व्यस्त जीवन उन्हें अपने बच्चों को और ध्यान नहीं देने देता । इसलिए बच्चों की शिक्षा माता या तम में कम कुछ हद तक, नर्सरी स्कूलों में होनी चाहिए ।

नर्सरी स्कूल—नर्सरी स्कूलों के खिलाफ एक यही बात कही जा सकती है कि उनकी शिक्षा बड़ी खर्चीली है और उनमें माता पिता जैसा अनुशासन नहीं हो सकता । अग्यथा, नर्सरी स्कूलों की पद्धति राष्ट्र के लिए बड़ी लाभदायक है । बच्चों की कुछ आवश्यकताएँ घर की अपेक्षा स्कूल में बहुत अच्छी तरह पूरी हो सकती हैं । खेलने के लिए खुली हवा और उचित तथा अनुचित सुरास स्कूल में बहुत अच्छी तरह मिल

सकती है। शोर करने की आजादी बच्चों के लिए बड़ी आवश्यक है। घरों में शोर करने वाले बच्चों को बड़े आदमी बड़ी गुमीबत समझते हैं। बच्चों की पूर्ण वृद्धि के लिए लगभग उसी उम्र के बच्चों का साथ भी परम आवश्यक है। इस आवश्यकता की पूर्ति धनी माता-पिता भी नहीं कर सकते। अन्तिम बात यह है कि बच्चों के मीसने और मनोरंजन के लिए उचित वातावरण नर्सरी स्कूलों में बनाया जा सकता है। इस प्रकार घर की शिक्षा की पूर्ति नर्सरी स्कूलों में शिक्षा देकर करनी चाहिए।

दूसरी मजिल—स्कूलों में शिक्षा—बट्टेण्ड रमल के अनुसार, ६ वर्ष की आयु तक चरित्र का निर्माण अधिवनर पूरा हो जाता है। उससे बाद बच्चों का बुरे वातावरण से बचाने की ही जरूरत रहती है। बुरे वातावरण मनुष्य के चरित्र को उससे जीवन की किसी भी मजिल में प्रभावित कर सकते हैं। स्कूल की शिक्षा के तीन मुख्य पहलू हैं, अर्थात् बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक।

बौद्धिक—दूसरी मजिल में पहले तो बौद्धिक प्रगति पर जोर देना चाहिए। छात्रों को सब तरह का ज्ञान पाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ग्रीक विषयों का ज्ञान भी उनसे छिपाना नहीं चाहिए। कुछ गुण, जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए बिल्कुल आवश्यक हैं, छात्रों में पैदा करने चाहिए। उदाहरणार्थ धैर्य, उद्योग, एकाग्रता, यथार्थता और खुले मनस्विता से विचार करना। गणित, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, आरम्भिक अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य शास्त्र या हाईजीन और आरम्भिक विज्ञान की शिक्षा इस उम्र में सब छात्रों के लिए आवश्यक समझी जाती है।

शारीरिक—बुद्धि का प्रशिक्षण तब तक अधूरा रहेगा, जब तक साथ ही शरीर की भी प्रशिक्षण न किया जाए। स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर परम आवश्यक है। कोई भी अच्छी शिक्षा प्रणाली बमरत और खेल रूढ़ के महत्व को कम नहीं समझ सकती। खेल और रूढ़ से जहां स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वहां छात्रों में कई नागरिक गुण भी पैदा होते हैं। अनुशासन, नेतृत्व, सहयोग और शितादीपन आदि गुण खेल के मैदान में ही अच्छी तरह गीले जाते हैं। प्राचीन ग्रीस में त्रिमनास्तिक और सैनिक प्रशिक्षण शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग होते थे। आज के जमाने में भी सैनिक प्रशिक्षण का महत्व अधिकाधिक समझा जा रहा है। विश्वविद्यालय सैनिक प्रशिक्षण दल और राष्ट्रीय सैन्य शिक्षाओं दल फिर सामने आ रहे हैं।

नैतिक—नैतिक शिक्षा शारीरिक और बौद्धिक शिक्षा से निकट सम्बन्ध रखती है। इसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। छात्रों को अपने साधियों के साथ व्यवहार करते हुए आत्म नियंत्रण, ईमानदारी, सहिष्णुता, न्याय, सम्मान, और दया की शिक्षा देनी चाहिए। इस प्रकार, किसी शिक्षा प्रणाली से सिर्फ विद्यार्थी कीड़े न पैदा होने चाहिए। निरी बौद्धिक शिक्षा छात्र के और पहलुओं को दबाकर सिर्फ एक पहलू को विकसित करती है। दूसरे पक्षों में, शिक्षा उदार होनी चाहिए, जिसका लक्ष्य छात्र के सब पहलुओं का विकास करना हो।

ध्यातृसार्वभौमिक शिक्षा—सामाजिक जीवन में आर्थिक बातों का महत्व बढ़ जाने

के कारण भव देशों में लोकमत व्यावसायिक शिक्षा ने अधिक प्रथम में होना जाता है । यह कहा जाता है कि निरी वितायी शिक्षा अधिकतर छात्रों के लिए गुप्त और अरविष्कर होती है । यह आदमी को जीवन में किसी व्यवसाय के लिए भी तैयार नहीं करती और इस तरह बेकारी और बेरोजी बनाने वाली बनाई जाती है । इसलिए, बहुत से लोग यह कहते हैं कि पढ़ाई किसी बुनियादी दम्नकारी के साथ-साथ चलनी चाहिए । अनुभव से जो यह सिद्ध हुआ है कि अधिकतर छात्रों के लिए वितायी पढ़ाई अरविष्कर होती है और इस तरह राष्ट्रीय तर्जों की बड़ी बरबादी होती है । यदि विभिन्न धर्मों, दम्नकारियों या पेशों के लिए छात्रों की रचि का पना लगाने का यत्न किया जाए तो बड़ा अच्छा हो । यह भव है कि १४ वर्ष की आयु तक प्रत्येक बच्चे को वितायी शिक्षा मिलनी चाहिए, पर इस अवस्था में छात्र की रचि का पना लगा लेना चाहिए और वितायी पढ़ाई के साथ-साथ उसे किसी काम दस्तकारी, व्यापार या पेशे में, जो उसकी रचि और योग्यता के अनुसार हो, प्रारम्भ देना चाहिए । किसी काम विषय का विशेष प्रशिक्षण बाद में, उस प्रयोजन के लिए बनाए गए विशेष शिक्षा केंद्रों में दिया जा सकता है । जिन छात्रों में वितायी शिक्षा की रचि दिखाई दे, उन्हें विश्वविद्यालय में भी उसी में चलने देना चाहिए । हर मूल में शिक्षा का काम १८ या २० वर्ष की आयु तक पूरा हो गया कहा जा सकता है ।

व्यावसायिक या शिल्पिक शिक्षा व्यक्ति के दृष्टिकोण में ही आवश्यक नहीं, बल्कि यह देश की आर्थिक प्रगति के लिए भी परम आवश्यक है । बड़े पैमाने के उद्योग मुख्यतः कृषक शिल्पिक नियमित रूप से चलाने रखने पर निर्भर होते हैं । वैकल्पिक शिक्षा में वाणिज्यिक और कृषि की शिक्षा भी शामिल है ।

तीसरी मजिल उच्च शिक्षा—विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा निर्णय उन्हें दी जानी चाहिए जो इसके उपयुक्त हो । बहुत कम के अनुसार विश्वविद्यालयों को दो प्रयोजन होने चाहिए—

१. कानून, चिकित्सा आदि कुछ पेशों के लिए पुरुषों और स्त्रियों को प्रशिक्षित करना ।

२. तात्कालिक उपयोगिता का बिना विचार किये ज्ञान और गवेषणा के मार्ग पर चलने जाना ।

इस प्रकार विश्वविद्यालय कुछ छोटे से चुने हुए छात्रों के लिए उपयुक्त होते हैं । कुछ लोग उच्च शिक्षा की बुराई करते हैं और इसे विप्लव के कारण बताते हैं । पर हमें याद रखना चाहिए कि उच्च शिक्षा का अपना ही मूल्य है । यह हमारे दृष्टिकोण और मन को विस्तृत करता है, आत्मा को सम्पन्न करता है और मन को शान्ति देती है । बिना उच्च शिक्षा के विश्व के रहस्य हमारे लिए रहस्य ही बने रहेंगे । विज्ञान, कला और दर्शन की कोई तकलीफ नहीं होगी । हमें बिना आदमी प्रकृति का स्वामी होने के बराबर दास होना ।

नागरिकता के लिए शिक्षा—स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय के जीवन का

एक महत्वपूर्ण लक्ष्य सामाजिक और नागरिक प्रशिक्षण के लिए सबको प्रस्तुत करना होना चाहिए। विनाशो शिक्षा के अलावा या नागरिकों के लक्ष्य और आलोचना के गुणों का विकास करती है, नागरिकता के प्रशिक्षण में पाठ्येतर कार्यों (extracurricular activities) के महत्व का भुगतान नहीं चाहिए। १२ वर्ष की आयु तक बालबाली, छात्र-नृत्य, अभिनय गेज, बमरस यात्रा और शोक की चीजें सबसे अधिक उपयुक्त हैं। इनके बाद की उम्र में स्वातंत्र्य, वाद विवाद, नाटक, महकरी मोमाइटिया, धाम सुधार मोमाइटिया और ऐसी ही अन्य मोमाइटिया बनावे की शिक्षा छात्रों को मिलनी चाहिए। पाठ्येतर कार्यों में छात्रों का प्राचीन समय में काम का काम मिल जाता है। काम इस अर्थ में होता है कि इनमें आदमी का व्यक्तित्व में वृद्धि होती है। छात्रों की परिपक्व और विधान मन्त्रण छात्रों को स्वातंत्र्य का प्रशिक्षण देती है। उन्हें नैतिक के प्रशिक्षण के अलावा, आत्म नियंत्रण, गहवाय और स्पष्ट-बर्तन के शिक्षा मिलनी है। परिवार और वाद-विवाद मन्त्रण गिनत और बाल्य में आत्मा-मिथ्यता का विकास करती है। यात्राओं में शरीर बनना है, ज्ञान की वृद्धि होती है और अनुभव का निवारण होता है। कर्म और मन्त्रण गगहन और प्रबंध का प्रयास गिरा देता है। उनमें स्पष्ट बर्तन, मिन्नकारी, गहवाय और बाल्य के गिनत सम्मान का भी विकास होता है। हमने पहले बताया है कि नागरिकता के लिए इन सभी प्रशिक्षण में वेद-बुद्ध का क्या महत्व है। सामाजिक गवा-गगहन, निस्वार्थ गवा और मानव अनुभव का पाठ पढ़ाने हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई नागरिक गुण पैदा होते हैं और नागरिकता की उत्तम शिक्षा मिलती है।

प्रौढ़ शिक्षा—प्रौढ़ शिक्षा का लक्ष्य राज्य के प्रत्येक सदस्य का दम और उपयोगी नागरिक बनाना है। प्रौढ़ों को शिक्षित करने की आवश्यकता लक्ष्यकारी राज्य में और भी अधिक है, क्योंकि इसकी मफ्यता और दमता इसके लोग का ज्ञान पर निर्भर है। शिक्षा लोग के दुष्टिकरण को बसा करके उनकी बुद्धि तथा लक्ष्यशक्ति का तेज परको उन्हें उपयोगी नागरिक बनाने हैं। इसके मन्त्रण प्रोत्साहन का शिक्षित करने का लक्ष्य उन्हें गिरा गांधी बना देना नहीं होना चाहिए। उनकी शिक्षा शिवालय भी होनी चाहिए। यह उन्हें अपनी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने के योग्य बनाने वाली होनी चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा में चित्र, मैजिक स्टेशन, चित्रमा, शमोपान और रडियो आदि द्रव्य और धार्मिक साधन बड़े सहायक मिड हो सकते हैं।

प्रौढ़ शिक्षा नई पीढ़ी की शिक्षा के लिए भी सहायक होती है। अनपढ़ माना-पिता अपने बच्चों की शिक्षा का महत्व नहीं समझ सकते। वे प्रायः जन-बुद्धि पर उन्हें स्कूल नहीं भेजते। जब वे स्वयं शिक्षा पाने हैं, तब ही उन्हें अपने बच्चे के लिए इसकी उपयोगिता का पता चलता है।

राज्य और शिक्षा—१९वीं सदी के प्रारम्भिक शिक्षा को विष्णुल निजी मामला समझा जाता था। अपनी शिक्षा के लिए हर आदमी खुद जिम्मेदार था। राज्य अपने नागरिकों को शिक्षित करने की कोई जिम्मेदारी नहीं समझता था। उन दिनों शिक्षा का

प्रबन्ध या तो धार्मिक गुरुवाजो यथार्थ चर्चों, मठों, मण्डिरों, और मंदिरों या कुछ धनी व्यक्तियों द्वारा, जो धर्मार्थ विद्यालय खोलते थे, किया जाता था। आज के जमाने में शिक्षा पाने का अधिकार आदमी का महत्वपूर्ण अधिकार है। मजबूतकारी राज्य होने के नाते राज्य को अपने नागरिकों को शिक्षा देने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसी विचार के कारण आजका प्रायः सब उन्नत देशों में मूल्य और अनिवार्य आरम्भिक शिक्षा दी जाती है।

लोकतन्त्र में नागरिकों को शिक्षा राज्य ने दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। कोई लोकतन्त्रीय राज्य, जिसके नागरिक शिक्षित और प्रबुद्ध नहीं, दसतापूर्वक नहीं चल सकता। निम्नलिखित कारणों से शिक्षा राज्य को जिम्मेवारी बनती जा रही है —

१ जैसा कि ऊपर बताया गया है, लोकतन्त्रीय राज्य की दक्षता के लिए छोटे-बड़े, गरीब-अमीर, नव नागरिकों की शिक्षा आवश्यक है। यद्यपि राज्य उनकी शिक्षा किसी व्यक्ति पर या किसी मस्जिद पर नहीं छोड़ सकता। यदि इसे निजी मस्जिदों पर छोड़ दिया जाए तो शिक्षा के भारी खर्च के कारण गरीब नागरिकों को अपने बच्चों को भिक्षा करने या मौना नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ अनपढ़ माता-पिता शिक्षा का महत्व समझ सकते भी न समझें। ऐसे लोगों को भी अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए मजबूर करना होगा।

२ दूसरी बात यह है कि देश भर में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने का खर्च इतना अधिक है कि कोई एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह शिक्षा के लिए आवश्यक धन नहीं जुटा सकता।

इन कारणों ने आज के जमाने में शिक्षा का बोझ राज्य उठाया है। आजकल राज्य या तो अपने रुपये से स्वयं स्कूल और कॉलेज खोलकर अपना निजी धर से बर्ताई जा रही शिक्षा मस्जिदों को सहायता देकर शिक्षा को बढ़ावा देता है।

शिक्षा का महत्व—शिक्षा व्यक्ति के विकास और समाज की तरक्की के लिये सबसे पहले जरूरी है। संक्षेप में शिक्षा के बिना अच्छा जीवन असम्भव है। व्यक्ति के लिए अच्छे जीवन का अर्थ है, उसके ऊँचे या बुद्धिमान जीवन का विकास। शिक्षा मनुष्य को अपने पारिवारिक भावों को तर्क द्वारा दबाने में सहायता देती है। यह उसका ज्ञान बढ़ाती है, उसका दृष्टिकोण विस्तृत करती है, उसकी बुद्धि तीव्र करती है, और उसकी सोचने और तर्क करने की शक्ति बढ़ाती है। शरीर सम्बन्धी शिक्षा से मनुष्य अच्छा स्वास्थ्य बना सकता है। नैतिक और सामाजिक शिक्षा चरित्र को ठीक रूप देती है। शिक्षा के बिना मानविक शान्ति और आन्तरिक सुख विनाशक अवस्था है।

शिक्षा गरीबी, रोग और बेकारी को हटाने में भी मदद करती है। यह बुद्धि, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य की तरक्की कराती है। इससे नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का सही ज्ञान होता है, और इस प्रकार वह अपने सामाजिक और राजनैतिक जीवन को सुधारता है। विज्ञान, कला, दर्शन, और साहित्य की महान रचनाएँ शिक्षा के

बिना कभी गृही बन सकती थी। इस प्रकार, शिक्षा मनुस्मृति और सभ्यता, दोनों, को तरक्की के लिए आवश्यक है। संक्षेप में यह मनुष्य जाति की प्रगति, समृद्धि और सुख की कुशी है।

सारांश

शिक्षा किसे कहते हैं—व्यक्ति की शिक्षा सीखने और भूलने की जीवन भर की प्रक्रिया है। इसमें ये तीन भागें आती हैं (१) उसके स्वाभाविक विकास के बजाए विमर्शित प्रशिक्षण। (२) अपने समाज के आदर्शों का प्रशिक्षण। (३) न केवल उसके बौद्धिक गुणों का, बल्कि उसके दारिद्र्यिक और नैतिक गुणों का भी विकास।

शिक्षा के लक्ष्य—(१) यह बिल्कुल उदार होनी चाहिए और इसका लक्ष्य व्यक्ति का पूर्ण दारिद्र्यिक, बौद्धिक और नैतिक विकास होना चाहिए। (२) माप-माप, इसका व्यावसायिक आधार भी होना चाहिए। (३) आज के जमाने में शिक्षा का लक्ष्य नागरिकता की शिक्षा देना भी होना चाहिए।

शिक्षा की मजिलें—(१) ५ या ६ साल की उम्र तक शिक्षा का लक्ष्य ठीक स्वास्थ्य और चरित्र का निर्माण तथा बच्चे की जानकारी का दायरा बढ़ाना चाहिए। इस अवस्था में बौद्धिक प्रशिक्षण का गौण महत्व है। बच्चों की उचित शिक्षा में घर और नर्सरी स्कूल दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है।

(२) ६ और १४ वर्ष की आयु के बीच स्कूलों की शिक्षा बिल्कुल उदार होनी चाहिए। छात्रों को सब तरह का ज्ञान हासिल करने के लिए उत्साहित करना चाहिए, पर वे निरंतर किताबी बीटे ही न बन जाएं; कसरत और खेलकूद भी शिक्षा के बैसे ही महत्वपूर्ण भाग हैं। इसके अलावा चरित्र के उचित प्रशिक्षण के बिना शिक्षा बधूरी रहती।

पर इन बिना उदार शिक्षा बिल्कुल नावाकी समझी जाती है। यह व्यावसायिक शिक्षा के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए, जिससे शिक्षा पूरी होने के बाद आदमी आसानी से जीविका बना सके। इसके अलावा, किताबी शिक्षा हर विद्यार्थी के लिए उपयुक्त नहीं। हो सकता है कि यदि उसे कोई दस्तकारी सीखने का मौका दिया जाए तो वह चमक जाए। आधुनिक औद्योगिक समाजों में व्यावसायिक या शिल्प सम्बन्धी शिक्षा का महत्व बहुत अधिक है।

(३) विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली उच्च शिक्षा, विज्ञान, कला और दर्शन की तरक्की के लिए बहुत आवश्यक है। पर यह सिर्फ उनमें लिए होनी चाहिए जिनकी इसमें रुचि हो।

नागरिकता की शिक्षा—सोवियत के युग में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में, पढ़ाई के अलावा, किये जाने वाले काम नागरिकता की शिक्षा देते हैं। इन कामों में सहयोग, मिलनसारि, सहिष्णुता, अनुशासन, स्वयं कर्तव्य, नेतृत्व, प्रशासन, स्वशासन, मार्गदर्शन, प्रापण कला, और सामाजिक सेवा की शिक्षा मिलती है।



राज्य और शिक्षा—विषी समय शिक्षा को व्यक्ति का निजी मामला समझा जाता था। पर अब यह राज्य की जिम्मेदारी है क्योंकि आजकल राज्य लोकतन्त्रीय और मजदूरी राज्य है। लोकतन्त्रीय राज्य जनता का सेवक है। इसे अपने स्वामियों को शिक्षित करना पड़ता है। राज्य की दशना के लिए भी आवश्यक है कि इसके नागरिक शिक्षित हों। हो सकता है कि कोई आदमी इतना गरीब हो कि वह शिक्षा पर खर्च न कर सके। इसलिए राज्य को उसे शिक्षित करना चाहिए। इसके अलावा शिक्षा के आवश्यक अर्थ भी राज्य ही अधिक अच्छी तरह कर सकता है।

शिक्षा का महत्व—यह मनुष्य की पंगुवृत्ति को खोलती है और उसके बौद्धिक अंग का विकास करती है। सामाजिक जीवन में शिक्षा गरीबी, बीमारी और बेरोजगारी को दूर करने में मदद देती है। यह आर्थिक उन्नति में भी सहायता देती है। सामाजिक और राजनैतिक जीवन को यह अधिक मोहार्थपूर्ण बनाती है। संक्षेप में शिक्षा मानव जाति की उन्नति और सुख की कुजी है।

प्रश्न

QUESTIONS

- १ शिक्षा किसे कहते हैं ? इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए ?
1. What is 'education'? What should be its aim ?
- २ शिक्षा में माता-पिता का क्या स्थान है ?
2. What is the role of parents in education ?
- ३ शिक्षार्थी और बड़े उम्र के बच्चों को किस तरह की शिक्षा को भइरत होती है ?
3. What type of education do infants and children of schoolgoing age require ?
- ४ व्यावसायिक शिक्षा के पक्ष में युक्तिवा बीगिए ।
4. Make out a case for vocational education
- ५ लोकतन्त्र के नागरिक के लिए शिक्षा का क्या महत्व है ?
5. What is the importance of education for a citizen of democracy ?
- ६ मान के नागरिक को किस प्रकार की शिक्षा चाहिए ?
6. What type of education does a citizen of today require ?
- ७ भारत में स्त्री शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के पक्ष में युक्तिवा बीगिए ?
7. Make out a case for female and adult education in India
- ८ शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी क्यों होनी चाहिए ?
8. Why should education be a responsibility of the state ?

86

पर ही किसी दावे को समाज द्वारा अभिवार माना जाएगा—

१. यह युक्ति-युक्त दावा होना चाहिए ।

२ दावा ऐसा होना चाहिए कि उसे नैतिक दृष्टि में उचित ठहराया जा सकता हो । चोरी करने, घराब पीने, माली देने और हत्या या आत्महत्या करने के दावों को नैतिक दृष्टि में उचित नहीं ठहराया जा सकता । दूसरे ओर, आदर्श जीने का, शिक्षा पाने का, और काम करने का दावा नैतिक रूप में कर सकता है ।

३ दावा स्वार्थपूर्ण न होना चाहिए, पर ऐसा होना चाहिए कि इसकी पूर्ति से व्यक्ति और समाज दोनों को लाभ हो । यह समाज द्वारा सामाजिक रूप में स्वीकृत होना चाहिए । उदाहरण के लिए, किसी आदमी की आत्महत्या करने का दावा स्वार्थपूर्ण दावा है । आत्महत्या आदमी को सब चिन्ताओं और परेशानियों में छुटकारा दे सकती है । पर यह समाज को उन लाभों से वंचित कर देगी, जो उसे इसके जीवन से मिलने । इसी प्रकार, भिक्ष मागने का अधिकार किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि भिखारी समाज पर बोझ है और वह सामाजिक जीवन में कुछ भी योगदान नहीं करता ।

४ उपर्युक्त विवेचन में यह परिणाम निकलता है कि वह दावा जो अपने में नैतिक कर्तव्य को नहीं स्वाकार करता, अभिवार नहीं माना जा सकता । यह खाली दावा होगा ।

५ जो दावा अधिकार माना जाता है वह सब जगह लागू हो सकता चाहिए । समाज के लिए यह अगम्य है कि वह अलग-अलग आदमियों की अवस्था में अलग-अलग दावों को मानते । लोगों के कुल सामान्य दावों को भी अस्वीकार माना जा सकता है । अधिकारों का उपयोग सब नागरिकों द्वारा समान रूप में किया जाना चाहिए ।

क्या किसी अधिकार के लिए राज्य की स्वीकृति आवश्यक है?—अधिकारों के लिए राज्य की स्वीकृति परम आवश्यक नहीं है । वे भी अधिकार हों मन्त्र है जिन्हें नैतिक दृष्टि में उचित ठहराया जा सकता है और जिन्हें मयाज स्वीकार करता है । माय हो, यदि राज्य भी उन्हें मान ले और अपने कानूनों को हिस्सा बना ले तो अधिकारों का बल बड़ा जाएगा । उस अवस्था में लोग अपने अधिकारों का उपयोग अधिक पक्के तौर से कर सकेंगे ।

अधिकारों का वर्गीकरण—अधिकारों को दो तौर से नैतिक और वैधिक (legal) अधिकारों में बाटा जाता है ।

नैतिक अधिकार—यदि किसी आदमी के दावे नैतिकता के आधार पर हैं और वे सिर्फ समाज द्वारा माने जाते हैं तो वे नैतिक अधिकार कहलाएंगे । नैतिक अधिकारों के दो छे जो अनुगति या बल हैं, वह लोकमत है, राज्य का प्राधिकार नहीं । नैतिक अधिकार स्थितिज अधिकार (potential rights) भी कहलाते हैं । उनमें अपने को राज्य से भी स्वीकार कराने की शक्ति नहीं होती । जो राज्य जनता का मित्र और गुमावामी होने का दावा करता है वह उनके उन दावों की उपेक्षा नहीं कर सकता जो नैतिकता और लोकमत के आधार पर हैं । इसलिए सब नैतिक अधिकारों में

वाद में वैधिक अधिकार बनने की प्रवृत्ति होती है। भारत में शिष्टा प्राप्त का अधिकार अभी नैतिक अधिकार है। पर अमेरिका, इंग्लैण्ड, रूस आदि अन्य राज्यों में यह वैधिक अधिकार है। भारत में भी कुछ समय बाद यह वैधिक अधिकार बन जाएगा।

वैधिक अधिकार—वैधिक अधिकार वे अधिकार हैं जो राज्य द्वारा अभि-स्वीकृत और प्रवर्तित किये जाते हैं। उनके पीछे राज्य का बल होता है। राज्य द्वारा स्वीकृत अधिकार इसके कानूनों का बल बन जाते हैं। उनका अतिक्रमण करने पर सजा हो दह दिया जाता है जैसा कानून का अतिक्रमण करने पर। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि यह आवश्यक नहीं कि सब वैधिक अधिकार नैतिक दृष्टि से उचित ठहराये जा सकें हों। उदाहरण के लिए, यह सुविध्य है कि आवश्यक अर्थात्त वैज्ञानिक सम्पत्ति का अधिकार नैतिक दृष्टि से उचित ठहराया जा सकता है। नागरिक शासन में हमें अधिकतर वैधिक अधिकारों पर विचार करना है।

वैधिक अधिकारों को फिर जानाद और राजनैतिक अधिकारों में बांटा जा सकता है।

जानपद अधिकार—जानपद अधिकारों का सम्बन्ध लोगों के जीवन और सम्पत्ति में है। वे सामाजिक जीवन की आरम्भिक चरों की पूर्ति की व्यवस्था करने हैं। उनके बिना मध्य जीवन सम्भव नहीं। उनमें जीवन और सम्पत्ति का अधिकार, श्रमिदा करने का अधिकार, पुत्रा और गर्भ का अधिकार, बोलने का, मन रखने का और हकूद होने का अधिकार, आदि आते हैं।

राजनैतिक अधिकार—राजनैतिक अधिकार जानपद अधिकारों में पृथक् होते हैं। प्रत्येक राज्य में अनन्यगम्य को राजनैतिक अधिकार विविध होते हैं। पर वह उन्हें जानपद अधिकार से भिन्न है। इन अधिकारों का उपयोग सिर्फ नागरिकों द्वारा किया जाता है, और ये अधिकार नागरिकों को राज्य के अन्य मध्य सदस्यों में पृथक् करते हैं। राजनैतिक अधिकार नागरिक को अपने राज्य के मामलों में हिस्सा लेने और उन्हें विनिर्णय करने के योग्य बनाते हैं। पर इन अधिकारों का पूरा और सामान्य उपयोग सरकार के लोचप्रधान आशे में ही सम्भव है। राजनैतिक अधिकारों में ये अधिकार शामिल हैं —

(क) शान्तिजनिक प्रार्थना पर बर्बा करने के लिए शान्तिपूर्वक हकूद होने का अधिकार।

(ख) सरकार से अपने कष्टों को दूर करने के लिए अल्प-अल्प या सामूहिक रूप में प्रार्थना करने का अधिकार।

(ग) मन देने का अधिकार।

(घ) चुनाव के लिए मते देने का अधिकार।

(ङ) कोई मरतारी पर धारण करने का अधिकार।

क्या नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार जैसी कोई चीज होती है ?

पहले यह कहा जाता था कि कुछ अधिकार मनुष्य को निर्मल प्राप्त हैं। मनुष्य उन्हें लेकर ही पैदा हुआ था, और वह उसी प्रकृति का वंश है जिससे वह है जैसा उसकी त्वचा का रंग। इन अधिकारियों को समाज और राज्य से भी अधिक प्रबल कहा जाता था। राज्य या समाज भी आदमी को उसका नैसर्गिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इन अधिकारों को तब तक कम भी नहीं किया जा सकता जब तक व्यक्ति स्वयं राज्य को बना कराने का अधिकार न दे। इन नैसर्गिक और अनिवार्य अधिकारों का संक्षेप में 'जीवन, स्वाधीनता और सम्पत्ति' कहते हैं।

नैसर्गिक अधिकारों का सिद्धान्त १७ वीं और १८वीं सताब्दी में बहुत प्रचलित था। समाज-संविधान सिद्धान्त के लेखकान् इस आशय को माना। पर आजकल यह सिद्धान्त नहीं माना जाता। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं आज आदमी को समाज में स्वतन्त्र कोई अधिकार नहीं है। इससे अलावा कुछ अधिकार नैसर्गिक रूप में परस्पर विरोधी हैं। उदाहरण के लिए, स्वतन्त्रता और समानता के अधिकार। इससे अलावा, नैसर्गिक अधिकारों का कोई भी मूल्य भी नहीं जिस पर सब सहमत हो।

मूल अधिकारों का अर्थ—कुछ अधिकार प्रत्यक्ष नागरिकों के विचार के लिए मौलिक महत्त्व के माने जाते हैं। आधुनिक लोकतन्त्रवादी राज्यों में इन अधिकारों को कभी-कभी संविधान का हिस्सा बना लिया जाता है और मूल अधिकारों का नाम दिया जाता है।

प्रायः संविधान में, जो देश का सर्वोच्च कानून होता है परिवर्तन के लिए लम्बी-चौड़ी और विमोचक प्रक्रिया अपनायी जाती है। जब अधिकार इसका हिस्सा बन जाते हैं, तब सरकार के लिए उन्हें काबू में रखने का सामान्य तरीका कम करने या छीनना कठिन हो जाता है। बहुमत पक्ष होने पर अल्पमत का उनसे अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस प्रकार, संविधान का हिस्सा बन जाने पर इन अधिकारों का बल बढ़ जाता है पर मूल शब्द का यह अर्थ न समझना चाहिए कि यह अधिकार अनिवार्य (inviolate) या निरन्तर (absolute) हो जाते हैं।

अधिकारों के साथ कर्तव्य अपने आप आ जाते हैं—हम सबमें यह प्रकृति है कि हम अपने अधिकारों पर जोर देने के साथ अपने कर्तव्यों की परवाह नहीं करते। पर हम यदि स्वतन्त्रता आदि अधिकारों और कर्तव्यों एक साथ रखते हैं। कोई अधिकार दिया कर्तव्य के सहित ही दिया जाता है। प्रत्येक अधिकार के साथ एक कर्तव्य जुड़ा होता है। अधिकार और कर्तव्य एक निष्ठा के दो पहलू हैं, जिन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यदि मूल कोई चीज दान का अधिकार है, तो मेरा यह कर्तव्य है कि मैं दूसरों का भी वह अधिकार स्वीकार करूँ। यह सामाजिक व्यवहार का सरल लेकिन सही नियम है। दूसरों से वह व्यवहार करे, जो तुम अपने से करना चाहते हो।

सुदान पैदा करने की आजादी है। यह अधिकार मानव-वंश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है।

स्वतन्त्रता का अधिकार—स्वतन्त्रता का अधिकार जीवन के अधिकार का एक आवश्यक भाग है। बिना स्वतन्त्रता के जीवन अर्थहीन हो जाता है। स्वतन्त्रता का अधिकार बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण अधिकार है। इसके अन्तर्गत, अन्य कई अधिकार आते हैं, जैसे उपामना की स्वतन्त्रता-चलने-फिरने और साहचर्य, की स्वतन्त्रता, विचार और भाषण की स्वतन्त्रता वैसे की स्वतन्त्रता। हम इन पर एक-एक करके विचार करेंगे।

उपासना की स्वतन्त्रता—यह एक आपुनिक अधिकार है। आपुनिक राज्य लौकिक या धर्म निरपेक्ष (secular) राज्य है। यह किसी भी धर्म से अपने आपको नहीं जोड़ता। उपासना के अधिकार से सब नागरिकों का अपनी इच्छा के अनुसार धर्म को मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने की आजादी घबलित होती है। यदि धार्मिक आचरण के साथ कोई धार्मिक या राजनैतिक गतिविधि भी सम्बन्धित है, तो इन गतिविधियों के विनियमन और अवरुद्ध करना राज्य के लिए पूर्णतया उचित होगा।

अबाध संचालन का अधिकार—इस अधिकार से अनुसार नागरिक को राज्य के क्षेत्र में कहीं भी आने-जाने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। इसमें यह बात भी आ जाती है कि कोई व्यक्ति दोषपूर्णता निरूपण या निरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए। यह अधिकार भी अवरुद्ध नहीं है। सरकार युद्ध के दिनों में या राष्ट्रीय आपात के समय नागरिकों के घूमने-फिरने की आजादी पर बहुत सी शर्तें लगा सकती है।

सविदा करने का अधिकार—इसका अर्थ यह है कि हर नागरिक को हमारे नागरिक के साथ सविदा करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। सविदा बार-बार और मामा-विदा मगठन की दुष्ट कर्ती है, और इसलिए समाज की प्रवृत्ति के लिए बहुत आवश्यक है। पर राज्य कुछ प्रकार की सविदाएँ करने की इजाजत नहीं दे सकता। उदाहरण के लिए, अपने आपको बेचकर दास बनाने की, या दासों का व्यापार करने की, या ऐसी सविदाएँ करने की इजाजत नहीं दे सकता, जिससे रिश्तत बेनी होनी है। न राज्य ऐसी सविदाएँ करने दे सकता है, जिनसे उसकी सुरक्षा को खतरा हो।

साहचर्य का अधिकार—हम देख चुके हैं कि आदर्शियों को अपनी अनेक तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साहचर्यों की आवश्यकता होती है। साहचर्य बनाना मनुष्य की महान प्रवृत्ति का स्वाभाविक परिणाम है। यदि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और रुचि के अनुसार साहचर्य बनाने के लिए स्वतन्त्र न हो तो उसका पूर्ण विकास संभव नहीं। निस्सन्देह, ऐसे किसी साहचर्य को नहीं रहने दिया जा सकता जिसका लक्ष्य राज्य का तन्त्रा पलटता हो।

सोचने, छापने और इच्छा होने का अधिकार—सोचने के अधिकार का अर्थ यह है कि हर आदमी को सरकारी दखल से आजाद रहने, हम सोचने की ओर सार्वजनिक रूप से अपनी राय जाहिर करने की आजादी है। सरकार की नीतियों और कार्यों की

आलोचना भी इसमें आ जाती है। फिर, कोर्टों के द्वारा ही हम दूसरों को राय और अनुभव से लाभ उठाते हैं। इस प्रकार, स्वतन्त्र मापक का अधिकार समाज को स्वयं प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर सामाजिक व्यवस्था के हित की दृष्टि से हम अधिकार पर भी राज्य के कानून ऐसी बात कहने पर सह होते हैं, जिसमें गार्हस्थित नैतिकता दृष्टि से हो। या लोगों को बदनाम किया जाना हो, या लोगों को अपराध के लिए मजबूर किया जाना हो, या राज्य के विरुद्ध झोठ फैलाया जाना हो। पर, ऐसी पाबन्दियों का अभिप्राय वैयक्तिक स्वतन्त्रता को कम करना नहीं है। वे पाबन्दियाँ हमारे को स्वतन्त्रता प्रतिष्ठित करने के लिए और राज्य की स्वायत्तता को रक्षा के लिए लागू की जाती हैं।

प्रेम या समाचार-पत्र के अधिकार का अर्थ यह है कि जो बात मनुष्य विधिपूर्वकता बोल सकता है, उसे प्रकाशित करने का उसे अधिकार। यह अधिकार सोचने के अधिकार से भी निराला है। प्रबुद्ध लोकमत बनाने में प्रेम बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। सोचने के अधिकार पर जो परिसीमाएँ हैं, वे छानने के अधिकार पर भी लागू होनी हैं।

सम्पत्ति का अधिकार—सम्पत्ति का अधिकार आदमी का बहुत पुराना अधिकार है। तथ्य तो यह है कि राज्य का निर्माण ही लोगों की सम्पत्ति की रक्षा के लिए किया गया था। अर्न्तः क्षमताओं का सम्यक् उपयोग और उपभोग भी इस अधिकार के अन्तर्गत आता है। इसका यह भी अर्थ है कि आदमी उपहार या विनिमय द्वारा अपनी सम्पत्ति देने के लिए स्वतन्त्र है। कुछ व्यक्ति सम्पत्ति नागरिक के अधिकार के स्वतन्त्र और पूर्ण विकास के लिए निराला आवश्यक है। पर वैयक्तिक सम्पत्ति के असीमित मूल्य के अधिकार पर आवश्यक समाजवादी विचारधारा के प्रभाव के कारण आगति उठानी आ रही है।

संरक्षित और भाषा का अधिकार—यह अधिकार किसी देश के अल्पमताओं के लिए विशेष महत्व का है। प्रत्येक अल्पमताएँ वर्ग को लोकतन्त्रीय देश में अपनी भाषा और संस्कृति के विकास के लिए स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

शिक्षा देने का अधिकार—यह एक जायज अधिकार है। १५० वर्ष पहले शिक्षा का एक वैयक्तिक मामला समझा जाता था। यात्राएँ अपने नागरिकों को शिक्षा की सुविधाएँ देने के लिए राज्य को जिम्मेदार बनाता जाता है। लोकतन्त्र के नागरिकों के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। यह उनकी समझने की शक्ति को बढ़ाती है और उनकी दृष्टिकोण विस्तृत करती है।

काम करने का अधिकार—यह भी एक जायज अधिकार है। इसका अर्थ यह है कि हर नागरिक को बेरोजगारी न बचाया जाए। यह राज्य की जिम्मेदारी मानी जाती है कि वह हर नागरिक के लिए काम की व्यवस्था करे। इस अधिकार में यह बात भी ध्यान रखनी है कि हर मजदूर को निर्वहण-मजदूरी निश्चित रूप में मिलनी चाहिए। उसकी मजदूरी इतनी होनी चाहिए कि वह अपने रहन-सहन का स्तर न्याय-संगत रूप में सुविधाजनक रख सके।

वातून के सामने बराबरी का अधिकार—इस अधिकार के अनुसार वातून हर नागरिक के लिए बराबर हाना चाहिए और उसे जन्म, धन, रंग, मूलवत्त, धर्म या लिंग का कोई ध्यान न करना चाहिए ।

मत देने का अधिकार—मत देने का अधिकार लोकतन्त्र का जन्म है । लोकतन्त्रीय राज्य के प्रत्येक नागरिक को अपनी सरकार के चुनने में हिस्सा लेने का मौका होना चाहिए । इसी कारण राज्य के हर वयस्क सदस्य को मत देने का अधिकार दिया जाता है । इस अधिकार के उपभोग के आश्वासन एकमात्र अपवाद अवस्था, दिमागिए, अपराधी और अन्यदेसीय हैं ।

सरकारी पद धारण करने का अधिकार—जिन नागरिकों को मत देने का अधिकार है, उन सबको जन्म, धन, रंग, मूलवत्त, धर्म या लिंग के भेदभाव के बिना, राज्य के अधीन पदधारण करने का भी अधिकार है ।

शांति बना देने का अधिकार—जिनो राज्य के सब सदस्यों का एक विशेष अधिकार है अपने बाटो के निवारण के लिए सरकार को शांति देना ।

भारतीय नागरिकों के अधिकार—उपर्युक्त सब अधिकार सब लोकतन्त्रीय राज्यों में नागरिकों को मिल जाने आवश्यक नहीं । भारत में अब तक शिक्षा पान का अधिकार और रोजगार पाने का अधिकार राज्य द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं । इसका कारण यह है कि हमारे राज्य के वित्तीय समाधान अभी बड़े सीमित हैं । अब तक सरकार के लिए यह सम्भव नहीं कि वह भारत की विशाल आबादी के लिए आवश्यक मत्स्य में स्थूल खोल सके । न हमारा राज्य, जिसकी आर्थिक जरूरतें गिच्छी हुई हैं, सब नागरिकों को रोजगार की ही गारंटी दे सकता है । वो भी ब्रिटिश शासन के दिनों की तुलना में औद्योगिकभारतीयों का आश्वासन बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है । ब्रिटिश शासन में मत देने का अधिकार जनता के सिर्फ़ थोटे से हिस्से को दिया गया था । बोलने की, माहुर्य बनाने की, सम्मेलन की, और प्रेस की आजादी भी बहुत सीमित थी । राज्य के कुछ ऊँचे और महत्वपूर्ण पद भारतीयों के लिए बिल्कुल बंद थे । अन्य पदों में भी रामनाथों आदि के और धनी आश्रमियों के सड़कों को पहले दिया जाता था । स्वतन्त्र भारत में सब नागरिकों को समान रूप से ये अधिकार हैं । गरीब से गरीब नागरिकों को भी राज्य के ऊँचे से ऊँचे पद पर पहुँचने में कोई रुकावट नहीं है ।

नागरिकता के कर्तव्य—जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कर्तव्य अधिकारों के साथ अनसुलझ जुड़े रहते हैं । यदि कोई आदमी अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों को नहीं पहचानता वह अच्छा नागरिक नहीं कहला सकता । अधिकार का आराम से उपभोग करता, यह ध्यान और भी आवश्यक कर देता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए ।

अधिकारों की तरह कर्तव्य भी वैधिक और नैतिक होते हैं । नैतिक कर्तव्य हमारी नैतिक शक्त के कारण हमारे पर आते हैं । उदाहरण के लिए हमारे ऊपर यह नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने मतों का ईमानदारी से प्रयोग करें । अब कोई कर्तव्य

लिए सदा तैयार रहना चाहिए। संक्षेप में, जिस आदमी को उसको महसूस हो कि आवश्यकता हो, और जो उसका पान हो, उसे महामत्तता देना उसका कर्तव्य है।

भारत

— अधिकार किसे कहते हैं—छास्की ने अधिकारों की यह परिभाषा की है कि “सामाजिक जीवन की वे अवस्थाएँ जिनके बिना कोई भी आदमी अपना अधिकतम विकास नहीं कर सकता।” इसका अर्थ यह है कि समाज को आदमी के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए कुछ सुविधाओं का गारण्टी देनी होगी। ऐसी अवस्थाओं और सुविधाओं को हम अधिकार कहते हैं।

इस प्रकार अधिकार सामाजिक जीवन का एक परिणाम है। कोई भी स्वार्थ-पूर्ण, अयुक्तियुक्त और अनैतिक दावा अधिकार नहीं बन सकता। हर एक अधिकार के साथ एक कर्तव्य जुड़ा रहता है।

कोई दावा अधिकार तभी बन सकता है जब समाज ने उसका अनुमोदन कर दिया हो। हम समाज से स्वतन्त्र अधिकारों का दावा नहीं कर सकते। राज्य द्वारा स्वीकृति आवश्यक नहीं, यद्यपि कानून की शक्ति अधिकारों का बल बढ़ा देती है।

(१) नैतिक अधिकार—यदि किसी आदमी का दावा नैतिकता के आधार पर है और वह सिर्फ राज्य द्वारा स्वीकृत किया जाता है तो उसे नैतिक अधिकार कहा जाएगा। उनके पीछे एकमात्र ताकत लोकमत है। लोकमत का बल नैतिक अधिकारों को वैधिक अधिकारों में बदलवाने की प्रवृत्ति रखता है।

(२) वैधिक अधिकार—वैधिक अधिकार वे अधिकार हैं जिन्हें राज्य स्वीकार और परिष्कृत करता है। उनके अस्तित्व पर राज्य दखल देता है।

वैधिक अधिकारों को जानपद और राजनैतिक अधिकारों में बांटा जा सकता है। जानपद अधिकारों में जीवन, सम्पत्ति, साहचर्य, मविदा और उपामना आदि के अधिकार शामिल हैं। राजनैतिक अधिकारों में स्वतन्त्र रूप से भाषण और विचार प्रकाशन, सम्मेलन, याचिका, मतदान और राज्य के भविष्य पर धारण के अधिकार शामिल हैं।

नैतिक या प्राकृतिक अधिकार या जन्मजात अधिकार कोई चीज नहीं होती। ‘सारे समाज के हित की दृष्टि से किसी भी अधिकार को भीमित किया जा सकता है।

जो अधिकार सुविधा का हिस्सा बना दिये जाते हैं, उन्हें और भी अधिक बल प्राप्त हो जाता है और वे मूल अधिकार कहलाने लगते हैं।

अधिकार कर्तव्यों को ध्वनित करते हैं—कोई अधिकार ऐसा नहीं जिसके साथ कर्तव्य जुड़ा हो। अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पार्श्वों की तरह हैं, जो हमेशा साथ रहते हैं। यदि क का एक अधिकार है तो म का एक कर्तव्य है कि वह उस अधिकार का सम्मान करे। फिर क का अधिकार क का कर्तव्य भी है। यदि क को एक अधिकार प्राप्त है तो उसका कर्तव्य है कि वह स के पैरों पर अधिकार का आदर करे। क का यह भी कर्तव्य है कि वह अपने अधिकार का प्रयोग ईमानदारी से और समाज तथा राज्य के सर्वोत्तम हित की दृष्टि से करे। अन्तिम बात यह है कि राज्य के

प्रति, जो हमारे अधिकारों को धरती देता है और रक्षा करता है, हम में से होकर कुछ कर्तव्य है।

नागरिक के विविध अधिकार—शामिल आधुनिक राज्य के नागरिक के निम्नलिखित जानपद और राजनैतिक अधिकार होने हैं।

जीवन का अधिकार, जिसमें आत्म-रक्षा और मृत्यु वीर्य करने का अधिकार भी शामिल है, स्वतन्त्रता का अधिकार, इच्छानुसार उपामता का अधिकार, निर्वाचन-धूमने-फिरने का अधिकार, मजिद्वारा करने का अधिकार, बोधने का अधिकार, माह्वान बनाने का अधिकार, प्रेम की स्वतन्त्रता का अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार, मस्तिष्क और भाषा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, कानून के सामने बराबरी का अधिकार, मन देने का अधिकार, सरकारी नौकर होने का अधिकार, और धार्मिक देने का अधिकार।

नागरिकता के कर्तव्य—कर्तव्य भी वैध और नैतिक होने हैं। नैतिक कर्तव्य हमारी नैतिक समझ द्वारा हमारे ऊपर आने जाते हैं। जब कर्तव्य कानून द्वारा प्रिक्लि हो जाते हैं, तब वे नैतिक कर्तव्य बन जाते हैं। नागरिक के वैध कर्तव्य यह हैं—(१) राज्य के प्रति निष्ठा, (२) राज्य के कानूनों का पालन, (३) राज्य को कर देना, (४) जूरी के रंग में कार्य करना और (५) अपने बच्चों को शिक्षा देना।

नैतिक कर्तव्य ये हैं—(१) मन का ईमानदारी में प्रयोग करना, (२) सरकारी पद पर रहने हुए ईमानदारी और (३) गमावित सेवा।

प्रश्न

QUESTIONS

- १ अधिकार किसे दते हैं? किसे दावे के अधिकार बनने के लिए कौन-कौन सी बातें आवश्यक हैं?
- 1 What is a 'Right'? What conditions are necessary for a claim to become a right?
- २ वैध और नैतिक कर्तव्यों में स्पष्ट रूप से भेद कीजिए। क्या किसी अधिकार के लिए राज्य की स्वीकृति आवश्यक है?
- 2 Distinguish clearly between legal and moral rights. Is state recognition necessary for a right?
- ३ "अधिकार कर्तव्यों को ध्वनि करने हैं" इसकी व्याख्या और विवेचना करो।
(५० वि० अप्रैल, १९४८, ५०)
- 3 "Rights imply duties" Explain and discuss. (P U April. 48 & 50)
- ४ 'अधिकार' और 'कर्तव्य' शब्दों की व्याख्या कीजिए। किसी आधुनिक राज्य के नागरिकों को प्राप्त कुछ अधिकारों का उल्लेख कीजिए।
(५० वि० अप्रैल, १९४९)

या

आधुनिक राज्य में किसे नागरिक के महत्वपूर्ण अधिकार और कर्तव्य कौन से हैं?

(५० वि० सितम्बर, १९५१)

4. Explain the terms 'Rights' and 'Duties'. Mention some of the rights enjoyed by citizens of a modern state
(P U. April, 1949)

Or

What are the important rights and duties of a citizen in a modern state ?
(P U Sept, 1950)

५. अधिकार की परिभाषा कीजिए। आरको राय में आधुनिक राज्य को किन अधिकारों की गारण्टी देनी चाहिए ?
(५० वि० दिसम्बर, १९५१)
5. Give definition of 'right'. What rights in your opinion should be guaranteed by the state
(P U Sept, 1951)
६. अधिकारों की परिभाषा करो ? आनन्द अधिकारों, राजनैतिक अधिकारों और नैतिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं ?
(५० वि० अप्रैल, १९५२)
6. Define 'Rights' What do you understand by Civil Rights, Political Rights and Natural Rights ?
(P.U April, 1952)
७. राज्य के प्रति नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं ?
(५० वि० अप्रैल, १९५३)
7. What are the obligations of the citizens towards the state ?
(P U April, 1953)
८. अधिकारों की परिभाषा करो ? क्या नागरिकों को राज्य के ऊपर कोई अधिकार प्राप्त हो सकता है ?
(५० वि० अप्रैल, १९५४)
8. Give a definition of Rights Can a man possess rights against the state ?
(P U April, 1954)

विधि, स्वाधीनता और समता—अपराध और दण्ड विधि या कानून

विधि का अर्थ और प्रकृति—'विधि' शब्द उन नियमों का निर्देश करता है जो मानवीय क्रियाओं के पर प्रदर्शन के लिए आवश्यक हैं। मनुष्य की सामाजिक प्रकृति यह चाहती है कि वह अपने अन्य साथी मनुष्यों के स्वार्थ में बचने के पारस्परिक आचरण के कुछ नियमों पर चले। यदि इन नियमों का सम्बन्ध मनुष्य की आंतरिक प्रेरक भावनाओं से है और वे उसके स्वचरण की सीमा हैं, तो वे नियम नैतिक नियम कहलाते हैं। यदि वे सिर्फ उसकी बाह्य क्रियाओं के सम्बन्ध रखते हैं तो वे सामाजिक या राजनैतिक नियम होते हैं।

राजनैतिक नियमों और सामाजिक नियमों में अन्तर है। यदि कोई आदमी सामाजिक नियम को न माने तो उसके काम को समाज द्वारा बुरा कहा जाता है, पर इसके परिणामस्वरूप उसे कोई सार्वजनिक दण्ड नहीं मिलता। पर राजनैतिक नियम का अतिप्रमाण करने पर दण्ड मिलता है। इन राजनैतिक नियमों की ही विधि या कानून कहते हैं। राजनैतिक नियम या विधियाँ राज्य द्वारा बनायी जाती हैं और उनके पीछे उसका प्राधिकार होता है। हार्तेट ने राजनैतिक नियम या विधि की यह परिभाषा की है कि 'बाहरी मानवीय क्रिया का व्यापक नियम, जो सभी पर राजनैतिक सत्ता द्वारा लागू किया जाता है।' नागरिक शासन के विद्यार्थी के रूप में हमारा ध्येय इसी प्रकार के नियम, अर्थात् विधि, से है। राजनैतिक नियमों, अर्थात् विधियों, के बारे में निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी चाहिए—

(१) विधि राज्य का एक आदेश है, जो इसकी सर्वोच्च सत्ता से सम्पन्न होता है। इस शब्द में विधि कस्टम (custom) से भिन्न है। कस्टम के पीछे सिर्फ लोकमत का बल होता है। राज्य के क्षेत्र में मौजूद सब आदमियों, समूहों और राष्ट्रों को इसके आदेशों का पालन करना चाहिए। उनको ओर से आज्ञा का पालन न किए जाने पर राज्य दण्ड देता है।

(२) राज्य के अणुका और कोई प्राधिकरण विधि जारी नहीं कर सकता। विधि सर्वोच्चता का फल है और सर्वोच्चता सिर्फ राज्य को प्राप्त है।

(३) कोई विधि स्वयं राज्य पर अपनकारी नहीं होती। राज्य किसी भी

समय विमा विधि को मसौदा या निरस्त (repeal) कर दिया है।

(४) विधि मनुष्यों की निम्न वांछों की पूर्ति करने वाली होती है और सामाजिकता के अर्थ में न्याय के अर्थ में न्याय नहीं करती।

विधि के अर्थ—राज्य की ही तरह विधि भी इतिहास की ही उपज है। यह विचार की अनेक मजिदों में से गुजरती है और कई बारकों में इसके विचार में योग दिया है। ये सब बारक विधि के अर्थ में बढ़ाने हैं। पर यह बाद रचना चाहिए कि बाहरी मानवीय व्यवस्था के नियमों का अर्थ चाहे कुछ भी हो, पर यदि उन नियमों को सर्वोच्च प्रभु की मजुरी प्राप्त न हो तो उन्हें विधि का बल नहीं मिल सकता। विधि के अर्थ निम्नलिखित बताए जा सकते हैं—

हट्टि—हट्टि विधि के अर्थ में पुगने अर्थों में से एक है। हट्टि। आचार्य के ये नियम हैं जो किसी समाज में आचार के कारण या किसी उपयोगिता की दृष्टि में व्यापक रूप में स्वीकार कर लिए जाते हैं। राज्य इन नियमों को बनाने में कोई हिस्सा नहीं लेता। वे आम प्रयोग और स्वीकृति के कारण बढ़ते हैं और समाज में फैलते हैं। पहले के राज्यों में हट्टि ही एक मात्र विधि थी। आज भी प्रायः राज्य में उसकी विधि प्रणाली का बहुत बड़ा हिस्सा हट्टि पर आधारित है। पर प्रायः हट्टि विधि प्रणाली के अर्थ में नये अर्थों। राज्य निम्न लेगी हट्टियों को स्वीकृत करता है जो समाज के जीवन के लिए उपयोगी और सुविधाजनक पाई जाती हैं।

धर्म—पहले के अधिनिमित्त समाज में जीवन के सब नियमों के पीछे धर्म का आदेश होता था और हट्टि तथा धर्म की एक दूसरे से मिली मिली जाती थी। मुस्लिम राज्यों की विधि का अर्थ में फैली है। ईसाई विधि और हिन्दू विधि भी बहुत दूर तक अपने धर्म धर्मों से निकली हैं।

न्यायिक निश्चय—हट्टि के अनुसार, राज्य का अर्थ विधि के अर्थ में अर्थ में नहीं हुआ। बल्कि हट्टि के निर्वाचन वार्ता और लागू करने वाले के रूप में हुआ। समाज की परिस्थितियाँ बदल जाते पर कोई हट्टि प्रायः कुछ स्थितियों और अवस्थाओं की दृष्टि में अर्थपूर्ण पाई गई। ऐसी परिस्थितियों में न्यायाधीश विधि की दृष्टि का निर्वाचन दृढ़ तरह करके कि कोई आम मान्यता उनके अर्थ में आ जाए, सभी धर्म अपने निर्वाचन के द्वारा नई विधियाँ पैदा कर देने थे। जहाँ कोई हट्टि नहीं थी, वहाँ न्याय और साम्य (Equity) के निर्वाचन लागू विधि जाते थे। ईसाई धर्म में सारी की सारी हट्टि विधि इसी प्रकार पैदा हुई।

धार्मिक भाव—यह भी सच है कि महान विधि शास्त्रों दृष्ट हैं। उनसे धर्मों में महान विधि सम्बन्धी निर्वाचन और अभिमत (opinions) हैं। इन अभिमतों का समय समय पर बदलाव और न्यायाधीशों पर बड़ा अर्थ पड़ा है। इन प्रकार उन्होंने विधि प्रणाली को एक रूप दिया है।

विधान (Legislation)—आधुनिक वास्तव में विधि का अर्थ विधान

मण्डली द्वारा अधिनियमित की जाती है। तब्य तो यह है कि आज विधानमण्डल विधि के एक मात्र स्रोत बनते जाते हैं। सदियों की भी सुनिश्चित लिखित विधियों का रूप दिया जा रहा है।

विधि के प्रकार—मंडल के अनुसार विधि को निम्नलिखित वर्गों में बाटा जा सकता है—

१. वैयक्तिक विधि (Private law) जो एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति के सम्बन्धों को विनियमित करता है।

२. लोकविधि, जो राज्य के साथ व्यक्ति के सम्बन्धों को विनियमित करती है।

३. अन्तर्राष्ट्रीय विधि, जो एक राज्य के साथ दूसरे राज्य के सम्बन्धों को विनियमित करती है।

१. वैयक्तिक विधि—वैयक्तिक विधि के अधीन किसी मामले में, निजी व्यक्ति पक्ष होते हैं। राज्य किन्हीं निर्धारक के रूप में कार्य करता है। राज्य व्यक्ति तयों के सब सम्बन्धों को विनियमित नहीं करता। यह किन्हीं उन सम्बन्धों को विनियमित करता है जो सार्वजनिक महत्व के हैं। सारे की सारी व्यवहार विधि (Civil law) इस वर्ग के अन्तर्गत आती है।

२. लोक विधि—लोक विधि के अधीन मूहूर्तों में एक गलत राज्य होता है। यह विधि एक तो राज्य के सभ्यता और नायों के सम्बन्ध में होती है, और दूसरे यह राज्य और उनके नागरिकों के सम्बन्ध विनियमित करती है।

लोक विधि के फिर से उपविभाग किए जा सकते हैं—

(क) संवैधानिक विधि (Constitutional law)—संवैधानिक विधि सामान्यविधि में सर्वथा भिन्न होती है। यह सरकार की संरचना, परिभाषा, नायों और नागरिकों की परिभाषा करती है। विधानमण्डल, जो सामान्य विधि बनाता है, स्वयं सार्वजनिक विधि से पैदा होता है।

(ख) प्रशासकीय विधि—लोक विधि का यह शाख विधि को लागू करने वाले प्रयोग के कार्य क्षेत्र को निर्धारित करता है। यह आदर्शों को यह भी बताता है कि यदि कार्यपालिका द्वारा उसके अधिकारों का अतिक्रमण किया जाए तो उसके पास क्या उपचार है।

(ग) दण्ड विधि—यह लोक विधि की एक शाखा है जो व्यक्ति या व्यक्तियों के उन नायों को निर्धारित करती है, जो राज्य के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं। अतः राज्य के विरुद्ध जुर्म हैं। राज्य दण्डविधि के अनुसार अपराधों पर अपराध के लिए मुहूर्ता प्रस्तुत है।

३. अन्तर्राष्ट्रीय विधि—यह एक राज्य के साथ दूसरे राज्य के सम्बन्धों को विनियमित करती है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि न तो अधिनियमित की जाती है, और न किसी सर्वोच्च न्यायिककरण द्वारा प्रवर्तित की जाती है। इसके पीछे विभिन्न राज्यों

में मौजूद लोकमत ही होता है। यदि कोई राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि का पालन करने से इनकार करदे तो उसे दण्ड नहीं मिलेगा।

विधि और नैतिकता का सम्बन्ध

विधि और नैतिकता का एक दूसरे से निवृत्त सम्बन्ध है, दोनों में बहुत सी बातों में भेद भी है। पहले हम विधि और नैतिकता में भेद करने वाली बातों पर विचार करेंगे।

भेद करने वाली बातें—विधि और नैतिकता अन्तर्वस्तु, पृष्ठबल और सुनिश्चितता (contents, sanction and definiteness) में एक दूसरे से भिन्न हैं। जहाँ तक अन्तर्वस्तु और अभिसंज्ञ (scope) का सम्बन्ध है, विधि मनुष्य के निर्णय बाहरी कार्यों से सम्बन्ध रखती है और इसे उसके विचारों, प्रेरक भावों और आशयों से कोई वास्ता नहीं। विधि विचारों और प्रेरक भावों पर सब ही विचार करती है, जब वे क्रियाओं में दिखाई देते हैं। झूठ बोलना नैतिक दृष्टि से बुरा है, पर विधि में यह सब ही बुरा है जब न्यायान्य में शपथ लेकर बोला जाए। ग़ुस्सा करना अनैतिक है, पर विधि में यह सभी बुरा है, जब मैं गुस्से में किसी को थोटा पहुँचाऊँ। नैतिकता के अनुसार थोरी की बात सोचना भी गलत है, पर विधि किसी आदमी को तभी दण्डित करेगी, जब यह वास्तव में थोरी करे।

जहाँ तक पृष्ठबल (sanction) में भेद का सम्बन्ध है, विधि सरकार द्वारा लागू की जाती है और इसके अपालन पर दण्ड दिया जाता है। इसके पीछे बल भी होता है। नैतिकता के नियम का अतिव्रमण करने पर सार्वजनिक दण्ड या जुर्माना नहीं होता। अनैतिक कार्य पर समाज अधिक से अधिक, आलोचना कर सकता है। नैतिकता के पीछे सिर्फ लोकमत की शक्ति है।

तीसरे, विधि स्वरूप में सुनिश्चित और सादृशिक होती है। विधि एक तमाम सब पर लागू होती है। दूसरी ओर, नैतिकता स्वरूप में अनिश्चित और व्यक्तिगत होती है। यह अलग-अलग व्यक्ति के भाव जलग-जलग होती है। उदाहरण के लिए, एक आदमी रिश्वत लेने को सर्वथा अनैतिक मान सकता है, और दूसरा इसे स्वीकार करने को सर्वथा उचित समझ सकता है।

चौथे, नैतिक विधियाँ या नियम सही और गलत, न्याय तथा अन्याय, के निरपेक्ष मानदण्ड बनाने हैं, पर विधि सामाजिक औचित्य (expediency) के मानदण्ड पर चलती है। जिस काम का विधि निषेध करती है, हो सकता है कि वह अनैतिक कार्य न हो, पर वह जनता के मंगल और देश के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए, तेज मोटर चलाना अनैतिक नहीं है, पर वह विधि द्वारा निषिद्ध है।

विधि और नैतिकता का सम्बन्ध—विधि और नैतिकता इन दोनों का उद्गम एक था। प्राचीन काल के समाजों में नैतिक नियमों और सामाजिक

धातमय के नियमों में कोई भेद नहीं किया जाता था। धीरे-धीरे उनमें भेद किया जाने लगा। अनेक संघों के होने हुए भी इन दोनों का सम्बन्ध आज भी बड़ा घनिष्ठ बना हुआ है। राज्य की विधियों के लिए आवश्यक है कि वे नैतिक नियमों के विरुद्ध न हों। उनके महात्म्यापूर्वक पालन के लिए यह आवश्यक है कि वे लोगों में मौजूद नैतिकता के मानदण्ड के विरुद्ध न हों। उदाहरण के लिए, ग़राब लोगों के विरुद्ध बार्डर् गेट् विधि का उन लोगों में चालन होता कठिन है जिनमें शराब पीने की आदत लोगों में बहुत आम है, पर विविध नैतिकता का ओशित मानदण्ड बनाने में भी बड़ा बार्ड करनी है। इसी जमाने में सती प्रथा और बाल विवाह बहुत आम चीज थी। कानून बन जाने पर ही ये प्रथाएँ रहीं।

स्वतन्त्रता या स्वाधीनता

स्वतन्त्रता हिमे कहते हैं—स्वतन्त्रता का मतार्थ है जो कुछ आदमी चाहे वह करने की आजादी, पर ऐसी स्वतन्त्रता असम्भव है। हम कुछ नियमों के बिना इच्छा नहीं रह सकते और नियमों का मतलब है हमारे बायों पर श्रावटें। इस प्रकार नागरिकों सामाजिक जीवन सभी सम्भव है, यदि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ निर्बन्धित स्वतन्त्रता हो। दूसरी ओर, यदि हर आदमी अपनी इच्छानुसार काम करना चाहे, तो लोगों में लडाइयाँ भी होती हैं। इसलिए स्वतन्त्रता का अर्थ है जब कुछ करने की आजादी बनने कि हमारे दूगों की आजादी को हानि न पहुँचे।

स्वाधीनता के प्रकार—स्वाधीनता शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग हुआ है इसलिए हमें इसके अर्थों की साफ़ तौर से समझने के लिए हर्षे इसके अनेक अर्थों में भेद करना चाहिए।

प्राकृतिक या नैसर्गिक स्वाधीनता—अबोध या निचबल में आजादी को नैसर्गिक स्वाधीनता कहते हैं। यह मनुष्य के अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के अपनी अधिकार को बताती है पर ऐसी स्वाधीनता सिर्फ़ बगली पशुओं में है। कहा जाता है कि यह अवस्था मनुष्य सुविदा निदान की बालनिक विमर्शविम्बा में मनुष्यों में भी मौजूद थी। यह स्वाधीनता समाज में रहते हुए मनुष्यों में कभी नहीं हो सकती। नैसर्गिक स्वाधीनता का विचार मुनने में बड़ा आकर्षक लगता है, पर व्यवहार में यह कभी भी नहीं जा सकता। यदि ऐसे व्यवहार में लाया जाय तो सबसे पहले आदमी को ही ऐसी स्वाधीनता मिल सकती है। अन्य लोग इस एक आदमी के गुलाम मात्र होंगे, और उन्हें कोई स्वाधीनता नहीं होगी। फिर सबसे सबल आदमी को भी नैसर्गिक स्वाधीनता स्थायी रूप में प्राप्त नहीं हो सकती। यह उने तब तक ही मिल सकती है, जब तक कोई अधिक बलवान आदमी उसे न मिले। इस प्रकार नैसर्गिक स्वाधीनता सब के लिए नहीं हो सकती।

नागरिक स्वाधीनता—नैसर्गिक स्वाधीनता में विरुद्ध नागरिक स्वाधीनता वह स्वाधीनता है जो मनुष्य को समाज में मिलती है। यह स्वाधीनता माना में

सीमित हो सकती हैं, पर यह वास्तविक, स्थायी, और समान के सब सदस्यों के लिए समान होती है। यह सब के लिए वास्तविक, स्थायी, और समान इस कारण होती है क्योंकि इसका उपभोग विधि के संरक्षण में किया जाता है। इस प्रकार नागरिक स्वाधीनता राज्य द्वारा जनित और रक्षित होती है।

नागरिक स्वाधीनता राज्य द्वारा स्वीकृत और प्रवर्तित अधिकारों के कुल योग को कहते हैं। जीवन और सम्पत्ति का अधिकार नागरिक स्वाधीनता के उदाहरण हैं।

राजनैतिक स्वाधीनता—राजनैतिक स्वाधीनता का अर्थ है नागरिकों को सरकार के चुनाव और परिचालन में हिस्सा लेने की आजादी। इसमें मत देने का अधिकार, चुने जाने का अधिकार, गवर्नरी पद धारण करने का अधिकार, और सरकार की नीति पर आजादी से विचार करने और उसकी आलोचना करना शामिल है।

सार्वभौमिक स्वाधीनता—यदि स्वाधीनता की, संविधान द्वारा, सरकार की दखलदाजी से भी रक्षा की जाती है तो इसे सार्वभौमिक स्वाधीनता कहते हैं।

आर्थिक स्वाधीनता—आर्थिक स्वाधीनता का अर्थ है अभाव के छुटकारा। आर्थिक स्वाधीनता के बिना, और सब प्रकार की स्वाधीनता निरर्थक हो जाती है। आजादी तब तक वास्तविक नहीं हो सकती जब तक आदमी को जीवन धारण की आवश्यकताएँ मिलनी सुनिश्चित न हों। हर आदमी को बरोखारी में बचाना चाहिए। उसे निर्वाह मजदूरी भी सुनिश्चित रूप में मिलनी चाहिए।

राष्ट्रीय स्वाधीनता—यह एक राष्ट्रियता में जादूझ लोगों के लिए आजाद, अनाश्रित और सर्वोच्च राज्य को सूचित करती है। राष्ट्रीय स्वाधीनता जगत् सब प्रकार को स्वाधीनता से अस्तित्व और पूर्ण उपभोग के लिए परम आवश्यक है। यह नागरिक, राजनैतिक और आर्थिक स्वाधीनता का मूल है।

विधि और स्वाधीनता का सम्बन्ध—जब से राज्य का जन्म हुआ है, तब से ही विधि और स्वाधीनता की समस्या एक महत्वपूर्ण विषय रही है। व्यक्तिवादी, अराजकतावादी, सिट्टिकेल्स्ट और बहुत से अन्य मतधारियों का यह कहना है कि स्वाधीनता और विधि में सामंजस्य नहीं हो सकता। ऊपरी दृष्टि में देखने वाले को भी विधि और स्वाधीनता शब्द एक दूसरे के विरोधी प्रतीत होंगे, क्योंकि विधि का मतलब है अवरोध लगाना, और स्वाधीनता का अर्थ है अवरोधों का न होना। पर यदि हम स्वाधीनता का अर्थ नानैतिक स्वाधीनता समझें तो विरोध शीघ्र ही खत्म हो जाएगा। यदि विधि और स्वाधीनता एक दूसरे के विरोधी होने लगे तो राज्य कभी का सत्तन हो गया होता। यह तथ्य ही कि यह इतने समय तक कायम रहा है और अब भी कायम है, प्रदर्शित करता है कि दोनों में कोई विरोध नहीं है।

विधि और स्वाधीनता परस्पर विरोधी तो हैं ही नहीं। वे अलग में महत्वपूर्ण हैं। तथ्यतः नागरिक स्वाधीनता विधि द्वारा पैदा की गई है। विधि सिर्फ नैतिक

स्वाधीनता की शय है। हम पहले ही देख चुके हैं कि नैसर्गिक स्वाधीनता कोई स्वाधीनता नहीं, नशोक यह अपिस्तर कालान्तर और अस्थायी है। यह सिद्ध होड़े से लोगो के लिए है। जो चीज वास्तविक, स्थायी और पक्की है वह नागरिक स्वाधीनता है। विधि ही नागरिक स्वाधीनता को वास्तविक और स्थायी बनानी है। नागरिक स्वाधीनता सीमित प्रकार की स्वाधीनता ही सकती है और इसके अनन्त वह सर आजादी है, जो मनुष्य और समाज के पूर्ण और चतुर्मुखी विकास के लिए पाछनीय है। आदमी समाज और राज्य के सदस्य के रूप में जिन अनेक अधिकारों का उपयोग करता है, वे विधि की देन हैं। ये अधिकार आदमी को हमारे लोगो के व्यक्तित्व के विकास में बिना बाधा डाले अपने व्यक्तित्व का विकास करने की पूरी स्वाधीनता देते हैं। विधि न हो तो आदमी के व्यक्तित्व का विकास तो ही नहीं सकता, उसके जीवन को भी हमेशा खतरा बना रहेगा। इस प्रकार हम यह कहते हैं कि विधि स्वाधीनता की मित्र है।

पर हमने हमें यह न समझ लेना चाहिए कि विधि महा स्वाधीनता की मित्र होनी है। जहां सरकार और समाज का गठन सम्मुख लोकतन्त्रीय होना है, वहां यह निश्चित रूप से स्वाधीनता की मित्र होनी है, पर जिन देशों में सरकार अल्प-देशीय होनी है, उनमें विधि स्वाधीनता की मित्र नहीं होनी। विधि और स्वाधीनता का उन समाजों में भी मेल नहीं बैठता जहां सामान्य एक या कुछ घोड़े से व्यक्तियों के हाथों में होता है।

विधि और स्वाधीनता के संबंध के प्रश्न में दो बातें और याद रखनी चाहिए, प्रथम तो विधि द्वारा नागरिकों पर लगाए गए अवरोध सब आदमियों के लिए समान होने चाहिए और पूर्ण निष्पक्षता से लागू किए जाने चाहिए। दूसरी बात यह कि वे अवरोध मुनिउत्पन्न होने चाहिए और समाज को उनके औचित्य का विश्वास होना चाहिए। वे बातें न होने पर विधि और स्वाधीनता में मेल नहीं रह सकता। उन अवस्था में लोग विधि को बार बार चुनौती देंगे।

समता

समता एक और शब्द है जिसे प्रायः लोग गलत रूप में समझते हैं। यह कहना तो ठीक है कि सब मनुष्यों को जन्म से साथ रहिया मिलती है। उनमें शारीरिक बल, इच्छाएं, वागनाएँ और मानसिक योग्यताएँ भी एक-सी ही मालूम होती हैं। इसलिए इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सब आदमियों के साथ एक-सा व्यवहार होना चाहिए। पर समता का यह विचार अनिर्जित विचार है और इसका तथ्यों से मेल नहीं बैठता। समाज में कोई दो वस्तुएँ एक-सी नहीं होती। मनुष्य भी अपने शारीरिक और मानसिक गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इस प्रकार, हम यह कह सकते हैं कि मनुष्यों में एक प्रकार की नैसर्गिक विषमता है। इन नैसर्गिक विषमताओं को दूर कर देना मनुष्य की शक्ति के बाहर है, चाहे वह अपने लिए

कितना भी यत्न करे। पर नैसर्गिक विषमताओं के अलावा मनुष्यकृत विषमताएँ भी हैं जिन्हें मनुष्यों द्वारा हटाया जा सकता है। जन्म, धन-दौलत, मूलवश, (race), धर्म, रंग, जाति या वर्ण, और लिंग के भेद भाव पर आधारित विषमताएँ मनुष्यकृत विषमताएँ हैं।

इस प्रकार नागरिक शास्त्र में जब हम समता की बात कहते हैं तब इससे हमारा अभिप्राय मनुष्यकृत विषमताओं को खत्म करना ही होता है। नागरिक शास्त्र में हमारी समता की अवधारणा यह मानकर चलती है कि प्रकृति द्वारा जनित विषमताएँ सदा दली रहेंगी। समता शब्द को जिस रूप में अब हम समझते हैं, उसमें इसका अर्थ होगा :—

(१) विधि के समक्ष समता।

(२) एक-ही अर्हताओं वाले सब आदमियों को और किसी बात का विचार किए बिना समान अवसर देना।

यह निश्चय है कि समान अवसर दिए जाने के बाद कुछ लोग अपनी नैसर्गिक योग्यता द्वारा औरो से बहुत आगे बढ़ जाएँगे। समान अवसर का अर्थ एक ही व्यवहार नहीं है।

स्वाधीनता और समता में सम्बन्ध

यदि स्वाधीनता का अर्थ नैसर्गिक स्वाधीनता हो और समता का अर्थ व्यवहार, धर्म और पुरस्कार की अभिन्नता हो, तो स्वाधीनता और समता एक दूसरे की विरोधी होंगे। नैसर्गिक स्वाधीनता समता की विरोधी है क्योंकि यह सबके लिए समान नहीं हो सकती। इसी प्रकार सब व्यक्तियों की योग्यता अर्हता पर बिना विचार किए सीधी समानता का अर्थ वास्तव में योग्य व्यक्तियों को स्वाधीनता से वंचित करना होगा क्योंकि उस अवस्था में मूर्ख और बुद्धिमान को समान पुरस्कार मिलेगा पर जिन अर्थों में स्वाधीनता और समता शब्दों को नागरिक शास्त्र में प्रयुक्त किया जाता है, उन अर्थों में वे एक दूसरे की विरोधी नहीं। जन्म, धन-दौलत, मूलवश, धर्म, जाति या वर्ण, रंग और लिंग पर आधारित मनुष्यकृत विषमताओं को हटाना और इन बातों का बिना विचार किए सब आदमियों को समान अवसर देना लोगों की स्वाधीनता में वृद्धि करता है। फिर, नागरिक शास्त्र में समता का जो अवधारण है उसका लक्ष्य उन लोगों को समान करना नहीं है जो निस्सर्वत असमान हैं या जिनमें अलग-अलग अर्हताएँ और योग्यताएँ हैं। इसलिए हमका लक्ष्य समर्थ लोगों की स्वाधीनता को कम करना नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वाधीनता और समता एक दूसरे की विरोधी नहीं हैं।

अपराध और दण्ड

अपराध और इसके दण्ड की समस्या सब युगों और सब देशों में रही है, चाहे वह बाल या देव कितना ही अच्छा रहा हो। इसका कारण यह तथ्य है कि गलती

स्वाधीनता की शुरु है। हम पहले ही देख चुके हैं कि नैसर्गिक स्वाधीनता कोई स्वाधीनता नहीं, क्योंकि यह अधिकतर काल्पनिक और अस्थायी है। यह सिर्फ थोड़े से लोगों के लिए है। जो चीज वास्तविक, स्थायी और पक्की है वह नागरिक स्वाधीनता है। विधि ही नागरिक स्वाधीनता को वास्तविक और स्थायी बनाती है। नागरिक स्वाधीनता सीमित प्रकार की स्वाधीनता हो सकती है और इसके अंतर्गत वह सब बाधाओं है, जो मनुष्य और समाज के पूर्ण और चतुर्मुखी विकास के लिए बाधनीय है। आदमी समाज और राज्य के सदस्य के रूप में जिन अनेक अधिकारों का उपयोग करता है, वे विधि की देन हैं। ये अधिकार आदमी को दूसरे लोगों के व्यक्तित्व के विकास में बिना बाधा डाले अपने व्यक्तित्व का विकास करने की पूरी स्वाधीनता देते हैं। विधि न हो तो आदमी के व्यक्तित्व का विकास तो ही ही नहीं सकता, उसके जीवन को भी हमेशा त्रस्त बना रहेगा। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि विधि स्वाधीनता की मित्र है।

पर हमसे हमें यह न समझ लेना चाहिए कि विधि सदा स्वाधीनता की मित्र होती है। जहां सरकार और समाज का गठन मजबूत लोकतंत्रीय होता है, वहां यह निश्चित रूप से स्वाधीनता की मित्र होती है, पर जिन देशों में सरकार अल्प-देशीय होती है, उनमें विधि स्वाधीनता की मित्र नहीं होती। विधि और स्वाधीनता का उन समाजों में भी मेल नहीं बैठता जहां शासन एक या कुछ थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में होता है।

विधि और स्वाधीनता के मेल के प्रयोग में दो बातें और याद रखनी चाहिए; प्रथम तो विधि द्वारा नागरिकों पर लगाए गए अवरोध सब जादमियों के लिए समान होने चाहिए और पूर्ण निष्पक्षता से लागू किए जाने चाहिए। दूसरी बात यह कि ये अवरोध युक्तिपूर्ण होने चाहिए और समाज को उनके जीवन का विकास होना चाहिए। वे बातें न होने पर विधि और स्वाधीनता में मेल नहीं रह सकता। उन अवस्था में लोग विधि को बार बार चुनौती देंगे।

समता

समता एक और शब्द है जिस प्रायः लोग बहुत रूप में समझते हैं। यह बहुत ही ठीक है कि सब मनुष्यों की जन्म से सब इशिया मिलती है। उनमें धार्मिक अंग, इच्छाएं, वासनाएं और मानसिक योग्यताएं भी एक-सी ही मालूम होती हैं। इसलिए इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सब जादमियों के साथ एक-सा व्यवहार होना चाहिए। पर समता का यह विचार अनिश्चित विचार है और इसका तथ्यों से मेल नहीं बैठता। मगार में कोई दो मनुष्य एक-सी नहीं होती। मनुष्य भी अपने शारीरिक और मानसिक गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इस प्रकार, हम यह कह सकते हैं कि मनुष्यों में एक प्रकार की नैसर्गिक विषमता है। इन नैसर्गिक विषमताओं को दूर कर देना मनुष्य की क्षमता के बाहर है, चाहे वह इसके लिए

कितना भी पल करे। पर नैसर्गिक विषमताओं के अलावा मनुष्यवृत्त विषमताएँ भी हैं जिन्हें मनुष्यों द्वारा हटाया जा सकता है। जन्म, धन-दौलत, मूलवश, (race), धर्म, रंग, जाति या वर्ण, और लिंग के भेद भाव पर आधारित विषमताएँ मनुष्यवृत्त विषमताएँ हैं।

इस प्रकार नागरिक शासन में जब हम समता की बात करते हैं तब इसमें हमारा अभिप्राय मनुष्यवृत्त विषमताओं को खत्म करना ही होता है। नागरिक शासन में हमारी गणना की अवधारणा यह मानकर बनती है कि प्रकृति द्वारा जनित विषमताएँ सदा बनी रहेंगी। समता शब्द को जिस रूप में अब हम समझते हैं, उसमें इसका अर्थ होगा—

(१) विधि के समान समता।

(२) एष-भी अर्हताओं वाले सब आदमियों को और किसी बात का विचार किए बिना समान अवसर देना।

यह निस्संदेह सच है कि समान अवसर दिए जाने के बाद कुछ लोग अपनी नैसर्गिक योग्यता द्वारा औरों से बहुत आगे बढ़ जाएँगे। समान अवसर का अर्थ एक ही व्यवहार नहीं है।

स्वाधीनता और समता में सम्बन्ध

यदि स्वाधीनता का अर्थ नैसर्गिक स्वाधीनता हो और समता का अर्थ व्यवहार का अर्थ और पुरस्कार की अभिन्नता हो, तो स्वाधीनता और समता एक दूसरे के विरोधी होंगे। नैसर्गिक स्वाधीनता समता की विरोधी है क्योंकि यह सबके लिए समान नहीं हो सकती। इसी प्रकार सब व्यक्तियों की योग्यता भर्तृता पर बिना विचार किए सीधी समानता का अर्थ वास्तव में योग्य व्यक्तियों को स्वाधीनता से वंचित करना होगा क्योंकि उस अवस्था में मूर्ख और बुद्धिमान की समान पुरस्कार मिलेगा पर जिन अर्थों में स्वाधीनता और समता शब्दों का नागरिक शासन में प्रयुक्त किया जाता है, उन अर्थों में वे एक दूसरे की विरोधी नहीं। जन्म, धन-दौलत, मूलवश, धर्म, जाति या वर्ण, रंग और लिंग पर आधारित मनुष्यवृत्त विषमताओं को हटाना और इन बातों का बिना विचार किए सब आदमियों को समान अवसर देना लोगों की स्वाधीनता में वृद्धि करता है। फिर, नागरिक शासन में समता का जो अवधारण है उसका लक्ष्य उन लोगों को समान करना नहीं है जो निस्सर्ग असमान हैं या जिनमें जलम-जल्प अर्हताएँ और योग्यताएँ हैं। इसलिए इसका लक्ष्य वस्तुतः समान लोगों की स्वाधीनता को कम करना नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वाधीनता और समता एक दूसरे की विरोधी नहीं हैं।

अपराध और दण्ड

अपराध और हमारे दण्ड की समस्या सब युगों और सब देशों में रही है, चाहे वह बाल या देश कितना ही अच्छा रहा हो। इसका कारण यह सत्य है कि मनुष्य

करनी मनुष्य का स्वभाव है। कभी-कभी अच्छे चरित्र और आशयो वाला आदमी भी अपराध कर देता है इसका कारण यह है कि अशुभ आदमी के लिए कानून के बारे में सब कुछ जानना कठिन है। पर कानून का अज्ञान कोई दलील नहीं। इसलिए जो आदमी भी अपराध करता है, चाहे वह जानते हुए करे या अनजाने हुए, उसे दण्डित होना पड़ेगा।

अपराध की समस्या से राज्य, समाज और व्यक्ति, सबका गहरा सम्बन्ध है। अपराध के बार-बार होने से राज्य के गौरव, समाज की शान्ति और व्यक्ति की स्वाधीनता को हानि पहुँचती है। इसके अलावा, अपराध की अधिकता इन तीनों पर बलर है। यह कहा जा सकता है कि अपराधों को रोकने की जिम्मेदारी राज्य की है। पर हमें यह याद रखना चाहिए कि यदि समाज और व्यक्ति राज्य की सहायता न करें तो अकेला राज्य अपराध को नहीं रोक सकता।

अपराध किसे कहते हैं—राज्य की विधि का या सर्वोच्च प्रभु के आदेश (command) का अतिक्रमण अपराध कहलाता है। राज्य सर्वोच्च प्रभु के रूप में अपने सैन्यों की बाह्य क्रियाओं को नियमित करने के लिए कुछ आदेश देता है। नियत सीमा से परे व्यक्ति का कोई भी कार्य निश्चय रूप से अपराध माना जाएगा।

पाप किसे कहते हैं—अपराध और पाप में अन्तर है। इन दोनों में तीन भेद हैं।

(१) अपराध किसी विधि का अतिक्रमण है और पाप किसी नैतिक उपदेश का अतिक्रमण है।

(२) अपराध का परिणाम राज्य द्वारा शारीरिक दण्ड या जुर्माना होता है। अपराध करने पर इसी दण्ड में आदमी को दण्ड मिलता है। दूसरी ओर, यदि कोई पाप साध हो कोई अपराध भी न हो तो उसका कोई शारीरिक दण्ड नहीं मिलता। पाप का दण्ड परलोक में सम्बन्ध रखता है।

(३) यद्यपि अधिकतर अपराध पाप भी होते हैं, तो भी दोनों एक ही बात नहीं हैं। सैज मोटर चलाना अपराध हो सकता है, पर यह पाप नहीं।

अपराधों के कारण—सब अपराधों का मूल आनुवंशिकता (heredity) या वातावरण या दोनों के प्रभाव में दूँदा जा सकता है। कुछ लोग जन्म से अपराध कर्ता होते हैं। उन्हें अपने माता-पिता में अपराध की प्रवृत्ति खून में ही मिलती है। कुछ तो जन्म से अपराध करने वाले नहीं होते, पर बुरे वातावरण के प्रभाव में अपराधी बन जाते हैं। उनका पालन पोषण बुरा हो सकता है, या वे बुरी संगत या परिस्थितियों में बढ गए हो सकते हैं। कुछ अपराधियों में दोनो प्रभाव काम कर रहे हो सकते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि अपराध अपराधी की प्रवृत्ति के कारण ही होता है। दूसरी ओर, अपराधों के अनेक कारणों का वातावरण से विरूपण करने से हमें पता चड़ेगा कि वातावरण का प्रभाव आनुवंशिकता से

भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। अधिकतर अपराधी अपने वातावरण के शिकार हो जाते हैं।

आनुवंशिकता—आनुवंशिकता अपराधियों के बर्तनों में ही अपराध का कारण होती है। बच्चे में अपने अपराधी माता पिता से कुछ मानसिक और शारीरिक असामान्यताएँ आती हैं। इन असामान्यताओं से बच्चे में भी अपराध की आदत का विकास होने में सुविधा होती है। पर यह कहना सही नहीं कि अपराधी का पुत्र हमेशा अपराधी ही होगा। अच्छे वातावरण में रहने में आनुवंशिक प्रभाव दबे रह सकते हैं।

वातावरण—वातावरण आदमी के जीवन में बर्तन से स्वरूप बड़ी उन्नत तक पहुँच महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। प्रथम तो गरिबाओं में बच्चों के शालन-शोषण पर बहुत कुछ निर्भर है। छोट प्यार करने वाले माता पिता प्रायः अपने बच्चों को बिगाड़ देते हैं। बच्चे पर बाहरी प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है और उसमें अनुकरण की प्रवृत्ति भी बहुत होती है। वह अपने माता-पिता की सब आदतें और फिशाएँ सीख लेता है। यही कारण है कि अपराधी माता पिता के बच्चे मुश्किल से ही अच्छे नागरिक बन सकते हैं।

दूसरे, वातावरण में वे सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक प्रभाव भी शामिल हैं जो समाज स्थिति पर डालता है। धार्मिक रुढ़िवा ना मुस्लिम, गरीब शक्तिशाली का पीड़ित, गरीबी और बेरोजगारी इन सबका परिणाम अपराध होता है। विधवा विवाह पर रोक, दहेज प्रथा और जात पाति के बन्धन सामाजिक अत्याचार के उदाहरण हैं। जब किसी आदमी को गरीबी भूख और उन्नत परिणामस्वरूप मौत का सामना करना पड़ता है, तब ही यह कोई भी अपराध कर सकता है। शराब पीने और जुआ खेलने की घुरी आदतें भी अपराध को बढ़ावा देती हैं। अन्तिम बात यह है कि किसी अन्यदोषी गश्तार की राजनैतिक अधीनता अच्छे से अच्छे लोगों से भी जानबूझ भगवती है।

दण्ड और उसके सिद्धान्त—राज्य समाज में शांति रखने के लिए विधि के अतिशय पर दण्ड देता है। यदि अपराधियों को दण्ड न दिया जाय तो व्यष्टियों के अधिपत्य और स्वाधीनता सुरक्षित नहीं रह सकते। फिर यदि अपराधों पर दण्ड न दिया जाय तो दूम्मे लोगों को अपराध करने के लिए बढ़ावा मिलेगा। हमें याद रखना चाहिए कि अपराध की प्रवृत्ति हम सब में है पर हम दण्ड के भय से अपराध नहीं करते। यदि ऐसा भय न हो तो कोई भी अपराध करने में संकोच नहीं करेगा। सब लोग राज्य की मत्ता का निगाहर करने लगेंगे और क्षत्र शौर्य को बड़ी हानि पहुँचेगी। इसलिए, विधि के अतिशय पर दण्ड देना विस्तृत आवश्यक है। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि दण्ड की प्रवृत्ति कौसी होगी चाहिए।

दण्ड की प्रवृत्ति और प्रयोजन के बार में तीन प्रमुख दृष्टिकोण या सिद्धान्त हैं—

(१) प्रतिशोधात्मक दण्ड का सिद्धान्त।

(२) प्रतिरोधक दण्ड का सिद्धान्त ।

(३) सुपायसमक दण्ड का सिद्धान्त ।

प्रतिशोभामक सिद्धान्त—दण्ड के बारे में यह सबसे पुराना सिद्धान्त है । प्रतिशोध का अर्थ है बदला । इस प्रकार उस सिद्धान्त के अनुसार दण्ड देने के पीछे प्रयोजन यह था कि अपराधी द्वारा किए गये अपराध के लिए दूसरे बदला लिया जाय । आँख के बदले आँख, दाँत के बदले दाँत, का मूल इस सिद्धान्त के प्रयोजन को बड़ी बेचड़ी तरह स्पष्ट करता है । पहले जमाने में, जब राज्य अभी ईशव व्यवस्था में ही था, अपराध एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध किया गया होय माना जाता था और पीड़ित व्यक्ति को दूसरे में बदला लेने की आशा ही थी । सैल्मन कालीन इंग्लैंड में हत्यारे को मृतक के आश्रितों को उसकी कीमत चुकानी पड़ती थी । धीरे-धीरे अपराध राज्य के विरुद्ध किया गया होय भी माना जाने लगा । राज्य अपराधी को दण्ड देने लगा और पीड़ित व्यक्ति का कोई हान न रहा । राज्य के दण्ड के पीछे भी बदले का ही विचार था, क्योंकि अपराध को राज्य का अपमान माना जाता था । अपराधी को दण्ड देकर राज्य के लिए अपनी मर्यादा बनाए रखना पड़ती थी ।

प्रतिशोध वाला विचार राज्य द्वारा दिए गए दण्ड में आज भी मौजूद है । पर यह स्पष्ट देखते हुए कि आज राज्य मण्डकारी राज्य है, यह विचार प्रतिष्ठा नहीं पा सकता । अपराधियों ने बदला लेना राज्य को शोभा नहीं देता । बदला लेना अनैतिक है । राज्य सबका सुमनाशी है, इस नाते उसे अपराधियों के कल्याण पर भी विचार करना चाहिए । प्रतिशोभामक सिद्धान्त अपराधी के कल्याण की ओर कोई ध्यान नहीं देता ।

प्रतिशोधक सिद्धान्त—उस सिद्धान्त के अनुसार दण्ड का लक्ष्य, बने पहले, अपराधी को सजा अपराध या गुनाह करने से रोकना होना चाहिए । दूसरे, अपराधी को दिया गया दण्ड ऐसा होना चाहिए जो समाज के अन्य सदस्यों के चित्त में भय पैदा करे, या दूसरे शब्दों में, अपराधी को दिया गया दण्ड उदाहरण रूप होना चाहिए जिससे दूसरे लोग वह अपराध करने से डरें । पिछले जमाने में निर्जित या अपराधी को पत्थर आदि से मार कर मृत्यु कर डालने और सूरी पर चढ़ाने जैसे दण्डों के पीछे और आक्रान्त फाँसी की सजा के पीछे यह प्रतिशोधक सिद्धान्त ही काम करता है । प्राचीन और मध्य कालीन युगों में अनेक प्रकार के अपमाननीय दण्ड दिये जाते थे । सूरी पर चढ़ाने और पत्थरों से मार डालने के अलावा कान, नाक, हाथ और पैर काट डालना, आँखें निकाल देना, अपराधी को शरीर के पैरों लगे कुचन्द्रा देना, आदि पाण्डित्य दण्ड दिये जाते थे, जो मनुष्य से लोगों के मन में भय पैदा करने के लिए विनियोजित थे । ऐसे अधिकतर अपमाननीय दण्ड आज के जमाने में नहीं हैं क्योंकि आज के जमाने में इन्हें सब जगह बुरा समझा जाता है ।

प्रतिरोधक दण्ड के सिद्धान्त में ये पगिया हैं

१. इसके तर्क के अनुसार, यह होना चाहिए कि कोई अपराध जितनी अधिक बार होता हो उसकी सजा उतनी ही अधिक होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि यदि चोरिया हत्याओं की अपेक्षा अधिक होती है तो हत्याओं की अपेक्षा चोरियों के लिए अधिक दण्ड मिलना चाहिए। यह बात स्पष्ट तौर से बहूदा है। हमें किसी अपराध की गम्भीरता में जिस अधिकार का अतिव्रमण किया गया है, उसके महत्व के अनुसार नापनी चाहिए। जीवन का अधिकार सम्पत्ति के अधिकार की अपेक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हत्या के लिए बड़ी सजा होनी चाहिए।

२. इस प्रकार, यह सिद्धान्त यह मान कर चलता है कि यदि एक बार कोई अपराध होता है तो और लोग भी वह अपराध करेंगे। पर ऐसा मान लेना अवारण है। कुछ अनिश्चित मनो में बचने मात्र के लिए अपराधी को भारी दण्ड देना न्याय विरुद्ध है।

३. प्रतिरोधक सिद्धान्त अपराध के लिए अपराध का सारा दोष अपराधी पर डालता है। यह अपराध में वातावरण के प्रभाव की अपेक्षा करता है।

४. यह सिद्धान्त एक अपराधी को एक साध्य का साधन बनाता है और वह साध्य है दूसरों के सामने उदाहरण पेश करना। पर अपराधी को अपने आप में एक साध्य मानना चाहिए, किसी साध्य का साधन नहीं।

५. प्रतिरोधक दण्ड से अपराधी के और पक्का हो जाने की सम्भावना रहती है।

सुधारात्मक सिद्धान्त—अन्य दो सिद्धान्तों के मुकाबिले में यह सिद्धान्त मानव प्रकृति के विषय में अधिक आशावादी विचार रखता है। उससे अनुसार अधिकतर अपराधी प्रकृति से बुरे नहीं होते, बल्कि परिस्थितियों और वातावरण के कारण बुरे हो जाते हैं। इस सिद्धान्त के समर्थक अपराधी के कल्याण पर बल देते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार, यदि कोई अपराधी बार-बार अपराध कार्य करते अन्यथा सिद्ध न कर दे तो उसे समाज के हाथ से निकल गया नहीं मानना चाहिए। यह कष्ट देने की बुराई करता है और अपराधी के लिए सहानुभूति रखने को कहता है। अपराधी को समाज के लिए फिर दान्तिपूर्ण नागरिक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यह सिद्धान्त अपराध को एक रोग मानता है और मरीज की तरह अपराधी का इलाज होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए जेलों की जगह हस्पताल और सुधारालय होने चाहिए। इस सिद्धान्त में तर्कसंगत विश्वास था यह अर्थ भी होगा कि एक अपराध का दण्ड दो अपराधियों के लिए एक होना आवश्यक नहीं। जिनने पहली बार अपराध किया है उससे, अभ्यस्त अपराधी की अपेक्षा, अधिक नरमी से दया होना चाहिए।

प्रतिरोधात्मक और प्रतिरोधक सिद्धान्तों की प्रतिक्रिया के रूप में सुधारात्मक सिद्धान्त बड़ा स्वागत योग्य है। जेलों की अवस्थाओं में मामूलबुल परिवर्तन

(२) प्रतिशोधक दण्ड का सिद्धान्त ।

(३) सुपारात्मक दण्ड का सिद्धान्त ।

प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त—दण्ड के बारे में यह सबसे पुराना सिद्धान्त है । प्रतिशोध का अर्थ है बदला । इस प्रकार उस सिद्धान्त के अनुसार दण्ड देने के पीछे प्रयोजन यह था कि अपराधी द्वारा किए गये अपराध के लिए हमें बदला लिया जाय । आंस ने बढ़ते आंस, दात के बढ़ने दात, का सूत्र इस सिद्धान्त के प्रयोजन को बड़ी अच्छी तरह स्पष्ट करता है । पहले जमाने में, जब राज्य अभी संशुद्ध अवस्था में ही था, अपराध एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध किया गया दोष माना जाता था और पीड़ित व्यक्ति को दूसरे ने बदला देने को आजादी थी । संकमन कालीन इंग्लैंड में हत्यारे को मुक्त के अधिकारों को उसकी कीमत चुकानी पड़ती थी । घीरे-भारे अपराध राज्य के विरुद्ध किया गया दोष भी माना जाने लगा । राज्य अपराधी को दण्ड देने लगा और पीड़ित व्यक्ति का कोई हाथ न रहा । राज्य ने दण्ड के पीछे भी बदले का ही विचार था, क्योंकि अपराध को राज्य का अपमान माना जाता था । अपराधी को दण्ड देकर राज्य के लिए अपनी मर्मांश बनाए रखना जरूरी था ।

प्रतिशोध वाला विचार राज्य द्वारा लिए गए दण्ड में आज भी मौजूद है । पर यह स्पष्ट देखते हुए कि आज राज्य मंगलकारी राज्य है, यह विचार प्रतियुक्त नहीं था सकता । अपराधियों के बदला लेना राज्य को शोभा नहीं देता । बदला लेना अनैतिक है । राज्य सबका दुश्मनाशी है, इस नाते उसे अपराधियों के कल्याण पर भी विचार करना चाहिए । प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त अपराधी के कल्याण की ओर कोई ध्यान नहीं देता ।

प्रतिशोधक सिद्धान्त—दूसरा सिद्धान्त के अनुसार दण्ड का लक्ष्य, घात पहले, अपराधी को वैसा अपराध या गुनाह करने में रोकना होना चाहिए । दूसरे, अपराधी को शिक्षा गया वह ऐसा होना चाहिए जो समाज के अन्य सदस्यों के दिल में सब पैदा करदे, या दूसरे शब्दों में, अपराधी को दिया गया दण्ड उदाहरण रूप होना चाहिए जिससे दूसरे लोग वह अपराध करने में डरे । पिछले जमाने में लिंबिंग या अपराधी को पल्लर आदि में मार कर मृत्यु कर डालने और सूली पर चढ़ाने जैसे दण्डों ने पीछे और आजकल पागो की सजा के पीछे यह प्रतिशोधक सिद्धान्त ही काम करता है । प्राचीन और मध्य कालीन युगी में अनेक प्रकार के अमानवीय दण्ड दिये जाते थे । सूली पर चढ़ाने और पल्लरो में मार डालने के अलावा बान, नाक, हाथ और पैर काट डालना, आँखें निकाल देना, अपराधी को हाथी के पैरों में कुचलवा देना, आदि पारंपरिक दण्ड दिये जाते थे, जो मनुष्य ने लोगों के मन में भय पैदा करने के लिए निकाले थे । हमें अपमानित अमानवीय दण्ड आज के जमाने में नहीं है क्योंकि आज के जमाने में हमें सब जगह दया गमभीर जाता है ।

प्रतिरोधक दण्ड के सिद्धांत में ये समिया है

१. इसने तर्क के अनुसार, यह होना चाहिए कि कोई अपराध जितनी अधिक बार होता हो उमरों मरना उतनी ही अधिक होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि यदि चोरिया हत्याओं की अपेक्षा अधिक होनी हैं तो हत्याओं की अपेक्षा चोरियों के लिए अधिक दण्ड मिलना चाहिए। यह बल स्पष्ट तौर से बहूदा है। हमें बिना अपराध की गम्भीरता में जिन अधिकार का अनिवार्य विद्या गया है, उमरों महत्त्व व अनुसार माननी चाहिए। जीवन का अधिकार समाप्ति व अधिकार की अपेक्षा बहुत महत्त्व पूर्ण है। इसलिए हत्या के लिए बड़ी मरना होनी चाहिए।

२. इन प्रकार, यह सिद्धांत यह मान कर चलता है कि यदि एक बार कोई अपराध होता है तो और लोग भी वह अपराध करेंगे। परंतु मान लेंता अपराध है। कुछ अभिविक्त भवों व बचने मानक व लिए अपराधी को भारी दण्ड देना न्याय विपक्ष है।

३. प्रतिरोधक सिद्धान्त अपराध के लिए अपराध का तात्पर्य अपराधी पर डालता है। यह अपराध में मानावरण के प्रभाव की अपेक्षा करता है।

४. यह सिद्धान्त एक अपराधी को एक माध्यम का साधन बनाता है और एक माध्यम है दूसरी के सामने उदाहरण देकर करना। पर अपराधी को अपने आप में एक माध्यम मानना चाहिए, बिना माध्यम का साधन नहीं।

५. प्रतिरोधक दण्ड व अपराधी के और पराजित हो जाने की सम्भावना रहती है।

मुपारामक सिद्धान्त—अन्य दो सिद्धान्तों के मुकाबिले में यह सिद्धान्त मानव प्रकृति व विषय में अधिक आगावादी विचार रखता है। उमरों अनुसार अधिकतर अपराधी प्रकृति में बुरे नहीं होते, बल्कि परिस्थितियों और आलावरण के कारण बुरे हो जाते हैं। इस सिद्धान्त के समर्थक अपराधी के बर्तान पर बल देते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार यदि कोई अपराधी बार बार अपराध करने करने अथवा गिरफ्तार कर दे तो उन समाज के हाथ से निकल गया नहीं मानना चाहिए। यह स्पष्ट होने की बुराई करता है और अपराधी के लिए सहानुभूति रखने को कहता है। अपराधी को समाज के लिए फिर दानिपूर्ण नागरिक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यह सिद्धान्त अपराध को एक रोक मानता है और मरोड़ की तरह अपराधी का इलाज होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए जेजों की जगह हस्पताल और मुपाराम होना चाहिए। इन सिद्धान्त में तर्कमय विश्वास है। यह जर्न भी हवा कि एक अपराध का दण्ड दो अपराधियों के लिए एक होना आवश्यक नहीं। जिनमें पहली बार अपराध किया है उनसे, बर्तान अपराधी की अतीता, अधिक नरमी से धर्मा होना चाहिए।

प्रतिरोधक और प्रतिरोधक सिद्धान्तों की प्रतिक्रिया के रूप में मुपाराम-समर सिद्धान्त बड़ा स्वागत योग्य है। जेना की अवस्थाओं में बामूल्युक्त परिवर्तन

होना चाहिए और उन्हें अधिक अच्छा बनाया जाना चाहिए। अपराधी को उसके जेल जीवन में उचित प्रशिक्षण द्वारा सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। पर गुना-रात्मक मिद्वान्त भी कमियों में रहित नहीं है।

१. सुधार निम्नोक्त दण्ड देने में एक महत्वपूर्ण घटक होना चाहिए, पर सुधार पर ही साग और डालना समाज के हितों की अपेक्षा करना है। अपराधी अपने गैर-अभिप्रेत ध्येयद्वार के लिए समाज के प्रति भी उत्तरदायी है।

२. यह भी याद रखना चाहिए कि यदि अपराधी में अपने की सुधारने की इच्छा न हो तो सुधार के प्रयत्नों में कोई नैतिक विफल नहीं हो सकता।

३. यह विश्वास कि पात्रावरण या समाज अपराध के लिए अधिक दोषी है, आशंका में रहित नहीं। इसका विरोधी विश्वास कि अपराध अधिकतर अपराधी की विप्लव प्रवृत्ति और अनुमानहीनता का परिणाम है, उतना ही प्रबल है।

४. सभी अपराध के लिए अलग-अलग दण्ड देना व्यवहार्य नहीं। कानून सब के लिए एक होना चाहिए। तब जनों की अत्यधिक विवेकविचार बेना पड़ेगा और वे प्रलोभनों में अधिक फसने की स्थिति में होंगे।

अन्त में हम यह कह सकते हैं कि दण्ड के तीनों मिद्वान्तों में सच्चाई का कुछ-कुछ भ्रम है। दण्ड के मजबूत मिद्वान्तों में तीनों मिद्वान्तों का उचित मिश्रण होना चाहिए। दण्ड के निम्नलिखित लक्ष्य उचित होंगे

१. दण्ड प्रथम तो, अपराध का निवारक होना चाहिए, पर वह अमानवीय न होना चाहिए। प्रभावशाली दण्ड के तहत दण्ड अधिक पाने अपराधी पेश करने लगते हैं। दण्ड किन्तु यदि अपराध के अनुपात में होना चाहिए। यह अनिवार्य कि दण्ड अपराध के महत्व के अनुसार होना चाहिए।

२. दण्ड को एक सामान्य का मानन मानना चाहिए। जो सामान्य सिद्ध करना अभीष्ट है, उसमें अपराधी का सम्मान और मार्गनिष्ठ शान्ति बनाए रखना भी शामिल होना चाहिए। अपराधी का सुधार देना ही महत्वपूर्ण है, जैसा विधि व्यवस्था की बनाए रखना।

सारांश

विधि

विधि का अर्थ और प्रकृति—हार्नेण्ड ने राजनैतिक विधि की यह परिभाषा की है "वाहरी मानवीय क्रिया का वह व्यापक नियम, जो सर्वोच्च राजनैतिक सत्ता द्वारा लागू किया जाता है।" इस प्रकार विधि राज्य का एक आदेश है जो उनकी सर्वोच्च सत्ता द्वारा नर्मायित होता है। विधि के अस्तित्व पर राज्य दण्ड देता है। राज्य के अन्तर्गत थोर कोई सत्ता विधि जारी नहीं कर सकती। स्वयं राज्य अपनी विधि में बद नहीं होता।

विधि के स्रोत—कृत्रिम विधि के सबसे पुराने स्रोतों में से है। बहुत सी सभ्यता

आजकल के जमाने में रुढ़ि बन गई । हिन्दुओं मुसलमानों और ईसाइयों की विधियाँ उनकी धार्मिक पुस्तकों में निरूपी थीं । आज के जमाने में विधि की अप्रगट बातों पर न्यायालयों के विनिश्चय और निधान मण्डलों द्वारा अधिनियमित (enacted) सविधियाँ (statutes) विधि के मुख्य स्रोत हैं ।

विधि के प्रकार विधियों का पहले इस प्रकार विभाजन किया जा सकता है —

१. संवैधानिक विधि, जो एक आदमी और दूसरे आदमी के सम्बन्धों को विनियमित करती है ।

२. लोक विधि, जो व्यक्ति और राज्य के सम्बन्धों को विनियमित करती है ।

३. अन्तर्राष्ट्रीय विधि, जो एक राज्य और दूसरे राज्य के सम्बन्धों को विनियमित करती है ।

लोक विधि का फिर यह वर्गीकरण किया जा सकता है

(१) सार्वभौमिक विधि, (२) प्रजासत्ताकीय विधि, (३) दण्ड विधि ।

विधि और नैतिकता का सम्बन्ध, दोनों में भेद करने वाली बातें — (१)

विधि निम्न बाहरी बातों से सम्बन्ध रखती है । नैतिकता प्रेरक भावों और आशयों को भी देखती है ।

(२) विधि के अतिशयण का परिणाम शारीरिक दण्ड या जुर्माना होता है ।

जिसी अनैतिक कार्य को समाज द्वारा आलोचना भर की जा सकती । (३) विधि मुनिविषय और स्वरूप में सार्वजनिक होती है । नैतिकता अप्रगट और वैयक्तिक होती है । (४) विधि सामयिक औचित्य के मानदण्ड के अनुसार चलती है । नैतिकता गलत और सही के निरपेक्ष मानदण्ड बनाती है ।

सम्बन्ध बताने वाली बातें—(१) विधि और नैतिकता दोनों का उद्गम एक

था । (२) राजनैतिक विधियों की स्थापना उनके नैतिक होने पर भी निर्भर है ।

(३) विधियाँ भी प्रायः नैतिकता को लागू करती हैं ।

स्वाधीनता स्वाधीनता किसे कहते हैं—नागरिक राज्य में स्वाधीनता के

हमारा मतलब है यह कुछ करने की आजादी यद्यपि यह दूसरों की आजादी को हानि न पहुँचाये । इसका अर्थ अवरोध का अभाव नहीं है ।

स्वाधीनता के प्रकार—(१) नैसर्गिक स्वाधीनता—अवरोध मुक्ति के अर्थ में

जो स्वाधीनता होती है, यह नैसर्गिक स्वाधीनता कहलाती है । ऐसी स्वाधीनता

समाज में सम्भव नहीं यह काल्पनिक, अव्यवहारिक और अस्थायी होती है । (२) नागरिक स्वाधीनता—यह वह स्वाधीनता है जो समाज में मनुष्य को प्राप्त होती है ।

यह भारतवर्ष, स्थायी और सबने लिए समान होती है, क्योंकि यह विधि द्वारा रक्षित होती है । (३) राजनैतिक स्वाधीनता—इसका अर्थ है सरकार चुनने और चलाने

में हिस्सा लेने की आजादी (४) सार्वभौमिक स्वाधीनता । (५) आर्थिक स्वाधीनता—

तमसि अर्थ ? अभाव से तृप्तता । (६) राष्ट्रीय स्वाधीनता ।

विधि और स्वाधीनता का सम्बन्ध - जयने साहित्य ग्रंथ की दृष्टि में ये परस्पर विरोधी प्रतीत होती हैं। स्पष्टवादी, अनात्मवादी और गिनितहेनित यह मानते हैं कि स्वाधीनता और विधि में समन्वय नहीं किया जा सकता। पर वास्तव में विधि स्वाधीनता की मित्र है। विधि नैतिक स्वाधीनता की राह है। पर यह अधिकारों के अन्त में नागरिक स्वाधीनता की गारण्टी और रक्षा करती है। दूतों और, डिस्टेंटरवादी और सामाज्यवादी राज्य की विधि स्वाधीनता की राह होती है। विधि का स्वाधीनता में समन्वय करने के लिए यह आवश्यक है कि लोग विधि को सुविश्वस्य समझते हों और इसे पूर्ण निष्ठापूर्वक से मानूँ किया जाना चाहिए।

सत्यता—नागरिक शास्त्र में सत्यता शब्द के दो अर्थ हैं —

(१) विधि के समस्त उपाय । (२) मन्त्री अहंता के मय लोगों को जय मन-शील, मूल्यवान्, धर्म, रय, आति या धर्म और निज पर बिना विचार किए समान अवसर देना ।

निम्नरुद्ध सामान अथवा दिये जाने के बाद कुछ लोच आन्तरी मूलनिक योग्यता द्वारा भीरी में आते रह जायेंगे । यमान वा अर्थ एक व्यवहार नहीं ।

स्वाधीनता और समता का सम्बन्ध—साक्ष्य—यदि हम अपनी दृष्टि में ये दोनों वास्तविक विरोधी प्रतीत होंगी। पर समता के ऊपर आधुनिक व्यवस्था के होने हुए समाज और नागरिक स्वाधीनता में कोई विरोध नहीं दिखाई देता। तब भी यह है कि समता का उत्पन्न अन्वयार्थ उन बहुत अधिक लोगों के लिए स्वाधीनता को जन्म देता है, जो धन, जन्म, दिग, मूलरस आदि की विशेषताओं भोगों में। दूसरी ओर, समता का हमारा अन्वयार्थ उन लोगों की स्वाधीनता में अन्विष्ट नहीं करता जिन्हें प्राप्ति में अधिक अच्छी स्थिति में रहता है।

अपराध और दंड- राज्य, मगान और व्यक्ति इन तीनों का अपराध की मर्यादा में गहरा सम्बन्ध है। अपराध की अधिकता इन तीनों पर बलक है।

अपराध होते कहते हैं—राज्य की विधि के बिना अनिवार्य को अपराध कहा जाता है। यद्यपि अधिनियम अपराध पाप भी होते हैं, तो भी दोनों बातें अभिन्न नहीं। पाप बिना नैतिक उपदेश के अनिवार्य को कहते हैं। अपराध करने पर राज्य द्वारा दण्ड दुनिया में धारोत्तिक दण्ड दिया जाता है या क्षमा किया जाता है। पाप का कोई धारोत्तिक दण्ड नहीं मिलता और हमरा दण्ड परलोक में मिलता है।

अपराध के कारण—मन अपराधी का मूल आनुवर्णिकता का या वातावरण का या दोनों का उभाव होता है। आनुवर्णिकता अपराधियों के वस्त्रों की अवस्था में ही अपराध का कारण होती है। अधिकतर अपराधी अपने वातावरण के कारण अपराधी बनते हैं। बुरी सामाजिक स्थिति, खराब आदतें, गरीबी और बेरोजगारी

लोगों को अपराध करने में दिष्ट मजबूर करती है।

दण्ड और उसके सिद्धान्त—प्रेमों के अधिकारों और स्वाधीनता को सुरक्षित करने के लिए अपराध का दण्ड अवश्य दिया जाना चाहिए। दण्ड के तीन प्रमुख सिद्धान्त ये हैं—

१. प्रतिशोधक दण्ड का सिद्धान्त—'आम के बदले आम और दान के बदले दात' के मूल में इसका प्रयोजन अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है।

२. प्रतिरोधक सिद्धान्त—इस सिद्धान्त के अनुसार दण्ड न केवल ऐसा होना चाहिए कि वह अपराधी को फिर वैसा ही अपराध करने से रोके बल्कि समाज के अन्य सदस्यों के मन में आतंक पैदा करने वाला भी होना चाहिए।

३. सुधारारमक सिद्धान्त यह सिद्धान्त अपराध को रोग मानता है। भोर रोगी की तरह इसका भी इलाज होना चाहिए और जेलों की जगह हस्पताल और सुधारालय होने चाहिए।

इन सिद्धान्तों में से कोई भी अकेला काफी नहीं। इन सबमें सत्य का कुछ अंश है। उचित दण्ड ऐसा होना चाहिए कि वह अमानवीय न हो, पर अपराध को रोक दे। दण्ड का लक्ष्य अपराधी का कल्याण और सार्वजनिक शान्ति बनाए रखना, ये दोनों ही होने चाहिए।

प्रश्न

QUESTIONS

१. विधि की परिभाषा करो। इसके स्रोत और प्रकार कौन कौन से हैं ?
(प० वि० १९५२)
- 1 Define 'Law' What are its sources and kinds ?
(P U 1952)
२. विधि की परिभाषा करो। किसी नागरिक को अच्छी विधियाँ बनवाने और बुरी विधियाँ खत्म कराने के लिए कौनसे साधन अपनाने चाहिए।
(प० वि० सितम्बर, १९५१)
- 2 Define 'Law' What means should a citizen adopt, to get good laws made and bad laws modified ? (P U Sep 1951)
३. विधि और नैतिकता में क्या सम्बन्ध है ?
- 3 What is the relation between law and morality
४. स्वाधीनता दण्ड से आम क्या सम्बन्ध है ? विधि और स्वाधीनता में क्या सम्बन्ध है ?
(प० वि० १९५१)
- 4 What do you understand by the term 'Liberty' ? What is the relation between 'Law and Liberty' ? (P U April 1951)
५. स्वाधीनता की परिभाषा करो। इसके कौन-कौन से प्रकार हैं ?
- 5 Define 'Liberty'. What are its various kinds ?
६. समता दण्ड से आम क्या सम्बन्ध है ? समता और स्वाधीनता में क्या सम्बन्ध है ?

सरकार—विधानांग, कार्याङ्ग, न्यायांग

सरकार किते कहते हैं—राज्य भंगूरी होना है और वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए इसे अपने काम कराने के लिए किसी भूत अन्विष्टा की जरूरत होती है। सरकार राज्य का वह अन्विष्टा है जिसके जरिये हमकी मत्ता का प्रकाशन होता है, और इसका प्रयोजन पूरा होता है। सरकार के विविध अंग इस काम में राज्य की सहायता करते हैं। राज्य की इच्छा विधानांग में रूप ग्रहण करती और अभिव्यक्त होती है। यह कार्यांग द्वारा अमल में लाई जाती है और न्यायांग द्वारा प्रवर्तित (enforced) कराई जाती है।

सरकार के अंग—आधुनिक सरकार के कार्य प्रायः तीन भागों में बंटे हुए हैं अर्थात् विधायक, कार्यात्मक और न्यायिक। इन तीन कार्यों के करने के लिए तीन ही अंग हैं। वे हैं विधानांग, कार्यांग और न्यायांग। जैसा ऊपर कहा गया है, विधानांग सरकार का वह अंग है जिसके जरिये राज्य की इच्छा रूप ग्रहण करती और अभिव्यक्त होती है। यह विधियाँ बनाता है। कार्यांग इन विधियों को लोगों पर लागू करने के लिए है। न्यायांग यह सुनिश्चित करने के लिए है कि राज्य में प्रत्येक व्यक्ति इन विधियों का ठीक-ठीक पालन करे।

विभिन्न अंगों का आपेक्षिक महत्व—तीनों अंग अपने-अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। इनमें से प्रत्येक शासन का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके बावजूद शासन के विभिन्न रूपों में किसी एक अंग को सामान्यतः औरों से ऊँची स्थिति प्राप्त होती है। निरंकुश राजनृप और तानाशाही शासनो में कार्यांग (राजा और तानाशाह) सर्वोच्च होते हैं। सघन (Federation) के अतिरिक्त अन्य लोकतन्त्रों में विधानांग को ऊँची स्थिति प्राप्त होती है। सघनों में न्यायिक उच्चता का सिद्धान्त चलता है, यद्यपि रिक्टनरलेड इस नियम का अपवाद है।

विधानांग—विधानांग के कार्य

विधान—विधानांग का करने महत्वपूर्ण काम विधियाँ बनाना है। नई विधियाँ बनाने के अलावा विधानांग मौजूदा विधियों का संशोधन और निरस्तन (repeal) भी करता है। कार्यांग और न्यायांग विधानांग द्वारा बनाई गयी विधियों

को लागू करते हैं और उनका निवेदन (Interpret) करते हैं। इस अर्थ में ही विधानमण्डल सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यदि विधियाँ बनायीं न जाएं तो उन्हें लागू और प्रवर्तित कैसे किया जा सकता है। कुछ विधान मंडलों को, जैसे ब्रिटिश संसद, सार्वधानिक विधि बनाने और समीक्षित करने की भी शक्तियाँ हैं।

वित्त का नियन्त्रण—आधुनिक काल में विधानमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण काम राज्य के वित्तों का नियन्त्रण करना है। लोकतन्त्र के युग में यह स्वाभाविक बात है कि विधानमंडल में लोगों के जो प्रतिनिधि हैं, उनकी आज्ञा न केवल विधियाँ बनाने में, बल्कि वित्त में भी अंतिम होनी चाहिए। उन्हें ही यह निश्चय करना चाहिए कि वे कौन से कर होंगे और उनसे होने वाली आमदनी कैसे खर्च की जाएगी। इस प्रकार, सरकार के वार्षिक बजट पर विधान-मंडल विचार करता है और उनका अनुमोदन करता है। इसे नये कर लगाने और पुराने कर बदलने या खत्म करने की शक्ति होती है। कामांग के विविध विभागों के खर्च को मंजूरी भी यह देता है। इस प्रकार विधानमंडल का सरकार के खर्च पर पूरा नियन्त्रण होता है।

कार्य पर नियन्त्रण—लोकतन्त्र में कार्यात्मक प्रवर्ध और प्रगति रूप में अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। तान के राष्ट्रपतीय रूप में, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, यह जिम्मेदारी प्रवर्ध है, पर शासन के समक्ष रूप में, जैसा कि भारत और इंग्लैंड में है, यह जिम्मेदारी विधानमंडलों में, जनता के प्रतिनिधियों की शक्ति, प्रगति है। विधान-मंडल मंत्रियों और उनके अधीन विभागों पर सख्त निगरानी रखता है। इनके सदस्यों को किसी भी मंत्री के विभाग के मामलों में आवश्यक पूछताछ करने के लिए उसमें प्रश्न करने का अधिकार है। विधान मंडल मंत्रियों के आचरण की निंदा करके उनकी हत्यापनाओं को अस्वीकार करके और उनके विपक्ष सीधे अविराग या प्रस्ताव पास करने उन्हें इस्तीफा देने को मजबूर कर सकता है।

अन्य कार्य—विधानमंडल कुछ अन्य कार्य भी करता है, अर्थात् निर्वाचन संबंधी, न्यायिक और कार्यकारी (Executive)। विधान मंडल अपने कार्य संचालन और कार्यवाही के लिए स्वयं अपने नियम बनाते हैं। वे अपने सदस्यों की शक्ति निर्धारित करते हैं, और चुनावों संबंधी विवादों का फैसला भी करते हैं। विधान मंडलों को मंत्रियों पर महाभियोग लगाने (impeaching) और उनकी बर्खास्त करने (trying) की शक्ति होती है और उन न्यायाधीशों को बर्खास्त करने की भी शक्ति होती है जो अप्रत्याचार के दोषी पाए जाएं। यूनाइटेड स्टेट्स में निवृत्तियों के मामले में और मंत्रियों पर हस्ताक्षर करने में राष्ट्रपति के साथ-साथ सेंनेट की भी शक्ति है। कुछ राज्यों में राज्य का अध्यक्ष भी विधान मंडल द्वारा निर्वाचित होता है।

विधान मंडल का षटन—विधान मंडल एकसदनी या एकचरे और द्विसदनीय या दोचरे (unicameral or bicameral) होते हैं, अर्थात् उनमें एक

सदन या दो सदन होने हैं। आजकल अधिकतर विधान मण्डलों में दो सदन होते हैं, अर्थात् प्रथम सदन या छोटा मन्था और द्वितीय सदन या बड़ा मन्था।

द्वितीय सदन—द्वितीय सदन या तो आनुवन्धित या नामजद का निर्वाचित या अथवा नामजद और अथवा निर्वाचित होने हैं। इंग्लैण्ड की लार्ड मन्था दुनिया का एकमात्र आनुवन्धित द्वितीय सदन है। विभिन्न देशों के दूसरे अधिकतर द्वितीय सदन अथवा परोक्ष निर्वाचन और अथवा नामजदगी में बने हुए हैं।

आनुवन्धित, नामजद और परोक्ष निर्वाचित द्वितीय सदनो की प्रथम सदनो की अपेक्षा, जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित होते हैं, कम शक्तियां होती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की सेंनेट, जो द्वितीय सदन है, ऐसा एकमात्र द्वितीय सदन है, जिसे प्रथम सदन से अधिक शक्ति प्राप्त है। इसका कारण यह है कि सेंनेट प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित विधान है, और वहाँ सरकार विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी नहीं।

द्वितीय सदनो के भय प्रत्यक्ष सामान्यतया स्थायी निराल हैं। वे जहाँ नामजद और निर्वाचित हैं, वहाँ भी उनके मारे सदस्य कभी नूब नहीं होते। प्रत्येक दो या तीन वर्ष बाद उनके एक तिहाई सदस्य बारी-बारी निकृत होते हैं और उनका स्थान पर नये सदस्य आ जाते हैं।

सब जगह द्वितीय सदन अधिकांश के लोगों का सदन भी है। द्वितीय सदन की सदस्यता के लिए अर्हता की आयु सामान्यतया प्रथम सदन वाली आयु की अपेक्षा ऊँची होती है।

प्रथम सदन—प्रथम सदन सब जगह एक निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। देश की निर्वाचन धर्मों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र विभिन्न देशों में प्रचलित चुनाव की विभिन्न रीतियों के अनुसार एक या अधिक सदस्य चुनता है। चुनाव दलीय आधार पर होते हैं। २५ वर्ष की या ऐसी ही आयु के सब नागरिकों को चुनाव में सहे होने का अधिकार होता है। प्रथम सदनो की अवधि सामान्यतया ४ से ५ वर्ष तक होती है। उनके आधार भी अलग-अलग होते हैं पर सदन बहुत बड़ा न होना चाहिए। प्रथम सदन में किसी भी अवस्था में ५०० से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए।

प्रथम सदन जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। इस नाते उसे द्वितीय सदन की अपेक्षा साधारणतया अधिक शक्तियां होती हैं। इन धन संबंधी मामलों में प्रायः अन्य (exclusive) नियमन प्राप्त होता है। जहाँ सामन में मन्त्रिमण्डल प्रणाली प्रचलित है, वहाँ प्रधान मंत्री प्रथम सदन का सदस्य होता है। मन्त्रिमण्डल दूसरे सदन की आशा इस सदन की इच्छाओं की अधिकांश परवाह करता है, क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधि सदन है और मन्त्रि परिषद इसके प्रति उत्तरदायी है।

इन पृष्ठभूमि में अब हम विधान मण्डल की व्यवधानी और द्विसदनी प्रणालियों के मूल-दोषों पर विचार करेंगे।

बचाती है। यदि गिरफ्तार सदन हो तो सम्भव है कि यह शक्ति के मद में भर जाए। तब हो सकता है कि यह डिस्टेंटर की तरह व्यवहार करे। इस प्रकार, यदि विधायक शक्ति को दो सदनों में बाँट दिया जाए तो जनता की अधिक स्वाधीनता प्राप्त होगी।

निहित स्वार्थों के प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक—कुलीन तथा या अल्पतम से जब लोकतंत्र में परिवर्तन होता है, तब कुछ निहित स्वार्थों को प्रतिनिधित्व देने के लिए द्वितीय सदन की आवश्यकता होती है। बड़े-बड़े जमींदारों और उद्योग पतियों को, जिनके निहित स्वार्थ हैं बानून बनाने में जनता के प्रतिनिधियों के साथ साझी बना लेना चाहिए। इंग्लैंड में लार्ड सभा इसी तरह बनी।

पैसों के आधार पर प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक है—प्रथम सदन में प्रतिनिधित्व क्षेत्रीय आधार पर होना है पर प्रतिनिधित्व की यह विधि पैसों पर प्रतिनिधित्व के प्रतिपादन को तनुष्ट नहीं करती। इस प्रकार, द्वितीय सदन का विभिन्न पैसों, पया किमानों, जमींदारों, पूँजीपतियों और मजदूरों, को प्रतिनिधित्व देने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक—उस अल्पसंख्यकों को, जिन्हें आम चुनावों में प्रथम सदन में स्थान पाने का कोई मौका नहीं है, विशेष प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

द्वितीय सदन के विषय में धुक्कियाँ—द्विसदनी प्रणाली के विषय प्रतिस्पर्धा बढ़ती जाती है। कहा जाता है कि द्वितीय सदन के लाभ गिरफ्तारों और अवास्तविक हैं। द्वितीय सदन के विषय में ये धुक्कियाँ हैं—

वे प्रतिनिधित्वाधीन निकाय हैं—कहा जाता है कि द्वितीय सदन प्रतिस्पर्धावादी निकाय होते हैं। उनमें आधारभूतता रुढ़िवादी दृष्टिकोण के बड़ी उम्र के लोग या निहित स्वार्थों के प्रतिनिधि होते हैं। वे दोनों सामाजिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन का विरोध करते हैं और इस प्रकार प्रगति के मार्ग में बाधा बन जाते हैं।

दो सदन होने से एकता गूँथ हो जाती है—द्विसदनी विधान मण्डल उस पर व समान है जिसमें फूट पड़ी हुई हो। कहा जाता है कि दो सदन होने से बार-बार अनिरीय होने हैं। विधायक न्यायवादी बसभव हो जाती है, और प्रगति रुक जाती है। लोगों के लिए अपनी इच्छा को एक रूप देना और उसे अभिव्यक्त करना भी कठिन हो जाता है।

अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक नहीं—यदि अधिकार पत्र (Bill of rights) के रूप में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा में उचित रीति से रक्षा की गई हो तो उक्त द्वितीय सदन में प्रतिनिधित्व की जरूरत नहीं रहेगी।

द्वितीय सदन व्यर्थ होते हैं—अन्य बात यह है कि कहा जाता है कि द्वितीय

गदन विस्तृत अनावश्यक होते हैं। उनकी क्रन्दवाजी में विधान बनाने में बनने के के लिए भी आवश्यकता नहीं। विधेयक को सिद्ध बनाने में पड़े अनेक मन्त्रियों में से गुजरना पड़ता है और इन प्रकार गान होने में उसे बहुत समय लगता है। इसमें कई पढ़न (reading) होने हैं और इस पर पूरी तरह चर्चा होती है। इसमें अतिरिक्त, आजकल लोकमत विधान मण्डलों के ऊपर काफी नियन्त्रण रहता है। एक सदन के जल्म का मय भी इसी कारण नहीं होता चाहिए।

नियमक—द्वितीय सदनों के पक्ष में चाहे जो कुछ कहा जाए, पर अतिरिक्त राज्यों में द्वितीय विधान मण्डल हैं। अब तक बिनी राज्य में अपने द्वितीय सदन को तत्पक्ष पक्षों का सम्मोहना में विचार नहीं किया। इसमें सिद्ध होता है कि द्वितीय सदन अवश्य कुछ उपयोगी कार्य कर रहे हैं। अब यह यह मानने हैं कि आदर्श द्वितीय सदन में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए—

(१) द्वितीय सदन न तो पारा अनुवर्तित होता चाहिए और न पारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। यह थोड़ा परोक्ष निर्वाचित और थोड़ा नामजद होता चाहिए। परोक्ष निर्वाचन इसे प्रथम सदन की अनेक कमजोर बनाए रखेगा। नामजदगी में कुछ अन्तर्गतों का प्रतिनिधान सुनिश्चित हो जाएगा और योग्य व्यक्तियों की मन्त्रापना मित्र मंगेगी।

(२) इसी मन्त्रिमण्डल प्रथम सदन की शक्तियों के समान नहीं होनी चाहिए। यह मुख्यतः मन्त्रणादाता और पुनरीक्षण (Reviving) किया जाता चाहिए।

(३) इसमें कहीं उस के और अनुभवों लोग होने चाहिए।

सब विधान मण्डलों की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। किसी विधान मण्डल की बैठक सारे साल नहीं होती। विधान मण्डलों के सत्र वर्ष में दो बार होते हैं। साधारणतया विधान मण्डल का आह्वान (Summoning), मन्त्रावसान (Prorogation) और विघटन राज्य के अन्तर्गत द्वारा किया जाता है। पर यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड में, मन्त्रिपरिषद् द्वारा निर्दिष्ट विधियों पर उनकी बैठक होती है और वे अपने आपकी विघटित कर लेते हैं। विधान मण्डल के प्रत्येक सदन में कार्यसभाओं एक मन्त्रागि या अध्यक्ष द्वारा किया जाता है जो साधारणतया स्वयं सदन द्वारा निर्वाचित होता है। सदन के सत्र सदन्य बोलेने के लिए उनकी इजाजत लेते हैं, और वे अपने भाषण और सदन के ही सम्मोहित करने हैं। तत्पक्ष तो यह है कि सदन में कोई भी बात उसकी उद्घाटन के बिना नहीं की जा सकती।

सदन के कार्य-प्रचालन के नियम साधारणतया सदन द्वारा ही बनाए जाते हैं। विधान मण्डल का प्रत्येक सदन अपने जाय का समितियों के रूप में बांट लेता है। जो कानून सदन के समस्त विचार के लिए जाते हैं वे असीसी के जाय करने के लिए इन समितियों को भेजे जाते हैं। इन समितियों के सदन के सत्र दलों की प्रतिनिधान मिलता है, पर समिति का सम्मानित साधारणतया दूरगमक दल का होता है। सदन के विचार के लिए विशेष कार्यसभा द्वारा (यहाँ सम्मोहित की मन्त्रिमन्त्रीय

प्रणाली है वही) या इसके किसी सदस्य द्वारा पुर स्थापित विधि जा सकते हैं। सब विधेयकों के साधारणतया तीन पठन होने हैं। विधेयकों पर मन्दाय दलीय आधार पर होता है। यदि कोई विधेयक तीसरे पठन में पास हो जाता है, तो यदि दूसरा सदन है, तो यह उसे भेजा जाता है। अन्यथा यह सीधे ही राज्य के अध्यक्ष के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। उसके हस्ताक्षर के बाद कोई विधेयक अन्तिम रूप से विधि बन जाता है। विधान मण्डलों के सदस्यों को भाषण की स्वतन्त्रता और गिरफ्तारी से रक्षा आदि के रूप में कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त होने हैं।

कार्याग या कार्यपालिका

कार्याग या कार्यपालिका की रचना—मोटे तौर से कहा जाए तो कार्याग या कार्यपालिका में न्यायाग और विधानाग के अफसरों को छोड़ कर राज्य के और सब अपनर शामिल हैं। इस अर्थ में सरकार की प्रदान की गयी के सब कर्मचारी—राजा या राष्ट्रपति से लेकर खपरासी तक सब के सब—कार्याग या कार्यपालिका के अंग हैं। पर नागरिक शास्त्र में कार्याग या कार्यपालिका शब्द राज्य के अध्यक्ष और उनके अधिकारी पर लागू होता है।

कार्याग के प्रारूप—विभिन्न राज्यों के कार्यागों की निम्नलिखित रीति से वर्णन किया जा सकता है।

राजनैतिक और स्थायी—यह भेद सब राज्यों में कार्याग के दो भागों पर लागू होता है। राज्य के अध्यक्ष या और उनके सभी राजनैतिक कार्याग हैं। वे राजनैतिक बड़े होते हैं क्योंकि वे अधिकतर चुनाव के द्वारा ही पद ग्रहण करते हैं, और हर चुनाव पर बदलते रहते हैं। राज्य की नीतियाँ कार्याग का पूरी भाग बनाता हैं।

स्थायी कार्याग में विभिन्न कार्यपालक विभागों के स्थायी कर्मचारी होते हैं। कार्याग के इस भाग की जानपद सेवा (Civil Service) भी कहते हैं। इसमें सचिव, अधीक्षक, सहायक और लिपिक या क्लर्क शामिल हैं। राजनैतिक कार्याग द्वारा निर्धारित नीति को स्थायी कार्यपालिका व्यवहार में लाती हैं।

आनुवंशिक, निर्वाचित और नामजद—कार्यपालिकाओं में यह विभेद राज्य के अध्यक्ष को नियुक्त करने की विधियों पर आधारित है। यदि वह राजा है तो कार्यपालिका आनुवंशिक इटलाएवी। इंग्लैण्ड में राजा आनुवंशिक होता है। यदि राज्य का अध्यक्ष प्रत्यक्ष या परोक्षत निर्वाचित होता है तो कार्यपालिका निर्वाचित होगी। जिस राज्य में कार्यपालिका का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, वह गणराज्य कहलाता है। भाग्य एक गणराज्य है। राज्य का अध्यक्ष नामजद भी हो सकता है, जैसे उदाहरण के लिए कनाडा का गवर्नर जनरल। अंग्रेजों के जमाने में भारत का गवर्नर जनरल भी नामजद होता था।

वास्तविक और नाममात्र—यह प्रभेद सामान्य के सदस्य रूप की कार्यपालिका पर ही लागू होता है। इसमें राज्य का अध्यक्ष नाममात्र कार्यपालिका

होना है और मन्त्रिमण्डल वास्तविक कार्यपालिका होना है। राज्य का अर्थ है, चाहे वह राजा हो या राष्ट्रपति, भिन्न कार्यकारी शक्तियाँ रखता है। सामान्य उमके नाम पर किया जाता है पर कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल द्वारा किया जाता है। इसलिए इस सामान्य प्रणाली में वास्तविक कर्ता-भर्ता उत्तरदायी मन्त्री होते हैं। राज्य के अर्थ है कोई वास्तविक अधिकार नहीं होना। यह भिन्न नाममात्र होना है।

मन्त्रीय और प्रजातीय या राष्ट्रपतीय—यह प्रभेद कार्यपालिका और विधान के सम्बन्ध की प्रकृति पर आधारित है। यदि कार्यपालिका विधान मण्डल में से चुनी जाती है और अपने सब कार्यों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी है तो वह राजकीय कार्यपालिका कहलाती है। जहाँ सामान्य मन्त्रीय ही और कार्यपालिका विधान मण्डल के नियन्त्रण में आजाद हो, वहाँ यह प्रजातीय या राष्ट्रपतीय कार्यपालिका कहलाती है।

एक शक्ति और बहुशक्ति—यदि कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग की शक्ति जिम्मेवारी एक आदमी पर हो तो वह एकशक्ति कार्यपालिका कहलाएगी। पर वास्तविक व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग कई व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, भारत में मध्य सरकार की कार्यपालिका शक्तियों के प्रयोग की सांगी जिम्मेवारी राष्ट्रपति की है, पर वास्तविक व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग केन्द्रीय सरकार के मन्त्री करते हैं। जहाँ कार्यपालिका की शक्तियों की अन्तिम जिम्मेवारी व्यक्तियों के किसी निवास पर होती है, वही कार्यपालिका बहुशक्ति कार्यपालिका कहलाएगी। स्विट्जरलैंड में मध्याह्न परिषद, यानी फेडरल कौन्सिल, जिसमें सात आदमी होते हैं, बहुशक्ति कार्यपालिका का एक उदाहरण है।

कार्यपालिका के धार—एक राज्य और दूसरे राज्य के कार्यपालक कार्यों में कोई एकत्वता नहीं होती। मोटे तौर से कहा जाय तो कार्यपालिका निम्नलिखित कार्य करती है—

प्रशासन—कार्यपालिका का मुख्य कार्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई विधियों को अमल में लाना है। इस प्रयोजन के लिए कार्यपालिका कई विभागों में बाँटी जाती है, और इनमें से प्रत्येक विभाग प्रशासन की एक शाखा के लिए जिम्मेवार होता है। कार्यपालिका पर यह देखने की भी जिम्मेवारी है कि कोई आदेशी विधि का अतिक्रमण न करे। पुलिस, ज़िम्मेदार काम विधि-यवस्था कायम रखता है, कार्यपालिका का एक हिस्सा है। पुलिस अवसरधियों को पकड़ती है, उनका चालान करती है और उन्हें उपयुक्त दण्ड के लिए न्यायपालिका के सामने उपस्थित करती है।

कार्यपालिका का दूसरा महत्वपूर्ण प्रशासकीय कार्य भीतरी तथा बाहरी मामलों में राज्य की नीति निर्धारित करना है।

कार्यपालिका अपने विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति,

वरलास्तगी और दैनिक आचरण के नियम भी बनाती हैं।

प्रतिरक्षा—कार्यपालिका का एक और महत्वपूर्ण कार्य राज्य के क्षेत्र और आबादी की विदेशी आक्रमणों की से रक्षा करना है। जो विभाग देश की प्रतिरक्षा की व्यवस्था करता है, वह प्रतिरक्षा और युद्ध विभाग कहलाता है। यह विभाग जेनाओं की सन्धि और सगठन का निश्चय करता है, और जनरल तथा कमाण्डर नियुक्त करता है।

विदेशी संबंध—विदेशी मामलों में सम्ग्रह रखने वाले कार्य राजनयिक कार्य कहलाते हैं। इनके अन्तर्गत युद्ध की घोषणा और राजनैतिक तथा वाणिज्यिक दोनों प्रकार की संधियों पर हस्ताक्षर करना भी सामिल है। अन्य राज्यों के साथ मैत्री सम्बन्ध बनाए रखने के लिए कार्यपालिका उनके साथ राजदूतों का नियुक्ति करती है। ऐसे मामलों में सम्ग्रह रखने वाले विभाग को परराष्ट्र विभाग कहते हैं।

विनीत कार्य—मन सम्भारें अपने बहुत तरह के कार्यों की पूर्ति के लिए प्रति वर्ष बड़ा-बड़ा धनराशिवा शर्ष करती हैं। यह धन उन कार्यों में जाता है जो कार्यपालिका द्वारा निम्न मण्डल की मजूरी से संचालित किये जाते हैं। कार्यपालिका का यह विभाग, जो धन सम्बन्धी कार्यों को सम्भालता है, वित्त विभाग कहलाता है। यह विभाग न केवल विभिन्न विभागों को धन बाँटना है, बल्कि जेना-परीक्षा (audit) द्वारा उनके व्यय की भी नियमित और निगरानी करता है।

विधान कार्य—विधान मण्डल का आह्वान, सभासदों और विपटन कार्यपालिका के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। शासन की मंत्रिमण्डलीय प्रणाली में विधियों के समन्वय कार्यपालिका के विभिन्न विभागों द्वारा बनाये जाते हैं और विधान मण्डल उनका भिन्न अनुमोदन या निरसमोदन (disapproval) कर देता है। कोई भी विदेशी विधि नहीं बन सकती यदि उस पर राज्य के अध्यक्ष के हस्ताक्षर न हों। इसमें अलावा, जब विधान मण्डल का मन न चल रहा हो, तब विधि बनाने की शक्ति राज्य के अध्यक्ष के हाथ में होती है। कार्यपालिका द्वारा इस तरह बनाई गई विधियाँ अप्पाईस कहलाती हैं।

न्यायिक कार्य—न्यायाधीश कार्यपालिका द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। सब जगह राज्य के अध्यक्ष को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह न्यायालयों द्वारा बनाये गये विधि दंडित गण आराधियों की क्षमा प्रदान कर सके। यह एक अर्थ में न्यायिक शक्ति है क्योंकि राज्य का अध्यक्ष क्षमा प्रदान करने में अपराधी पर दया दिखाता है, और मामलों पर कानूनी आधार पर विचार नहीं करता।

अच्छी कार्यपालिका के लिए आवश्यक गुण

१. कार्यपालिका में इच्छा की एकता होनी चाहिए और उसके फंडमें दृढ़ होने चाहिए।

२. इसका कार्य स्वरित होना चाहिए।

होता है और मन्त्रिमण्डल वास्तविक कार्यपालिका होता है। राज्य का अन्त्यश, चाहे वह राजा हो या राष्ट्रपति, निरंकुश शक्तियों रखता है। सामन उसके नाम पर किया जाता है पर कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल द्वारा किया जाता है। इसलिए इस सामन प्रणाली में वास्तविक वर्तमान-पदा उत्तरदायी नहीं होते हैं। राज्य के अन्त्यश को कोई वास्तविक अधिकार नहीं होता। यह सिर्फ नाममात्र होता है।

सम नीर और प्रधातीय या राष्ट्रपतीय—यह प्रभेद कार्यपालिका और विधायिका के सम्बन्ध की प्रकृति पर आधारित है। यदि कार्यपालिका विधान मण्डल में से चुनी जाती है और अपने सब कार्यों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी है तो वह मण्डीय कार्यपालिका कहलाती है। जहाँ सामन गणतन्त्रीय हो और कार्यपालिका विधान मण्डल के नियमन में आना न हो, वहाँ यह प्रधानी या राष्ट्रपतीय कार्यपालिका कहलाती है।

एक-शक्ति और बहुशक्ति—यदि कार्यपालिका शक्तियों के प्रयोग की शक्ति निम्न-वर्गीय एक प्रादमी पर हो तो वह एकशक्ति कार्यपालिका कहलाएगी। पर वास्तविक व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग कई व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, भारत में सब सरकार की कार्यपालिका शक्तियों के प्रयोग की शक्ति निम्न-वर्गीय राष्ट्रपति की है, पर वास्तविक व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग केन्द्रीय सरकार के मंत्री करते हैं। जहाँ कार्यपालिका की शक्तियों की अन्तिम निम्न-वर्गीय व्यक्तियों के किसी निम्न पर होती है, नहीं कार्यपालिका बहुशक्ति कार्यपालिका कहलाएगी। मिड्वटरलैंड में मरानीय परिषद, यानी कंसल काउंसिल, जिसमें सात आदमी होते हैं, बहुशक्ति कार्यपालिका का एक उदाहरण है।

कार्यपालिका के कार्य—एक राज्य और दूसरे राज्य के वास्तविक कार्यों में कोई एकपक्ष नहीं होती। बड़े नीर से कहा जाय तो कार्यपालिका निम्न-लिखित कार्य करती है—

प्रशासन—कार्यपालिका का मुख्य कार्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई विधियों की क्रम में जाना है। इस प्रयोजन के लिए कार्यपालिका कई विभागों में बाँटी जाती है, और इनमें से प्रत्येक विभाग प्रशासन की एक शाखा के लिए जिम्मेदार होता है। वास्तविक पर यह देखने की भी जिम्मेदारी है कि कोई आदमी विधि का अतिक्रमण न करे। पुलिस, क्रिमिनल काम विधि व्यवस्था कायम रखना है, कार्यपालिका का एक हिस्सा है। पुलिस अपराधियों को पकड़ती है, उनका चालान करती है और उन्हें उपयुक्त दण्ड के लिए न्यायपालिका के सामने उपस्थित करती है।

कार्यपालिका का दूसरा महत्वपूर्ण प्रशासकीय कार्य भीड़ों तथा बाहरी मामलों में राज्य की नीति निर्धारित करना है।

कार्यपालिका अपने विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति,

वरमोस्तगी और दैनिक आपरण के नियम भी बनानी हैं।

प्रतिरक्षा—कार्यपालिका का एक और महत्वपूर्ण कार्य राज्य के क्षेत्र और आबादी की विदेशी आक्रमणों की रक्षा करना है। जो विभाग रक्षा की प्रतिरक्षा की व्यवस्था करता है, वह प्रतिरक्षा और युद्ध विभाग कहलाता है। यह विभाग गन्तारों के समर्थ और मजबूत का निश्चय करता है, और जनरल तथा कमाण्डर नियुक्त करता है।

विदेशी सम्बंध—विदेशी मामलों में समर्थ रहने का कार्य राजनयिक कार्य कहलाता है। इन सम्बंधों युद्ध की घोषणा और राजनयिक तथा वाणिज्यिक दोनों प्रकार की संधियों पर हस्ताक्षर करना भी शामिल है। अन्य राज्यों के साथ मैत्री सम्बंध बनाए रखने के लिए कार्यपालिका उन सब मायमसुओं का नियंत्रण करती है। ऐसे मामलों में सम्बंध रखने वाले विभाग को परराष्ट्र विभाग कहते हैं।

द्वितीय कार्य—महत्त्वपूर्ण अर्थों से युक्त व कार्यों की भूमि व गति प्रति वर्ष उड़ी-बड़ी परिवर्तित हो सकती है। यह सब उस कार्य में आता है जो कार्यपालिका द्वारा विधान मण्डल की मजूरी में लगाये जाते हैं। कार्यपालिका का यह विभाग, जो सब सम्बन्धी कार्य को सम्भालता है, वित्त विभाग कहलाता है। यह विभाग में वरत विभिन्न विभागों को सब बाँटता है, वित्त सहायक-परीषद (audit) द्वारा उनके व्यय को भी निरीक्षण और नियंत्रित करना है।

विधायक कार्य—विधान मण्डल का आह्वान, महासभा और विपदन कार्य पालिका के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। शासन की तद्विषयकीय प्रणाली में विधियों के समन्तिरे कार्यपालिका के विभिन्न विभागों द्वारा बना दिए जाते हैं और विधान मण्डल उनका गिके अनुमोदन या निरनुमोदन (disapproval) का देता है। कोई भी विरोध विधि नहीं हो सकता यदि उस पर राज्य के अध्यक्ष के हस्ताक्षर न हो। इनके अलावा, जब विधान मण्डल का मत न चल रहा हो, तब विधि बनाने की पवित्र राज्य के अध्यक्ष के हाथ में होती है। कार्यपालिका द्वारा इन तरह बनाई गई विधियों अध्यादेश कहलाती हैं।

न्यायिक कार्य—न्यायाधीश कार्यपालिका द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। सब जगह राज्य के अध्यक्ष की यह पवित्र प्राप्त होती है कि वह न्यायालयों द्वारा न्याय-विधि दंडित गण अपराधियों को क्षमा प्रदान कर सकते हैं। यह एक अर्थ में न्यायिक पवित्र है क्योंकि राज्य का अध्यक्ष क्षमा प्रदान करने में अपराधी पर दया दिखाता है, और मामले पर कानूनी आधार पर विचार नहीं करता।

मजबूती कार्यपालिका के लिए आवश्यक गुण

१. कार्यपालिका में इच्छा की एकरता होनी चाहिए और उसके पंगुने दृढ़ होने चाहिए।

२. इसका कार्य स्वरित होना चाहिए।

३. इसे अपने निमित्तको और जीव-गन्तान के बारे में पूर्ण गोनोया रखनी चाहिए। वे लोगों को मदद में पहुँचे बना न बटने चाहिए।

४. कार्यपालिका को बहुत भी विवेकशील शक्तियाँ न देने चाहिए। अदया दया परिलक्ष्य अस्म्य होगा।

५. इसकी अरथि इतनी काफी लम्बी होनी चाहिए कि यह अपने काम में जिन दिग्दर्शियों से सजे।

६. अच्छी कार्यपालिका का मतमें महत्त्वपूर्ण गुण यह है कि वह विधियों को लागू करने में शिष्टुल ईमानदार और निष्ठा होनी चाहिए। कार्यपालिका को घुग न लेनी चाहिए या पक्षपात न करना चाहिए।

न्यायपालिका या न्यायाग

जब न्याय कार्य एक मात्र राज्य का कार्य है। पर यह हमें ऐसा नहीं रहा। शुरू में राज्य के न्यायालय आदि के रूप में कोई न्यायिक अंग नहीं होते थे, और न्याय कार्य हमारे कार्यों में नहीं माना जाता था। हानि उठाने वाला हानि करने वाले से लुट बदला लेता था। धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि कोई दोष राज्य के विरुद्ध भी अपराध माना जाने लगा। इस प्रकार धीरे-धीरे न्याय राज्य के एकाधिकार में आ गया।

न्यायपालिका का महत्व—हम अपने समाज की रचना कर सकते हैं जिनमें विधि बनाने वाले मज न हो। वास्तविकता तो यह है कि पूर्णतया परिष्कृत विधान मण्डल अंशदा हाल ही में पैदा हुए हैं। वे ५०० या ६०० वर्षों में अधिक पुराने नहीं। विधान मण्डल की अनुपस्थिति में न्यायालय दण्डों या धार्मिक पुस्तकों के नियम लागू करते थे। इस प्रकार विधान मण्डल इनने महत्त्वपूर्ण नहीं हैं जिनमें न्यायालय। हम ऐसे सम्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते, जिनमें न्यायालय न हो, क्योंकि हम उनकी जगह किसी और मनोपन्नक चीज की कल्पना नहीं कर सकते। लाई डाइन के कथन में न्यायपालिका का महत्व अनुभव हो जायगा। उसके अनुसार, 'किसी शासन की श्रेष्ठता की मांग अच्छी नवीरो इसकी न्यायिक प्रणाली की दृष्टि ही है क्योंकि कोई और चीज अमान नागरिक के कल्याण और सुरक्षा से इतना निकट सम्बन्ध नहीं रखती जितना निकट सम्बन्ध यह भावना रखती है कि वह सुनिश्चित और स्वरित न्याय पर भरोसा कर सक्ता है।'।

न्यायपालिका के कार्य

अराधियों को दण्डित करती है और विधियों को सशक्त करती है—न्यायपालिका का पहला कार्य यह देखना है कि कोई व्यक्ति विधि का अतिव्रत न करे। यह मोबूदा कानून को अपराध के अलग-अलग मामलों पर लागू करती है और मज कानून तोड़ने वालों को दण्ड देती है, पर किसी कानून को लागू करने में यह कैमला करना न्यायधीन का काम नहीं कि कोई कानून अच्छा है या बुरा, सशक्त है या नरम।

उमे तो उमी रूप में कानून को मानता है, जिस रूप में वह है ।

जनता के अधिकारों की रक्षा करती है—दूसरे यह देखना भी न्यायालयों का कर्तव्य है कि कार्यपालिका विधि को प्रवर्तित कराने में विधि की सीमाओं में परे न चली जाए। यदि वह उससे परे जाती है तो इसका अर्थ हुआ जनता की स्वाधीनता में हस्तक्षेप । न्यायपालिका का कर्तव्य है कि कार्यपालिका को ज्यादातियों में जनता के अधिकारों और स्वाधीनता की रक्षा करे ।

नई विधियाँ बनानी हैं—विधि का विवेचन करते हुए न्यायपालिका प्रायः नई विधि बना देती है। कभी-कभी किसी मामले की कोई सामान्य बात किसी कानून के मीठे उदाहरणों में किसी में नहीं आती। ऐसी परिस्थितियों में निकटतम उपबन्ध का विवेचन इस तरह किया जाता है और उसे इस तरह विस्तृत कर दिया जाता है कि वह उस स्थिति पर लागू हो सके। न्यायाधीश-निर्मित विधि प्रत्येक राज्य की विधि प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

न्यायपालिका सचिवान की पहरेदार है—जहाँ शासन का गृहनीय रूप है, वहाँ न्यायपालिका सचिवान के पहरेदार के रूप में कार्य करती है। सचिवानी और राज्य सरकारों की वे सब विधियाँ, जो सचिवान के प्रतिकूल जाती हैं न्यायपालिका द्वारा शून्य और अप्रवृत्त घोषित कर दी जाती हैं।

न्यायिक के अलावा अन्य कार्य—बहुत बार न्यायाध्यक्ष कई-ऐसे कार्य करते हैं, जो असल में न्यायिक नहीं होते। वे अनुमतिपत्र देते हैं, अभिभावक और न्यायी नियुक्त करते हैं, वसीयत लेते हैं, तलाक़ मंजूर करते हैं, विवाह प्रमाणित करते हैं, और मृत व्यक्तियों की सन्तानों का उनके अवयस्कों के निमित्त प्रबन्ध करते हैं।

मद्रास देने सम्बन्धी कार्य—कार्यपालिका विधि सम्बन्धी किसी प्रश्न पर न्यायपालिका से परामर्श कर सकती है। ऐसी अवस्था में न्यायालय मन्वीक्षा (trial) की औपचारिकताओं में बिना गये विधि का अर्थ और अवेताएँ घोषित करते हैं। पर ऐसी राय या मद्रास खुली अदालत में देनी होती, वृष्ट रूप में नहीं। भारत का उच्चतम न्यायालय मद्रास देने का कार्य करता है।

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता—हम यह देख चुके हैं कि न्यायपालिका विधि और व्यवस्था कायम रखने में तथा जनता की स्वाधीनता कायम रखने में महत्वपूर्ण हिस्सा लेती है। बहुत आवश्यक है कि न्याय जल्दी, दक्षता से और निष्पक्षता से हो। लार्ड ब्राइस ने बहुत ठीक कहा है कि “यदि न्याय-कार्य बेईमानी में किया जाय तो नमक का नमकीनपन ही जाता रहा। यदि उसे कमबोरी या सनस से लागू किया जाए तो गारण्टिया या व्यवस्था बेकार हो जाती है, क्योंकि अपराधियों को दण्ड की कठोरता से उत्तम नहीं दवाया जाता जितना उसकी निन्दितता से। यदि अघरे में दोषर मुक्त जाए तो कितना अधिक अवसर हो जाएगा।” इस प्रकार न्याय को सीधे और निष्पक्ष करने के लिए न्यायाधीश कार्यपालिका और विधान मण्डल से स्वतन्त्र

३. इसे अपने विनिश्चयो और जाँच-गडना के बारे में पूर्ण गोपनीयता रखनी चाहिए। वे लोगों को गवय से पहले पना न चलने चाहिए।

४. कार्यपालिका को बहुत सी विवेकशील दायित्वों न देने चाहिए। अन्यथा इसका परिणाम जून होना।

५. इसकी अवधि इतनी काफी लम्बी होनी चाहिए कि यह अपने काम में उचित दिखसपी में रहे।

६. अच्छी कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह विधियों को लागू करने में विनम्र ईमानदार और निष्पक्ष होनी चाहिए। कार्यपालिका को धूम न लेनी चाहिए या पक्षपात न करना चाहिए।

न्यायपालिका या न्यायांग

अब न्याय कार्य एक मात्र राज्य का कार्य है। पर यह हमें ऐसा ऐसा नहीं रहा। शुरू में राज्य के न्यायालय आदि के रूप में कोई न्यायिक अंग नहीं होते थे, और न्याय कार्य इसके कार्यों में नहीं माना जाता था। हानि उठाने वाला हानि करने वाले में खुद बदला लेता था। धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि कोई दोष राज्य के विरुद्ध भी अदालत गिना जाने लगा। इस प्रकार धीरे-धीरे न्याय राज्य के एकाधिकार में आ गया।

न्यायपालिका का महत्व—हम ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जिनमें विधि बनाये जाते अंग न हों। साम्यविज्ञता तो यह है कि पूणतया परिवर्तित विधान मण्डल अदालत हाल ही में पैदा हुए हैं। वे ५०० या ६०० वर्षों में अधिक पुराने नहीं। विधान मण्डल की अनुपस्थिति में न्यायपालिका अधिक या धार्मिक गुणों के नियम लागू करते थे। इस प्रकार विधान मण्डल इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने न्यायपालिका। हम ऐसे सम्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते, जिनमें न्यायपालिका न हों, क्योंकि हम उनकी जगह किसी और संगठन या चीज की कल्पना नहीं कर सकते। एडमंड्स के कथन में न्यायपालिका का महत्व अनुभव हो जाएगा। उसके अनुसार, किसी समाज की सभ्यता की सभ्यता अच्छी बनौती इसकी न्यायिक प्रणाली की दृढ़ता ही है क्योंकि कोई और चीज जीवन नागरिक के कल्याण और सुरक्षा से इनका निकट सम्बन्ध नहीं रखती जितना निकट सम्बन्ध यह भावना रखती है कि वह मुनिविद्वत् और स्वर्ग न्याय पर श्रेयों का मन्त्र है।

न्यायपालिका के कार्य

अदालतों को दण्डित करती है और विधियों को मर्यादित करती है—न्यायपालिका का पहला कार्य यह देखना है कि कोई व्यक्ति विधि का अतिव्रत न करे। यह मौजूदा कानून को अदालत के जलन-जलग भाषणों पर लागू करती है और सब कानून तोड़ने वालों को दण्ड देती है, पर किसी कानून को लागू करने में यह फैसला करता न्यायधीन का काम नहीं कि कोई कानून अच्छा है या बुरा, मजबूत है या कमजोर।

जंग तो उसी रूप में कानून को मानना है, जिस रूप में वह है।

जनता के अधिकारों की रक्षा करती है—दूसरे यह देखना भी न्यायालय का कर्तव्य है कि कार्यपालिका विधि को प्रवर्तित रखने में विधि की सीमाओं से परे न चली जाए। यदि वह उससे परे जाती है तो इसका अर्थ हुआ जनता की स्वाधीनता में हस्तक्षेप। न्यायपालिका का कर्तव्य है कि कार्यपालिका की ज्यादातियों से जनता के अधिकारों और स्वाधीनता की रक्षा करे।

नई विधियाँ बनानी हैं—विधि का विवेचन करते हुए न्यायपालिका प्रायः नई विधि बना देती है। सभी-वर्षी किसी मामले कीवाई खाम अवस्था किसी कानून के मोड़का उदाहरणों में किसी में नहीं आती। ऐसी परिस्थितियों में निश्चित रूप से विवेचन इस तरह किया जाता है और उसे इस तरह विस्तृत कर दिया जाता है कि वह उस स्थिति पर लागू हो सके। न्यायाधीश-निर्मित विधि प्रत्येक राज्य की विधि प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

न्यायपालिका सुविधान को पहरेदार है—जहाँ शासन का मर्यादीय रूप है, वहाँ न्यायपालिका सुविधान के पहरेदार के रूप में कार्य करती है। मर्यादीय और राज्य सरकारों की वे सब विधियाँ, जो सुविधान के प्रतिकूल जाती हैं न्यायपालिका द्वारा शून्य और अप्रवृत्त घोषित कर दी जाती हैं।

न्यायिक सुविधान का अर्थ—यह मत है कि न्यायालय जहाँ जहाँ कार्य करते हैं, जो अवसरों में न्यायिक नहीं होते। वे अनुमतिपूर्ण होते हैं, अभिभावक और न्यायी नियुक्त करते हैं वसीयतें करते हैं, तलाक़ मंजूर करते हैं, विवाह प्रमाणित करते हैं, और मृत व्यक्तियों की सम्पत्तियों का उनके अवयवों के निमित्त प्रयत्न करते हैं।

मरणा के समय की कार्य—कार्यपालिका विधि सम्बन्धी किसी प्रश्न पर न्यायपालिका परामर्श का सहती है। ऐसी अवस्था में न्यायालय अन्वीक्षा (Inquiry) की और कारिश्ताओं में विवाद पड़े विधि का अर्थ और अपेक्षाएँ घोषित करते हैं। पर ऐसी राय का मरणासुली अदालत में देनी होगी, गुप्त रूप में नहीं। भारत का उच्चतम न्यायालय मरणा देने का कार्य करता है।

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता—हम यह देख चुके हैं कि न्यायपालिका विधि और व्यवस्था कायम रखने में तथा जनता की स्वाधीनता कायम रखने में महत्वपूर्ण हिस्सा लेती है। बहुत आवश्यक है कि न्याय जल्दी, दक्षता से और निष्पक्षता से हो। लार्ड वाशर ने बहुत ठीक कहा है कि "यदि न्याय-कार्य बेईमानी से किया जाय तो मरणा का नमकीनपन हो जाता रहा। यदि उसे कमजोरी या सनक से लागू किया जाए तो कारिश्ता या व्यवस्था बेकार हो जाती है, क्योंकि अपराधियों को दण्ड की फ़ोला से उतार नहीं दिया जाता जितना उसकी निश्चितता से। यदि अधीरे में धीरे धीरे जाय तो जितना अधिक अधीरे हो जाएगा।" इस प्रकार न्याय को दीर्घ और निष्पक्ष बनाने के लिए न्यायाधीश कार्यपालिका और विधान मण्डल से स्वतन्त्र

इस सिद्धान्त का ध्येय—मौनवैश्वर्य का यह बहना सही है कि दो या तीन शक्तियों को एक जगह इकट्ठा कर देना जलाने की स्वाधीनता के लिए अहितकर है। दूसरे, आज के जमाने में शासन कार्य को सब मामलों में नियोजित शक्ति की आवश्यक होती है। इस प्रकार शक्तियों और कार्यों का पुनर्व्यवस्थापन शासन की दक्षता के लिए भी आवश्यक है।

पर यह ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ जहाँ हम शक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन की बात कहते हैं, सब हमारा आशय बहुत अधिक पुनर्व्यवस्थापन से नहीं होता, बल्कि मध्यम पुनर्व्यवस्थापन से होता है। मध्यम पुनर्व्यवस्थापन का मतलब यह है कि सरकार की तीनों शाखाओं में, जहाँ तक दक्षता के लिए आवश्यक है वहाँ तक, सहायोग रहे। अन्य मामलों में, जहाँ उनमें पुनर्व्यवस्थापन वांछनीय है, तीनों अथवा एक दूसरे पर रोक के रूप में कार्य कर सकते हैं।

आलोचना—शक्तियों के अत्यधिक पुनर्व्यवस्थापन के सिद्धान्त की अनेक प्रकार से आलोचना हुई है और आज के जमाने में इस पक्ष में नहीं किया जा सकता। इस सिद्धान्त पर निम्नलिखित आपत्तियाँ उठाई जाती हैं—

अत्यधिक पुनर्व्यवस्थापन वांछनीय नहीं—मौनवैश्वर्य में तीनों शक्तियों का जमा पुनर्व्यवस्थापन किया है, वंशासक्तिकार के दस स्वतंत्रता की दृष्टि से वांछनीय नहीं।

कुछ पुनर्व्यवस्थापन तो दक्षता बढ़ाने के लिए आवश्यक है, पर पूर्ण पुनर्व्यवस्थापन का परिणाम हमने विपरीत होता है। यह शासन मन को डर कर देता है।

अत्यधिक पुनर्व्यवस्थापन असमभव है—अत्यधिक पुनर्व्यवस्थापन न केवल अवांछनीय है बल्कि यह असमभव भी है। सरकार एक इकाई है और इसके कार्यों को एक दूसरे से विलुप्त पुनर्व्यवस्थापन में बांट देना असमभव है।

अत्यधिक विभाजन नहीं सही है—वास्तविक व्यवहार में शासन के तीनों अंगों में पूर्ण पुनर्व्यवस्थापन नहीं है। आधुनिक काल में अधिकतर देशों में शासन की मंत्रिमण्डलीय प्रणाली है और इस प्रणाली में कार्यवाह और विधानाग निरुद्ध सहायोग से काम करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ही एकमात्र महत्वपूर्ण राज्य है, जहाँ शासन शक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के सिद्धान्त पर आधारित कहा जा सकता है। पर यूनाइटेड स्टेट्स में कार्यवाह और विधानाग में पूर्ण पुनर्व्यवस्थापन नहीं है। उक्त तो यह है कि मौनवैश्वर्य ने स्वयं अपने द्वन्द्व-निवारण में इच्छित विधान की गन्त रूप में पड़ा। वहाँ उसके समय भी मंत्रिमण्डलीय प्रणाली प्रचलित थी और मंत्रिमण्डलीय प्रणाली मौनवैश्वर्य द्वारा सोचे गए शक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के सिद्धान्त का निरर्थक है।

तीनों अंगों में समता नहीं—शक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन का सिद्धान्त इस कल्पना पर आधारित है कि शासन के तीनों अंग प्रतिष्ठा और शक्ति में समान हैं, पर उनकी समानता सिद्धान्त रूप में ही है। साधारणतया व्यवहार में आजकल विधानाग की अन्य दोनों अंगों से ऊँचा स्थान प्राप्त है।

यह सिद्धान्त पुराना पड़ गया—मन्त्रियों ने दुरुस्वरण का सिद्धान्त पुराना पड़ चुरा है। यह आजकल के विधानशास्त्रियों को पसंद नहीं। यह बात हम तथ्य से स्पष्ट हो जाएगी कि पिछले १०० वर्षों में बहुत अधिक विधान मन्त्रिमंडलीय शासन के नमूने पर बनाए गये हैं। दूसरी बात यह कि शासन के किसी अंग द्वारा अपनी शक्ति के दुरुपयोग करने पर प्रबुद्ध लोकमत भीतनेस्वयं द्वारा मुनाई गई रोकों की अपेक्षा अपितु अच्छी रोक लगा सकता है।

सारांश

सरकार कितने करते हैं—सरकार राज्य की वह अभिवृत्ति है जिसके द्वारा इसके प्राधिकार का प्रयोग होता है और इसका प्रयोजन पूरा किया जाता है।

सरकार के अंग—आज के जमाने में प्रत्येक सरकार के तीन अंग होने हैं (१) विधायिका या विधानांग वह अंग है जिसके द्वारा राज्य की इच्छा रूप ग्रहण करती है और विधियों के रूप में अभिव्यक्त होती है। (२) कार्यपालिका या कार्यशासिका विधायिका द्वारा बनाई गई विधियों को लागू करती है। (३) न्यायांग या न्याय-पालिका यह देखती है कि प्रत्येक व्यक्ति इन विधियों का ठीक-ठीक पालन करे। अपने-अपने स्थान में ये तीनों अंग महत्वपूर्ण हैं, पर लोकजनों में (कुछ संधानों को छोड़ कर) विधायिका की ऊँची स्थिति प्राप्त है। संधानों में प्रायः न्यायिक सर्वोच्चता का मिटान लागू किया जाता है।

विधायिका

विधायिका के कार्य—(१) नई विधियाँ बनाना और प्रचलित विधियों को संशोधित या निरस्त करना। (२) राज्य के बजट का नियंत्रण करना। (३) शासन के संसदीय रूप में कार्यपालिका का नियंत्रण करना। (४) अपने कार्य-अंशालन और कार्य-याही के लिए नियम बनाना। (५) अपने सदस्यों की अर्हताएँ निर्धारित करना। (६) राजद्रोह के अपराधी मंत्रियों और अन्य अधिकारियों पर महाभियोग लगाना। (७) भ्रष्ट न्यायाधीशों की बर्खास्तिकी का समर्थन करना।

विधानमंडल का गठन—आजकल अधिकतर विधानमंडल दो सदनों वाले होते हैं। द्वितीय सदन और प्रथम सदन। द्वितीय सदन आनुवंशिक या नामजद या निर्वाचित या अथवा नामजद और अथवा निर्वाचित होते हैं। जो विधानमंडल प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, उन्हें छोड़कर दूसरे द्वितीय सदनों को साधारणतया प्रथम सदन या लोकसभा की अपेक्षा कम शक्तिशाली होती है। प्रथम सदन या लोकसभाएँ सब जगह जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होती हैं। यदि अभी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है तो वे प्रथम सदन के प्रति ही अपनी जिम्मेदारी अनुभव करते हैं। प्रथम सदनों की साधारणतया घन सबसे मामलों में अनन्य नियंत्रण होता है।

द्वितीय सदनों की उत्पत्ति—द्वितीय सदनों की उत्पत्ति पर प्रायः

न्यायपालिका या न्यायाग

जनताधारण की दृष्टि से न्यायपालिका गवसे महत्वपूर्ण अंग है। औनत व्यक्ति सरकार की थोछता का फंसला इसकी न्यायपालिका से करता है।

न्यायपालिका के कार्य—(१) अपराधियों को दण्ड देकर यह जनता से कानूनों का आदर कराती है। (२) यह कार्यपालिका के अनुविन हस्तक्षेप से जनता के अधिकारों की रक्षा करता है। (३) अस्पष्ट विधियाँ के निर्वचन द्वारा यह नई विधियों को जन्म देती है, जो न्यायाधीश-निर्मित विधि कहलानी है। (४) सघानों में न्यायपालिका सविधान से पहरेदार या रक्षक के रूप में काम करती है। (५) विधि सम्बन्धी मामलों में कार्यपालिका के सलाह माँगने पर न्यायपालिका उसे सलाह देती है।

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता—न्यायपालिका को स्वतन्त्र रहने के लिए निम्नलिखित बातें करनी आवश्यक हैं— (१) न्यायाधीश बकीलों में से छांटने चाहिए। (२) वे नामजद होने चाहिए, निर्वाचन नहीं। (३) वे सदाचरण-पर्यन्त अपने पदों पर रहने चाहिए और उनकी बर्खास्तगी अकेली कार्यपालिका या विधायिका के हाथ में नहीं होनी चाहिए। (४) उन्हें अच्छा वेतन मिलना चाहिए, और उनके पदधारण काल में उनका वेतन घटाया नहीं जाना चाहिए।

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त

इस सिद्धान्त से साथ एक फ्रेंच दार्शनिक मोनतेस्कु का नाम जुड़ा हुआ है। इस सिद्धान्त के अनुसार, शासन की तीनों शक्तियाँ एक जगह इकट्ठी हो जाने से जुलूम आता है और उनके पृथक्करण से स्वाधीनता आती है। जनता की स्वाधीनता उस व्यवस्था में अधिक होगी, यदि प्रत्येक अंग अन्य अंगों के हस्तक्षेप से स्वतन्त्र रहता हुआ अपने लिए निर्धारित क्षेत्र में अपनी शक्ति का प्रयोग करे।

सिद्धान्त का मुख्य—मोनतेस्कु का यह कहनाय ही है कि वो या तीन शक्तियों का इकट्ठा हो जाना जनता की स्वाधीनता के लिए अहितकर है। आजकल शासन की बक्षता के लिए यह भी आवश्यक है कि शक्तियों और कार्यों का पृथक्करण हो। पर हमारा आशय सिर्फ मध्यम दर्जे के पृथक्करण से है, पूर्ण पृथक्करण से नहीं। मध्यम दर्जे के पृथक्करण में यह बात या जानी है कि बक्षता के लिए जहाँ तक आवश्यक है वहाँ तक तीनों शाखाओं में सहयोग हो।

मान्योचना—(१) अत्यधिक पृथक्करण बाछनीय नहीं। (२) अन्यधिक पृथक्करण असम्भव है। (३) अत्यधिक पृथक्करण कही नहीं है। (४) तीनों अंगों में कोई शक्ति नहीं है। (५) यह सिद्धान्त अब पुराना नर था है।

प्रश्न

१. शासन में मुख्य अंग कौन से है ? उनके अपने-अपने कार्य बताइए।

(५० वि०घप्रश्न, १९५८ और मप्रश्न, १९५३)

1. What are the chief organs of Government ? Describe their respective functions (P U. April 1948 and April 1953)
२. सरकार के विभिन्न भग्न कौन-कौन से हैं ? उनमें क्या-क्या सम्मेलन है ?
(पं० वि० नितम्बर, १९५१)
- 2 What are the different organs of Government ? What is the relationship between them ? (P U. Sept, 1951)
- ३ द्विसदनी विधानमण्डल के पक्ष और विपक्ष में क्या-क्या युक्तियाँ हैं ?
- 3 What are the arguments for and against a bicameral system of legislature ?
- ४ कार्यपालिका के कार्य और प्रकार क्या-क्या हैं ?
- 4- What are the functions and kinds of executive ?
- ५ लोकतन्त्रीय राज्य में न्यायपालिका के क्या-क्या कार्य हैं ? न्यायपालिका का गठन कैसे होना चाहिए ? इसकी शक्तियाँ क्या होनी चाहिए ?
(पं० वि० सितम्बर, १९५३)
- 5 Describe the functions of the Judiciary in a democratic state ? How should the judiciary be constituted ? What should be its powers ? (P U Sept, 1953)
- ६ शक्तियों के पृथक्करण का क्या अर्थ है ? किसी सम्मेलन राज्य में स्वतन्त्र न्यायपालिका का होना क्यों आवश्यक है ? (पं० वि० अप्रैल, १९५३) ।
- 6 What is meant by 'Separation of Powers' ? Why is an independent judiciary necessary in a civilised state ?
(P U April, 1952)
- ७ शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए ।
7. Critically examine the theory of separation of powers
- ८ न्यायपालिका का कार्यपालिका और विधानिका से क्या सम्बन्ध होना चाहिए ?
- 8 What should be the relations of the judiciary with the executive and legislature ?
- ९ लोकतन्त्रीय राज्य में कार्यपालिका के मुख्य कार्य क्या हैं ? विधान मण्डल के साथ इसके क्या सम्बन्ध हैं ?
- 9 What are the main functions of the executive in a democratic state ? Describe its relations with the legislature.

सरकार के रूप—राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र, लोकतन्त्र, और अधिनायकतन्त्र

पुराना वर्गीकरण—राजनीति विज्ञान ने पिता अरस्तू ने सरकारों का वर्गीकरण उन व्यक्तियों की संख्या के अनुसार किया था जिनमें राज्य की सर्वोच्चता की शक्ति निहित होती थी।

इस मिश्रण के अनुसार सरकारों का वर्गीकरण निम्नलिखित रीति में किया गया था—

(१) राजतन्त्र—सर्वोच्च अधिकार एक व्यक्ति में निहित होता था।

(२) कुलीनतन्त्र—सर्वोच्च शक्ति कई (सर्वोपर) व्यक्तियों में निहित होती थी।

(३) बहुतन्त्र (Polity)—सर्वोच्च शक्ति बहुत से व्यक्तियों में निहित होती थी।

अरस्तू के अनुसार उपर्युक्त तीन रूप सामान्य के शुद्ध या सामान्य रूप थे, क्योंकि उनमें एक, कई या बहुत से व्यक्ति सर्वशक्ति की दृष्टि से शासन करते थे। पर इन तीनों में न प्रत्येक रूप का एक भ्रष्ट या विकृत रूप भी था। जब शासन सत्ताधिकारियों के अपने शुद्ध स्वार्थों के लाभ के लिए चलाया जाता था, तब राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र और बहुतन्त्र विपट कर अत्याचारी शासन अल्पतन्त्र और लोकतन्त्र का रूप ले लेता था। इस प्रकार अरस्तू के अनुसार तीन शुद्ध या सामान्य रूप और तीन भ्रष्ट या विकृत रूप हैं।

शुद्ध रूप

- (१) राजतन्त्र
- (२) कुलीनतन्त्र
- (३) बहुतन्त्र

विकृत रूप

- (१) अत्याचारी शासन
- (२) अल्पतन्त्र
- (३) लोकतन्त्र

अरस्तू का यह वर्गीकरण आधुनिक दशावधि के साथ मेल नहीं खाता। आज-कल लोकतन्त्र शासन को सबसे अच्छा और सबसे अधिक पसन्द किया जाने वाला रूप समझा जाता है। पर अरस्तू ने इसे एक विकृत रूप बतलाया था। इसका अर्थ यह हुआ कि अरस्तू की दृष्टि में न तो इससे ठीक में मौजूदा शासन अच्छा माना जाएगा

भारत अमरीका में। आजकल के किसी भी सम्य देश में सर्वोच्चता किसी एक व्यक्ति या छोटे से वर्ग में निहित नहीं। इम्पेरियल में रानी है, पर इन तथ्य से अस्तु के वास्तविक वर्गीकरण का कोई निर्देश नहीं मिलता और यह आज की सरकारों पर लागू नहीं किया जा सकता।

वर्गीकरण—आज के जमाने में हम सरकारों के दो भोटे भाग कर सकते हैं—

(१) लोकतन्त्र

(२) अधिनायक तन्त्र

यू कि अधिकतर राज्यों में प्रामाण्य का लोकतन्त्रीय रूप है और यू कि वे गठन में एक दूसरे से भिन्न हैं इसलिए लोकतन्त्रों को भी आगे तीन शीर्षकों में रखा जा सकता है—

(१) यह सार्वभौमिक राजतन्त्र है या गणतन्त्र ?

(२) यह शासन का समक्षीय रूप है अथवा प्रधानीय या राष्ट्रपतीय रूप है ।

(३) यह एकीय (Unitary) रूप है या सविधानीय रूप है ।

पर यह याद रखना चाहिए कि कोई सरकार समक्षीय और एकीय होनी हुई भी सार्वभौमिक राजतन्त्र हो सकती है। इंग्लैंड में राज्य की अघ्यक्ष रानी है, पर उसमें कार्यपालिका ससक्षीय है और शासन एकीय है। दूसरी ओर, कोई सरकार एक ही समय लोकतन्त्र और अधिनायक तन्त्र नहीं हो सकती। इसी तरह यह एक ही समय प्रधानीय या राष्ट्रपतीय और सगक्षीय दोनों नहीं हो सकती।

अब हम पुराने वर्गीकरण में से सिर्फ राजतन्त्र और कृशीनतन्त्र पर तथा नए वर्गीकरण के सब रूपों पर विचार करेंगे।

राजतन्त्र—राजतन्त्र से अस्तु का आशय राज्य के लोगों के आम हित की दृष्टि से किए जाने वाले एक व्यक्ति के निरक्षुभ शासन से था। राजतन्त्र आनुवंशिक या निर्वाचित या इन दोनों का मेल हो सकता है, पर अधिकतर राजतन्त्र आनुवंशिक ही हुए हैं।

राजतन्त्रों में एक और भेद यह हो गया है कि वे निरक्षुभ राजतन्त्र हो सकते हैं या सार्वभौमिक राजतन्त्र हो सकते हैं। पूर्ण राजतन्त्र का राजा राज्य के पूर्ण अधिकार का प्रयोग करता है। उनकी इच्छा ही विधि है। भारत में अश्वमेध, अशोक और अश्वर ये सब निरक्षुभ राजा हुए हैं। इसके विपरीत, सार्वभौमिक राजा वह है जिसका प्राधिकार सीमित और विधि प्रथा, परम्परा और रुढ़ि द्वारा नियत है। इंग्लैंड की रानी आज सार्वभौमिक राजा की एक उदाहरण है।

पूर्ण और हितकर राजतन्त्र के बहुत से लाभ बताए जाते हैं। प्रायः यह कहा जाता है कि राज्य की शक्ति और ससाधन एक व्यक्ति के हाथ में इकट्ठे हो जाने से निरक्षुभ राजा अपनी प्रजा के लिए बहुत थोड़े समय में जीवन की आसरां अस्थाएँ पैदा कर सकता है। इस व्यक्ति के समर्थन में इतिहास से अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। अशोक, अकबर, एलिजाबेथ, पीटर महान, ये सब ऐसे ही शासक थे।

उनके शासनकाल में लोगों का जीवन बड़ा मुसीबत था, पर पूर्ण राजतन्त्र के समर्थक यह भूल जाते हैं कि वस्तुतः अच्छे राजाओं के उदाहरण इतिहास में दुर्लभ हैं। दूसरी ओर, इतिहास क्रूर और दुष्ट राजाओं की पहचानों से भरा पड़ा है, जिन्होंने अपनी शक्ति, लिप्ता, सनक और विलास के लिए अपनी प्रजा के जीवनों को बरबाद कर दिया। आजकल व्यक्ति स्वाधीनता के प्रेमियों को हिनकर राजतन्त्र पर भी आपत्ति होगी।

कुलीनतन्त्र—कुलीनतन्त्र की परिभाषा यह की जा सकती है कि वह शासनतन्त्र जिसमें राज्य के अकमरो को चुनने और राज्य की नीतियों के निर्धारण में अनेकता धीरे से नागरिकों की भावाज होती है। चीन लोग इसे सर्वोत्तम व्यक्तिगत द्वारा शासन मानते थे। पर यह बात स्पष्ट नहीं है, कि सर्वोत्तम शब्द का अर्थ ज्ञान, शिक्षा, अनुभव, और नैतिक चरित्र की दृष्टि से सर्वोत्तम या या धन, वस्त्र और सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से सर्वोत्तम या। सर्वोत्तम शब्द का चाहे जो अर्थ हो पर कुलीनतन्त्र शासन का वह रूप है, जिसमें मात्रा या सत्ता के बजाय श्रेष्ठता की महत्व दिया जाता है। कुलीनतन्त्र के प्रेमी लोकतन्त्र को भ्रष्टान का गायन करते हैं। दूसरी ओर लोकतन्त्र के समर्थक कुलीनतन्त्र की बुराई करते हैं, क्योंकि इसमें धीरे से आदमी अपने स्वार्थ के लिए बहुतों का शोषण करते हैं। कुलीनतन्त्र का अर्थ कुछ अच्छे शिक्षित और अनुभवी व्यक्तियों का शासन है, जो भी इसमें सीधे ही विगड़ कर अल्पतन्त्र के रूप में अर्थात् कुछ घनी व्यक्तियों के शासन में बदल जाने की प्रवृत्ति होती है। इसके अन्वयात्, यह निश्चय करना बड़ा कठिन है कि सर्वोत्तम कौन है, और उनके लिए क्या बमोटी है।

लोकतन्त्र

लोकतन्त्र का अर्थ—हम लोकतन्त्र के युग में रहते हैं। लोकतन्त्र शासन, राज्य और समाज का एक रूप है।

शासन का रूप—अधिकांश सम्य राज्यों में शासन का प्रचलित रूप लोकतन्त्र है। शासन के एक रूप के तौर पर लोकतन्त्र की अनेक तरह परिभाषा की गई है। प्राचीन ग्रीक लोग इसे बहुतों द्वारा शासन के रूप में परिभाषित करते थे। प्रोफेसर सीली ने इसे ऐसा शासन बनकाया है जिसमें प्रत्येक का हिस्सा होना है। लार्ड बाइस ने इसे शासन का ऐसा रूप बनकाया है जिसमें प्रत्येक राज्य की शासन शक्ति किसी खास वग या वर्ग में निहित न होकर मुख्यतः सारे राष्ट्र के सदस्यों में निहित होती है। एक और परिभाषा जो बहुत बार उद्धृत की जाती है अब्राहम लिंकन द्वारा की गई परिभाषा है। उसने 'इसे जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए दिया जाने वाला शासन' बताया है। इस प्रकार, लोकतन्त्र में राज्य की सर्वोच्च सत्ता सारी जनता में निहित होती है। सब लोगों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शासन में हिस्सा होना है। शासन का यही एक रूप है, जिसमें शासक और शासित में कोई भेद नहीं होता।

राज्य के रूप में—लोकतन्त्र शासन का ही रूप नहीं है। यह राज्य का और समाज का भी एक रूप है। प्रायः लोकतन्त्र इन तीनों का मेल होता है। शासन के लोकतंत्रीय रूप से लोकतंत्रीय राज्य ध्वनित होता है, पर किन्हीं लोकतंत्रीय राज्यों में यह आवश्यक नहीं कि सरकार लोकतंत्रीय ही हो। लोकतंत्रीय राज्य वह है जिस में सारा समुदाय सर्वोच्च और नियन्त्रणकारी सत्ता होता है। लोकतंत्रीय राज्य का शासन राजतन्त्र, कूलीनतन्त्र या लोकतन्त्र हो सकता है।

समाज के रूप में—राज्य के और प्रकार के रूप के अलावा, लोकतन्त्र समाज की व्यवस्था का नाम भी है। समाज की व्यवस्था के रूप में लोकतन्त्र अपने सब सदस्यों में समता और समता की भावना ध्वनित करता है। पर हमें स्मरण रखना चाहिए कि यह आवश्यक नहीं कि लोकतंत्रीय समाज, राज्य और सरकार एक साथ ही हों। मूलतः समाज लोकतंत्रीय था, पर उनकी सरकार निरवस्था राजतन्त्र थी। आजकल हमें लोकतंत्रीय समाज तो है, पर शासन का लोकतंत्रीय रूप नहीं है। हिन्दुओं का समाज लोकतंत्रीय नहीं था, पर प्राचीन हिन्दू भारत में लोकतंत्रीय राज्य भी थे और सरकारें भी।

लोकतन्त्र के प्रकार—लोकतन्त्र का वर्गीकरण इस तरह किया जा सकता है—

- (क) प्रत्यक्ष या सीधा लोकतन्त्र।
- (ख) परोक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र।

प्रत्यक्ष लोकतन्त्र—प्रत्यक्ष लोकतन्त्र में सब नागरिक सभा के रूप में बैठते हैं, और राज्य की इच्छा को रूप देते और अभिव्यक्त करते हैं। वे अपनी ओर से काम करने के लिए प्रत्यायुक्त या प्रतिनिधि नहीं चुनते। जैसा कि इनकी प्रवृत्ति से स्पष्ट हो जाएगा, प्रत्यक्ष लोकतन्त्र तब तक उन राज्यों में संभव है, जिनकी आबादी बहुत छोटी है और जिनकी समस्याएँ बहुत थोड़ी तथा सरल हैं। प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की प्रणाली आधुनिक कागज के बड़े और सख्त राज्यों के लिए ठीक नहीं। जहाँ एक राज्य की आबादी करोड़ों में है, वहाँ सब नागरिकों को एक सभा में इकट्ठा करना संभव नहीं। प्राचीन ग्रीस और रोम में, जहाँ राज्य नगर-राज्य होता था, प्रत्यक्ष लोकतन्त्र चल सकता था। आजकल प्रत्यक्ष लोकतन्त्र के एतन्त्र उदाहरण स्विट्जरलैंड के बार कैंटन या जिले हैं। स्विट्जरलैंड के अन्य कैंटनों में, जहाँ प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र है, प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की हानि को पूरा करने के लिए रेफरेंडम या परिषुन्द (Referendum) का और अवक्रमण या प्रारम्भ (Initiative) का प्रयोग किया जाता है। हम इन उपायों के अर्थ और प्रयोजन पर एक बाद के अध्याय में विचार करेंगे।

परोक्ष लोकतन्त्र—आजकल लोकतन्त्र का यही प्रारूप प्रचलित है। परोक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र में राज्य की इच्छा जनता द्वारा अपने उन प्रत्यायुक्तों या प्रतिनिधियों की माफ़त अभिव्यक्त की जाती है, जो आम चुनाव में निश्चित अवधि के लिए उनके द्वारा चुने जाते हैं। प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र में भी प्राधिकार का मूल

सौत जनता ही है, पर यह प्रत्यक्ष लोकतन्त्र से इस बात में भिन्न है कि प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र इस मिश्रान्न पर आधारित है कि जनता स्वयं उस प्राधिकार का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से और सनोपत्रनक रीति से नहीं कर सकती।

लोकतन्त्र के पक्ष और विपक्ष में युक्तियाँ

लोकतन्त्र के गुण

✓समता पर आधारित है—लोकतन्त्र ही शासन का एक रूप है जो समता के मिश्रान्न पर आधारित है। प्रथम तो, यह जन्म धन, ज्ञान या वन, रस, धर्म और लिंग का बिना विचार किए, सब आदमियों के परिवर्धन और सुधार को बराबर महत्व देता है। दूसरे, सब नागरिकों को, चाहे वे बड़े हों या छोटे, पनी हा या गरीब, राज्य के मामले में बराबर अधिकार होता है। राज्य की विधि सबमें एक सा व्यवहार करती है। सब नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य बराबर है। संक्षेप में, लोकतन्त्र हम धारणा पर आधारित है कि राज्य सब नागरिकों का है और कि इसके मामले हर किसी की चिन्ता का विषय है। इस प्रकार, यह मनुष्य को उठा कर सबके बराबर कर देता है और किसी से हीन नहीं रहने देता।

✓अधिकतम स्वाधीनता देता है—दूसरे, लोकतन्त्र शासन का एकमात्र रूप है जिसमें आदमी को अधिकतम स्वाधीनता मिल सकती है। राज्य की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए यह विचार, भाषण, संचरण, और साहचर्य की पूर्ण स्वाधीनता देता है। इतनी अधिक स्वाधीनता शासन के किमी और रूप में समत नहीं।

✓सम्मति द्वारा शासन—लोकतन्त्र की एक और अच्छी विशेषता यह है कि यह सम्मति द्वारा शासन है। लोग शासन के लिए अनुपयुक्त सरकार के नीचे बैठ पाने के लिए बाधित नहीं होते। लोकतन्त्र में लोग बिना हिंसा का प्रयोग किए अपनी सरकार बदल सकते हैं। शासन के अन्य किसी रूप में यह सुविधा नहीं। फिर, यह शासन का ऐसा एकमात्र रूप है जिसमें शासक और शासित में कोई भेद नहीं और शासक शासित भी हैं तथा शासित शासक भी हैं।

✓यह शिक्षा है—लोकतन्त्र का शिक्षात्मक महत्व भी बड़ा है। राज्य के सामने थाने वालों और शासन के संचालन सम्बन्धी बहुत सी समस्याओं के बारे में लोगों को लोकतन्त्र प्रणाली में जितना ज्ञान होता है, उतना शासन के किसी अन्य रूप में नहीं होता। आम जनता लोग अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक मामलों में लोगों की दिलचस्पी ही नहीं पैदा करते, बल्कि उन्हें इनके बारे में सोचने और तर्क करने के लिए मजबूर करते हैं।

✓चरित्र-निर्माण करता है—लोकतन्त्र का जनता के चरित्र पर ऊँचा उठाने वाला प्रभाव होता है। यह अपने नागरिकों में स्वावलम्बन, स्वयंसेवक, सहयोग, सहिष्णुता और जिम्मेदारी के गुण पैदा करता है। तथ्यतः, लोकतन्त्रीय शासन और समाज आदमी के चतुर्मुखी विकास में सहायक होते हैं।

/ देशभक्ति को बढ़ाता है—लोकतन्त्र आदमी के मन में देशभक्ति या अपने देश का प्रेम बढ़ाता है। इसका कारण यह सत्य है कि लोकतन्त्र में राज्य और सरकार जनता की होती है।

यह स्वार्थी होता है—यदि किसी राज्य में शासन का रूप लोकतन्त्रीय है तो शान्ति का स्तर बढ़त कम हो जाता है। जब लोग आम चुनावों में शांतिपूर्ण तरीके से शासन को बदल सकते हैं तब उन्हें हिंसक और जानिकारी विधियों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जनता का उन विधियों को अतिशय खाना और उन्हे अपने लिए उपायी है, नैतिक दृष्टि में उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए, लोकतन्त्र शासन का एक स्वार्थी रूप है।

लोकतन्त्र के दोष

लोकतन्त्र की बहुत खालोचना की गई है। इन पर निम्नलिखित आपत्तियाँ उठायी जाती हैं —

(१) कुर्यातन्त्र के प्रथी लोकतन्त्र को अज्ञानियों का शासन बताते हैं। उनकी मान्यता यह है कि शासन कार्य के लिए विशेष ज्ञान और विशेष प्रशिक्षण चाहिए जो मजिरी तथा जनता के प्रतिनिधियों को प्राप्त नहीं हो सकता। उनके अनुसार, लोकतन्त्र मात्र या मजिरी को अनुचित महत्व देता है और श्रेष्ठता की उपेक्षा करता है। लोकतन्त्र बहुमत का शासन होता है। इसलिए हममें थोड़े से बुद्धिमान मजिरी की अपेक्षा १०० मजिरी की बात ज्यादा चलेगी।

(२) दूसरी बात यह है कि कहा जाता है कि अधिकतर लोग राज्य के मामलों में निष्कृत दिलचस्पी नहीं लेते। इस कारण लोकतन्त्र में भी मजिरी का प्रयोग सामान्य में थोड़े से व्यक्तिनी द्वारा ही किया जाता है और इस प्रकार अपने सामान्य मजिरी में बड़ अज्ञान्य में अस्था नहीं।

(३) उपायुक्त बात में यह भी कहा जाता है कि लोकतन्त्र में जिम्मेदारिता और समता का दावा किया जाता है वे मिटाने मात्र हैं, व्यवहार में नहीं आता।

(४) यह भी कहा जाता है कि लोकतन्त्रीय देशों में राजनैतिक दल अपने मत प्रचार, मित्रतापरी और भ्रष्टाचार से जनता को लाभ की अपेक्षा हानि अधिक पहुँचाने हैं। राजनैतिक नेता लोगों की भावनाएँ प्रेरणा कर उनके मत प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें जाने के बाद में अपनी दक्षिण का प्रयोग अपनी स्वार्थ-मिष्टि के लिए करते हैं। ऐसी अवस्था में जनता का शिक्षण और चरित्र-निर्माण नहीं हो जाता। मजिरी के साथ लोगों का मीठा सम्पर्क होने के कारण अनुशासन सिद्ध हो जाता है। लोग मजिरी में संमिलित अनुष्ठान की आज्ञा करते हैं, और मजिरी अपने मजिरी और मित्रों की बड़ी-बड़ी नोकरीयों में मदद करते हैं। इसका परिणाम होता है पक्षपात और भ्रष्टाचार और उनमें शासन में अक्षमता पैदा होती है।

(५) लोकतन्त्र शासन का अधिक सर्वांगीण रूप है। सरकार को चुनावों पर और विधान मंडल के सदस्यों के वेतनों और भत्तों पर बहुत बड़ी धनराशियाँ खर्च करनी पड़ती हैं।

लोकतन्त्र का मूल्यव्यवस्था—लोकतन्त्र पर किए गए उपयुक्त प्रत्येक आरोप में कुछ न कुछ सचाई है, पर साथ ही वे आरोप बहुत अतिरिक्त हैं। शासन की कोई भी प्रणाली भ्रष्टाचार नहीं पर शासन के अन्य व्यक्तियों की तुलना में लोकतन्त्र में कम बुराई है। इसके गुण इसके दोषों की अपेक्षा सुनिश्चित रूप से बहुत अधिक हैं।

हमें याद रखना चाहिए कि लोकतन्त्र शासन का एक कठिन रूप है। इसके दस सप्ताहों के लिए होने चले जाने वाले लोगों में चरित्र और प्रतिष्ठान का एक निश्चित स्तर होना चाहिए। लोकतन्त्र की सफलता के लिए कुछ नानों का होना परमावश्यक है। यदि वे बातें हो तो लोकतन्त्र में उन अनेक बुराइयों से नुकसान होने की सम्भावना नहीं रहती जो इसमें बताई जाते हैं।

लोकतन्त्र की सफलता के लिए मर्यादक शर्तें सबल और प्रबुद्ध लोकमत—सबल और प्रबुद्ध लोकमत लोकतन्त्र की सफलता के लिए पहली और सबसे अधिक आवश्यक शर्त है। यह विधानमंडल के सदस्यों और अन्य मर्यादारी अफसरों की नियमित रखने के लिए आवश्यक है। ऐसा न होने पर वे जनताधारण के हितों की रक्षा करके स्वार्थ मित्रि की दिशा में जाएंगे।

शिक्षा—यहाँ शिक्षा का अर्थ राजनीतिक शिक्षा है, पढ़ाई-लिखाई नहीं, यद्यपि बड़ा पढ़ाई-लिखाई ही तो और भी अच्छा है। शिक्षा से ही लोगों की जागरूकी प्राप्त होती है। उन्हें अपने सामने आनेवाले प्रश्नों और समस्याओं का पता लगता है। ऐसी परिस्थितियों में लोग अपने प्रतिनिधियों के कामों का अधिक अच्छी तरह फँसला कर सकते हैं। लोगों की शिक्षा होने पर स्वाधीनता और समता की अतिरिक्त भावनाएँ पक्षपात, गलत प्रचार और अनुशासनहीनता, ये सब बुराइयाँ खत्म हो जाएगी।

स्थानीय स्वशासन—पचायती और नगरपालिकाओं में लोगों की स्वशासन की जो शिक्षा मिलती है, वह नागरिकता के लिए उनकी राजनीतिक शिक्षा और प्रशिक्षण की दिशा में एक कदम होता है।

स्वतन्त्र प्रेस या प्रतियोगिता—सबल लोकमत बनाने के लिए स्वतन्त्र प्रेस या प्रतियोगिता का होना परम आवश्यक है।

आर्थिक मुक्त—लोकतन्त्र की सफलता के लिए एक और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि लोगों की आर्थिक सुरक्षा अनुभव होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, अभाव में मृत्ति होनी चाहिए। अपने कर्तव्यों के ईमानदारी से निर्वाह के लिए आर्थिक समृद्धि बहुत आवश्यक है। राज्य के कर्मचारियों आर्थिक दृष्टि से सुखी होने पर प्रलोभनों में कम पड़ेंगे और मतदान अपने मत नहीं बेचेंगे। समृद्धि से नागरिकों को राज्य सम्बन्धी

मामलों की ओर ध्यान देने के लिए बहुत खाली समय भी मिल जाएगा।

सच्छा चरित्र—लोकतन्त्र के नागरिक को अपने कर्तव्यों के निर्वाह में ईमानदार होना चाहिए। उसे स्वार्थी नहीं होना चाहिए। उनमें देश-प्रेम, सहयोग और सहिष्णुता की भावना रहनी चाहिए। उसे उत्तरदायी और अनुशासित रीति से व्यवहार करना चाहिए।

अधिनायकतंत्र या तानाशाही

लोकतन्त्र तो सम्मति द्वारा शासन है और एक व्यक्ति या एक दल के मतमाने शासन को अधिनायकतन्त्र या तानाशाही का नाम दिया जाता है। एक व्यक्ति के शासन की दृष्टि में अधिनायकतन्त्र में राजतन्त्र ने यह भेद है कि अधिनायक मुकुट नहीं पहनता, या सिंहासन पर नहीं बैठा। अधिनायक या पद राजा के पद की तरह आनुवंशिक भी नहीं होता। अधिनायक जननाशरणा में से होता है और राजा की तरह उसमें कोई वृत्तीय रक्त नहीं होता। जहाँ तक मन्त्र के साम्प्रदायिक प्रयोग का प्रश्न है, अधिनायक और निरंकुश राजा में कोई अन्तर नहीं है।

पुरानी और नयी तानाशाही—तानाशाही, शासन का कोई नया रूप नहीं है। यह पुराने भी मौजूद थी। जूलियस और नैपोलियन के नाम हममें से अधिकतर लोग जानते हैं। प्राचीनकाल में तानाशाही मन्त्रों जयों में एक आदमी का शासन होती थी। आजकल एक आदमी के हाथ में बाहर से ही अधिकार शिफारी देता है, पर वास्तव में वह व्यक्ति एक राजनैतिक दल के नेताओं के रूप में सत्ता का प्रयोग करता है। हिटलर, मुसोलिनी और स्टालिन आज भी अपने-अपने तानाशाह हुए हैं। वे सब हमें बाल्य में तानाशाही से ही के सत्ताकाद दल के नेता थे। इस प्रकार मौजूदा दल व्यक्ति की तानाशाही के बजाय दल की तानाशाही का युग है। हमारे अलावा आज की तानाशाहियाँ लोकतंत्रीय षेप में रहती हैं, यद्यपि वास्तव में वे लोकतन्त्र से बिल्कुल दूरी होती हैं।

लोकतन्त्र बनाम तानाशाही

(१) लोकतन्त्र सम्मति द्वारा शासन है। दूरागी और, तानाशाही का आधार बल है।

(२) लोकतन्त्र में विचार, भाषण, सचरण और साहचर्य की बहुत स्वाधीनता होती है। तानाशाही में सबने पहले इन्हीं पर पाबन्दी लायी है। लोगों को तानाशाह द्वारा नियम किया गया पेशा करना, वेस पहनने और शिक्षा लेने के लिए भी मजबूर किया जाता है।

(३) लोकतन्त्र में राजनैतिक दल बनाने की स्वाधीनता होती है। तानाशाही में एका राजनैतिक दल के अलावा अन्य सब राजनैतिक दलों पर पाबन्दी होती है।

तानाशाही के पुरा—कुछ देशों में १९१४-१८ के विश्वयुद्ध के बाद तानाशाही का पंरा हुई। उन देशों में युद्ध ने अधिक अवस्थाएँ बहुत विगाह दी थी और

उन सरकारों को लोकतन्त्र के ऊपर डाला जाता था। लोकतन्त्र को शासन का अर्थ रखा जाता था और इसलिए तानाशाही को एक मौजा दिया गया था। आज भी हमारे जैसे देशों में, जहाँ अधिकतर जवम्थाएँ राज हैं, और अनुशासन-हीनता, स्वार्थरति, घृणापूरी और चौरागारी आम चीज हैं, लोग कभी कभी लोकतन्त्र की जगह तानाशाही का पक्ष पोषण करते हैं। इस प्रकार, तानाशाही का मुख्य गण इमनी दस्ताना बनाया जाता है। इसे देश की भव्य वृत्तियों का एक ग्राहक कहा जाता है। लोकतांत्रिक मन्दगति है, पर तानाशाही उपशान्त रास्ते में समय में जीवन में शान्ति ला सकती है।

तानाशाही के दोष—तानाशाही के दोष हमारे युगों की अपेक्षा बहुत अधिक हैं। इसकी सबसे बड़ी बुराई यह है कि यह व्यक्ति को बड़े स्वाधीनता नहीं भगने देती। ममान का जीवनमय चालि मा होने लगता है। आदमी की मौलिकता और स्वयं वस्तुत्व की विकसित नहीं होने दिया जाता। न विचार का स्वतन्त्र विचार हो सकता है। आखिरकार, आदमी तक के अनुसार चलने वाला आदमी है, और वह गिरफ्तारी में जीवित नहीं रहता। विचार, भावना, चारित्रिक और साहस्य की स्वतन्त्रता उसके पूर्ण विकास के लिए बहुत आवश्यक है। उसके जलावा, तानाशाही न केवल देश की आन्तरिक नीति में बल्कि इसकी वैदेशिक नीति में भी बल प्रयोग पर जोर देती है। वैदेशिक मामलों में तानाशाह युद्ध की नीति पर चलते हैं, और इस प्रकार, अपने देशों को विनाश की ओर ले जाते हैं। बल पर आधारित हानि के कारण तानाशाही लोकतन्त्र की अपेक्षा कम स्थायी है।

सार्वभौमिक राजतन्त्र और गणराज्य—कोई लोकतन्त्र या तो सार्वभौमिक राजतन्त्र होता है और या गणराज्य होता है। सार्वभौमिक राजतन्त्र पर हम पहले ही विचार कर चुके हैं। गणराज्य शासन का वह रूप है जिसमें राज्य का अध्यक्ष या इसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी या तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में और या पराक्ष रूप में निर्वाचित होता है। यूनाइटेड स्टेट्स और भारत दोनों लोकतन्त्रीय गणराज्य हैं, पर गणराज्य का लोकतन्त्रीय होना आवश्यक नहीं। भोविवन तब भी एक गणराज्य है पर वह लोकतन्त्रीय नहीं है।

सारांश

सरकार के रूप—सरकार का वर्गीकरण

१. राजतन्त्र—सर्वोच्च सत्ता एक व्यक्ति में निहित होती है।
२. कुलीनतन्त्र—सर्वोच्च सत्ता थोड़े से (सर्वोच्च) व्यक्तियों में निहित होती है।
३. भुक्तन्त्र—सर्वोच्च सत्ता बहुत से व्यक्तियों में निहित होती है।

ऊपर बताए गये शुद्ध या सामान्य रूपों के साथ-साथ एक भ्रष्ट या मिश्रित रूप होता है अर्थात् अत्याचारी शासन, अल्पतन्त्र और लोकतन्त्र।

अस्तु कि यह वर्गीकरण आधुनिक युग की अवस्थाओं से मेल नहीं खाता।

अस्तु लोकतन्त्र को एक विवृत रूप मानता था, पर आज यह शासन का सर्वोत्तम रूप माना जाता है। लोकतन्त्र आज सबसे अधिक प्रचलित रूप भी है।

प्राथमिक वर्गीकरण—(१) लोकतन्त्र, (२) तानाशाही या अधिनायकतन्त्र।

लोकतन्त्र को फिर तीन शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है—

१. सार्वधानिक राजतन्त्र या गणराज्य।

२. एकीय या प्रधानीय।

३. समदीय या प्रधानीय (राष्ट्रपतीय)।

पर कोई शासन सदीय और एकीय होते हुए सार्वधानिक राजतन्त्र हो सकता है। पर कोई शासन एक ही समय में राजतन्त्र और गणराज्य या समदीय और प्रधानीय (राष्ट्रपतीय) नहीं हो सकता।

राजतन्त्र—राजतन्त्र आनुवंशिक या निर्वाचित और निरकुल या सार्वधानिक हो सकता है। सार्वधानिक राजा वह है, जिसे सीमा अधिकार होता है। निरकुल और हिनकारी राजतन्त्र के पक्ष में प्रायः यह युक्ति दी जाती है कि यह लोगों के लिए जीवन की आदर्श अवस्थाएँ पैदा कर सकता है। पर बहुत छोटे निरकुल राजा अच्छे शासक हुए हैं। आज के जमाने में राजतन्त्र पसन्द नहीं किसे जाने, और जहाँ बहा है भी, वह सार्वधानिक है।

कुलीनतन्त्र—कुलीनतन्त्र सर्वोत्तम व्यक्तिगतों द्वारा शासन कहा जाता है, पर सर्वोत्तम की परिभाषा करना कठिन है। यदि कुलीनतन्त्र का अर्थ कुछ अच्छे शिक्षित और अनुभवी व्यक्तियों का शासन है, तो हममें धीरे-धीरे छोटे से बनी व्यक्तियों का रूप लेने की प्रवृत्ति हो जाती है।

लोकतन्त्र—हम लोकतन्त्र के युग में रहते हैं। लोकतन्त्र न केवल शासन का एक रूप है, बल्कि राज्य का और समाज का भी एक रूप है। शासन के रूप के तौर पर, इसे वह शासन कहा जा सकता है जिनमें हर कोई हिस्सा लेता है। लेकिन ने हमारी परिभाषा यह भी कि 'जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन।' लोकतन्त्र में सर्वोच्चता जनता में निहित होती है और सामक़ी तथ्य शासन में कोई भेद नहीं होता।

लोकतन्त्रीय राज्य वह होता है जिसमें सारा समुदाय सर्वोच्चता-सम्पन्न होता है। किसी लोकतन्त्रीय राज्य का शासन राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र या लोकतन्त्र हो सकता है।

लोकतन्त्रीय समाज हमके सदस्यों में समता और समता की भावना को सूचित करता है। मुगलमानों का समाज लोकतन्त्रीय था, जबकि उनका शासन निरकुल राजतन्त्र था। हिंदुओं में समाज कभी लोकतन्त्रीय नहीं रहा, यद्यपि प्राचीन हिन्दू भारत में राज्य और शासन लोकतन्त्रीय थे।

लोकतन्त्र के प्रकार—(१) प्रत्यक्ष, (२) परोक्ष या प्रतिनिध्यात्मक। प्रत्यक्ष लोकतन्त्र में कानून बनाने के लिए सब नागरिक विधान सभा के रूप में बैठते हैं।

कोई प्रतिनिधि नहीं चुने जाते। प्रत्यक्ष लोकतन्त्र बहुत छोटे राज्यों के लिए ही हो सकता है। अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र आजकल प्रचलित लोकतन्त्र है। इसमें जनता की इच्छा विधानमण्डलों में उनके प्रतिनिधियों के द्वारा जताई जाती है।

लोकतन्त्र के गुण—(१) शासन का एकाग्र यह रूप है, जो मजबूती के सिद्धान्त पर आधारित है। (२) अधिकतम स्वाधीनता लोकतन्त्र में ही हो सकती है। (३) मित्र लोकतन्त्र में ही सामक और साधित में भेद नहीं होता। (४) लोकतन्त्र ही ऐसा शासन है, जिसे जिना हिंस के बदला जा सकता है। (५) यह सम्मति द्वारा शासन है। (६) लोकतन्त्र में साधारण निर्वाचनों का बड़ा शिक्षात्मक महत्त्व है। (७) लोकतन्त्र जनता के चरित्र को ऊँचा उठाता है। (८) यह देशप्रेम बढ़ाता है। (९) यह शासन का सबसे स्थिर रूप है।

बोध—(१) लोकतन्त्र के प्रेमी लोकतन्त्र को अशान्तियों का शासन कहते हैं। यह गलती के मुकाबले में गुण की उद्देश्य करता है। (२) जनता राज्य के मामलों में बहुत कम हिस्सेदारी लेती है। इसलिए कार्य सरकार की दृष्टि में लोकतन्त्र अल्पतन्त्र (Oligarchy) में अधिक अच्छा नहीं है। (३) लोकतन्त्र में स्वाधीनता और समता सिद्धान्तरूप में ही अधिक होती है, व्यवहार में नहीं। (४) राजनैतिक दल शिक्षा देने की उद्देश्य निम्न अधिक करते हैं। (५) लोकतन्त्र बड़ा लक्ष्य होता है।

सूचक—यद्यपि उद्योग आर्थिक क्षेत्रों में से प्रत्येक में कुछ सच्चाई है, पर उनमें दुराहमों की बहुत बड़ा-बड़ा करवड़ा गया है। लोकतन्त्र के दश परिष्कारण के लिए जनता में चरित्र का एक निश्चित स्तर होना जरूरी है। यदि उचित अवस्थाएं विद्यमान हों तो लोकतन्त्र में इनमें से कोई भी बुराई नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर लोकतन्त्र शासन का सर्वोत्तम रूप है।

लोकतन्त्र की सफलता के लिए आवश्यक बातें—(१) मुक्ति और प्रबुद्ध लोकतन्त्र। (२) जनता की शिक्षा। (३) स्थानीय स्वशासन की शिक्षा। (४) स्वतन्त्र प्रेस या अवधार। (५) जनता की व्यक्ति अवस्था अच्छी होनी चाहिए। (६) लोग ईमानदार, सहिष्णु, सहयोगपूर्ण, उत्तरदायी और अनुशासित होने चाहिए।

तानाशाही या अधिनायकतन्त्र

तानाशाही या अधिनायकतन्त्र एक आदमी या एक दल के मनमाने शासन को कहते हैं। यह दल द्वारा शासित है और इस रूप में लोकतन्त्र का विरुद्ध उल्टा है। पुरानी तानाशाहियाँ एक-एक आदमी की हुंमा करती थीं, पर आधुनिक युग दल की तानाशाही का युग है।

गुण—तानाशाही का मुख्य गुण इसकी दृष्टि को बनाया जाता है। कहा जाता है कि लोकतन्त्र बहुत धीरे चलता है और तानाशाही अनेकधा घड़े समय में जीवन को ऊपर से नीचे तक बदल सकती है।

शेय—तानाशाही में आजादी नहीं रहती । समाज का जीवन मशीन की तरह चलने लगता है । आदमी के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का मौका नहीं होता । तानाशाह अपने देशों को युद्ध में झोक देने हैं । तानाशाही लोकतन्त्र से कम स्थायी भी है ।

प्रश्न

१. 'लोकतन्त्र' शब्द का क्या समझते हैं ? प्रत्यक्ष और परोक्ष लोकतन्त्र में भेद करो ।

1. What do you understand by the term 'Democracy' ? Distinguish between direct and indirect democracy

२. शासन पद्धति के रूप में लोकतन्त्र के गुण और दोषों में पृथक्ता करो ।

या

शासनपद्धति के रूप में लोकतन्त्र के गुणों और दोषों की आलोचना करो ।

(१० वि० अप्रैल, १९५१)

2 Make out a case for and against democracy as a form of government

or

Explain the merits and demerits of democracy as a form of government. (P U April, 1951)

३ लोकतन्त्र की सफलता के लिए कौन-सी शर्तें आवश्यक हैं ?

(१० वि० सितम्बर, १९५१)

3 What are the necessary conditions for the success of democracy ? (P U Sept., 1951)

४ लोकतन्त्र और तानाशाही के आर्थिक गुणों और दोषों की विवेचना करो ?

4 Examine the relative merits and demerits of democracy and dictatorship

५ प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र के गुण और दोष बताओ । (१० वि० अप्रैल, १९५४)

5 Point out the merits and demerits of a representative democracy (P U April, 1954)

अध्याय : : १७

शासन के रूप (क्रमागत)

एकीय, स्थानीय-संसदीय और प्रधानीय या राष्ट्रपतीय शासन का एकीय रूप

यदि किसी राज्य के सारे अधिकार का प्रयोग धामन के एक ही संघटन के अन्तर्गत होता हो जो केन्द्रीय सरकार कहलाती है तो सरकार एकीय है। शासन के इस रूप में प्रान्तीय सरकारें होने पर भी उन्हें सिर्फ केन्द्रीय सरकार से दिया गया अधिकार ही प्राप्त होता है। उनका अधिकार केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी भी समय कम या अधिक किया जा सकता है, या विलुप्त के लिया जा सकता है। इस प्रकार शासन के एकीय रूप में सारा अधिकार एक जगह केन्द्रीभूत हो जाता है। इंग्लैंड में एकीय प्रणाली चलती है।

गुण—शासन के एकीय रूप के निम्नलिखित गुण हैं —

(१) प्रशासन की एकरूपता—कहा जाता है कि अधिकार के एक जगह केन्द्रीभूत होने से सारे देश में विधि, नीति और प्रशासन की एकरूपता हो जाती है।

(२) एकता और एकता—सारे अधिकार का प्रयोग एक स्थान से होने से प्रशासन में अधिक एकता आ जाती है। विधि और प्रशासन की एकरूपता से देश की जनता में एकता की भावना बढ़ती है।

(३) आपातों के समय तात्कालिक—जारी सत्ता एक स्थान पर होने के कारण एकीय रूप वाली सरकार युद्ध काल में और अन्य आपातों में अधिक तात्कालिक और दक्षता दिखा सकती है।

(४) कम खर्च—सिर्फ एक सरकारी संघटन होने से एकीय सरकार खर्च की दृष्टि से कम खर्चीली पड़ती है।

दोष—शासन के एकीय रूप के निम्नलिखित दोष हैं —

(१) स्थानीय स्वशासन नहीं रहता—एकीय प्रणाली में मुख्य दोष यह है कि इसके स्थानीय संघों को उन मामलों में, जो अधिकतर सिर्फ उनसे ही सम्बन्ध रखते हैं, स्वशासन का अधिकार नहीं मिलता। कहा जाता है कि एक केन्द्रीय सरकार स्थानीय इलाकों से दूर होने के कारण उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे सकती। यह उन्हें संतुष्ट करने की अव्यवस्था नहीं करती है। और वे भी यह

बहुत देर के बाद करती है। इसका कारण आसानी से समझ में आ जाता है। सरकार का भिन्न एक संगठन होने के कारण, केन्द्रीय सरकार को पचासी तरह के काम करने होते हैं। इसपर नाम का बहुत बोझ होता है। पहले सामान्य समस्याओं पर विचार किया जाता है और विभिन्न क्षेत्रों की अपनी-अपनी समस्याएँ हल होने में देर लग जाती है।

(२) नागरिकता की संस्था नहीं मिल पाती—इसके अलावा लोगों की स्थानीय स्वशासन की शिक्षा देने की जरूरत होती है ताकि वे लोकतंत्र के उपयुक्त नागरिक बन सकें। पर शासन के एकीय रूप में नागरिकों में स्वयं कीर्तित्व, सहयोग और जिम्मेदारी आदि नागरिक गुणों का विकास होने के कम मौके मिलते हैं।

(३) शासन का एकीय रूप साधारणतया उन छोटे-छोटे राज्यों के लिए ठीक होता है, जिनके क्षेत्र सब एक जगह हो और जिनकी जागहरी घेरी और एकता हो। यह उन देशों के लिये ठीक नहीं रहता जो बहुत लम्बे-चोड़े हो और जिनमें स्थानीय अवस्थाएँ सभी अलग-अलग हों और मनुष्यों की विविधता हो। इन प्रकार, शासन के इस रूप में विविधता को एकता और एकत्वना पर कुरान करना पड़ता है।

मधान या शासन का मधानीय रूप

संधान कितने कहते हैं—जब कई छोटे-छोटे स्वतन्त्र सर्वोच्चता-भरमान राज्य कुछ मामलों में अपना सर्वोच्च प्राधिकार एक साथी मध्य सरकार को देने के लिए आपस में सहमत होकर एक मध्य के रूप में इकट्ठे हो जाना स्वीकार करते हैं, पर साथ ही वेव मामलों में अपनी सर्वोच्चता और स्वतन्त्रता कायम रखते हैं। तब ऐसा मध्य मधान कहलाता है।

इस प्रकार संधान में सरकार की कुछ शक्तियाँ एक लिखित सन्धिधान द्वारा दो शासन संगठनों अर्थात् केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार में बाँट दी जाती है। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, चढाव यांनी करों और विनिमय (Exchange), वाणिज्य और व्यापार आदि, सब के सामान्य हित के विषय केन्द्रीय सरकार को दे दिये जाते हैं और विधि और व्यवस्था, न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि स्थानीय महत्त्व के विषय मधान के राज्यों के अधीन रहते हैं।

संधान की आवश्यक विशेषताएँ

(१) संध है, ऐक्य नहीं—प्राकृतिक मधान में निम्नलिखित विशेषताएँ अवश्य होती हैं। मधान कुछ राज्यों का संध होता है, ऐक्य नहीं होता (Union and not a Unity)। ऐक्य शब्द का मतलब यह होता कि मधान बनाने वाले राज्यों का स्वतन्त्र अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो जाएगा पर हम ऊपर देख चुके हैं कि राज्य अपनी सर्वोच्चता भिन्न कुछ विषयों में मध्य सरकार को सौंपते हैं। वेव मामलों में उन्हें बेगरी हो स्वतन्त्र सत्ता रहती है जैसी मध्य के निर्माण से पहले थी।

शासन के दो संगठन होते हैं—मधान में स्पष्ट तौर ॥ शासन के दो संगठन

होते हैं—एक केन्द्र में, दूसरा सधान बनाने वाले राज्यों में से प्रत्येक में। विषयों की कम-से-कम दो और कभी-कभी तीन सूचियाँ होती हैं। धारण के प्रत्येक समूहों को विषयों की अपनी सूची में परम प्राधिकार होता है। केन्द्र को प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण विषय दे दिए जाते हैं। केन्द्रीय सरकार के लिए विषयों की भी सूची होती है उसे केन्द्रीय सूची या सध सूची कहते हैं। राज्यों के प्रशासन के विषय राज्य सूची में होते हैं। कुछ सधानों में ऐसे विषय भी होते हैं, जो केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के लिए सामान्य होते हैं। ऐसे विषयों की सूची को समवर्ती सूची कहते हैं। शेष विषय जो न केन्द्र को दिये गये हैं, न राज्यों को, और न दोनों के सामान्य हैं, अवशिष्ट विषय (Residuary Subjects) कहलाते हैं। कुछ राज्यों में, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में, अवशिष्ट विषय राज्यों के अधिकार में होते हैं और कुछ देशों, जैसे भारत में वे केन्द्र को दिये गये हैं। यह सब व्यवस्था सम्बन्धित देश व सविधान में साफ़ तौर से लिखी होती है।

(३) मिलित सविधान—सधान का सविधान लिखित होना चाहिए क्योंकि शासन के दोनों समूहों के अधिकारक्षेत्र स्पष्टतः निर्दिष्ट होने जरूरी है। सधान में सर्वोच्चता सविधान में होती है। केन्द्रीय सरकार या इकाइयों की सरकार को राज्य का सर्वोच्च प्राधिकार नहीं होता। दोनों का प्राधिकार सविधान से पैदा होता है। इस प्रकार किसी सधान की इकाइयों का प्राधिकार मौलिक होता है, और केन्द्रीय सरकार से लिया हुआ नहीं होता।

(४) सधानीय न्यायालय—सधान में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या एक या अधिक राज्यों तथा सध के बीच विवाद पैदा होने की सम्भावना रहती है। इसका कारण यह है कि धारण के दोनों समूहों के बीच विषयों का विभाजन किया गया है, और सविधान को पढ़ने में मनभेद हो सकता है। इसलिए विवादों का फैसला करने और सविधान का अर्थ लगाने के लिए किसी निष्पक्ष प्राधिकरण की जरूरत है। यह काम एक न्यायालय द्वारा किया जाता है जिसे उच्चतम या सधानीय न्यायालय कहते हैं। भारत में भी ऐसा न्यायालय है और यह भारत का उच्चतम न्यायालय कहलाता है। अमेरिका में भी ऐसा न्यायालय है जो यूनाइटेड स्टेट्स का उच्चतम न्यायालय कहलाता है। इसलिए सधान में उच्चतम न्यायालय होता जरूरी है।

सधानीय शासन के लाभ

एकता और स्वतन्त्रता दोनों धनी रहती है—धारण के स्थानीय रूप का सबसे बड़ा लाभ यह बताया जाता है कि इसमें सध के सब लाभ मिल जाते हैं और ऐंक्ट की हानि कोई नहीं होती। धारण का यह रूप ऐंक्ट और स्वतन्त्रता के बीच उत्तम मध्य मार्ग पैदा करता है। प्रतिक्रिया, विदेशी मामलों, संचार साधनों और मुद्रा आदि मामलों में, जिनमें ऐंक्ट वास्तवीय है, सधान बनाने वाले राज्यों को अमीरत लाभ मिल जाता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन और कृषि

आदि मामलों में, जिनमें स्थानीय व्यवस्थाओं के भेद के कारण अलग-अलग नीतियाँ वांछनीय होती हैं, राज्यों की पूरी स्वायत्तता रहनी है। इस प्रकार संधान में स्थानीय क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन की आवश्यकताएँ एकता को जिना भग बिने आसानी से पूरी हो जाती हैं।

(२) वचन—संधानों से सर्वे में वचन होती है। जब संधान बनाने वाले राज्य अलग-अलग और स्वतन्त्र थे तब प्रत्येक की अलग फौज, राजदूत और टुकड़ानें आदि थीं। अब वे मध्य में आकरने हैं और संधान बना लेते हैं तब सेना रखना, राजदूत भेजना और बिकड़े कागजात केन्द्रीय सरकार का काम हो जाता है। इस तरह, वह बहुत मा धन बच जाता है जो प्रत्येक राज्य पहले खर्च कर रहा था, क्योंकि उनसे खर्चन एक हो जाते हैं।

(३) छठे राज्यों के लिए उपयुक्त है—बहुत पैसों हुए और बहुत भावार्थी यदि राज्यों के लिए शासन का मर्यादा रूप ही उपयुक्त होता है।

(४) दक्षता सत्ता है—शासन का काम मध्य सरकार और राज्य सरकारों में बंट जाने से अधिक दक्षता आ जाती है। एकीय प्रणाली में केन्द्रीय सरकार पर ध्यान का बहुत घोल रहता है।

(५) निरक्षरता को रोकता है—क्योंकि न तो केन्द्रीय सरकार को पूरा अधिकार है और न राज्य सरकारों को, और दोनों एक दूसरे पर रोक का काम करती हैं, इसलिए संधानीय शासन में निरक्षरता का भय नहीं रहता।

(६) विश्व राज्य के लिए नमूना पैदा करता है—यदि विश्व राज्य बनेगा तो उसका रूप संधानीय ही होने की संभावना है।

(७) यह अधिकाधिक समझ दिया जा रहा है—आज की दुनिया में संधान की अधिकाधिक समझ दिया जा रहा है। इसमें भी हमकी अन्तर्दृष्टि का पता चलता है।

संधान की हानियाँ

शासन के संधानीय रूप की ये हानियाँ बताई जाती हैं —

(१) मर्यादों के समय कमजोर—आमलों के मध्य सरकार की बहाल और ताकत के लिए यह जरूरी होता है कि मारी यक्ति एक जगह इच्छी हो। अधिकारों के बँटवारे के कारण संधान में जल्दी किए जाने वाले कामों में गम्भीर और देर लगने का खतरा रहता है।

(२) प्रशासन में एकदमता का अभाव—शासन के संधानीय रूप में प्रशासन की एकरूपता नभय नहीं। संधान के राज्यों में विविध और प्रशासन अलग-अलग होने की सम्भावना है। इस प्रकार उपर्युक्त कारण से लोगों में एकता की भावना भी कमजोर रहेंगी।

(३) जिम्मेदारी का बंट जाना—शासन के संधानीय रूप में जिम्मेदारी बँटी रहती है। कभी-कभी बुरे शासन की जिम्मेदारी दोनों में से किसी एक पर

हालना बठिन हो जाता है।

(४) प्रत्यक्ष होने का अर्थ—संघान में किसी राज्य या राज्यों के रूप से अलग हो जाने का अर्थ हमेशा बना रहता है।

(५) अधिक संघीला—शासन के दो संगठन होने के कारण संघानीय शासन एकीय शासन की अपेक्षा अधिक संघीला बँटता है। अनेक सरघाएँ दोहरी बनानी पड़ती हैं। उदाहरण के लिए, हर एक राज्य में अपनी अलग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अवश्य होती है।

संसदीय और प्रधानीय (राष्ट्रपतीय) सरकारें

सरकारों का संसदीय और प्रधानीय (राष्ट्रपतीय) रूप में वर्गीकरण नाम-पालिका और न्यायपालिका के आपसी सम्बन्ध की प्रवृत्ति पर आधारित है।

शासन के संसदीय रूप में कार्यपालिका (मन्त्रिमण्डल) और विधायिका (संसद) एक दूसरे के साथ बहुत सहयोग करती हुई चलती हैं। शासन का यह प्ररूप इंग्लैण्ड की देन है, क्योंकि वहाँ ही मन्त्रिमण्डल और संसद की सरघाएँ सबसे पहले पैदा हुईं। शासन के संसदीय रूप को मन्त्रिमण्डलीय रूप या उत्तरदायी रूप भी कहते हैं क्योंकि इस में असली कार्यपालिका मन्त्रिमण्डल है और यह उत्तरदायी सरकार इस कारण है कि मन्त्रिमण्डल या असली कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। इस प्रणाली में राज्य का अध्यक्ष, राजा या राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है।

दूसरी ओर शासन के प्रधानीय (राष्ट्रपतीय) रूप में राज्य का अध्यक्ष असली कार्यपालिका है; मंत्री यह स्वयं बनाता है और वे उसके अधिकार के अधीन ही होते हैं। संसदीय रूप के विपरीत प्रधानीय (राष्ट्रपतीय) रूप में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से स्वतन्त्र रहकर कार्य करता है। राष्ट्रपति विधानमण्डल में से अपने मंत्री नहीं चुनता और वह विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी नहीं है। शासन के इस रूप को अपनाने वाला पहला राज्य यूनाइटेड स्टेट्स था और आज भी वही इसका सबसे अच्छा उदाहरण है।

संसदीय शासन की मुख्य विशेषताएँ

(१) शासन के संसदीय रूप में कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग असल में मन्त्रिमण्डल द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका का अध्यक्ष (राजा या राष्ट्रपति) राज्य का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। वह अपने मंत्रियों की सलाह पर कार्य करता हुआ माना जाता है। मन्त्रिमण्डल न केवल कार्यपालिका की सामे नीति तय करता है, बल्कि विधान और विन में विधान मण्डल का प्रदर्शन भी करता है।

(२) विधानमण्डल भी मन्त्रिमण्डल को नियंत्रित करता है। शासन के संसदीय रूप में मन्त्रिमण्डल विधानमण्डल की एक समिति है। इसके सदस्य विधानमण्डल के बहुमत दल में से छोटे होते हैं, और इस दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है।

प्रधानमंत्री अन्य मंत्री छाटता है। वे भी संसद के सदस्य और उसके दल के आदमी होने चाहिए।

प्रधानमंत्री और उसके सहयोगी अर्थात् मंत्रिमंडल अपने सब राजकीय कार्यों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वे तब तक अपने पदों पर रहते हैं जब तक उन्हें विधानमंडल का विश्वास प्राप्त रहे। विधानमंडल अपने प्रति मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी की शक्तियों में प्रश्न पूछकर, निंदा प्रस्ताव द्वारा और अविश्वास प्रस्ताव द्वारा लागू करता है।

गुण—शासन की संसदीय पद्धति के निम्नलिखित गुण हैं—

(१) कार्यपालिका और विधायिका में सहयोग—मंत्रिमंडलीय प्रणाली शासन की ऐसी एकमात्र प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका में मंत्रीपूर्ण सहयोग होना सुनिश्चित है। कानून बनाने वाले और कानून लागू करने वाले प्राधिकरणों में नजदीकी सहयोग से कानून व्यवस्थित ढंग का बनता है। इसी प्रकार, धन देने वाले और धन खर्च करने वाले अधिकारियों में सहयोग होने पर खर्च कम होता है और दक्षता आती है। शासन के इन रूप में फैसले और काम जल्दी होते हैं और कार्यपालिका और विधायिका में सख्त और गतिरोध की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है।

(२) कार्यपालिका की जिम्मेदारी निरंकुशता पर रोक लगानी है—शासन के संसदीय रूप में कार्यपालिका की जनता के प्रतिनिधियों के सामने सीधी जिम्मेदारी निरंकुशता पर रोक लगती है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली ही ऐसी एकमात्र प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका की जिम्मेदारी की अच्छी व्यवस्था है। जो लोग शासन करते हैं, वे सदा उनके नियंत्रण में रहते हैं, जिनपर शासन होता है।

(३) मंत्रिमंडलीय प्रणाली नम्य और सजोसी है—मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नम्यता और लचीलापन आजाद और खूब के समय दृष्टिदायक बन जाता है। मंत्रिमंडल एक ऐसी समिति है, जिसमें विधानमंडल को पूरा विश्वास है। इसका धन पर पर रहना भी विधानमंडल की दृष्टि पर निर्भर है। इसलिए आपात के समय मंत्रिमंडल की बैठकें विलुप्त शक्तियाँ दी जा सकती हैं, और जब आपात खत्म हो जाए तब असाधारण शक्तियाँ ले ली जाती हैं।

मंत्रिमंडलीय प्रणाली के दोष—मंत्रिमंडलीय प्रणाली के आलोचक इसमें निम्नलिखित दोष बताते हैं—

(१) यह शक्तियों के पुनर्करण के सिद्धांत को नग्न करता है—कहा जाता है कि मंत्रिमंडलीय प्रणाली शक्तियों के पुनर्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है। इस प्रणाली में विधायक और कार्यपालक कर्म प्रायः एक ही व्यक्ति हो जाते हैं।

(२) यह अधिकतर दलीय सरकार की प्रणाली है—लार्ड ब्राइस ने संसदीय प्रणाली के बारे में कहा है कि इसने दलीय भावना को बढ़ाया है। दलों में सत्ता

माने के लिए लगातार होठ रहती है। सनारूढ़ दल और विरोधी दल के संपर्क में बहुत-सा समय और शक्ति बर्बाद होते हैं और उससे समाज में भी सघर्ष पैदा होता है। विभिन्न दलों के लोग हमेशा एक दूसरे से विरोधी रहते हैं।

(३) मंत्रिमंडल की तानाशाही—यंत्रिमंडलीय प्रणाली की एक और आलोचना यह है कि इस से विधानमंडल पर मंत्रिमंडल की तानाशाही हो जाती है। यह आलोचना सामान्य ने इंग्लिश मंत्रिमंडल प्रणाली के बारे में की जाती है कहा जाता है कि इस प्रणाली में विधानमंडल मंत्रिमंडल द्वारा पहले ही कर लिए गए निश्चयों को दर्ज करने वाला अंग मात्र रह गया है।

(४) कुछ काल में कमजोर—प्रोफ़ेसर डिस्ली के अनुसार, मंत्रिमंडल प्रणाली में काम और जिम्मेदारी कई मंत्रियों में बंटी होती है। संसदे एक आदमी को बजाए कई आदमियों से वर्षों के बाद किए जाते हैं। इस कारण प्रोफ़ेसर डिस्ली इसे पुष्ट और गंभीर राष्ट्रीय सबोट के समय कमजोर ढंग की सरकार कहते हैं।

(५) इसकी अस्थिरता—यदि शासन की मंत्रिमंडलीय प्रणाली बहुदल प्रणाली के अधीन चलाई जाए तो इसने कार्यपालिका अस्थिर हो जाती है। मंत्रिमंडल में बार-बार परिवर्तन होने में सरकार अर्द्ध हो जाती है। मास में बहुत से बल हैं और वहाँ सरकार का जीवन बहुत छोटे दिन चलता है। कभी-कभी वह सिर्फ़ एक दिन का होता है, पर मंत्रिमंडल का औमत जीवन ६ मास में कुछ अधिक रहा है।

प्रधानीय (राष्ट्रपतीय) प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ—हम पहले ही कह चुके हैं कि शासन की प्रधानीय (राष्ट्रपतीय) प्रणाली में कार्यपालक और विधायक मालाएँ प्रायः पूरी तरह अलग हो जाती हैं। यह दोनों एक दूसरे से स्वतन्त्र रहकर कार्य करती हैं और दोनों एक दूसरे पर रोक का काम करती हैं। शासन के इस रूप में राज्य का अध्यक्ष अस्थली कार्यपालक है, मंत्री नहीं। वह मंत्रिपरिषद् द्वारा तय किए गए किसी निश्चित समय के बीच चुना जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स में यह अवधि चार साल है। उसकी शक्तियाँ भी सीधे संविधान से उद्भूत होती हैं, और कार्यपालक क्षेत्र में वह सर्वोत्तम है। वह अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों को नियुक्त और बर्खास्त करता है। वह उससे प्रति ही उत्तरदायी है, और उसके ही निर्देशान और नियंत्रण में अधीन है। इस प्रकार विधानमंडल या मंत्रिमंडल पर कोई नियंत्रण नहीं रहता।

इसी तरह, विधानमंडल भी कार्यपालिका के नियंत्रण से स्वतन्त्र होता है। इसका बैठक और विघटन संविधान द्वारा तय की गई विधियों पर होता है। राज्य का अध्यक्ष न तो इसे आहूत करता है, और न विघटित करता है। मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमण्डल को उसके कार्यों में मार्ग दिखाने और नियंत्रित करने के लिए वहाँ नहीं बैठते। विशेषक मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा नहीं बनाए जाते और

न पास कराए जाने हैं, जैसा कि संसदीय प्रणाली में होता है।

इससे गुण—शासन की संसदीय प्रणाली के ये गुण बताए जाते हैं—

(१) कार्यपालिका की अधिक स्थिरता—राष्ट्रपतीय प्रणाली में कार्यपालिका की स्थिरता सुनिश्चित हो जाती है, जैसा कि ऊपर कहा गया है। कार्यपालिका एक निश्चित और पूरी अवधि तक बनी रहती है और विधानमण्डल में प्रतिबन्ध मनवाने द्वारा उसे हटाया नहीं जा सकता।

(२) नीति की निरंतरता कार्यपालिका की स्थिरता के कारण देश की कम से कम चार या पाँच वर्षों के लिए एक नीति रहने का निश्चय होता है।

(३) कार्यपालिका की शक्तियाँ एक आदमी में केन्द्रित होने के कारण कार्यपालिका आराज के समय अधिक जोर-शोर से और तत्परता से काम कर सकती है।

(४) दलीय प्रणाली की वृद्धि कम होती है। शासन की इस प्रणाली में दलीय प्रणाली की वृद्धि कम होने की सम्भावना है। कोई राष्ट्रपति दलीय राजनीति से ऊपर उठ कर निष्पक्ष रूप से काम कर सकता है।

इसके शेष—शासन की राष्ट्रपतीय प्रणाली में निम्नलिखित दोष बताए जाते हैं—

(१) यह एकतन्त्रीय होता है—यह प्रणाली एकतन्त्रीय, अनुसरवादी और सत्तरनाक बताई जाती है, क्योंकि इनमें कार्यपालिका अधिकार एक व्यक्ति, अर्थात् राष्ट्रपति, के हाथ में रहता है। राष्ट्रपति अपने निर्वाचन के बाद जो कुछ चाहे कर कर सकता है। पर उसे वह सावधानी रखनी होगी कि उसे सुविधान के अतिप्रमाण का बोझ न डराया जा सके।

(२) कार्यपालिका और विधायिका में सहयोग नहीं—कार्यपालिका और विधायिका के बीच सहयोग आज के जमाने में बड़ा आवश्यक माना जाता है। दूसरी ओर, सहयोग न होने से शासन की दोनों शाखाओं में बार-बार गतिरोध आते हैं। विधान और वित्त के कामों में कार्यपालिका का संयुक्त न होने से एक-एक बात कई-कई कानूनों में आ जाती है और जनता का धन खर्च हो जाता है।

(३) शासन की मंद गति—शासन के अनुसार राष्ट्रपतीय प्रणाली सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई थी, चाल की नहीं। मन्त्रियों के पृथक्करण से सरकारी काम में देर और गड़बड़ी होती है।

सारांश

एकीय सरकार—एकीय सरकार में सत्ता केन्द्रीय सरकार में निहित है और प्रशासन की इकाइयों सुविधा के लिए बनाई जाती है। इकाइयों को सत्ता

मौलिक नहीं होनी यह सी हुई होनी है और केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर बढ़ाई घटाई या यापस ली जा सकती है। केन्द्रीय सरकार स्वायत्त होनी है और इकाइयों की सरकारें इसकी वसुधार्थी।

ऐसी सरकार से मुख्य लाभ ये हैं —

१. विधि, नीति और प्रशासन में एकरूपता,
२. एकीकृत प्रशासन,
३. दृढ़ विदेश नीति, और
४. यह शासन प्रदेशों के अलग होने को रोकता है।

इसकी श्रुतियाँ ये हैं —

१. प्रशासन व तो प्रभावी होता है और न दबा,
२. केन्द्रीय सरकार स्थानीय समस्याओं को नहीं समझ सकती और उनका हल नहीं निकाल सकती,
३. स्थानीय क्षेत्र उन्नति नहीं कर सकते,
४. एकीकृत सरकार लोकप्रिय नहीं होनी, और
५. इसमें केन्द्रीयकृत नोकरशाही हो जानी है।

संघान या फ़ैडरेशन—संघान एक नया तरीका है जिसमें सर्वोच्च सत्ता सम्पूर्ण राज्य मिलकर एक नया राज्य बना लेते हैं। यह सघ आर्थिक या राजनैतिक कारणों से बनाया जाता है।

यह आवश्यक है कि सघ के लिए इच्छा हो। सघ बनाने की इच्छा के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ ये हैं —

१. संघान बनाने वाले राज्यों का पड़ोस
२. भाषा, धार्मिक प्रथाओं, संस्कृति और राजनैतिक परम्पराओं की समानता, पर ये सघ वाले विलुप्त अनिवार्य नहीं हैं।
३. सामान्य राष्ट्रीय भावना का होना,
४. जहाँ तक सम्भव हो वहाँ तक संघान बनाने वाली इकाइयों में समानता।

संघान की विशेषताएँ ये हैं —

- (क) यह मिलने के परिणाम स्वरूप बनता है,
- (ख) इसका लिखित संविधान अवश्य होना चाहिए,
- (ग) संविधान अनम्य (Rigid) होना चाहिए,
- (घ) केन्द्रीय सरकार की और इकाइयों की गतिविधियों में सुनिश्चित

होनी चाहिए,

- (ङ) विधायक, कार्यपालक और न्यायिक विभाग स्पष्टतः अलग-अलग होने

चाहिए,

- (च) न्यायपालिका सर्वोच्च होनी चाहिए, और
- (छ) दुहरी नागरिकता।

इसके ये गुण हैं—

(१) सधान में राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वायत्तता दोनों के लाभ हो जाते हैं,

(२) यह केन्द्रीकरण को रोकता है,

(३) यह स्थानीय विधान और प्रशासन के प्रयोग होने देता है,

(४) यह कम-खर्च होता है क्योंकि इसमें दुहरी कस्थाएँ नहीं होतीं,

(५) यह इस बात का सर्वोत्तम उपाय है कि राज्य अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखें और विदेशी आक्रमण से बचे रहें.

(६) अनेक दफ्तारों को एक साथ में लाकर यह अंतर्राष्ट्रीय प्रेम-भाव पैदा करना है;

(७) यह नये और विस्तृत देश को विकसित करने का सर्वोत्तम साधन है जिनमें अलग-अलग क्षेत्रों को अपनी विशेष आवश्यकताओं का विश्रुति, जिस तरह वे दीज समझें उस तरह करने का अवसर मिलता है।

सधान की कमजोरियाँ—१. यह विदेशी मामलों के संचालन में दुर्बल होता है।

२. सत्ता दो सरकारों के बीच बंट जाने से भीतरी शासन निबन्ध हो जाता है।

३. सधान में इसके विघटन की संभावना हमेशा बनी रहती है।

४. प्रशासन और विधान की दुहरी पद्धति से अनावश्यक व्यय और विलम्ब होता है।

५. यह इसने अधिक स्थानीय स्वयं पैदा कर देता है कि राष्ट्रीय संगठन को गम्भीर हानि पहुँचती है।

६. क्योंकि सधान अनन्य सविधान होता है इसलिए प्रशासनीय व्यवस्था को समय की बदली हुई आवश्यकताओं के लिए आसानी से अनुकूल नहीं बनाया जा सकता।

७. सधान में शक्तिशाली व्यावहारिक प्रतिशिल दलों के लिए बड़ी खराब है क्योंकि वह सविधान के अर्थों पर चलता है जिसे कानून की उपयोगिता पर नहीं।

समशील शासन—उपरीय भागन को उत्तरदायी या मजिस्टरीय शासन भी कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएँ ये हैं :—

(क) राज्य का अध्यक्ष राजा या राष्ट्रपति नाममात्र को कार्यवाहक होता है।

(ख) वाम्बविक कार्यकर्ता मंत्री होते हैं।

(ग) मंत्री विधानमण्डल के बहुमत दल के होते हैं।

(घ) वे अपने सब सरकारी कार्यों के लिए विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी

होते हैं और तब तक अपने पदों पर रहते हैं, जब तक (i) वह दल जिसके वह सदस्य हैं बहुमत में रहे, (ii) इसे विधानमण्डल का विश्वास प्राप्त रहे या (iii) विधानमण्डल को जीवन-पर्यन्त ।

(3) मंत्री विधानमण्डल के सदस्य तथा अपने कार्यपालक विभागों के अध्यक्ष होते हैं ।

शासन की इस प्रणाली के ये लाभ हैं —

१. यह कार्यपालिका और विधायिका में मेल-मिलाप रखती है

२. यह प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र का सर्वोत्तम नमूना है ।

३. यह कुलीनतन्त्र और कौन्तन्त्र का मिश्रण है ।

४. इसमें नम्यता (Flexibility) और लोच या श्रयास्थिता का गुण है ।

५. इसका फिज्जात्मक दृष्टि में बड़ा महात्व है ।

६. यह आलोचना द्वारा शासन है ।

७. यह शासन के सारे तन्त्र को लोकतन्त्रीय रूप देने में सफल हुई है ।

इसकी हानियाँ—

१. यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को खोड़ती है ।

२. यह अस्थिर और उतार-चढ़ाव वाली शासन पद्धति है ।

३. मंत्रियों के पद की अनिश्चितता रहती है और यह दूरदर्शिता-पूर्ण नीति नहीं पैदा करती ।

४. विरोधी पक्ष तथा विरोध करता रहता है ।

५. यह गैर पेशेवर लोगों द्वारा शासन है ।

६. मंत्री राजनीतिज्ञ लोग होते हैं और उन्हें बहुत से अन्य राजनैतिक कार्य रहते हैं इसलिए वे सरकारी काम में पूरा ध्यान नहीं दे सकते ।

७. यह दलीय सरकार होती है और इसमें राजनैतिक फायदा उठाया जाता है ।

८. यह पद्धति, विशेषकर घापानों में, निर्वंक सिद्ध होती है ।

शासन का राष्ट्रपतीय या प्रधानीय रूप—यह शासन का प्रतिनिध्यात्मक रूप है पर उत्तरदायी रूप नहीं । कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती । राज्यों का मुख्य कार्यपालक अध्यक्ष जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में राष्ट्रपति या संघीय कार्यपालक होता है और उसका पद निश्चित काल तक चलता है । वह अपने मंत्री चुनता है जो उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं । इस प्रकार कार्यपालिका और विधायिका में पूर्ण पृथक्ता रहती है ।

लाभ—१. यद्यपि यह शासन का प्रतिनिध्यात्मक रूप है तो भी यह विधानमण्डल की बदलती-बदलती इच्छा पर निर्भर नहीं होता ।

का मताधिकार पावल आदमी के हाथ में सत्कार देने के समान बताया जाता था ।

(२) सम्पत्ति-सम्बन्धी अर्हता—सम्पत्ति सम्बन्धी अर्हता के पक्ष में पहली दलील यह दी जाती है कि जिन लोगों के पास कोई सम्पत्ति है उनका ही उचित रूप से देश में कोई जोखिम माना जा सकता है, और उन्हें ही मताधिकार दिया जाना चाहिए । दूसरी ओर, जिन लोगों के पास कोई सम्पत्ति नहीं, उन्हें मताधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे अपने ही जैसे आदमियों को विधानमण्डल के लिए चुनेंगे । ऐसे व्यक्तियों में हमेशा उन लोगों को गोपित करने की प्रवृत्ति रहेगी जिनके पास सम्पत्ति है ।

दूसरे, यह दलील दी जाती है कि मताधिकार उन व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए जो सरकार को बर देते हैं । जॉन स्टुअर्ट मिल सम्पत्ति सम्बन्धी अर्हता का भी प्रबल समर्थक था । वह यह मानता था कि जो लोग कर नहीं देते, वे वरो से प्राप्त धन को वैसे ही बिना विचारे खर्च करेंगे क्योंकि उनका कुछ नहीं जाता ।

(३) लिंग सम्बन्धी अर्हता—बहुत काल तक मताधिकार सिर्फ पुरुषों को था, स्त्रियों को नहीं । जो लोग स्त्रियों के मताधिकार को विरोधी हैं वे इस बात पर बल देते हैं कि स्त्री घर की रानी हैं और मातृ कार्य ही उसका उचित कार्य है । प्रकृति ने उसे राजनैतिक जीवन के लिए नहीं बनाया । उसके राजनीति में हिस्सा लेने से परिवार के जीवन में निश्चित रूप से गड़बड़ पड़ेगी । सब बच्चों को बौन पालेगा और घर के कामों की देख-भाल कौन करेगा इसके अगवा राजनीति के रही काम में पड़ने से स्त्रियों को मिलने वाला सम्मान और प्रतिष्ठा भी खरम हो जाएंगे ।

आम वयस्क मताधिकार के पक्ष में युक्तियाँ—लोकतन्त्र के बारे में आजकल जो हमारे विचार हैं, उन्हें देखने हुए ऊपर दी हुई दलीलों में से किसी में भी आज की दुनिया में कोई बल नहीं । आजकल सब वयस्कों को, शिक्षा, सम्पत्ति और लिंग सम्बन्धी अर्हताओं का बिना विचार किये, मताधिकार दिया जाता है । आम वयस्क मताधिकार के पक्ष में ये युक्तियाँ हैं—

(१) समता का अर्थ है समान मताधिकार—समता लोकतन्त्र का परम आवश्यक तत्व है । राजनैतिक समता के बिना कोई समता नहीं हो सकती । राजनैतिक समता का मिलना तभी सुनिश्चित हो सकता है जब सब नागरिकों को मताधिकार हो ।

(२) शासन से सबका वास्ता है—जिन बात से सबका वास्ता है, वह सबको ही करनी चाहिए । सरकार, कानून और नीतियाँ सब लोगों से वास्ता रखने हैं । इस प्रकार, सब नागरिकों को कानून बनाने में और सरकार की नीतियाँ तय करने में हिस्सा लेने का मौका होना चाहिए । यह तभी हो सकता है जब सब नागरिकों को मताधिकार हो ।

(३) कितनी शिक्षा आवश्यक नहीं—यह याद रखना चाहिए कि मताधिकार के दस प्रयोग के लिए राजनैतिक शिक्षा की आवश्यकता है, कितनी शिक्षा की

नहीं। राजनैतिक शिक्षा का अर्थ यह है कि आदमी का सामान्य सत्य के काम करने और देश के सामान्य मौजूद समस्याओं का पता होना चाहिए। यह ज्ञान सभी हो सकता है जब कोई नागरिक पढ़ना-लिखना जानता हो। यह ठीक है कि बिनाबी शिक्षा नागरिक को ठीक तरह का ज्ञान दबटठा करने में मदद देती है, पर इसे मताधिकार देने की कोई धन नहीं बनाया जा सकता। दूसरा अल्पा, लोकतन्त्र स्वयं लोगो को शिक्षित करता है। इस प्रकार यह कहना कि मताधिकार से पहले शिक्षा होनी चाहिए, दोनों चीजों की उल्टे तथ्य में रचना है।

(४) तब लोग कर देने हैं—हम इस दलील की मजबूत मानते हैं कि जो लोग कर देते हैं उन्हें ही मताधिकार होना चाहिए। पर इन दलील का सम्बन्ध व धारण से कोई सम्बन्ध नहीं। मताधिकार सम्पत्तिशाली क्यों तब ही सीमित करने से समुदाय के अन्य सब भागा और हिस्सा से बड़ा अन्वय होगा। आज की दुनिया में कर प्रायशः रूप से या परोक्ष रूप में हम में से सब देने हैं; अगले सम्पत्तिशाली क्यों ही नहीं देते। गरीब से गरीब आदमी भी दियागलाही खरीदता है और इस प्रकार सरकार को उत्पादन शुल्क देता है। इन तरह जो लोग सरकार के सब के लिए धन देते हैं, उनके पास यह देखने का उपाय अवश्य होना चाहिए कि वह धन कैसे खर्च किया जा रहा है। यह वे सभी कर मारते हैं, यदि उन्हें मन देने का और अपने सामान्य कर्तव्यों के पत्राव में हिम्मा सेने का अधिकार हो।

(५) समता में लिये की समता भी है—लोकतन्त्र के करने के साथ साथ रिक्तियों के मताधिकार की मांग भी बढती रही है। पिछले न के रूप में, लोकतन्त्र एक आदमी और दूसरे आदमी में कोई भेद-भाव नहीं करता। तो, इसे लिंगा का भेद-भाव क्यों करना चाहिए? रिक्तियों गारोहिक दृष्टि से दुर्बल ही मक्ती है पर और दृष्टियों से वे पुरुषों से किसी बात में पडिया नहीं हानो। उन्हें करने और समझने की क्षमता जो मत के उचित प्रयोग के लिए परमानन्द है बोना लिंगा में समान होती है। धरीर से दुर्बल होने की कारण स्त्रियों को अपनी रक्षा के लिए विधि और समान की आदमी से अधिक आवश्यकता भी है। इस लिए विधियाँ बनाने में उन का हाथ होना और भी जरूरी है।

दूसरे, स्त्री की मताधिकार न देने का मतलब है स्त्रियों को अच्छे नागरिक मतदान की प्रवृत्ति से वंचित करना। हम पहले देख चुके हैं कि नागरिकता के लिये वक्ते को प्रशिक्षित करने में माना क्या हिम्मा ले मक्ती है। यदि उन्हें नागरिक भावना से वंचित कर दिया जाये तोवे अपने वक्ते की कुछ भी शिक्षा न दे सकनी।

समाजशास्त्रियों द्वारा प्रत्यक्ष विधान—आधुनिक लोकतन्त्र का रूप प्रतिनिध्यात्मक है। विधियाँ माधारणतया निर्वाचकमण्डल द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों द्वारा बनाई जाती हैं, पर प्रतिनिधित्वात्मक लोकतन्त्र की बड़ी आलोचना की गई है। कहा जाता है कि विधान मण्डल गरीबों के हितों की उपेक्षा करते हुए दलगत भावना से विधियाँ बनाते हैं। दूसरे, हो सकता है कि किसी भी समय किसी सामान्य

दृष्ट करने का अधिक अच्छा दृग् यह है कि यह आवश्यक है कि यह सब लोगों की राय नहीं होगी, पर मुनिदिनक रूप में सब लोगों के लिए राय होगी है। दूसरे पक्षों में, यह वह राय है जिसका लक्ष्य किसी शान्ति के बजाय सारी जनता का कल्याण होता है। जिस राय का लक्ष्य किसी शान्ति मनुष्य, चर्च का महानर्थ का लाभ है, वह वर्गीय राय कहलाएगी।

आशयक नहीं कि यह बहुजन की राय हो—आशयक नहीं कि लोकमत बहुजन की राय हो यद्यपि यह अधिकतर लोगों का मत है। तो अधिक अच्छा होगा पर कभी-कभी बहुजन की राय स्वार्थ-भरी या अहित देखने वाली हो सकती है और जनमत की राय जनसाधारण के हित पर विचार करने वाली हो सकती है। उस अवस्था में जनमत की राय लोकमत होगी। उदाहरण के लिए, १९४७ में भारत का विभाजन होने पर उस हिन्दुओं और मुस्लिमों की पाकिस्तान में लगे दिया गया तो भारत में बहुजन पाकिस्तान में बूढ़ के पक्ष में था। भारत में छोटे बहुत लोग यह अनुभव करने के कि ऐसा कार्य हमारी नई पापी दुई आजादी के लिए हानिकारक होगा। इस प्रकार इस मामले में जनमत की राय ही लोकमत है।

लोकमत में लोकमत का महत्व—उपरोक्त, लोकमत होने का महत्व सिर्फ लोकमत में ही पैदा होता है। तानाशाही में कोई लोकमत नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें विचार और भावना की आजादी नहीं होती। दूसरे, लोकमत की अन्य रायों से जल्य करने की कठिनाई भी लोकमत में ही पैदा होती है। तानाशाही में अगर कोई अभिमत होता भी है, तो वह निरर्थक होता है। वहाँ जनता की राय नहीं होती है जो सरकार की। सरकार की राय से निम्न राय रखने वाले आदमी को देशद्रोही माना जाता है और देशद्रोही को कठोर दण्ड दिया जाता है।

लोकमत लोकमत द्वारा सामान्य है। लोकमत में लोकमत केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों के कार्यमंचालन में विभिन्न स्तरों पर आता है। विधानमंडल और कार्यपालिका दोनों को लोकमत द्वारा की गई आलोचना और प्रश्न पर उत्तर विचार करना पड़ता है। लोकमत में सामाजिक जीवन के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी लोकमत बड़ा प्रभाव डालता है। सब तो यह है कि लोकमत की प्रगति ही प्रबुद्ध, प्रागल्भिक और आधुनिक लोकमत पर निर्भर है।

प्रबुद्ध लोकमत के बनने के लिए आवश्यक शर्तें—किसी देश में प्रबुद्ध लोकमत बन गये इसके लिए जीवन की निम्नलिखित अवस्थाओं का होना अनिवार्य है—

(१) विचार और सोचने की आजादी—मोर्गेन की सोचने और अपनी बात कहने की आजादी होती चाहिए। यदि सोचने और सोचने की आजादी नहीं है तो लोकमत का निर्माण नहीं हो सकता और न वह प्रकट किया जा सकता है। इसलिए प्रबुद्ध

लोकमन के लिए यह बात आवश्यक है कि आपस में स्वाभाविकपूर्वक चर्चा और आलापना हो। इसने लिए जासक लोकतन्त्रीय होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के आलापन में ही मोचने, बोझों और अपनी बात प्रकट करने की आजादी को गारंटी रहती है।

(२) स्वतन्त्र अभिव्यक्ति—क्योंकि अधिकतर लोग अज्ञान और दम परिभाषों के मन को ही अपना मन बना लेते हैं, इसलिए मुद्दों लोकमन के लिए स्वतन्त्र ईमानदारी और निष्पक्ष अवधारणों का होना एक और आवश्यक शर्त है। प्रम या अवधारणों के बिना या समुदाय के हित साधन के उद्वेग नहीं होना चाहिए, और न उनपर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। अवधारणों को जनता के सामने मही और दम पारदर्शित समाचार और विचार रखने चाहिए।

(३) शिक्षा—बुद्धि को तेज करने, ज्ञान को बढ़ाने, और दृष्टिकोण को बड़ा करने के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। शिक्षा जनता की तर्क और आलोचना करने की योग्यता बढ़ाती है और लोगों को स्वतन्त्र विचार की आदत पड़ती है। अनपढ़ और अज्ञानी आदमी मूल्य प्रचार में गमराह हो सकता है। बुद्धिमान और जानकारी रखने वाले ही अच्छी और स्वतन्त्र राय रख और प्रकट कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा दृढ़ और प्रबुद्ध लोकमन बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शिक्षाप्रणाली साम्प्रदायिक दृष्टिकोण में रहित होनी चाहिए, क्योंकि स्कूलों और कॉलेजों में बने हुए विचार और मत स्थायी न हो पाते हैं।

(४) मेल मिलान—गुस्विन और प्रबुद्ध लोकमन मेल मिलान और तद्भावना के वातावरण में ही तरक्की करता है। जनता को आपस में पूर्ण विश्वास और समझ-बूझ होनी चाहिए और उनका जीवन गन्तागिनापूर्ण होना चाहिए। आपसी ईर्ष्या और अनिद्वन्द्व अन्ते लोकमन के बड़े दुश्मन हैं। सामाजिक जीवन में साम्प्रदायिक दलों या मजहबों और मालिकों के शक्ति ने उल्लंघन न होनी चाहिए।

(५) अवस्था और लक्ष्य—आम लोग सामाजिक और राजनैतिक समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कर गये। इसके लिए उनके पास उन समस्याओं के अध्ययन के लिए काफी मात्रा में समय होना चाहिए। माली समय उन्हें तभी मिल सकता है, जब वह आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र हों। और इस प्रकार, लोकमन के निर्माण के लिए माली समय और समृद्धि दोनों जरूरी हैं।

(६) राजनैतिक दल—अवधारणों की तरह राजनैतिक दलों का भी लोगों को शिक्षित करने में बहुत बड़ा स्थान है। राजनैतिक दल अपने प्रचार द्वारा लोगों को देश की अनेक समस्याओं की जानकारी देते रहते हैं और इस तरह उन्हें अपनी राय बनाने के योग्य बनाते हैं। पर यह बहुत आवश्यक है कि दल दृढ़ आर्थिक और राजनैतिक सिद्धांतों के आधार पर बनाए जाएं। वे धार्मिक आधार पर नहीं होने चाहिए।

लोकमन के निर्माण और अभिव्यक्ति के माध्यम—यूँ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि सब लोग अपनी राय मूढ़ नहीं बनाते । उनके पास अनेक समस्याओं के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए साधन भी नहीं होते और उनके बारे में स्वतन्त्र निर्णय और सम्मति बनाने की योग्यता भी नहीं होती । सब लोगों के पास न इतना समय ही होता है कि वह सार्वजनिक मामलों का अध्ययन और विचार कर सकें । इसलिए अधिकतर लोग किसी न किसी जगह बनी-बनाई राय अपना लेते हैं । सार्वजनिक मामलों में बहुत छोटे लोग सक्रिय दिग्दर्शक लेते हैं । वे लोग वेरोवरा राजनीतिज्ञ, राजनैतिक दलों के नेता, विपक्ष सम्राज्ञी के सदस्य और पत्रकार होते हैं । इन लोगों का काम है विविध समस्याओं का सर्व अध्ययन करना और उनके हुए सत्यापन करना । वे लोग अल्पकारी और समाजों द्वारा अपने विचारों का प्रचार भी करते हैं, जहाँ से लोग अपनी अपनी पक्ष के अनुसार विभिन्न विचार ग्रहण कर लेते हैं ।

जो लोग बनी बनाई राय अपना लेते हैं, वे दो तरह के होते हैं । पहली तरह के लोग तो बहुत बड़े होते हैं, अखबारों और समाजों में प्रबल की जाने वाली रायों की बहुत सार्वजनिक के बाद स्वीकार करने हैं । वे अपना दिमाग खुला रखते हैं, और उन्हें किसी सार्व दृष्टिकोण के पक्ष का विपक्ष में कोई पूर्वाग्रह नहीं होता । दूसरी तरह के लोग, जो देश की भाषाओं का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं, कुछ नेताओं के व्यक्तिगत, भाषणों या तारों में बहुर उन्ने दृष्टिकोण की स्वीकार कर लेते हैं ।

लोकमन बनाने के काम में लगे हुए अभिव्यक्ति ये हैं—प्रेस या अखबार, समाज, राजनैतिक दल, सिनेमा, रेडियो, शिक्षा मण्डल और विधानमंडल । अब हम लोकमन के बनाने और उसे प्रकट करने में इनमें से प्रत्येक के कार्य पर विचार करेंगे ।

(१) प्रेम या अखबार—नागरिक शास्त्र में प्रेम का मतलब दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक अखबार और घटनाचक्र मध्यस्थी पुस्तकें हैं । अखबारों में रोज़ सब तरह की खबरें छपती हैं और उनका मूल्य अस्पासी है । पत्रिकाएँ और पुस्तकें कुछ महत्वपूर्ण विषय लेकर उन पर विचार करती हैं और इस रूप में उनकी मूल्य अधिक स्थायी होता है ।

लोकमन में प्रेम का कार्य—जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, लोकमन लोकमन द्वारा साधन है । अखबार लोकमन के निर्माण और अभिव्यक्ति के मुख्य माध्यम होने के नाते लोकमन में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं । वे निम्नलिखित कार्य करते हैं ।

जानकारी देने का काम—अखबारों का पहला काम है लोगों को देश-विदेश की अनेक राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक घटनाओं के बारे में जानकारी देते रहना । यदि लोकमन बनना का, जनता द्वारा, जनता के लिए साधन है, इसलिए

यह बहुत आवश्यक बात है कि लोगों को सरकार की नीतियों, निश्चयों और कार्यों के बारे में सब कुछ पता हो। अखबार लोगों को इन सब बातों की जानकारी देते हैं। जानकारी देने के कार्य द्वारा अखबार शासन के संचालन में लोगों की दिलचस्पी बनाये रखने हैं।

निर्माणात्मक कार्य—अखबारों का काम सिर्फ जानकारी देने का ही नहीं है, बल्कि निर्माण का भी है। ये पहले लोगों को जानकारी देते हैं, फिर उन्हें अपनी राय बताने में सहायता देते हैं। समाचार देने के अलावा, अखबार अपने सम्पादकीय लेखों और अप्रलेखों में कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय भी देते हैं। जनता, जो यकीननाई राय अपना लेती है, अखबारों द्वारा प्रकट की हुई राय को ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि अखबार लोकमत को बालता और संगठित करता है।

अखबार लोकमत प्रकट करने का माध्यम है—अखबार सरकारी नीतियों और निश्चयों पर जनता की भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को प्रकट करने का साधन भी है। इस प्रकार अखबार पहले तो लोकमत के निर्माता के रूप में, और फिर उसके प्रकाशक के रूप में जनता के हितों की रक्षा करते हैं। अखबार प्रचार का संचित-पाली साधन है, और इसलिए उनका जनता पर बड़ा प्रभाव होता है। कोई लोक-सभा मरकार इसके महत्व की उपेक्षा नहीं कर सकती।

अखबार सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता करता है—जनता और सरकार के बीच में होने में अखबार को दोनों का आदर और विश्वास प्राप्त होता है। इसलिए जनता और सरकार में विरोध होने पर यह सर्वोत्तम मध्यस्थ है। यह दोनों तरफ की भावनाओं को हटका करके वहाँ उत्तम काम कर सनता है। यह उन दोनों को तर्कसंगत होने में सहायता देता है। यह सरकार को आधार से और जनता को क्रांतिकारी होने से रोकता है। इसलिए अखबार वह मेल-मिलाप बनाए रखता है जो लोकतन्त्र की स्थापना के लिए बहुत आवश्यक है।

अच्छे प्रेस के गुण—अच्छा प्रेस यानी अखबार सच और निष्पक्ष होना चाहिए। जिसे कम महत्व की बातों की बड़े बड़े शीर्षक देकर अतिरजित नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, इसे सनमनीदार खबरें देने और किसी खबरों के लिए कतक बचाने से बचना चाहिए। यदि वह ऐसा न करेगा तो एक ओर तो सरकार और जनता के बीच और दूसरी ओर, लोगों में परस्पर खाई खोदी जा जाएगी।

इसी प्रकार, अखबार को अपनी खबरों और विचारों में ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। इसे सरकार या किसी दल की स्वार्थसिद्धि या किसी समुदाय विशेष का हित-साधन नहीं करना चाहिए। अगर अखबार पक्षपात करने वाला है तो जनता की स्वाधीनता और समाज की शांति खतरे में पड़ जाएगी। हमारे देश में विभाजन से पहले के दिनों में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच कटुता बढाने की

प्रिमेदारो बहुत हद तक अवधारो पर थी। इस प्रकार अच्छे प्रेस का काम लोगों में तनाव के बजाय मेल मित्राप पैदा करना होना चाहिए।

(९) सभामंच—नागरिक शास्त्र में सभामंच से मतलब उस जगह से है जहाँ से सार्वजनिक सभाओं में भाषण दिये जाते हैं। मंच सरकार की नीतियों और कामों के विरुद्ध जनता की तिकायने प्रचारित करने का एक साधन है। यह ऐसा स्थान भी है जहाँ सरकार के सदस्य अपने कामों और नीतियों की तफाई देते हैं। इसलिए सार्वजनिक सभाओं में लोगों को दोनों तरफ की बात सुनने का मौका मिलता है। वे अपनी इच्छानुसार निष्कर्ष निकाल सकते हैं और अपनी राय बना सकते हैं।

(१) राजनैतिक दल—किसी राजनैतिक दल का मुख्य काम सत्ता प्राप्त करना है। लोकमत में राजनैतिक सत्ता उनके हाथ में रहनी है, जो बहुमत में होती है। इसलिए प्रत्येक राजनैतिक दल अपने लिए अधिक से अधिक अनुयायी हासिल करने का दल बनाता है। इस प्रयोजन के लिए, राजनैतिक दल अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार करते रहते हैं। चुनावों में पहले यह प्रचार तीव्र कर दिया जाता है क्योंकि अधिकतर लोग उस समय ही सार्वजनिक मामलों में दिलचस्पी दिखाने हैं। राजनैतिक दल चुनाव के मनीफेस्टो या आदिषपत्र निकालते हैं, और सार्वजनिक सभाएँ करते हैं। उनमें वे प्रत्येक दल अपने कार्यक्रम और नीति के पक्ष में बोलता है। इसलिए राजनैतिक दल अपने-अपने कार्यक्रम के पक्ष में लोगों को शिक्षित करते हैं, और लोकमत संगठित करते हैं।

(४) सिनेमा—आधुनिक काल में सिनेमा भी लोकमत बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन हो गया है। कुछ दृष्टियों से फ़िल्म का काम अवधारो के काम से भी अधिक महत्वपूर्ण है। सब लोग अवधार नहीं पढ़ते, पढ़ उनमें से अधिकांश लोग फ़िल्म देखते हैं। इसलिए सिनेमा बुरी में दिखायी जाने वाली समाचार चित्रावली अधिक लोगों को लाभ पहुँचाती है। फ़िल्मों का रूप चित्रात्मक होने में लोगों को बहुत-सी बातें आसानी से समझाना सम्भव हो जाता है। जनता की बेगना को मचेन दिया जा सकता है और फ़िल्मों में हृदयस्पर्शी कहानियाँ पेश करके अनेक सामाजिक और आर्थिक बुराइयों के खिलाफ लोकमत को जागारी से संगठित किया जा सकता है।

(५) रेडियो—लोकमत के संगठनकर्ता के रूप में रेडियो, अवधार, सिनेमा और सभामंच इन तीनों के थोड़े-थोड़े लाभ का संयोग है। अवधार की तरह रेडियो भी सबसे प्रसारित करके और जनपर टीनाटिप्पणी करके लोकमत संगठित करता है। सार्वजनिक हित के अनेक विषयों पर वात्ताएँ और बातचीत की व्यवस्था करके रेडियो अत्यंत सभामंच का काम करता है। सिनेमा की तरह रेडियो मनोरंजन और शिक्षा एक साथ देता है। मनोरंजन के साथ शिक्षा देने के उदाहरण देहाती प्रोग्राम और स्त्रियों तथा बच्चों के प्रोग्राम हैं।

इसलिए रेडियो का स्थान प्रेम से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। अक्सर तो निर्दोष-लिये आदमी के लिए उपयोगी है, पर रेडियो अनपढ़ लोगों के लिए भी फायदेमंद है। भारत में अशिक्षित लोगों के अनपढ़ होने के कारण यहाँ जन-साधारण को शिक्षित करने में रेडियो का उपयोग लाभदायक हो सकता है। हमारा सहारा लेकर हम कई सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक बुराइयों को हटा सकते हैं और जनता के दृष्टिकोण को अधिक प्रगतिशील बना सकते हैं। रेडियो का एक और लाभ यह है कि इसके जरिये एक साथ लाखों लोगों में अपनी बात कही जा सकती है। इस प्रकार रेडियो में थोड़ी-सी देर में लोकमत संगठित करना आसान हो जाता है।

पर यह याद रखना चाहिए कि जैसे की तरह रेडियो का भी दुरुपयोग किया जा सकता है। अधिकतर देशों में रेडियो पर सरकार का एकाधिकार है। वहाँ हमारा अच्छा या बुरा उपयोग करना सरकार के ही हाथ में है। यदि सरकार जनता का हित चाहती है तो वह रेडियो का सही उपयोग करेगी। पर अगर किसी देश की सरकार स्वार्थी लोगों के हाथ में है, तो रेडियो में जनता को गुमराह किया जाएगा। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान में सरकार लोगों में भारत-विरोधी भावनाएँ फैलाने में इसका उपयोग कर रही है।

(६) शिक्षा समस्या—स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय आदि शिक्षा संस्थाएँ भविष्य के नागरिकों के प्रशिक्षण की जगह हैं। कथयुक्त के निर्माण काल में इन संस्थाओं में लिए हुए विचार और बनाई हुई राय बाद के जीवन में भी उनके साथ चलती रहती हैं।

(७) विधानमण्डल—किसी लोकतांत्रिक देश के विधानमण्डल में सब स्थितियों और विचारों के योग होने हैं। इसलिए इसमें होने वाली भाषण लोकमत को प्रकट भी करने हैं और बनाते भी हैं।

राजनैतिक दल

राजनैतिक दल कितने होते हैं—कोई राजनैतिक दल उस नागरिकों का एक संगठित समूह है जिनके सार्वजनिक प्रश्नों पर एक ते विचार होते हैं, और वे जिस नीति को मानते हैं, उसे लागू करने के लिए सरकार पर विषयों हासिल करने के वास्ते एक राजनैतिक इकाई के रूप में काम करते हैं। प्रत्येक राजनैतिक दल मानवीय स्वभाव की निम्न दो विशेषताओं पर आधारित है—

(१) लोगों की राय बलम-जलग होनी है।

(२) साथ ही वे, स्वभाव से गूँथबारी या समूह बनाकर रहने वाले (Gregarious) होते हैं। अपने मनमोहों के बानबूट उन्हें कुछ मोटे उमूलों पर एकमत होना ही पड़ता है और उन नीति को जमल में लाने के लिए काम करना ही पड़ता है।

किसी राजनैतिक दल का आवश्यक लक्ष्य—किसी राजनैतिक दल को, सही

जाता है। इसलिये दल साधारणतया उम्मीदवारों के चुनाव में बहुत गतिधारी रहते हैं।

(३) दल उम्मीदवार के लिए समर्थन प्राप्त करता है—दल उम्मीदवार को न केवल पक्ष करना है बल्कि उसके लिए ओर-ओर से समर्थन भी हासिल करता है। अपने-आपकी के लिए खुद बोट हासिल करना बड़ा मुश्किल काम है। दल के लिए यह कुछ कठिन काम नहीं, क्योंकि इसकी छात्तार्थ मांगे देश में होती हैं।

(४) दलीय प्रणाली गरीब आदमी को भी चुनाव में लड़ा होने का मौका देती है—दलीय प्रणाली गरीब आदमियों को भी चुनाव में लड़े होने का मौका देती है। हर चुनाव में प्रचार पर कुछ न कुछ खर्च करना पड़ता है। कभी-कभी चुनाव का खर्च हजारों रुपये होता है। अगर उम्मीदवार गरीब आदमी हो तो दल उसकी ओर से खर्च करता है। अगर राजनैतिक दल न होते तो सिर्फ धनी आदमी चुनावों में लड़े होते।

(५) दलीय प्रणाली शिक्षादायक है—राजनैतिक दल अपने चुनाव प्रचार द्वारा लोगों को शिक्षित करते हैं और लोकमत गठित करते हैं।

(६) एकल होने पर दल अपने बचतों को अनुसार बानून बनाते हैं—चुनाव के बाद बहुमत पक्ष को सामन का नियंत्रण मिलता है। तब दलवा बल्लेबल है कि लोगों को दिए हुए वचनों के अनुसार बानून बनाए। दिगी दल के लिए जनता की दिए हुए वचन का भंग करना अच्छा नहीं।

(७) विरोधी दल का प्रति पक्ष का कार्य—जिन दलों की विधानमंडल में बहुमत नहीं मिलना वे मिलकर एक प्रबल विरोधी दल के रूप में संघटित हो जाते हैं। लोकमत में विरोधी दल भी बहुतबूनी हिस्सा लेता है। इसका यह काम है कि मत-दानाओं को सरकार की क्रियाओं के बारे में निरंतर जानकारी देता रहे और इस तरह शासन को बड़ा बनाए। प्रबल विरोधी दल सरकार को जवाबदारी होने से रोक्ता है, क्योंकि लोकमत में जरा गा भी परिवर्तन संतुलित सरकारों दल को उसके पद में हटा सकता है। पर यह याद रखना चाहिए कि विरोधी दल को हानिकारक आलोचना नहीं करनी चाहिए। इसे संतुलित दल को रचनात्मक सुझाव देने चाहिए। विरोधी दल को राष्ट्रीय हित के नामों में सरकार से सहयोग करना चाहिए।

दलीय प्रणाली के साथ—दलीय प्रणाली के मुख्य लाभ यह हैं—

(१) दलीय प्रणाली लोकमत को चलने योग्य बनाती है। अगर दल न होते तो प्रतिनिधियों का चुनाव और सरकारों का निर्माण कठिन काम होगा। हम अगर ऐसा चुके हैं कि लोकतन्त्रीय सरकार के गठन में दलों का क्या स्थान है।

(२) दल अपने चुनाव आंदोलनों द्वारा लोगों को शिक्षित करते हैं। वे चुनाव पॉलिटिक्स को बजाते हैं और देश के सामने भीड़ समाजियों के पार में लोगों

को जानकारी देने के लिए सार्वजनिक मनाह करले हैं। दण्ड न केवल जनता को जानकारी देते हैं, बल्कि वे उन्हें अपनी राय बनाने में भी सहायता देते हैं।

(३) दलीय प्रणाली साधारण के व्यवहारी व्यवहार में बचाती है। जिस लोगों के हाथ में शासन की बागडोर रहती है, वे मुदा दण्ड के नियंत्रण में रहते हैं। वे जो चाहें नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी दण्ड मनदाताओं या विश्वास नहीं माना जाता। फिर, विरोधी पक्ष सरकार के कार्यों पर कड़ी निगरानी रखते हैं। वे मनदाताओं को जो मोहनन्त्र में बमलों मानिए हैं उसकी कमियाँ बताने रहते हैं।

(४) दलीय प्रणाली जनता और शासन के बीच में आवश्यक कड़ी होती है। यह शासन और नागरिक के बीच पुल का काम करती है।

(५) दलीय प्रणाली गुणानों के लिए साक्षीर में उपयोगी है। अगाधों में दलीय प्रणाली द्वारा सहयोग समर्थ हो जाता है।

(६) शासन की प्रभावी या राष्ट्रीय प्रणाली के लिए भी दलीय प्रणाली विशेष उपयोगी है। इस प्रणाली में दण्ड ही कार्यपालिका और विधायिका को सहयोग में काम करने योग्य बनाता है।

दलीय प्रणाली की हानियाँ—दलीय प्रणाली के आगेवाह हमने कुछ दोष बताते हैं—

(१) कहा जाता है कि दलीय प्रणाली राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है। यह लोगो में अनाकाम्य और द्वितीय भेदभाव पैदा करती है। लोग परस्पर-विरोधी समूहों में बंट जाते हैं, और एक दूसरे की अपना दुश्मन समझने लगते हैं। यह भेदभाव राष्ट्रीय प्रगति में बाधा डालता है।

(२) कहा जाता है कि दलीय प्रणाली किसी देश के जीवन को मशीन जैसा बना देती है। विरोधी दल सरकार द्वारा पैदा किए गए नव कानूनों का विरोध करना अपना कर्तव्य समझता है। इसी प्रकार, सरकार विरोधी दल द्वारा नहीं जाने वाली सब बातों पर सम्मोहता में विचार नहीं करती।

(३) दलीय प्रणाली की एक और आलोचना यह है कि यह दण्ड के सदस्यों की व्यक्तिता (Individuality) को नष्ट कर देती है। उन्हें दण्ड के अनुशासन में रहना पड़ता है, और इसलिए वे किसी मामले पर दण्ड की इच्छाओं के विभिन्न स्वरूप रख नहीं अपना सकते। आत्मसम्मान की आदमी को प्रायः दण्ड का नियंत्रण अपने लिए असहनीय मान्य होता है। इसलिए दलीय प्रणाली बहुत से अच्छे नागरिकों को सार्वजनिक जीवन में अलग रखती है।

(४) दलीय प्रणाली के विरोधियों का कहना है कि यह प्रणाली समाज के नैतिक स्तर को कम करती है। दलीय प्रचार में झूठ और कथक कथाओं का दोल-धाना होता है। दण्ड मनदाताओं को रिक्त भी देते हैं।

रोहमीय और बट्टीय प्रजाति—विगी राज्य में दो यह अधिक राजनरिष दत्त हो गये हैं। जब दत्त की मृत्यु हो जाती है, तब यह दो दत्तीय प्रजाति बन जाती है। जब दो न अधिक दत्त होते हैं, तब यह बट्टीय प्रजाति बन जाती है। दत्तीय और बट्टीय प्रजाति में दो दत्तीय प्रजाति है। इन दोनों में राजनरिष दत्तों की प्रजाति मृत्यु हो न अधिक है पर दत्त न प्रजाति में मृत्यु दत्त दत्त है। यूरोप के दत्त न दत्त में, गाम न दत्त में बट्टी न दत्त है जिनकी मृत्यु दत्त दत्त १० न २० दत्त है। जहाँ बट्टी न दत्त होते हैं, वहाँ यह दत्त बट्टी और बट्टी। वे मृत्यु में राजनरिष मृत्यु होते हैं।

दो दत्तीय प्रजाति के मृत्यु—दो दत्तीय प्रजाति का मृत्यु दत्त है कि दत्त अधिक दत्तों और दत्त दत्त का दत्त मृत्यु दत्त हो जाता है। विधानमण्डल में एक दत्त का विधान मृत्यु दत्त हो जाता है। दत्तिय मृत्यु दत्त को दत्त दत्त बट्टीय का मृत्यु दत्त मृत्यु का निरपत्त हो जाता है। तब मृत्यु दत्त दत्त न दत्त न दत्त मृत्यु दत्त का मृत्यु दत्त हो जाता है।

दत्त, दो दत्तीय प्रजाति में मृत्यु मृत्यु में प्रतिनिधित्व दत्त दत्त है एक दत्त मृत्यु प्रजाति है जिनमें मृत्यु दत्त मृत्यु दत्त मृत्यु दत्त है। दो दत्त के दत्तिय दत्त मृत्यु दत्त हो जाते हैं और दत्त दत्त दत्त न मृत्यु दत्त की मृत्यु है। निरपत्त दत्त दत्त दत्त में न दत्त दत्त मृत्यु और दत्त दत्त मृत्यु है कि दत्त दत्त दत्त दत्त हो।

दत्त, दो दत्तीय प्रजाति विरोधो दत्त की मृत्यु दत्त के दत्त दत्त दत्त में अधिक दत्तिय और दत्तिय दत्त दत्त है। दत्त प्रजाति में मृत्यु दत्त की मृत्यु दत्त अधिक दत्तिय दत्त न की मृत्यु है।

दो दत्तीय प्रजाति के मृत्यु—दो दत्तीय प्रजाति का विरोधो दत्त दत्त है कि दत्त मृत्यु दत्त में दत्तिय दत्त दत्त हो जाते हैं। दत्त प्रजाति में मृत्यु दत्त की विधानमण्डल में दत्त बट्टीय दत्त जाता है। विधानमण्डल को दत्तिय मृत्यु दत्त के दत्तिय दत्त दत्त और दत्तिय दत्त मृत्यु दत्त दत्त है। दत्तिय, मृत्यु दत्त की विधानमण्डल में दत्तिय दत्त दत्त हो जाती है, और दत्त दत्त विधानमण्डल को दत्तिय दत्तिय दत्त दत्त है।

दत्त, दत्तिय दत्त दत्तिय दत्त दत्त के दत्तिय दत्त में दत्त हो जाता है। दत्त मृत्यु दत्त है कि दत्त दत्त दत्त दत्त दत्त है तब दत्त दत्त दत्तिय दत्त के दत्तों की दत्त की दत्तिय दत्त दत्त है।

दत्त, दो दत्तीय प्रजाति में निरपत्तों की दत्त दत्त दत्त के दत्त दत्त-

परिपूरणा—यह वह मापन है जिसमें विभी छोटे बालून पर, जिन पर विधान-मंडल अपनी राय प्रकट कर चुका है, निर्वाचकों का पैमरा मापा जाता है।

प्रारम्भ या उपक्रम—यह वह मापन है जिसमें निर्वाचकों की दोरी विविध निर्दिष्ट सरकारी धाम बालून बनाने के लिए विधानमण्डल को आदेश दे सकती है।

परिपूरणा और प्रारम्भ या उपक्रम के पञ्च में युक्तियाँ —

(१) वे जनता की सर्वोच्चता का प्रमाण हैं।

(२) उनके द्वारा जनता की वास्तविक इच्छा का पता लगाया जा सकता है।

(३) वे राजनैतिक दलों के प्रभाव को कम करने हैं।

(४) इन विधियों में बनाये गए बालूनों का पालन अधिक आसानो में होता है।

(५) वे लोगों को शिक्षित करने हैं और उनमें दैवशक्ति के भाव बढ़ाने हैं।

परिपूरणा और प्रारम्भ या उपक्रम के विषय में युक्तियाँ—(१) वे विधान मण्डल के प्रभाव को कम करने हैं, और विधानमण्डल सारस्वाह होने लगता है। (२) इन उपायों में बालूनों के ड्राफ्ट (Draft) में त्रुटि रहती है। (३) विप्रे-यक या तो खराब मानना पड़ता है या रद्द करना पड़ता है। (४) ये उपाय राजनैतिक दलों की बुराइयों को ही बढ़ाने हैं। (५) मिशा देने की दृष्टि में इनका कोई मूल्य नहीं।

लोकमत : लोकमत कितने बहते हैं—आवर्ग लोकमत उसे वह मरने हैं जिसका लक्ष्य जनमाधारण की मलाई हो और जो बहुत में लोपो का हो। पर वह जरूरी नहीं कि यह राजका या बहुमत का विचार हो। कोई सर्व-पक्षपाती विचार लोकमत नहीं रखता।

लोकमत लोकमत द्वारा प्राप्त होता है और इसकी प्रगति लोकमत के अनुसार और सजग होने पर निर्भर होती है।

प्रमुख लोकमत के सिद्ध आचार्यक दलों .—

(१) विचार और भाषा की आजादी।

(२) स्वतन्त्र प्रेस।

(३) आम शिक्षा।

(४) लोगों की अवस्था और सुगहली का होना।

(५) आर्थिक और राजनैतिक सिद्धांतों के आधार पर अच्छी तरह संगठित राजनैतिक दल होने चाहिए।

लोकमत बनाने और प्रकट करने के साधन—अधिकतर लोग बनी-बनाई राय अपना लेते हैं। लोकमत बनाने के काम में ऐसे हुए साधन हैं प्रेस, सामान्य राजनैतिक दल, सिनेमा, रेडियो, शिक्षा मर्यादा और विधान-मण्डल।

प्रेम—प्रेम लोगों को देश-विदेश की अनेक राजनैतिक, जायिक और सामाजिक घटनाओं का परिचय देता है और मन्दादीय लोगों और अपने-प्रायः अपनी राय बनाने में मदद देता है। प्रेम द्वारा सरकार की नीतियों और फैसलों पर जनता की भावनाओं और प्रतिनिधियों का प्रचार भी किया जा सकता है। इस प्रकार, यह सरकार को अत्याचारों होने में रोकता है। अच्छा प्रेस विचारशील, निष्पक्ष और ईमानदार रहकर सबको और विचार देने वाला होना चाहिए। तब ही यह सरकार और जनता के बीच मन्त्रस्थान का काम कर सकता है।

समास—समास जनता की निराशाओं लोगों के सामने लाने का मापन है और यह सरकार के ऊँचे अधिकारियों को अपने कामों और नीतियों की सफाई देने का मौका देता है।

राजनैतिक दल—राजनैतिक दल लोगों को शिक्षित करते हैं और अपने चुनाव प्रचार द्वारा लोकमत संगठित करते हैं। वे निर्णयों को निराकरण देते हैं, और मार्गदर्शक प्रभाव करते हैं।

निर्मा—निर्मा कुछ दृष्टियों में प्रेम में भी अधिक महत्वपूर्ण मापन है, क्योंकि यह जनता पर भी असर डालता है। फिल्मों में जाने वाली सबको और दिन को छूने वाली कहानियाँ बहुत जल्दी लोकमत संगठित करती हैं।

रेडियो—रेडियो में सप्ताह, निर्मा और समास तीनों के गुण एकत्र हो जाते हैं। मिक्रो, मक्को और रेडियो के विविध कार्यक्रम मनोरंजन के साथ-साथ शिक्षा देते हैं। रेडियो ही एकमात्र मापन है जिसके द्वारा लोकमत कम से कम समय में संगठित किया जा सकता है। इसके द्वारा हम कई सामाजिक और जायिक घटनाओं को भी दूर कर सकते हैं।

शिक्षा महशार—स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भावी नागरिकों के प्रशिक्षण की जगह हैं। यहाँ बहुत कठिन विचार और बनाई गई राय बहुत कुछ स्थायी बन जाती होती हैं।

विधानमण्डल—विधानमण्डल में होने वाले विचार लोकमत को प्रकट भी करते हैं और बनाने भी हैं।

राजनैतिक राजनैतिक दल—राजनैतिक दल उन नागरिकों का संगठित समूह है जिनके आर्थिक मकालों पर एकमे विचार हो और जो अपनी नीति को लागू करने के लिए सरकार पर नियंत्रण हासिल करने के वास्ते एक राजनैतिक द्वाय के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार किसी राजनैतिक दल में चार चीजें होती जरूरी हैं—

(१) इनके सदस्यों का कुछ मूल सिद्धान्तों पर एक मत होना चाहिए। (२) यह एक गठित समूह होना चाहिए। (३) इनके अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए वैधानिक उपायों में काम लेना चाहिए। (४) इसे राष्ट्रीय हित के लिए काम करना चाहिए,

कितनी पक्ष या वर्ग के हितों के लिए नहीं।

राजनैतिक दलों के कार्य—प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र राजनैतिक दलों के बिना काम नहीं चला सकता। वे निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य करते हैं—(१) वे चुनाव के लिए उम्मीदवार छांटते हैं। (२) प्रत्येक दल अपने उम्मीदवार के चरित्र और भाषण की गारण्टी होता है। (३) प्रत्येक दल अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन प्राप्त करता है। (४) राजनैतिक दलों की सहायता से गरीब लोग भी चुनावों में लड़ें हो सकते हैं। (५) दल लोग्मन को शिक्षित और संगठित करते हैं। (६) विरोधी दल सरकार को दक्ष बनाये रखते हैं और लोगों को सरकार के भ्रष्टाचार से बचाने हैं।

दलीय प्रणाली के लाभ - राजनैतिक दलों के जो कार्य हैं, वे दलीय प्रणाली के लाभ भी हैं। उपर्युक्त बातों के अलावा, प्रधानीय या राष्ट्रपतीय और सभानीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच तथा सभ सरकार और राज्य सरकार के बीच आवश्यकता सम्बन्ध दलीय प्रणाली के द्वारा ही होता है।

दलीय प्रणाली की हानियाँ—(१) दलीय प्रणाली राष्ट्रीयता के लिए अहितकर है। (२) यह देश के राजनैतिक जीवन को मजबूत जैसा बना देती है। (३) यह दल के सदस्यों की व्याप्टिमा को दबा देती है। (४) यह समाज के नैतिक स्तर को नीचा करती है।

दो-दलीय प्रणाली के लाभ—(१) इससे सरकार अधिक स्थायी और स्थिर रह पाती है। (२) यही एक प्रणाली है जिसमें सीधे जनता सरकार को चुनना है। (३) इसमें विरोधी दल सरकार के साथ अपने सम्बन्धों में अधिक व्यवस्थित और जिम्मेदार होता है।

दो-दलीय प्रणाली के दोष—(१) यह मजिस्ट्रेटकी तानाशाही को जग देती है। (२) बहुमत दल विधानमण्डल में अपनी होश ताउत के कारण नबिन से अपा होने लगता है। (३) दो-दलीय प्रणाली में मतदान की किसी एक पक्ष का सारा कार्य कम मानना या ठुकराना होना है। कोई बीच का रास्ता नहीं हो सकता।

बहुदलीय प्रणाली के गुण और दोष—दो-दलीय प्रणाली के जो गुण हैं वे बहुदलीय प्रणाली में दोष बन जाते हैं, और उनके दोष इसके गुण बन जाते हैं।

प्रश्न

- आप वस्तुक मताधिकार से क्या क्या समझते हैं ? इस प्रणाली पर कौन-कौन से मुख्य आक्षेप किये जाते हैं और आप उनका क्या जवाब देंगे ?
- What do you understand by the system of Universal Adult Franchise ? What are the chief objections to this system and how will you meet them ?
- परिपक्वता और प्रारम्भिक या उपक्रमण से क्या क्या समझते हैं ? उनके गुण और दोष क्या हैं ?

2. What do you understand by 'Referendum' and 'Initiative'? What are their merits and demerits?
३. लोकमत का क्या अर्थ है? लोकतन्त्रिय राज्य में इसका क्या महत्व है?
(प० वि० अप्रैल, १९५०)
3. What is meant by 'Public Opinion'? Estimate its importance in a democratic state.
(P.U. April 1950)
४. लोकमत के निर्माण और प्रकट करने के प्रमुख साधनों का संक्षेप में वर्णन करो।
(प० वि० अप्रैल, १९५२)
4. Describe briefly the various organs or agencies for the formation and expression of public opinion.
(P.U. April, 1952)
५. लोकमत बनाने में प्रेस का क्या स्थान है?
(प० वि० अप्रैल, १९५६)
5. What part does the press play in moulding public opinion?
(P.U. April, 1949)
६. लोकमत बनाने में प्रेस और रेडियो द्वारा किये गए काम का उल्लेख करो।
(प० वि० सितम्बर, १९५० और अप्रैल १९५८)
6. Describe the part played by press and broadcasting in moulding public opinion.
(P.U. Sept. 1950 and April 1948)
७. दलीय सरकार कितने कहते हैं? इनके गुण और दोष लिखो।
(प० वि० सितम्बर, १९५०)
7. What is Party Government? Mention its merits and demerits.
(P.U. Sept. 1950)
८. राजनैतिक दल से क्या क्या सम्बन्ध हैं? राजनैतिक दलों का राज्य के काम और नागरिकों की शिक्षा में क्या स्थान है? प० वि० अप्रैल, १९५०)
8. What do you understand by 'Political Party'? What part do political parties play in the work of the state and the education of the citizen?
(P.U. April, 1952)

Or

- किसी लोकतन्त्रिय राज्य में राजनैतिक दलों के कार्य का वर्णन करो।
Describe the role of political parties in a democratic state.
६. क्या दलीय प्रणाली लोकतन्त्र के लिए आवश्यक है? दलीय प्रणाली की प्रशंसा करो।
(प० वि० अप्रैल, १९५४)
 9. Is party system necessary for democracy? Give a criticism of the party system.
(P.U. April, 1954)
 १०. दो-दलीय और बहु-दलीय प्रणालियों के गुण और दोषों की तुलना करो।
 10. Examine the relative merits and demerits of two-party and multi-party system.

संस्कृति और सम्यता, अवकाश और मनोरंजन

संस्कृति और सम्यता

नागरिक शास्त्र अच्छी नागरिकता का विधान है और अच्छे नागरिक की सम्य और सुमस्तुत आदमी होना चाहिए। इसलिए नागरिक शास्त्र का अध्ययन करते हुए हमारे लिए संस्कृति और सम्यता के अर्थों की समझना जरूरी हो जाता है।

संस्कृति का अर्थ—संस्कृति की परिभाषा करना यदा रहित है। इसमें समय-समय पर अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग अर्थ समझा है। पर हम इस अध्याय में संस्कृति शब्द के दो अर्थों का उल्लेख करेंगे—

१. व्यापक अर्थ में संस्कृति का मतलब।

२. सीमित या ठीक अर्थ में संस्कृति का मतलब।

संस्कृति का व्यापक अर्थ—मोटे तौर से वह तो संस्कृति शब्द का प्रयोग आदमी के बनाये हुए मारे बानावरण और आदमियों के मारे भीखे हुए व्यवहार (Learnt behaviour) के लिए हो सता है।

मनुष्य अपने कार्य में अपने प्राकृतिक बानावरण को, अपने बनाए हुए बानावरण में बदल देता है। मोटे तौर से वह जय तो आज तक मनुष्य ने जो कुछ किया है, वह सब मनुष्य निर्मित बानावरण के अन्दर आ जाता है। इसमें मनुष्य की सब भौतिक और अमीतिक सकलनाएँ आ जाती हैं। इस तरह मोटे अर्थ में, संस्कृति शब्द में कला, अधिार और मशीनें आदि मारे भौतिक आविष्कार तथा दर्शन, कला, साहित्य और विज्ञान आदि, अमीतिक सकलनाएँ भी आ जा जायेंगी।

मनुष्य का सीखा हुआ व्यवहार भी मोटे अर्थ में संस्कृति है। मनुष्य का अधिकतर व्यवहार सीखा हुआ या संस्कार-जनि व्यवहार है। उदाहरण के लिए, चलना, बोलना, खाना और पीना—ये सब सीखे हुए व्यवहार हैं। योग के आसनो और डबकी लगाने में साय रोकने की अवस्था में साय लेना भी एक सीखा हुआ व्यवहार हो जाता है। खड़े होना और बैठना भी प्राकृतिक नहीं, बल्कि अनजाने में सीखे हुए व्यवहार हैं।

इस तरह मोटे अर्थ में संस्कृति शब्द में मनुष्यों के सब कार्य और सकलताएँ आजायेंगी।

सही अर्थ में संस्कृति का मतलब—अंशद्वर ने संस्कृति शब्द का प्रयोग

- 2 What do you understand by 'Referendum' and 'Initiative' ? What are their merits and demerits ?
३. लोकमत का क्या अर्थ है ? लोकतन्त्रात्मक राज्य में इसका क्या महत्व है ?
(प० वि० अप्रैल, १९५०)
- 3 What is meant by 'Public Opinion' ? Estimate its importance in a democratic state
(P U April, 1950)
- ४ लोकमत के निर्माण और प्रकट करने के अनेक साधनों का मर्मप में वर्णन करो ।
(प० वि० अप्रैल, १९५२)
- 4 Describe briefly the various organs or agencies for the formation and expression of public opinion.
(P.U April, 1953)
५. लोकमत बनाने में प्रेस का क्या स्थान है ? (प० वि० अप्रैल, १९६६)
- 5 What part does the press play in moulding public opinion ?
(P U April, 1949)
६. लोकमत बनाने में प्रेस और रेडियो द्वारा किये गए काम का उल्लेख करो ।
(प० वि० सितम्बर, १९५० और अप्रैल १९५८)
- 6 Describe the part played by press and broadcasting in moulding public opinion
(P U. Sept. 1950 and April 1949)
७. दलीय सरकार किसे कहते हैं ? उसके गुण और दोष लिखो ।
(प० वि० सितम्बर, १९५०)
7. What is Party Government ? Mention its merits and demerits.
(P U. Sept, 1950)
८. राजनैतिक दल से क्या समझते हैं ? राजनैतिक दलों का राज्य के काम और नागरिकों की शिक्षा में क्या स्थान है ? प० वि० अप्रैल, १९५२)
8. What do you understand by 'Political Party' ? What part do political parties play in the work of the state and the education of the citizen ?
(P U April, 1952)

Or

निम्नी लोकतन्त्रात्मक राज्य में राजनैतिक दलों के कार्य का वर्णन करो ।

Describe the role of political parties in a democratic state

९. क्या दलीय प्रणाली लोकतन्त्र के लिए आवश्यक है ? दलीय प्रणाली की प्रशंसा करो ।
(प० वि० अप्रैल, १९५४)
9. Is party system necessary for democracy ? Give a criticism of the party system.
(P U April, 1954)
१०. दो-दलीय और बहु-दलीय प्रणालियों के गुण और दोषों की तुलना करो ।
- 10 Examine the relative merits and demerits of two party and multi-party system

अध्याय : १६

संस्कृति और सम्यक्ता, अवकाश और मनोरंजन

संस्कृति और सम्यक्ता

नागरिक साम्प्र अच्छी नागरिकता का विज्ञान है और अच्छे नागरिक को सम्यक् और सुसंस्कृत आदमी होता चाहिए। इसलिए नागरिक धारण का अध्ययन करते हुए हमारे लिए संस्कृति और सम्यक्ता के अर्थों को समझना जरूरी हो जाना है।

संस्कृति का अर्थ—संस्कृति की परिभाषा करना यथा कठिन है। हमने समय समय पर अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग अर्थ समझा है। पर हम इस अध्याय में संस्कृति शब्द के दो अर्थों का उल्लेख करेंगे—

१. व्यापक अर्थ में संस्कृति का मतलब।

२. सीमित या ठीक अर्थ में संस्कृति का मतलब।

संस्कृति का व्यापक अर्थ—मोटे तौर से कह तो संस्कृति शब्द का प्रयोग आदमी के बनाये हुए गारे वातावरण और आदर्शों के माते सीखे हुए व्यवहार (Learnt behaviour) के लिए हो सकता है।

मनुष्य अपने कार्य में अपने प्राकृतिक वातावरण को, अपने बनाए हुए वातावरण में बदल देता है। मोटे तौर से कहा जाय तो आज तक मनुष्य ने जो कुछ किया है, वह सब मनुष्य निर्मित वातावरण के अन्दर आ जाता है। इसमें मनुष्य की सब भौतिक और अमीतिक सम्पत्तियाँ आ जाती हैं। हम तरह मोटे अर्थ में, संस्कृति शब्द में विचार, जीवन और मूल्यों आदि सारे भौतिक आविष्कार तथा दान, बला, साहित्य और विज्ञान आदि, अमीतिक सम्पत्तियाँ भी आ जा जाएँगी।

मनुष्य का सीखा हुआ व्यवहार भी मोटे अर्थ में संस्कृति है। मनुष्य का अधिभार व्यवहार सीखा हुआ या संस्कार जनित व्यवहार है। उदाहरण के लिए, पचना, पीना, खाना और पीना—ये सब सीखे हुए व्यवहार हैं। योग के आसन और हठयोग लगाने में सास रोकने की अवस्था में सास लेना भी एक सीखा हुआ व्यवहार हो जाता है। खड़े होना और बैठना भी प्राकृतिक नहीं, बल्कि अनुमानों से सीखे हुए व्यवहार हैं।

इस तरह मोटे अर्थ में संस्कृति शब्द में मनुष्य के सब कार्य और सफलताएँ आ जाएँगी।

सही अर्थ में संस्कृति का मतलब—महादेव ने संस्कृति शब्द का प्रयोग

भारत में प्रचार के उन साधनों के द्वारा भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित और प्रचारित करने के यत्न किये जा रहे हैं।

सभ्यता कितने कहते हैं—मैकाइवर के मतानुसार, मनुष्य के कुछ काम उसकी व्याप्त आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए होने हैं। इनका सम्बन्ध मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं से होता है। इनका अपना कोई भीगरी महत्त्व नहीं होता। उनका इसलिए महत्त्व है कि वे मनुष्य की बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन हैं। फिर ये कार्य सांस्कृतिक कार्यों से इस बात में भिन्न हैं कि वे अनिवार्य ढंग के हैं। वे मनुष्य के अस्तित्व के लिए और पान्ति तथा आराम के लिए आवश्यक हैं। एक अच्छी सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था, मोजार, मशीनें, खेती, उद्योग, पीढ़ाक और मकान ये सब आदमियों के लिए जरूरी हैं। ये सब चीजें सभ्यता शब्द के अन्तर आजायेंगी। इन प्रकार सभ्यता शब्द का प्रयोग उन सारी भौतिक सफलताओं के लिए किया जा सकता है जो किसी समाज ने सुखी और आराम का जीवन बिताने की कोशिश में प्राप्त की है।

सभ्यता और संस्कृति में अंतर

सभ्यता और संस्कृति दो विन्धुल अलग शब्द हैं, और इनके बारे में किसी तरह का धम न होना चाहिए। उनमें भेद बताने वाली बातें नीचे दी जाती हैं —

संस्कृति आत्मपरक (Subjective) है और सभ्यता वस्तुपरक (Objective) — संस्कृति आदमी के भीतरी जीवन से सम्बन्ध रखती है और इसलिए आत्मपरक या आत्मा सम्बन्धी होती है। दूसरी ओर सभ्यता बाहरी जीवन से सम्बन्ध रखती है और इसलिए वस्तुपरक या भौतिक होती है।

संस्कृति व्यक्तिगत और व्यक्तिगत होती है तथा सभ्यता सामूहिक और सामूहिक—वस्तुपरक और भौतिक होने के कारण सभ्यता में किसी परिवार के सब सदस्य या किसी देश के या सारी दुनिया के सब लोग हिस्सेदार हो सकते हैं। इसलिए यह सामूहिक होती है, और इसका स्वाभित्व सादा होता है। दूसरी ओर संस्कृति जो आत्मपरक या आत्मिक होती है, हमेशा व्यक्तिगत चीज होती है। यह एक ही परिवार में भी आदमी-आदमी में अलग-अलग होगी है। यह आवश्यक नहीं कि सुसंस्कृत आदमी का पुत्र भी सुसंस्कृत हो और न कोई सुसंस्कृत पिता अपनी अन्य बच्चों के साथ अपनी संस्कृति अपने पुत्रों को पहुँचा ही सकता है।

सभ्यता की तुलना की जा सकती है पर संस्कृति की नहीं—हम सभ्यता के बारे में अपना पैगला दे सकते हैं। एक सभ्यता को दूसरी से घटिया या बढ़िया कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए, माच की रेलगाड़ी को पुराने जमाने की बैलाश से अच्छा बताया जा सकता है। इसलिए वर्तमान सभ्यता की पहले की सभ्यता से ऊँचा धनाया जा सकता है। पर सांस्कृतिक वस्तुओं के बारे में फैसला देना कठिन है। उदाहरण के लिए, हम यह नहीं कह सकते कि भारतीय संगीत पश्चिमी संगीत से बढ़िया या घटिया है।

सम्पत्ता सदा सरवरी करती है, ससृति नहीं—सम्पत्ता के बारे में यह कहा जा सकता है कि यह गदा सरवरी करती है। उदाहरण के लिए कुछ मशीनें पटों की अपेक्षा आज सपार के साधन अधिक अच्छे और तेज हैं। दूसरी ओर, हो सकता है कि सम्पत्ति में कोई प्रगति न हो। भारत में अनेक राजा-दिवों में सम्पत्ति के लोगों में बाँट प्रगति नहीं हुई।

सम्पत्ता एक देश से दूसरे देश में ले जाई जा सकती है, पर ससृति नहीं—सम्पत्ता को आगामी से एक देश से दूसरे देश में ले जाया जा सकता है। यह इस बात से निश्चित होता है कि रीढ़ी, हार्ड जूता और मिनेमा गुलाब के गंध लगे की सामा सम्पत्ति है। ससृति को एक देश में उठाकर दूसरे देश में नहीं ले जाया जा सकता। इसका कारण यह है कि सम्पत्ता को अपेक्षा सम्पत्ति की मरत करना अधिक कठिन है। भारतीयों को परिचित सम्पत्ता बनाने में कुछ भी समय नहीं लगा। पर अपनी सम्पत्ति में वे बहुत दिनों तक अग्रणी मानते रहते हैं और भी भारतीय बने रहे। यह बात यह है कि सम्पत्ति की मरत नहीं की जा सकती, इसे आत्मगत करना पड़ता है। इस प्रकार ससृति बनाने वाले को अधिक योगिता करनी पड़ती है।

ससृति का क्षेत्र सीमित है—ससृति का क्षेत्र सम्पत्ता की अपेक्षा बहुत सीमित है। जिस तरह सब लोग विज्ञानी के पंते की हवा लेना पसंद करते हैं इसी तरह सब लोग रीढ़ीय खना चाहते हैं, पर हमने ये सब लोग सामा सम्पत्ति की पसंद नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि पंते की हवा का आनन्द लेने के लिए आपको इसकी मर-मरत जानने की जरूरत नहीं है, पर सामा सम्पत्ति समझने के लिए आपको स्वयं मंथन का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।

ससृति और सम्पत्ता में सम्बन्ध—दोनों भेद होते हुए भी ससृति और सम्पत्ता एक दूसरे से बहुत अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध रखती हैं। मन में आना-करन की पृथक् नहीं किया जा सकता। ससृति मन को निम्नित करती है, और सम्पत्ता इसके आना-करन को, इसलिए ससृति और सम्पत्ता को भी अलग-आलग नहीं किया जा सकता। वे एक-दूसरे पर अधिकृत हैं और एक दूसरे में सम्मिलित हैं। वे दोनों घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए, हम यह नहीं कह सकते कि परिवार स्वाभाविक दण्ड का परिणाम है या गिर-बनने सम्पत्ति के कारण बना हुआ है।

सम्पत्ता और ससृति एक-दूसरे पर प्रभाव भी डालती हैं। उदाहरण के लिए, आज का हमारा बहुत-सा ज्ञान अलेक्जान्देर के आधिपत्य का परिणाम है। वैज्ञानिक आविष्कारों के लोगों के कारण विचारों और दृष्टिकोण में ऊपर से नीचे तक परिवर्तन कर दिया है। इसी प्रकार विचारों और दृष्टिकोणों में सुधार से सम्पत्ता भी गति बढ़ जाती है।

अवकाश और मनोरंजन

अवकाश किसे कहते हैं—जबसे समाज बना है, तब से ही मनुष्य पसीना पहाकर अपनी रोजी पमाता रहा है। कुछ घोंडे से आदमियों को छोड़ दीजिए। अधिकतर लोगो को अपनी रोटी बगाने के लिए काम करना पड़ता है। पर कोई भी आदमी लगातार काम करता नहीं रह सकता, और लगातार काम करने पर शरीर और मन स्वस्थ नहीं रह सकता। आदमी की बात छोड़िए, पर मशीन भी बहुत दिनों तक, बिना विधाम के, काम नहीं कर सकती। इसे भी सफाई और तेल की जरूरत होती है। मशीन की तरह मनुष्य के शरीर को भी ताजगी हासिल करने के लिए आराम की जरूरत होती है। काम के समय के बीच जो वह आराम का समय होता है, उसे अवकाश या फुरगत कहते हैं।

अवकाश और निरुत्पादन एक नहीं—अवकाश या फुरगत और निरुत्पादन दो एक नहीं समझ लेना चाहिए। इन दोनों में दो तरह से भेद है। प्रथम तो, अवकाश के लिए काम जरूरी है। निरुत्पादन का मतलब है काम का अभाव। अवकाश का मतलब है काम के बाद आराम। निरुत्पादन में आराम ही आराम होता है, काम नहीं होता। दूसरे, अवकाश स मुफ्त मिलता है, यह शरीर और मन के स्वास्थ्य के लिए सहायक होता है। दूसरी ओर, निरुत्पादन अनुभवकर और धराने वाला होता है। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अवकाश आदमी की शक्ति और क्षमता बढ़ाता है। निरुत्पादन न केवल शक्ति और क्षमता को कम करता है, बल्कि यदि बहुत दिनों तक जारी रहे तो यह मनुष्य को किसी भी काम के योग्य नहीं रहने देता। इस प्रकार, अवकाश और निरुत्पादन दो भिन्न पदार्थ हैं।

अवकाश मुस्ती पंदा करने वाले या बकानेवाले काम से दूर भागने की भी सहायता है। अवकाश, जैसा कि पहले कहा गया है, काम के बाद आराम से कहते हैं। चाहे वह काम कितना ही या शुष्क। असल में सब तरह के काम कुछ न कुछ थकानेवाले होते हैं और कुछ न कुछ समय बाद थकने लगने लगते हैं, इसलिए, हर काम के बाद अवकाश की जरूरत होती है।

अवकाश पहले और अब—प्रायः कहा जाता है कि पुराने जमाने के सरल और गान्धर्व जीवन के मुकाबिले में आधुनिक जीवन की दो-भाग अवकाश नहीं मिलने देती। पर इस विषय का आधार पिछड़े जमाने का मूल्य अध्ययन है। पहले अवकाश बड़े विषम रूप में बँटा हुआ था। कुछ घोंडे से लोगो को अवकाश मिलता था और बाकी लोग उनका काम करते थे। प्राचीन ग्रीस और रोम में अवकाश पाने का अधिकार सिर्फ नागरिकों को था, जो सारी आबादी का बहुत थोड़ा हिस्सा होते थे। दासों और स्त्रियों को, जो आबादी का काफी बड़ा हिस्सा होते थे, अवकाश नहीं मिलता था। पुराने जमाने में अवकाश का मूल्य भी इतना नहीं

या, जितना अब । पुराने जमाने की तुलना में आजकल व्यवसाय के अनेक तरह के उपयोग के बारे में भी ज्ञान बढ़ गया है ।

आधुनिक काल में व्यवसाय का विस्तार

आधुनिक काल में व्यवसाय का आसता और विस्तार, दोनों बढ़ गए हैं । इस वृद्धि के कई कारण हैं और वे नीचे दिये जाते हैं—

१. विज्ञान—वैज्ञानिक ज्ञान की वृद्धि ने अनेक समय बचाने के उपाय निष्पन्न किये हैं । मनुष्य मशीन की सहायता से आजकल बहुत कम समय में काम पूरा कर लेता है, इसलिए वह व्यवसाय का आनन्द बहुत अधिक ले सकता है । मशीन में काम करने पर उसकी परिस्थिति भी नहीं होती । इस प्रकार, इस व्यवसाय दुनिया में अगर आदमी को विज्ञान के लिए थोड़ा थोड़ा समय भी मिल जाय तो वह फिर राजा हो सकता है । अतीत काल में शारीरिक मेहनत अधिक होती थी, जिसके कारण आराम का समय भी अधिक चाहिए था ।

२. शिक्षा—व्यापक शिक्षा आदमी की बुद्धि को पैदा कर देती है और टेक्नीकल शिक्षा में उसे अपने काम का अच्छी तरह ज्ञान हो जाता है । शिक्षित और कुशल मजदूर अनिश्चित या अतृप्त मजदूर की अपेक्षा बहुत जल्दी अपना काम खत्म कर लेगा ।

३. आदमी का महत्व बढ़ गया है—पहले आदमी का कोई महत्व नहीं था । दासता का होना ही इसका प्रमाण है । शोषण के जाने से ही आदमी का महत्व बढ़ा है । शोषण में हर आदमी एक जैसा अच्छा माना जाता है । गरीब नागरिक की भलाई का भी उतना ही महत्व है, जितना धनी नागरिक की भलाई का ।

४. मजदूरी या हितकारी राज्य—आजकल राज्य मजदूरी राज्य होता है । राज्य किसी को कमजोर और गरीब नागरिकों की मेहनत का नाजायज लाभ नहीं उठाने देता । फैक्टरी कानून पास करके राज्य मालिक को मजदूरों को छुट्टियाँ देने को मजबूर करता है । काम के घंटे निर्दिष्ट हो जाते हैं, और काम के घंटों के बीच में आराम का समय रखा जाता है ।

इस प्रकार उन्मुक्त मानों के कारण, समाज के गरीब और कमजोर नागरिकों को भी व्यवसाय मिलना सम्भव हो गया है ।

के योग्य कमाई करने में बहुत कठिनाई भी न होनी चाहिए।

आदमी के लिए अवकाश का महत्व—हम देख चुके हैं कि अवकाश आदमी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खेल, बाहर की घंटी, पढ़ाई और बातचीत उसने सामूहिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। अनेक तरह के शौक और सांस्कृतिक काम, जैसे वागवानी, संगीत, कविता और पेंटिंग आदमी का भोजन है। बिना अवकाश के इनमें से कोई काम नहीं किया जा सकता। अवकाश में ही आदमी ध्यान और आत्म निरीक्षण कर सकता है। इस प्रकार, अवकाश आदमी के शारीरिक, मानसिक और भौतिक अवकाश के लिए बहुत आवश्यक है।

लोकतन्त्र के लिए अवकाश का महत्व—लोकतन्त्र और अवकाश का घनिष्ठ सम्बन्ध है। ये दोनों एक दूसरे की सहायता पर निर्भर हैं। हम देख चुके हैं कि लोकतन्त्र ने अवकाश का दायरा बड़ा दिया है। अवकाश भी लोकतन्त्र के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। लोकतन्त्र में दक्षता अभी आती है जब उसके नागरिक उसने कार्य संचालन में दिलचस्पी लें। उदाहरण के लिए, हर नागरिक को अपना मत देने से पहले, अनेक समस्याओं और प्रश्नों पर रायधानी से विचार करना चाहिए। उसे सरकार के रोजाना के कामों की जानकारी रखनी चाहिए। इसलिए लोकतन्त्र के हर नागरिक के लिए अवकाश बहुत आवश्यक है जिससे उसे अनेक सार्वजनिक समस्याओं को सोचने के लिए काफी समय मिल सके।

संस्कृति और सम्यता के लिए अवकाश का महत्व—सब देशों में सम्यता और संस्कृति का काम अवकाश वाले वर्गों ने ही किया है। समृद्धि, मित्रता, ऊँचे दर्जे का विचार, जो सम्यता और संस्कृति के लिए इतनी जरूरी चीजें हैं, अवकाश वाले वर्गों में ही मिल सकती हैं। आविष्कार, बड़ी बड़ी कलाकृतियाँ, दर्शन, साहित्य और कविता मजदूरों से नहीं पैदा हुईं। कारण यह है कि मजदूर अधिस्तरीय समय अपनी रोजी कमाने में लगाता है। काम के बाद उसे जो अवकाश मिलता है, वह ऐसा ही होता है कि उसने शरीर और मन को आराम मिल जाए। मजदूर को अपने व्यक्तित्व की जरूरतों की ओर ध्यान देने का समय नहीं मिलता इसलिए आदमी को ऊँचे विम्व का विचार करने के लिए, सांस्कृतिक कार्यों के लिए, काफी समय अधिक मिलना चाहिए।

मनोरंजन कितने कहते हैं?—मनोरंजन का अर्थ है, काम से आने वाली थकान और दुःखना को हटाने के लिए आनन्दपूर्ण कार्य। मनोरंजन से न केवल शरीर और मन की ताजगी हासिल होती है, बल्कि आदमी के व्यक्तित्व का विकास भी होता है। अवकाश मनोरंजन के लिए बहुत आवश्यक है। अवकाश का ठीक उपयोग करने से ही मनोरंजन होता है। यदि अवकाश का ठीक उपयोग न किया जाए तो उसका उलटा परिणाम होगा।

अवकाश का ठीक उपयोग या मनोरंजन के रूप

अवकाश के ठीक उपयोग के बारे में अलग-अलग लोगों के अलग-अलग विचार हैं। पर निम्नलिखित बातों को अवकाश का ठीक उपयोग माना जा सकता है —

१. खेल—गेड-गूड जैसे फुटबाल, हॉकी, क्रिकेट, और टेनिस तथा शिकार खेलना, बूटना, दोड़, तैरना, घुड़सवारी और पैदल यात्रा या हाइकिंग दिमागी काम करने वाले लोगों को विशेष रूप में उपयोगी हैं। बहुत देर तक पढ़ने या दफ्तर का काम करने के बाद लोगों में शरीर का व्यायाम हो जाता है। स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में ही रह सकता है। तनाव, टेन्शन, डेप्रेशन, क्रिपिके और बीजम आदि लोगों में शारीरिक पचान नहीं होती। इनमें शारीरिक और दिमागी दोनों तरह के काम करने वाली का मनोरंजन होता है।

गेड-गूड किसी राष्ट्र का स्वाम्य बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत में नागरिक गुण, जैसे गृहयोग, अनुशासन, आत्मनिर्भरता, टीम की भावना, तिला-टीरन की भावना और नेतृत्व खेल के मैदान में ही सीखे जाते हैं। खिलाड़ी को चाहे वह किसी ही अछड़ा खेलना हो, स्वयंपूर्ण गेड न गेडना चाहिए। किसी मैच का जीतने के लिए महयोग और टीम की भावना बहुत आवश्यक है। खिलाड़ियों को अपने कैप्टन के अनुशासन में रहना चाहिए। उन्हें रैफरी के फैसले मानने चाहिए। कैप्टन अछड़ा नेता होना चाहिए। उसका अछड़ा खिलाड़ी होना आवश्यक है। वह अछड़ा पतनसंदाता होना चाहिए, और हार के समय टीम के हौसले को बनाए रखने में समर्थ होना चाहिए। खिलाड़ीका हार और जीत दोनों में समुलन बनाए रखने के गुण को कहते हैं।

२. शौकिया काम (hobby)—जो लोग शान्त स्वभाव के होते हैं, या शारीरिक मेहनत पसन्द नहीं करते, उनके लिए अवकाश का उपयोग करने का सबसे अच्छा साधन कुछ शौकिया काम हैं। वाद्ययंत्र, टिक्ट और निक्के जमा करना, पेंट्रिपी हल करना, फांटीबाजी, पेंटिंग और मगीन कुछ बड़े मनोरंजक शौक हैं। शौकिया कामों में कई लाभ होते हैं। उनमें मन प्रसन्न होता है। ज्ञान और अनुभव बढ़ते हैं, इसके अलावा उनका सामुहिक महत्व भी है। कभी-कभी शौकिया कामों से आर्थिक लाभ भी हो जाता है।

कुछ लोग अपना खाली समय रिताबे, पत्रिकाएँ और अखबार पढ़ने में लगाते हैं। उपन्यास, यात्रा-वर्णन और जीवन-चरित्र पढ़ने में हस्के होते हैं। जीवन-चरित्र और यात्रा-वर्णनों में प्रेरणा और शिक्षा भी मिलती है। पत्रिकाएँ और अखबार मार्गबन्धक घटनाओं का ज्ञान कराते हैं, और अपना मत बनाने, आदमी

रंजन है। मनोरंजन का एक और साधन रेडियो है। रेडियो और सिनेमा मनोरंजन के साथ-साथ शिक्षा भी देते हैं।

४. सामाजिक सेवा—कुछ लोग, यद्यपि उनकी धनकी थोड़ी है, न तो खेती में दिव्यरसी रखते हैं, और न किसी शौकिया काम में। ऐसे लोगों की खाली समय का उपयोग सामाजिक सेवा में करना चाहिए। जनल में तो हर नागरिक को अपने खाली समय का कुछ हिस्सा सामाजिक सेवा में लगाना चाहिए।

अवकाश का सही उपयोग—अवकाश का सही उपयोग भी किया जा सकता है। शराब पीने और जुआ खेलने में अवकाश का उपयोग करना लाभदायक तो है ही नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। अच्छा नागरिक वह है जो अपने खाली समय का ज़रूर से ज़रूरता चाहे वे भौतिक हों या अमौलिक हों, का उपयोग करता है।

सारांश

संस्कृति और सभ्यता—संस्कृति का अर्थ—मोटे तौर से कहा जाए तो संस्कृति शब्द का प्रयोग सारे मनुष्य-जनित वातावरण के लिए और मनुष्य के सारे शीले हुए व्यवहारों के लिए किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत, मनुष्यों के सब कार्य, चाहे वे भौतिक हों या अमौलिक हों, आजायें हैं।

सीमित अर्थ में संस्कृति शब्द मनुष्य के सिवा उन कामों पर लागू होगा जो उसने सततता की दृष्टि के लिए किए जाते हैं। पेंटिंग, मीन और मूर्ति निर्माण आदि सब कलाएँ, उद्योग, नाटक और शिल्प आदि सारा साहित्य, दर्शन और धर्म ऐसे ही कार्य हैं। इस प्रकार, संस्कृति का अर्थ है हमारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का उच्चिष्ठ भाग। सुसंस्कृत आदमी वह है जिसका व्यवहार सदा सदा बुद्धि और भावना पर निर्भर है और जो जीवन के सत्य शिव, सुन्दर को तीव्रता से अनुभव करता है।

संस्कृति आदमी और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह आदमी को प्रत्यक्ष, भद्र, शान्ति प्रेमी और सक्रिय बनाने वाला है। संस्कृति नागरिकता के लिए बहुत जरूरी है। नागरिक के रूप में सुसंस्कृत व्यक्ति अपने अधिकारों की अपेक्षा अपने कर्तव्यों पर अधिक ध्यान देता है।

सांस्कृतिक फैलाने के साधन, परिवार, मित्र, स्कूल, बालक विद्यालय और अनेक मासुक्तिक माहचय हैं।

सभ्यता किसे कहते हैं—सभ्यता शब्द मनुष्य के कामों के उन परिणामों को सूचित करता है जो बाह्य आत्मा की जगहों की पूर्ति करते हैं। आविष्कार, औजार, मशीनें, खेती, उद्योग, नौका और मकान सभ्यता के अलग-अलग भाग हैं।

संस्कृति और सभ्यता में अंतर—(१) संस्कृति आत्मपरक होती है, और

सम्पत्ता वस्तुपरक, (२) सृष्टि व्यक्तिगत और व्यक्तिगत होती है, सम्पत्ता सामूहिक और साझी होती है। (३) सम्पत्ता को तुलना आसानी से हो सकती है, सृष्टि की नहीं, (४) सम्पत्ता सदा सत्यही रहती है, सृष्टि नहीं, (५) सम्पत्ता एक देश से दूसरे में पहुँचाई जा सकती है, पर सृष्टि नहीं; (६) सृष्टि सम्पत्ता की अपेक्षा कम लोगों को प्रभावित करती है।

सृष्टि और सम्पत्ता का सम्बन्ध—वस्तु में भेदों के बावजूद इन दोनों का परिप्लव सम्बन्ध है। मन को वानावरण से ग्रस्त नहीं किया जा सकता। सृष्टि मन को बनाती है और सम्पत्ता हमारे वातावरण को। परस्पर सम्बन्धित होने के अलावा वे एक दूसरे पर अमर भी डालती हैं।

अवकाश और मनोरञ्जन अवकाश किसे कहते हैं?—काम के घटो के बीच में जो आराम का समय होता है, उसे अवकाश कहते हैं। इस प्रकार अवकाश निवर्त्तमान से मिले वस्तु है। निवर्त्तमान का मतलब है, काम न होना। पर अवकाश का मतलब है काम के बाद विराम। दूसरी बात यह कि अवकाश मुक्त देना है और स्वास्थ के लिए आवश्यक है। निवर्त्तमान अनुभव और स्वास्थ के लिए हानिकारक है।

पहले अवकाश कुछ ही लोगों को मिल पाता था और इसका अधिक मूल्य नहीं था। आजकल विज्ञान और शिक्षा के प्रभाव ने अवकाश का परिमाण और घाटा बढ़ा हो गया। आधुनिक राज्य मजदूरों के राज्य है, और यह सब आदमियों को समान महत्व देता है। इस विचार ने मजदूर और गरीब लोगों के लिए भी अवकाश पाना मजबूर कर दिया है। समय बचाने वाले माधनों, राज्य के सुरक्षण और शिक्षा के अलावा, आर्थिक अभाव ने छुटकारा, अवकाश के अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक चीज है।

अवकाश का महत्व—अवकाश का सबसे अधिक महत्व व्यक्ति के लिए है। यह हमारे शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरे अवकाश लोकतन्त्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतन्त्र की दृष्टि से अवकाश पर निर्भर है जो हमारे नागरिकों को समाज और राज्य की अनेक समस्याओं पर विचार करने के लिए मिलता है। तीसरे, अवकाश सृष्टि और सम्पत्ता की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह हमें तब तक से निश्चित होता है कि आविष्कार, कला की महान् रचनाएँ, दर्शन, साहित्य और कविता का नूतन अधिकतर अवकाश वाले लोगों ने ही किया है।

मनोरञ्जन किसे कहते हैं?—मनोरञ्जन का अर्थ है काम की घबराहट और नीरसता को दूर करने के लिए कोई आनन्दपूर्ण कार्य। अवकाश का उचित उपयोग करने से ही मनोरञ्जन होता है।

अवकाश का उचित उपयोग या मनोरञ्जन के प्रत्यक्ष—(१) खेल-कूद। (२), यागदान, टिक्ट और सिक्के जमा करना, पहेलियाँ हल करना, फोटोग्राफी, पेंटिंग,

संघीत और पढ़ना आदि शौकिया काम । (३) मिनेमा, थियेटर और रेडियो आदि मनोरंजन । (४) समाज-सेवा ।

अवकाश का सही उपयोग—छात्रों को और जूआ खेलना अवकाश के सही उपयोग के उदाहरण हैं

प्रश्न

QUESTIONS

१. संस्कृति और सभ्यता शब्दों को सावधानी से व्याख्या कीजिए ।
(प. वि अग्रेल, १९४०)
1. Explain carefully the terms 'culture' and 'civilization'
(P U April, 1930)
२. संस्कृति और सभ्यता शब्दों को परिभाषा कीजिए और इन दोनों में भेद बताइए ।
(प. वि. अग्रेल १९४३)
2. Carefully define and distinguish between 'culture' and 'civilization'
(P U April, 1933)
३. आदमी के जीवन में अवकाश का क्या महत्व है ? अवकाश का सही से प्रयोग कैसे किया जाए ? (प. वि अग्रेल १९४९ और सितम्बर १९५०)
3. Estimate importance of leisure in the life of an individual
How should leisure be best utilized ?
(P U April 1939 and Sep 1950)
४. अवकाश के मूल्य और सही उपयोग पर एक निबन्ध लिखो ।
(प. वि० अग्रेल, १९२०)
4. Write an essay on the value and right use of Leisure
(P U April, 1931)
५. निम्नी नागरिक के जीवन में मनोरंजन सम्बन्धी कार्यों का महत्व बताओ ।
(प. वि. अग्रेल, १९४०)
5. Estimate the importance of recreational activities in the life of a citizen
(P U April, 1930)
६. नागरिक के जीवन में खेल-कूद का क्या महत्व है ?
(प. वि. १९४८)
6. Discuss the importance of games and sports in the life of a citizen
(P U 1945)

राष्ट्रवाद और अन्तर्राष्ट्रवाद—संयुक्त राष्ट्र संघ

राष्ट्रवाद

कोई नागरिक चिन्तन करने राष्ट्र और राष्ट्र का ही सङ्ग नहीं है, बल्कि वह मारी मानव-विरादों का भी सङ्ग है। उदा. हमने निष्ठाओं को ठीक काम में रखने पर विचार किया था, वहाँ हम बता चुके हैं कि नागरिक को अपनी निष्ठाएँ ऐसे काम में रखनी चाहियें कि उसकी अपने राष्ट्र और राष्ट्र के प्रतिनिष्ठा संसार-व्यापी मानव विरादों के प्रति उसकी निष्ठा की विरोधी न हो। साथ ही, हमने यह भी बताया था कि मनुष्य में अपने प्रति प्रेम इतना प्रबल है कि अधिकतर लोगों के लिए अपनी निष्ठाओं को ठीक काम में रखना असम्भव है। आदर्श राष्ट्रवाद की भावना के कारण लोग मानव जाति के प्रति अपनी निष्ठा को, जो अधिक बड़ी और अधिक महत्वपूर्ण है, पहचानने को तैयार नहीं। आज की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में बल-शाली तत्त्व इसी कारण है। इसलिए नागरिक राष्ट्र के विद्यार्थी के लिए राष्ट्रवाद तथा अन्तर्राष्ट्रवाद की समझाओं का अध्ययन बड़ा महत्वपूर्ण है। इन अध्याय में राष्ट्रवाद के शीर्षक के अन्तर्गत हम निम्नलिखित बातों का अध्ययन करेंगे—

- (१) राष्ट्रवाद, राष्ट्र और राष्ट्रवाद दोनों का अर्थ।
- (२) राष्ट्रवाद की जन्म देने वाले कारण और उनका जातिगत महत्व।
- (३) राष्ट्रवाद के गुण और दोष।

इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रवाद के शीर्षक के अन्तर्गत हम इन बातों पर विचार करेंगे—

- (१) अन्तर्राष्ट्रवाद किन शक्तियों का परिणाम है।
- (२) अन्तर्राष्ट्रवाद के लाभ।
- (३) अन्तर्राष्ट्रवाद के मार्ग की बाधाएँ।
- (४) हम संघ में संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य महासभा का भी वर्णन करेंगे।

राष्ट्रियता (Nationality)—राष्ट्रियता एक उन लोगों के लिए प्रयुक्त शब्द है, जो एकता की भावना से सज्जित होते हैं। यह एकता की भावना आत्मपरक एकता या मानविक एकता है, जिसका कारण, भूतत्व और भाषा, एक धर्म, एक निवास-स्थान, एक इतिहास और परम्परा आदि कुछ वस्तुपरक कारक हैं। पर

राष्ट्रिकता के अस्तित्व के लिए वस्तुपरक या बाहरी एकाता या सादृश्य जरूरी नहीं है। जो चीज जरूरी है वह यह है कि लोगों की भावनाएँ और विचार एक होने चाहिए। उनका बाह्य रूप एक दूसरे से भिन्न हो सकता है। उनकी भाषा अलग हो सकती है, उनकी पूजा के देवता अलग अलग हो सकते हैं, और उनके वेग आदि अलग-अलग हो सकते हैं।

राष्ट्र—जब कोई राष्ट्रिकता अपने-आपको राजनैतिक निकाय के रूप में संगठित कर लेती है, या जब वह बाहरी एकाता भी हासिल कर लेती है, तब वह राष्ट्र कहलाने के योग्य हो जाती है। इसके अनुसार, जो राष्ट्रिकता स्वतन्त्र या स्वतन्त्र होने की इच्छा वाले राजनैतिक निराश्रय के रूप में संगठित हो गई है, वह राष्ट्र कहलाती है। दूसरे शब्दों में कह तो राष्ट्रीयता और राज्य मिश्रित राष्ट्र कहलाने हैं।

राष्ट्रवाद—राष्ट्रवाद का अर्थ है राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रीय हित, एकाता और स्वतन्त्रता का समर्थन, या राष्ट्रवाद उस भावना की वह स्रजन है जो किसी राष्ट्रिकता को संगठित होने और अपने लिए स्वाधीनता प्राप्त करने की प्रेरित करती है। संक्षेप में, राष्ट्रवाद का अर्थ है, अपने राष्ट्र से प्रेम और उसके हितों की उत्साह-पूर्वक आगे बढ़ाना।

राष्ट्रवाद के कारण—राष्ट्रवाद की भावना में अनेक तत्त्व हैं। यह एक मूलवश और भाषा, एक मातृदेश, एक धर्म, सामी सांस्कृतिक यात्री, सामी परम्पराशा और सामी राजनैतिक आकांक्षाओं जैसे कई कारकों का फल है। यह पाद रखना चाहिए कि इस भाव को पैदा करने के लिए इनमें से कोई भी कारक परम आवश्यक नहीं, तो भी किसी प्राति में इनमें से जितनी अधिक बातें होती, राष्ट्रवाद की भावना उतनी ही प्रबल होती। अब हम इन कारकों का महत्व और हिस्सा संक्षेप में नीचे बताएँगे।

सामी भाषा—भाषा के द्वारा विचारों की अदला-बदली होती है। सामी भाषा होने से लोग अपनी भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं और इस प्रकार उनमें एकाता पैदा होती है। भारत में अंग्रेजों के अंग्रेजी बोलाने से इस देश में राष्ट्रवाद की वृद्धि में बड़ी सहायता मिली।

सामी भूतल—पुरानी कहावत है कि 'अपना अपना, पराया-पराया'। एक ही भूतल के लोगों में अत्यन्त निकटता अनुभव होगी। उनमें जीवन का प्रति एक से विचार और दृष्टिकोण हाने। पर भूतलीय घुड़ता सत्तर में बड़ी दुर्लभ चीज है। पर भूतलीय के मामूली मिथल से राष्ट्रीय-भावना पैदा होने में कोई रुकावट नहीं आती।

सामी धर्म—इतिहास में धर्म एक महत्वपूर्ण तत्व जोड़ने वाला बल रहा है। आज भी पट्टरी, जापानी और आयरिश राष्ट्रिकताओं में धर्म एकाता का प्रबल बंधन है। पर आजकल साधारणतया धर्म कोई परमावश्यक कारक नहीं रहता। आजकल के राष्ट्रीय राज्य अधिकतर सौनिक राज्य हैं, जहाँ एक से अधिक धर्म साथ साथ रहते हैं।

साम्प्रदायिक-देश—एक ही क्षेत्र पर निवास निम्नदेह बड़ा शक्तिशाली बंधन है और यह न होने पर राष्ट्रीय भावना दबी रहती है। तब भी, यहूदियों का ऐसा उदाहरण है जिसमें कुछ समय पहले तक एक राष्ट्रियता थी, पर मानुदेश नहीं था।

साम्प्रदायिक और मानु—कला, दर्शन, साहित्य, भोजन, वेश, आचार, और प्रथाओं की सामान्य मान्यताएँ बाहरी किसी जाति में एकता का प्रबल बंधन हैं। मूलभूत, भाषा और धर्म की उही भिन्नताओं के बावजूद भारतीय लोगों की एक सामान्य मान्यता है, जिसने उनमें और अन्य जातियों में सदा अंतर किया है। परम्परा लोगों को उन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान दिनाती रहती है, जिनमें वे होकर राष्ट्र में सम्बन्ध की है। गृहीतों और बीरों की स्मृतियाँ भी परम्परा द्वारा जीवित रहती हैं।

साम्प्रदायिक—साम्प्रदायिक हित या साधों प्रतिरक्षा समस्या भिन्न प्रकार के लोगों की भी एक राष्ट्रियता में संगठित कर देती है। इन कारकों ने यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा की विभिन्न जातियों को राष्ट्रियताओं का रूप दे दिया है।

साम्प्रदायिक—एक ही दुश्मन के कारण कष्टमूलक की स्मृतियाँ लोगों में एकता की भावना पैदा करने में सबसे अधिक काम करती हैं। भारतीय लोगों की अंग्रेजों के कारण जो कष्ट सहने पड़े उन्होंने भारत में राष्ट्रवाद की गति को बढ़ाया।

राष्ट्रवाद के गुण—राष्ट्रवाद के निम्नलिखित गुण बताए जाते हैं—

(१) राष्ट्रप्रेम या राष्ट्रीय हित, एकता और स्वतंत्रता का समर्पण के अर्थ में राष्ट्रवाद विस्तृत टीका है। यह गुलाम राष्ट्रों की आजादी पाने की प्रेरणा देता है।

(२) राष्ट्रवाद किसी देश की प्रगति की ओर ले जाता है। इस भावना में हर आदमी अपने देश की प्यार करता है और राष्ट्रीय प्रगति में अधिक से अधिक योग देने की कोशिश करता है।

(३) राष्ट्रवाद प्रत्येक राष्ट्र को अपनी सृष्टि का विकास करने के योग्य बनाता है। राष्ट्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहती है। प्रत्येक राष्ट्र दूसरे में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वे एक दूसरे के अनुभवों में भी सीखते हैं। इसने सारी मानव-जाति को उन्नति दी है।

(४) स्वतंत्र समस्याएँ भी राष्ट्रीय राज्यो में अधिक सम्बन्ध करती हैं।

(५) किसी राष्ट्रीय राज्य में ही राज्य की सर्वोच्चता का अर्थ की स्वाधीनता में सर्वोत्तम सम्बन्ध होता है।

राष्ट्रवाद के दोष—राष्ट्रवाद तब तक अच्छा है, जब तक वह आक्रमण न हो जाए। यह तब तक अच्छा है, जब तक इसका ध्येय-वाक्य 'जिसे और जीने दो' है। पर आजकल राष्ट्रवाद जिस रूप में चलता है, उस रूप में इसमें बहुत-सी बदलाव हैं।

(१) नानी जर्मनी के प्रत्येक ना राष्ट्रवाद लोगो में यह विद्वान्त पैदा कर देता है कि वे ईश्वर के चुने हुए लोग हैं। उनमें अहंकार हो जाता है और उनका अहंकार दूसरे राष्ट्रों के प्रति बावनामक रूप ग्रहण कर लेता है। वे सोचने हैं कि वेवल उन्हें ही स्वयं होने का अधिकार है। इस प्रकार राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद की ओर ले जाता है।

(२) सब राष्ट्रों के साथ बराबर नहीं। कुछ राष्ट्र अधिक दृष्टि में धीरे की अपेक्षा अच्छी स्थिति में हैं। हमारे राष्ट्रों में आपसी ईर्ष्या पैदा हो जाती है।

(३) ईर्ष्या की भावना संघर्ष को जन्म देती है। राष्ट्रों में संघर्ष होने पर महात्तन दृष्टि दिये जाते हैं और उनका उपयोग भोजिया जाता है। युद्ध अभिवार्य हो जाता है। आजकल युद्ध भूमंडल-व्यापी होते हैं, और वे इतने विनाशकारी हो गये हैं कि पारी मानव-जाति का अस्तित्व संभ हो जाने का वास्तविक खतरा है।

(४) निरंतर तनाव और मय की अवस्था प्रत्येक राष्ट्र को युद्ध के लिए तैयार रखती है। राष्ट्रीय भाव का बहुत बड़ा हिस्सा विनाश के तत्वों पर खन किया जाता है। परिणाम यह होता है कि राष्ट्र-निर्माण के कार्य बन की दमी से नहीं हो पाते, और राष्ट्रीय प्रगति रुक जाती है।

(५) आर्थिक राष्ट्रवाद के कारण अतीत काल में राष्ट्रों ने अपनी फाफू बस्तुएँ दूसरे राष्ट्रों के उपयोग में आने वनों के बजाए उन्हें जला देना ठीक समझा।

(६) राष्ट्रवाद के कारण अनेक छोटे-छोटे और कमजोर राज्य बन गये हैं। न तो वे अपनी आर्थिक आवश्यकताएँ ठीक तरह पूरी कर सकते हैं, और न वे प्रबल राज्यों के आक्रमण से अपनी रक्षा ही कर सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रवाद

अंतर्राष्ट्रवाद उस प्रणाली या व्यवस्था की बनाना है जिससे अनेक अपना शासन आय करने वाले और आत्म-सम्मान की सब राष्ट्र सभ्यता, सम्भावना और तर्क के बंधनों द्वारा संयुक्त होकर शान्ति में रह सकते हैं। इसका लक्ष्य यह है कि राष्ट्रों के मध्य होने वाले विवादों का फैसला पशु-वैतक के बजाए-तर्क के से हो। राष्ट्रवाद में युद्ध का जन्म होता है। पर अंतर्राष्ट्रवाद युद्ध को संस्था क्षम कर देना चाहता है। अंतर्राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद का भी दुश्मन है।

पर राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद को एक दूसरे का विरोधी नहीं समझना चाहिए, बल्कि राष्ट्रवाद अस्तित्व और मानवता के बीच एक आवश्यक बड़ी है। अंतर्राष्ट्रवाद में राष्ट्रीय राज्यों की आंतरिक सर्वोच्चता फिर भी बनी रहेगी। ये अन्य राज्यों के साथ व्यवहार करने में ही अंतर्राष्ट्रीय संस्था के फैसलों के अनुसार चलेंगे। यदि कभी विश्व राज्य बना तो उसका ढांचा सघनीय ही होगा।

अंतर्राष्ट्रवाद को जन्म देने वाली शक्तियाँ—विभिन्न राष्ट्रीय राज्यों में युद्ध की सम्भावना को कम करने के लिए सहयोग की आवश्यकता बहुत दिनों से अनुभव

की जानी रही है, पर १९वीं शताब्दी तक इस दिशा में किये गये सब कर्म बिल्कुल बेकारने से भरे हुए रहे :

१. युद्ध नीमित क्षेत्र में होने से ।
२. आर्थिक दृष्टि से राज्य एक दूसरे पर कम निर्भर थे ।
३. अन्तर्राष्ट्रीय राज्य असंभव माना जाता था ।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए कोई संस्था बनाने का पहला सम्झौता प्रत्यक्ष १९१४ के बाद दिया गया । राष्ट्र सघ (League of Nations) की स्थापना की गई । दूसरे विश्वयुद्ध के बाद भी सम्बन्ध राष्ट्र सघ की स्थापना की गई । अन्तर्राष्ट्रवाद अब कोई स्वप्न-भाष नहीं रहा । यह प्रतिदिन एक वास्तविकता बनता जा रहा है । पिछले ५० वर्ष में परिस्थितियाँ बहुत बदल गई । परिवहन और संचार के इन साधनों ने सभ्यता को एक दराई बना दिया है । हवाई जहाज, ब्रेडर, तार और समुद्री तार के वैज्ञानिक आविष्कारों ने स्थान, दूरी और समय संबंधी विचारों को परिवर्तित कर दिया है । आर्थिक दृष्टि से भी दुनिया एक होनी जा रही है । कोई भी देश अपनी अर्थ-व्यवस्था में आत्मनिर्भर नहीं । न कोई देश सिकं अपने लिए उत्पादन करता है । आजकल बाजार विश्वव्यापी है । युद्ध अधिक विनाशकारी और विस्फोटकी हो गये हैं । अब वे सीमित क्षेत्र में नहीं होते । हम बीसवीं शताब्दी में दो भयंकर युद्धों का अनुभव ले चुके हैं और तीसरा विश्व युद्ध किसी भी समय हो सकता है ।

अन्तर्राष्ट्रवाद के लाभ—(१) युद्धों का अन्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रवाद एकमात्र हल है । यह अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने के लिए बल के स्थान पर तर्क का उपयोग करने के लिए होता है । आजकल युद्ध बड़े विनाशकारी हो गये हैं, उनसे जन-धन की बड़ी हानि होती है, लाखों आदमी मारे जाते हैं, और इनमें भी अधिक गृह-हीन हो जाते हैं । आजकल युद्ध अर्धनैतिक आवासी पर भी चलना ही मसर झलते हैं । असल में तो कैंटरी और मकान, हवाई जहाजों का पहला शिकार होने हैं । उनसे लाखों स्त्रियाँ विधवा हो जाती हैं, और बच्चे अनाथ हो जाते हैं । अन्तर्राष्ट्रवाद इन सब बुराइयों और मुसीबतों का इलाज है ।

(२) शांतिस्थिति पर होने वाला मारा खर्च घट कर आता है । इससे कोई उत्पादक कार्य नहीं होता । अन्तर्राष्ट्रवाद के होने पर यह शांति खर्च राष्ट्र-निर्माण के कामों में लगाया जा सकता है । अगर शांतिस्थिति पर कोई खर्च न हो तो दुनिया के लोगों की सब सामाजिक और आर्थिक बुराइयाँ दूर हो जाएँ ।

(३) राष्ट्रवाद के जो लाभ बताये जाते हैं वे अन्तर्राष्ट्रवाद में कम नहीं हो जाएंगे । सघानीय ढाँचे वाले अन्तर्राष्ट्रीय राज्य के होने पर प्रत्येक राष्ट्र को अपने भीतरी मामलों पर पूरी आजादी रहेगी ।

(४) अन्तर्राष्ट्रवाद सब आर्थिक ईर्ष्याओं को खत्म कर देगा । सब राष्ट्र एक दूसरे के साधनों का लाभ उठा सकेंगे । जो राज्य जो वस्तुएँ बनाने के लिए सब से

अधिक संपृक्त हैं, उसे उन वस्तुओं के बनाने में विशेष योग्यता शामिल करने का मौका मिलेगा।

(५) अन्तर्राष्ट्रवाद से राष्ट्रों में सस्कृतियों और विचारों का बाधाहीन विनिमय हो सकेगा। प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों की वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक सफलताओं का लाभ उठा सकेगा। इस प्रकार सारे मानव-समाज का जीवन अधिक सम्पन्न होगा। कुछ पिछड़े हुए राष्ट्र भी दूसरे आगे बढ़े हुए राष्ट्रों के सम्पर्क से तरक्की करेंगे।

अन्तर्राष्ट्रवाद के मार्ग की रूकावट—(१) राज्यों की सर्वोच्चता या प्रभु सत्ता अन्तर्राष्ट्रवाद के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। राज्य अपनी सर्वोच्चता पर किसी भी तरह रोक लगाने को तैयार नहीं। अन्तर्राष्ट्रवाद में राज्यों की बाह्य सर्वोच्चता पर कुछ पाबन्दियाँ लगाना जरूरी है।

(२) अन्तर्राष्ट्रवाद में साम्राज्यवाद की कोई जगह नहीं। विश्व-राज्य का परीक्षण तब तक तत्कल नहीं हो सकता, जब तक हर तरह का साम्राज्यवाद शासक न हो जाए। पर साम्राज्यवादी राष्ट्र अपने उपनिवेशों को आजादी देने को तैयार नहीं।

(३) अन्तर्राष्ट्रवाद में एक और रूकावट मूलबस या रंग की उच्छता है। विश्व राज्य में छोटे-बड़े सब राज्य और काले-बोरे सब लोग समान स्तर पर खड़े होंगे।

(४) अन्तर्राष्ट्रवाद की सफलता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के फैसलों को लागू करने के निमित्त एक प्रबल सेवा का होना अनिवार्य है। पर अब तक ऐसी सेवा बनाना सम्भव नहीं हुआ।

(५) अन्तर्राष्ट्रीय सेना के अभाव में अन्तर्राष्ट्रवाद तभी सफल हो सकता है, जब मानव प्रकृति में आमूल परिवर्तन हो जाए। मनुष्य अपना स्वार्थ और लोभ छोड़ दे और तर्क के अनुसार चलने को तैयार हो। मनुष्य में अब भी पशु का अंश बड़ा प्रबल है।

संयुक्त राष्ट्र संधि

राष्ट्र संधि को १९३९-४५ के दूसरे विश्व युद्ध ने खतम कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संधि, जो अब इसके स्थान पर है, अप्रैल १९४५ में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में पास किए गये संयुक्त राष्ट्र संधि घोषणापत्र से पैदा हुआ। राष्ट्र संधि की तरह संयुक्त राष्ट्र संधि भी ससार में छान्ति बनाए रखने के लिए बनाया गया है। लोग महमूश करते हैं कि दुनिया को कानून और निष्पक्ष न्याय की छत्रछाया में लाना जरूरी है। अन्तर्राष्ट्रीय सगर्बी का निपटारा बातचीत और तर्क से होना चाहिए, बल प्रयोग से नहीं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य और प्रयोजन—संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में संयुक्तराष्ट्र संघ के ये लक्ष्य और प्रयोजन बताये गये हैं—

(१) संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला प्रयोजन अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा कायम रखना है। यह नष्ट शान्ति पर खाने वाले सत्रों को रोकने या हटाने और जाग्रत के कार्यों तथा अन्य शान्ति-भंगों को दमने के लिए सब शान्तिपूर्ण साधन उपयोग में लाएगा और न्याय तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार ही अन्तर्राष्ट्रीय झगड़े निपटायेगा।

(२) संयुक्त राष्ट्र संघ को मूल मानवीय अधिकारों का आदर करना होगा।

(३) संयुक्त राष्ट्र संघ का सब राष्ट्रों के लोगों में दोस्ती का सम्बन्ध बनाने के उपाय करने चाहिए। इसका यह लक्ष्य भी है कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय ढंग की अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने में सब देशों का सहयोग स्थानित किया जाए।

(४) संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्य संयुक्त संगठन होने के नाते इन सामान्य समस्याओं की निधि के लिए राष्ट्रीय कार्यों के समन्वय के केंद्र के रूप में काम करेगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग

संयुक्त राष्ट्र संघ के पोषण-रस के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में उसके सिद्धान्त और लक्ष्य बताए गये हैं, और दूसरे में इसके सदन का वर्णन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के छ मुख्य अंग हैं और कई सहायक अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग ये हैं—

१. बृहत् सभा या जनरल असेम्बली।
२. सुरक्षा परिषद।
३. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय।
४. सचिवालय।
५. सामाजिक और आर्थिक परिषद।
६. दृष्टीक्षिप्त बौद्धिक या न्यायिक परिषद।

सहायक अंग ये हैं—

१. अन्तर्राष्ट्रीय यम समिति (I. L. O.)
२. खाद्य और कृषि समिति (F. A. O.)
३. संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा-विज्ञान-संस्कृति-समिति (U.N.E.S.C.O.)
४. विश्व स्वास्थ्य-समिति (W. H. O.)
५. निस्त्रीकरण आयोग।
६. पुनर्निर्माण और विकास का अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (I. B. R.)
७. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राविधि (I. M. F.)

बृहत्सभा या जनरल असेम्बली—यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सब से बड़ा अंग है। अब इसके कुल ८० सदस्य हैं। प्रत्येक सदस्य राज्य का एक मत होता है। पर उस

५ प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। इस प्रकार सब सदस्य राज्यों को इस सभा में समानता की स्थिति प्राप्त है। जनरल असेम्बली मुख्यतः एक विचार करने वाली सभा है और इसकी मुलाकात किसी राज्य के विधान मण्डल से की जा सकती है। यह घोषणा पत्र के अन्तर्गत हर बात पर विचार कर सकती है। असेम्बली का अध्यक्ष हर सत्र के लिए निर्वाचित होता है। असेम्बली दो तिहाई बहुमत से सुरक्षा-परिषद के छ अस्थायी सदस्य दो वर्ष के लिए चुनती है। यह आर्थिक और सामाजिक परिषद को १८ सदस्य भी चुनती है। ट्यूटोरशिप कौंसिल के सदस्य और अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के १५ जज भी असेम्बली द्वारा चुने जाते हैं। महासचिव, जो संयुक्त राष्ट्र सच के सचिवालय का अध्यक्ष है, इसी सभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। असेम्बली नये सदस्य प्रविष्ट करने और किसी वर्तमान सदस्य को निकालने के बारे में भी फैसला करती है।

सुरक्षा परिषद—यह संयुक्त राष्ट्र सच की कार्यपालिका है। सदस्य राज्यों ने विश्व शांति और सुरक्षा कायम रखने की जिम्मेवारी इसे सौंप दी है। प्रत्येक सदस्य राज्य ने इसके कर्तव्य मानने की शक्ति की है। सुरक्षा परिषद में कुल ११ सदस्य हैं और वे दो प्रकार के हैं अस्थायी और स्थायी। ५ स्थायी सदस्य ये हैं—चीन, यूनाइटेड किंगडम (इंग्लैंड), फ्रांस, सोवियत संघ और यूनाइटेड स्टेट्स। ६ अस्थायी सदस्य जनरल असेम्बली द्वारा दो वर्ष के लिए चुने जाते हैं।

कार्यपालिका सभा होने के कारण सुरक्षा परिषद पर दुनिया की हिफाजत करने और अगर आवश्यक हो तो बल प्रयोग में विश्व शांति कायम रखने का भार है। यह संयुक्त राष्ट्र भग्न का सबसे महत्वपूर्ण और सक्रिय अंग है। इसका सच लगातार रहता है। सुरक्षा परिषद के सब महत्वपूर्ण फैसला के लिए सात मत होने आवश्यक हैं। आर्थिक अनुनास्तियों (Economic sanctions), विवादों के पक्ष निर्णय और सैनिक बलप्रयोग सम्बन्धी सब मामले सात मतों द्वारा ही तय होते हैं। इन सात में से ५ मत स्थायी सदस्यों के होने अनिवार्य हैं। इस प्रकार, सुरक्षा परिषद के किसी कार्य पर ५ बड़ी शक्तियों में से कोई भी वीटो या अभियोग का प्रयोग कर सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय—यह संयुक्त राष्ट्र भग्न का न्यायालय है। इसके सामने सदस्यों द्वारा भी मामले लाने या सकते हैं और गैर सदस्यों द्वारा भी। पर यह न्यायालय मामलों की सुनवाई तभी कर सकता है, यदि विवाद के दोनों पक्ष इसके क्षेत्राधिकार को मानें। इस न्यायालय का स्थायी अधिष्ठान हागे में हेग नगर में है। इसमें १५ सदस्य हैं। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश सामान्यतया ९ वर्ष के लिए चुना जाता है।

सचिवालय—संयुक्त राष्ट्र सच के सचिवालय में एक महासचिव और अन्य कर्मचारी होते हैं। महासचिव सुरक्षा परिषद की सफाई पर जनरल असेम्बली द्वारा नियुक्त किया जाता है। कर्मचारियों की नियुक्ति जनरल असेम्बली के विनि

यमों के अन्तर्गत महासचिव द्वारा की जाती है।

सामाजिक और आर्थिक परिषद—यह एक महत्वपूर्ण निदेश है जो उन सब आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों पर विचार करती है, जो संसार के देशों को परेशान करने हैं। इनका मुख्य प्रयोजन अनुसंधान और गवेषणा है। इसके १८ सदस्य हैं। वे जनरल असेम्बली द्वारा ९ साल के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक ३ वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य निवृत्त हो जाते हैं।

इंस्टीट्यूट ऑफ़ मित्र—इस निदेश का काम उन क्षेत्रों पर जो इसके न्यास के अधीन दिये जाए प्रभावित करना है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद घटी शक्तियों से जीने गये राज्य क्षेत्रों और पुराने राष्ट्र संघ के अधिदेशों का प्रभावित करना है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की सकलता—संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिकतर सकलता राजनैतिक क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में हुई है। अपने परों से उलटने हुए लोगों को फिर से बसाने में संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्वासि अधिकरण की, लोगों का मुकाबिला करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन की, और दुनिया के अनाज की विनियमित करने में खाद्य और कृषि संगठन की सफलताएं उल्लेखनीय हैं। शिक्षा-विज्ञान-संस्कृति संघ सामाजिक शैक्षणिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में उपयोगी काम कर रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय धन संगठन की मददों का, कम से कम जीवन स्तर लागू करने में सफलता हुई है। विश्व बैंक युद्ध से घबराते देशों को अपनी अर्थ-व्यवस्था सुधारने के लिए ऋण दे रहा है। राजनैतिक क्षेत्र में भी संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व युद्ध रोकने में अब तक सफल रहा है। इसने विश्व राजनीति की शिक्षा को बहुत व्यापक कर दिया है। यह एक महत्वपूर्ण लाभ है। आज अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग १० वर्ष पहले की अपेक्षा बहुत अधिक है। विश्व लोकमत का परिमाण और शक्ति पहले से अधिक तेजी से बढ़ रही है। अन्तर्राष्ट्रीय नेमा के अभाव में, योजनित संयुक्त राष्ट्र संघ के फैसलों के पीछे प्रभावकारी बल है।

३. **संयुक्त राष्ट्र संघ की विद्यतता**—संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता राजनैतिक क्षेत्र में अधिक स्पष्ट है। यह बात ठीक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया को बहुत से संकटमय प्रश्नों पर युद्ध के बचावा है, पर फिर भी ब्यापकता से माना जाता है कि इसने शान्ति की आशा पूरी नहीं की। अब तक भी मय से छुटकारा नहीं हुआ। राजनैतिक क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं:—

१. जर्मनों के एकीकरण की समस्या अब तक हल नहीं हुई।
२. हिन्दचीन के सवाल का अन्तिम निबटारा नहीं हुआ।
३. कासीर के सवाल पर अब तक गरिबीय दूर नहीं हुआ।
४. दक्षिण अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र संघ एंग्लोनों और अफ्रीकियों को बुनि-

मादो मानवीय अधिकार प्राप्त नहीं कर सका ।

५. राष्ट्रीय राज्यों द्वारा सरकारों के सचय को संयुक्त राष्ट्र सभ नहीं रोक सका । यह परमाणु शक्ति पर अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण नहीं कर सका ।

संयुक्त राष्ट्र सभ की श्रुतियाँ या इसकी विप्लवता के कारण—१. तत्कालीन शक्ति गुटों में विभाजन—संयुक्त राष्ट्र सभ की ४ प्रमुख श्रुतियाँ हैं । संयुक्त राष्ट्र सभ दो प्रमुख शक्ति गुटों अर्थात् एम्को-अमरीकन और रूसी, कम्युनिस्ट गुट में बँटा हुआ है । उनमें आदर्यों का विरोध है । इस विरोध का परिणाम है शक्ति राजनीति । इस कारण संयुक्त राष्ट्र सभ में किसी समस्या पर निष्पक्ष विचार सम्भव हो गया ।

२. वीटो या अनिवेध की शक्ति—सुरक्षा परिषद का गठन बहुत अधिक अनोक्तनीय है । ५ स्थायी सदस्य इसका नियंत्रण करते हैं । प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों को अलावा अन्य मामलों में कोई भी सदस्य परिषद के फैसले को वीटो कर सकता है चाहे दोष दसों सदस्य इसके पक्ष में हों । इसलिए वीटो राष्ट्र सभ की सफलता में बड़ी रुकावट है ।

३. अन्तर्राष्ट्रीय सेना का अभाव—संयुक्त राष्ट्र सभ के पास अपने फैसले लागू करने के लिए कोई सेना या पुलिस नहीं । इसलिए सदस्य-राज्य संयुक्त राष्ट्र सभ के फैसले के अनुसार काम करने से पहले अपना हित और सुविधा देखते हैं ।

४. पुरी शक्तियों की सदस्यता पर रोक थी—राष्ट्र सभ की तरह संयुक्त राष्ट्रीय जनरल असेम्बली में भी सभी राज्यों के, और उन राज्यों के, जिनका हित विजेताओं के प्रति अनुकूल नहीं था, प्रवेश पर रोक थी । जर्मनी और जापान मक भी संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्य नहीं हैं । यह बान म्याम और औषिय के साथ मिझातों के विषय है ।

संयुक्त राष्ट्र सभ की विफलता के मुख्य कारण उसकी ये श्रुतियाँ ही हैं । इसकी विफलता का एक कारण यह भी है कि अभी राष्ट्रवाद की भावना बड़ी प्रबल है । हम सब लोग अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता को अनुभव करते हैं, पर हम विद्वद सरकार के लिए तैयार नहीं आलूम होते । साम्राज्यवादी प्रवृत्ति भी अभी खत्म नहीं हुई । कुछ सीमा में सब काम कर रहे हैं ।

संयुक्त राष्ट्र सभ का भूतपूर्व—संयुक्त राष्ट्र सभ की ऊपर बताई हुई विफलता पर विचार करने पर हमें यह दिखाई देने लगता है कि राष्ट्र सभ की तरह यह भी खत्म हो जाएगा । पर इस अनुमान को स्वीकार करना, अभी मर्यादाधिक और आत्महत्या के समान है । अगामधिक तो इसलिए है कि अभी हम कुछ नष्ट नहीं हुआ । यह आत्महत्या के समान इसलिए है । क्योंकि हम मानव के जीवित रहने के लिए बनाए गए एकमात्र साधन को खत्म कर रहे होंगे । यह मे मानव जाति के खत्म हो जाने का सतरा हर समय बना हुआ है । यह भी सच है कि अमरीका और रूस के मौजूदा संबंध युद्ध से कुछ कम नहीं हैं । तो भी आपने-सामने बँठकर

मानवीय करने में मतभेद दूर होने में प्रायः मदद मिलती है। मंगुसा राष्ट्र सभ मानव जाति के इतिहास में एक बहुत महत्त्वपूर्ण और युगारम्भ करने वाली सभ्या है। इसके साथ गम्यता की उच्चतम और भद्रतम आकाशाएँ जुड़ी हुई हैं। यह तूफानों भरी दुनिया में हो सने वाली सुरक्षा का एकमात्र आधार है। अगर संयुक्त राष्ट्र सभ विफल होता है तो अगल में दुनिया के लोग हो विफल होने हैं।

शिक्षा-विज्ञान-संस्कृति-सभ—मंगुसा राष्ट्रीय शिक्षा-विज्ञान-संस्कृति सभ संयुक्त राष्ट्र सभ का एक सहायक अंग है। १९४६ में इसे शुरू करने का लक्ष्य संसार के राष्ट्रों की शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्रों में निकट लाना था।

अंतर्राष्ट्रीय धर्म संगठन—अंतर्राष्ट्रीय धर्म संगठन का लक्ष्य सारी दुनिया के मजदूरों को काम की मानवीयता अवस्थाएँ और न्याय प्राप्त कराना है। यह संस्था राष्ट्र सभ में ही संयुक्त राष्ट्र सभ को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय धर्म संगठन ने मजदूरों की दशा समालने के लिए बहुत कुछ किया है। इसने मजदूरों की उचित मजदूरी, काम के निश्चित घंटे और रोग, बुढ़ापे और वंशजगती में मुक्ति दिलाने की कोशिश की है।

सारांश

प्रत्येक नागरिक सारी मानव विरासती का भी मालिक है। इस प्रकार नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी की राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद की समस्याओं का अध्ययन भी करना जरूरी है।

राष्ट्रियता—राष्ट्रियता शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग में आता है जो एकत्व की भावना से सगठित होने हैं। इस प्रकार राष्ट्रियता के लिए परमावश्यक बात यह है कि लोगों में साझी भावनाएँ और विचार हों। वे बाहर में देखने में एक-दूसरे से भिन्न दिखाई दे सकते हैं। पर बाहरी सादृश्य की कुछ बातों में एकत्व की भावना पैदा होने में मदद मिलती है, ये बातें राष्ट्रियता की वारक कहलाती हैं, और वे हैं (१) भाषा मूलवंश, (२) साझी भाषा, (३) साझा धर्म, (४) साझा निवास, (५) साझा इतिहास, और (६) साझी संस्कृति। यद्यपि इनमें से कोई भी कारक राष्ट्रियता की भावना पैदा करने के लिए परमावश्यक नहीं है तो भी किसी जाति में उनमें से जितने अधिक वारक होते हैं, एकत्व की भावना उतनी ही प्रबल होती है।

राष्ट्र—राष्ट्र वह राष्ट्रियता है जिसने अपने आप को एक स्वयंत्र या स्वतंत्र होने की इच्छा वाले राजनैतिक निकाय के रूप में सगठित कर लिया है, या राष्ट्र राष्ट्रियता और राज्य का जोड़ है।

राष्ट्रवाद—राष्ट्रवाद राष्ट्रिय हित, एकात्मता और स्वतंत्रता में अनुराग या उनके समर्थन को कहते हैं। अथवा राष्ट्रवाद उस भाव को कह सकते हैं जो किसी राष्ट्रियता की एक होने और अपने लिए आजादी हासिल करने के लिए प्रेरणा देता है।

राष्ट्रवाद के गुण—(१) यह गुलाम राष्ट्रों को स्वतंत्र होने की प्रेरणा देता है। (२) इस भावना के होने पर हर व्यक्ति राष्ट्रीय उन्नति में अपना अधिक से अधिक हिस्सा देता है। (३) इसमें राष्ट्रों में आने बहने के लिए स्वस्थ प्रतियोगिता पैदा होती है। इस प्रकार सारी मानव-जाति का जीवन समृद्ध होता है। (४) राष्ट्रीय राज्य में ही सर्वोच्चता और स्वाधीनता का सबसे अच्छा मेल मिलता है।

दोष—(१) अन्तर्देशीय राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद को जन्म देता है। (२) राष्ट्रों के साधनों में अधिक अन्तर होने से आपसी ईर्ष्या और युद्ध पैदा होते हैं। (३) युद्धों में बड़ा बिलाल होता है। (४) राष्ट्रवाद में अनेक छोटे छोटे और कमजोर राज्य बन जाते हैं।

अन्तर्राष्ट्रवाद—यह ऐसी प्रणाली या व्यवस्था है जिसमें अपना धानन आप करने वाले और आत्मसम्मान को सब राष्ट्र सगता, सदभावना और तर्क के बल से सब दर क्षति से जीवन बिताने के योग्य होने हैं। इसका लक्ष्य यह है कि राष्ट्रों में युद्ध की जगह तर्क को प्रतिष्ठित किया जाए।

पर अन्तर्राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद एक दूसरे के विरोधी नहीं। बल्कि राष्ट्रवाद अदृष्टि और मानव-जाति के बीच एक कड़ी है। अन्तर्राष्ट्रवाद में राष्ट्रीय राज्यों की स्थिति बड़ी होगी जो किसी म्यान में राज्यों या प्रान्तों की होती।

अन्तर्राष्ट्रवाद की जन्म देने वाली शक्ति—१९वीं शताब्दी तक कोई भी अन्तर्राष्ट्रवाद पर गंभीरता से विचार नहीं करता था। इस दिशा में पहला गंभीर प्रयत्न राष्ट्र सच था। जो विश्व युद्ध के भयान अनुभव और देशों की एक दूसरे पर आधिक निर्भरता से मजबूर होकर राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रवाद की ओर जा रहे हैं। वैज्ञानिक आविष्कारों ने सारी दुनिया को एक इकाई बना दिया है।

अन्तर्राष्ट्रवाद के लाभ—(१) यह युद्ध घटाने का एकमात्र तरीका है। यह बल की जगह तर्क के प्रयोग के लिए कहता है। (२) इसके होने पर साम्राज्यों पर तर्क होने वाला घन राष्ट्र-निर्माण के कामों में लगाया जा सकता है। (३) अन्तर्राष्ट्रवाद से राष्ट्रवाद की कोई हानि नहीं होती। (४) अन्तर्राष्ट्रवाद सब आर्थिक ईर्ष्याओं को खत्म कर देगा। (५) इसमें सन्तुष्टियों और विचारों का बाधाहीन आदान प्रदान हो सकेगा।

अन्तर्राष्ट्रवाद में बाधाएँ—राज्य बाहरी मामलों में अपनी सर्वोच्चता छोड़ने की तैयार नहीं। (२) साम्राज्यवादी राष्ट्र साम्राज्यवाद छोड़ने की तैयार नहीं। (३) मूलवशील और रंग सम्बन्धी उत्कृष्टता के विचार राष्ट्रों में अब भी मौजूद हैं। (४) मनुष्य में पसुता जब भी बहुत प्रबल है, और इसलिए अभी युद्धों से छुटकारा नहीं मिल सकता।

समुन्नत राष्ट्र सच—इसका जन्म अप्रैल १९४५ में सान फ्रांसिस्को में पास किए गए समुन्नत राष्ट्रीय घोषणा-पत्र द्वारा हुआ। इसने लक्ष्य और प्रयोजन ये हैं,—

(१) युद्ध से बचने के शान्तिपूर्ण उपाय अपना कर अन्तर्गोष्ठ्य शांति और सुरक्षा बनाए रखना । (२) मूल मानवीय अधिकारों के प्रति सम्मान कायम करना । (३) राष्ट्रों में धार्मिक, सामाजिक और सामूहिक मामलों में सहयोग करना ।

संयुक्तराष्ट्र संघ के अंग—इसमें ६ मुख्य अंग और कई महापक्ष संग हैं । मुख्य अंग ये हैं :—

(१) सुरक्षा मंडल या जनरल असेम्बली—इसमें ८० सदस्य हैं, और प्रत्येक का एक मत है । यह संयुक्त राष्ट्र संघ का विधानमण्डल है । इसने कार्य विचारारमक और निर्वाचन सम्बन्धी हैं ।

(२) सुरक्षा परिषद—यह संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाहिका है । इसमें ११ सदस्य हैं, जिनमें से पाँच स्थायी सदस्य हैं । स्थायी सदस्यों की वीटो या प्रतिषेध की शक्ति भी है । इस पर जहाँ तक हो सके पंचनिर्णय द्वारा और अन्यथा दल प्रयोग द्वारा विवाद शांति कायम रखने का गार है ।

(३) आर्थरगोष्ठ्य न्यायालय—इसमें १५ न्यायाधीश हैं और यह हेग में है । यह अन्तर्गोष्ठ्य विधि के अधीन मामले सुन संभाला है परन्तु यह है कि दोनों पक्ष इसके क्षेत्राधिकार की स्वीकार करें ।

(४) सांविधानिक—इसमें एक महासचिव और बहुत से कर्मचारी होते हैं ।

(५) सामाजिक और आर्थिक परिषद—इसमें १८ सदस्य हैं, और यह संघ के आर्थिक और सामाजिक मामलों पर विचार करती है ।

(६) दुस्तीनिष्ठ कौमिल—यह उन क्षेत्रों पर ध्यान करती है, जो इसके न्याय के अधीन होते हैं ।

संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता—संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता अधिकतर राजनीति से निम्न क्षेत्र में हुई है । राजनैतिक क्षेत्र में भी संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व युद्ध रोकने में सफल रहा है । इसने पहले की अपेक्षा बहुत अधिक लोगों को विश्व-राजनीति का परिचय करा दिया है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता और उसके कारण—इसकी विफलता राजनैतिक क्षेत्र में अधिक उल्लेखनीय रही है । अबतक दुनिया भय से भूक्त नहीं हो सकी । संयुक्त राष्ट्र संघ की पार प्रमुख त्रुटियाँ या विफलता के चार कारण हैं :—(१) सदस्यों का शक्ति गुटों में बंट जाना, (२) पाँच बड़ी शक्तियों की वीटो या प्रतिषेध की शक्ति, (३) संयुक्त राष्ट्र संघ के पास करने फैसलों की लागू करने के लिए कोई फौज या पुलिस नहीं है, (४) पुरी शक्तियों की सदस्यता पर रोक लगा दी गई ।

यह सब होते हुए भी संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व-इतिहास में सब से महत्वपूर्ण और मुक्त-प्रवर्तक संस्था है । यह इस दुर्गम और लूटने भरे समार-द्वन्द्व में सुरक्षा का एकमात्र सहाय है ।

प्रश्न QUESTIONS

१. राष्ट्रवाद शब्द से आप क्या समझते हैं ? इसकी मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ?
(५ वि० गितानगर, १९४३)
- 1 What do you understand by the term 'Nationalism'? What are its salient features? (P U Sep 1953)
२. राष्ट्रवाद को पैदा करने वाले कारक कौन-कौन हैं ?
- 2 What are the factors contributing to 'Nationalism'?
३. राष्ट्रवाद के गुणों और दोषों को परिभाषा करो ?
- 3 Examine the merits and demerits of nationalism
४. अन्तर्राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं ? इसे पैदा करने वाली शक्तियाँ कौन कौन सी हैं और इनके मार्ग में कौन कौन से रुकावटें हैं ?
- 4 What do you understand by 'Internationalism'? What are the forces contributing to it and what are the hinderances in its way?
५. समुच्चय राष्ट्र संध के उद्देश्य क्या हैं ? (५० वि० अप्रैल, १९५०)
- 5 What are the objects and aims of U N O? (P U April, 1950)
६. अन्तर्राष्ट्रीयता के क्या लाभ हैं ?
- 6 What are the advantages of Internationalism?
७. समुच्चय राष्ट्र संध के बुनियादी सिद्धान्त और घन कौन-कौन से हैं ?
(५० वि० गितानगर, १९५२)
- 7 What are the basic principles and organs of the United Nations Organisation? (P U Sep 1952)
८. अन्तर्राष्ट्रीय शांति के सगंधे रूप में समुच्चय राष्ट्र संध की सफलता और विफलता पर एक छोटी टिप्पणी लिखो। इसकी कौन-कौन सी मुद्दियाँ हैं ?
- 8 Write a short note on the success and failure of the U N O as an organ for international peace. What are its defects?
९. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखो —
(१) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन।
(२) समुच्चय राष्ट्रीय शिक्षा विज्ञान-संस्कृति संध।
(३) सुरक्षा परिषद।
Write short notes on —
1 The International Labour Organisation
2 The U N E S C O
3 Security Council

